राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या: 15

शुक्रवार,

03 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 268

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र जी मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल मीणा।

झाडोल में डी एम एफ टी से स्वीकृत कार्य

269. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर), (श्री बाबु लाल (झाडोल) के स्थान पर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र झाडोल में विगत दो वर्षों में डी एम एफ टी योजना के अन्तर्गत कितने कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान एवं पैट्रोलियम मंत्री (श्री प्रमोद भाया): विधान सभा क्षेत्र झाडोल में वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 (दिनांक 27.02.2023 तक) में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से 83 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 22 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त 22 कार्यों में से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान में समस्त कार्य प्रगतिरत हैं। विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी एम एफ

(श्री अमृतलाल मीणा)

टी के कार्यों के प्रस्ताव विधायकों से लिये जाते हैं परंतु उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं होती हैं या कलेक्टर अपने लेवल पर प्रस्ताव बदल लेते हैं। विशेष रूप से उदयपुर जिले में झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कों के लिये प्रस्ताव दिये थे, उनकी आज तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। प्रशासनिक स्वीकृतियां निकल गईं, लेकिन वित्तीय स्वीकृतियां आज तक जारी नहीं हो पाई हैं। इसका कारण सहित बताएं।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद वित्तीय स्वीकृति में एस्टिमेट बनना है या कोई डबल स्वीकृति जारी हो गई, दूसरी योजना में कोई कार्य सैंक्शन है, कई बार इस तरह के टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं और इसलिए विलम्ब हो जाता है। माननीय सदस्य की पीड़ा वाजिब है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इनकी जो प्रशासनिक स्वीकृतियां निकल चुकी हैं, शासन की ओर से जिला कलेक्टर को निर्देशित करके जल्दी से जल्दी उनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करवा दी जायेंगी।

प्रश्न संख्या 270

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

गोचर भूमि का आबादी क्षेत्र में परिवर्तन

271. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जो काश्तकार वर्षों से जिस भूमि पर काबिज व कृषि कर रहे हैं उस भूमि को पटवारियों द्वारा एक सूची बनाकर विशेष आबंटन सूची में डाल दिया गया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने काश्तकार हैं जो उक्त सूची में सम्मिलित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को विशेष सूची से हटाकर वर्षों पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की गोचर भूमि को आबादी क्षेत्र में घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा रकबा राज भूमि को विशेष आबंटन हेतु विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा आरक्षित किया गया था। कुछ प्रकरणों में पूर्व में सामान्य श्रेणी में आबंटित भूमि/गैर खातेदार काश्तकारों की भूमि विशेष आबंटन के लिए आरक्षित कर दी गई थी। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के तहसील घड़साना में ऐसे 7 प्रकरण तहसील रावला में 19 प्रकरण तथा तहसील अनूपगढ़ में 10 प्रकरण इस प्रकार विशेष आबंटन के कुल 36 प्रकरण चिह्नित हैं, जिनमें काश्तकार मौके पर काबिज है।

(2) विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकारों के प्रकरणों का परीक्षण उपरान्त जिन प्रकरणों में काश्तकारों का कब्जा विधिक रूप से प्रमाणित/योग्य पाया जाता है, उन प्रकरणों में भूमि को विशेष आबंटन से मुक्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती रही है/की जाती है।

(3) विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गोचर भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है, उसमें बताया गया है कि अनूपगढ़ में इस प्रकार के 10 प्रकरण, घड़साना तहसील में 7 और रावला में 19 प्रकरण, कुल 36 प्रकरण चिह्नित किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो काश्तकार काफी वर्षों से काबिज हैं, क्या सरकार राजस्थान उपनिवेशन आबंटन नियम, 1975 के नियम 21 (ए) के तहत इन्हें आबंटन करने का विचार रखती है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दूसरे खण्ड में मैंने कहा है इनके जितने भी प्रकरण हैं, उनका हम परीक्षण करवा रहे हैं, परीक्षण करवा कर उनको जल्दी ही राहत देंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): इसमें आप नियम के अनुसार कमेटी बनाकर कर सकते हैं। क्या आप कमेटी बनाने का विचार रखते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें जिला कलेक्टर देखते हैं। जिला कलेक्टर के पास जितने भी आवेदन पहुंच गये हैं, जो पहले डी-नोटिफाइड हुआ है, वह हमने कह दिया कि गलत

(श्री शाले मोहम्मद)

हुआ है। जिला कलेक्टर नियमानुसार पूरा परीक्षण करायेंगे कि कितने लोग हैं, अभी काबिज हैं, क्या स्थिति है। जैसे ही यह पूरी जानकारी आयेगी, वहां जिला कलेक्टर के स्तर पर ही यह सब चीज हो जायेगी। इसमें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। वह राज्य सरकार को भेजेंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह। अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। सॉरी, इधर बैठे हैं। मेरी निगाह इधर ही थी कि लाखन सिंह जी की सीट इधर है।

करौली में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

272. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में विगत चार वर्षों में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्तमान में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र करौली में विगत 4 वर्षों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया है।

(2) प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या एक में ही समाहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्तमान में बाल विकास परियोजना, करौली के अधीन 261 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना, हिण्डौन सिटी के आंशिक क्षेत्र में 82 आंगनबाड़ी केन्द्र सहित कुल 343 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.07.2015 द्वारा सूचित किया गया कि आई सी डी एस सेवा विस्तार हेतु अभी नवीन केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

इसके उपरान्त भी स्थानीय प्रतिनिधियों/जन-प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए जनसंख्या एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 8000 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2000 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की गई है, जिसकी पालना में राज्य में सर्वे करा कर निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं या जो किराये पर चल रहे हैं, क्षत-विक्षत भवन हैं, उनमें बच्चों को खतरा भी है, क्योंकि कई बार छत गिर जाती है। मंत्री महोदय, क्या आप इनको बनाने की इच्छा रखती हैं या नहीं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में नरेगा की गाइडलाइन है और जो हमारा स्थानीय पैसा है, दोनों के कंपोजिट से नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाते हैं। वित्तीय सुविधा होते ही हम इन केन्द्रों को भी आगे बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री लाखन सिंह (करौली): अभी चार साल में तो एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं बनाया गया है और न ही भवन बनाये गये हैं। अगर बनाये गये हैं तो आप बताएं कि कितने भवन बनाये गये हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी चार साल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं बनाये गये हैं। हम लोग उनका सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। जो भवन हैं, उनको माडर्नाइज कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि नरेगा और इनका कंपोजिट हमें जल्दी मिले तो हम इन लोगों के भवनों को आगे बनवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन (नदबई) में नवीन खण्ड कार्यालय की स्थापना

273. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय उच्चैन में नवीन खण्ड कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय उच्चैन में नवीन खण्ड कार्यालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

खण्डीय कार्यालय का सृजन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल 66 पंचायतें हैं, जिनमें 36 पंचायतें नदबई उप खण्ड मुख्यालय पर हैं, एक नगरपालिका क्षेत्र है नदबई, एक नगरपालिका क्षेत्र उच्चैन है, 8 पंचायतें सेवर में हैं, जो मेरी विधान सभा में आती हैं। 20 पंचायतें उच्चैन में और उसके साथ-साथ दो पंचायतें रूपवास में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र हैं, चाहे वह भरतपुर हो, वैर हो, बयाना हो, डीग हो, कामां हो, सभी पर एक्स ईएन आफिस है लेकिन केवल नदबई में नहीं है, जिसकी दूरी लगभग सवा सौ किलोमीटर है। नदबई से एक्स ईएन आफिस, भरतपुर 40-45 किलोमीटर दूर है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी बोल चुके हैं कि विचार ही नहीं है तो अब आप क्या बोल रहे हैं?

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): और इसी तरह उच्चैन से एक्स ईएन आफिस लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। क्या मंत्री जी इस तरह की कोई मंशा रखते हैं कि वहां एक्स ईएन आफिस खोला जाये?

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे दिया है। इसमें विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 274

श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न, श्री प्रताप सिंह।

छीपाबड़ौद लहसुन मण्डी की चारदीवारी का निर्माण

275. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद में लहसुन की विशेष मण्डी संचालित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मण्डी हेतु कितनी भूमि कब-कब आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों की सुविधाओं को देखते हुए उक्त आबंटित जमीन पर चारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। छीपाबड़ौद में जिन्स लहसुन गौण मण्डी संचालित है। छीपाबड़ौद में लहसुन मण्डी यार्ड हेतु 33 बीघा भूमि का आबंटन किया है। आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) गौणमण्डी छीपा बड़ौद को आबंटित 25 बीघा भूमि पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है।

जिला कलेक्टर, बारां के आदेश दिनांक 25.11.2022 द्वारा आबंटित 8 बीघा भूमि का कब्जा मण्डी समिति को प्राप्त नहीं हुआ है। मण्डी समिति को उक्त भूमि का कब्जा मिलने के उपरान्त चारदीवारी निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि शुरू में जब मंडी बनी थी, उस समय 25 बीघा जमीन अलाट हुई थी। चूंकि स्पेशल मंडी है पूरे प्रदेश का और मध्य प्रदेश का लहसुन वहां पर बिकने के लिए आता है। किसान लोग आते हैं। उनके ट्रैक्टरों की लाइन रोड पर लग जाती है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए 8 बीघा जमीन जो कि 25.11.2022 को अलाट हुई, इसको अब तक कब्जे में क्यों नहीं लिया है? अब तक पजेशन क्यों नहीं लिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। माननीय मंत्री जी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर बारां के आदेश दिनांक 25.11.2022 द्वारा आबंटित आठ बीघा भूमि का कब्जा मौके पर उपस्थित होने पर अभिभाषक परिषद्, छीपाबड़ौद के तीन-चार अभिभाषकों के द्वारा उग्र प्रदर्शन करने के कारण सम्बन्धित हलका पटवारी द्वारा कब्जा नहीं सौंपा गया। अभिभाषक परिषद्, छीपाबड़ौद ने उक्त आठ बीघा भूमि का कब्जा मंडी समिति को नहीं सौंपने के संबंध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, छीपाबड़ौद के समक्ष वाद दायर किया है, जिसमें यथास्थिति के आदेश हैं। उक्त वाद में आगामी पेशी दिनांक 18.03.2023 को नियत है। हम कोशिश करेंगे कि स्टे जल्दी वैकेट हो। माननीय सदस्य, आप भी थोड़ी-सी मदद करना।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि जो 8 बीघा जमीन आबंटन हुई है, वह मंडी समिति की चारदीवारी के पीछे आबंटित हुई है। वहां से मुंसिफ कोर्ट करीब आधा किलोमीटर दूर है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोर्ट के मामले में नहीं। कोर्ट के बारे में अपन थोड़े ही बोल सकते हैं?

अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

होम गार्ड्स का नियमितीकरण

276. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत बजट में बारह हजार होमगार्ड की भर्ती करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा समय पर पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार होमगार्ड रूल्स एक्ट, 1962-63 में संशोधन कर होमगार्ड को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त को वर्ष भर रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने, ई एस आई, डी ए व निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) जी नहीं। बजट में बारह हजार होमगार्ड भर्ती करने की घोषणा नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। स्वयंसेवकों को नियमित करने हेतु होमगार्ड रूल्स एक्ट, 1962-63 के तहत संशोधन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) गृह रक्षा विभाग एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी मूल भावना स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है। गृह रक्षा स्वयंसेवकों को मांगकर्ता एजेन्सी/विभाग की मांग के अनुसार नियोजित किया जाता है। वर्तमान में गृह रक्षा विभाग में आनरोल नफरी 25,823 है तथा विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित स्वयंसेवक 15,237 है। इस प्रकार आनरोल की तुलना में नियोजन के अवसर कम होने के कारण सभी सदस्यों को ड्यूटी के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिये स्वयंसेवकों को विभागीय रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी दी जा रही हैं। सभी होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी दिया जाना सम्भव नहीं है।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को ई एस आई, पी एफ, डी ए (महंगाई भत्ता) दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होमगार्ड स्वयंसेवकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदान की जा रही है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट 2022-23 में बिन्दु संख्या 127 पर राजकीय कार्यालयों में लाजिस्टिकल कार्यों हेतु इनकी ड्यूटी लेना प्रस्तावित किया था। इसमें अब तक कितने लोगों का नियोजन किया गया है? माननीय मंत्री महोदय, जब इन्हें काम में ही नहीं लेना है तो इनका रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? आपने सात बार इनके धरनों पर जाकर आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या हुआ? यह बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): होमगार्ड स्वयंसेवक संस्था है। हमसे जो डिपार्टमेंट मांगते हैं, हम होमगार्ड दे देते हैं। जो विभाग हमसे मांगे, उसके हिसाब से अनुपात में दिये जाते हैं। नहीं मांगते हैं तो नहीं देते हैं। यह हमारा काम नहीं, अलग-अलग विभागों का काम है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सात बार, आप घोषणा करके आये..

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज, दे दिया। अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर के बेरोजगारों को भत्ता

277. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जालौर के जिन बेरोजगारों को भत्ता दिया गया, उनका वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना

278. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस मद में कितना बजटीय प्रावधान किया गया व माह दिसम्बर, 2022 तक कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त यूनिवर्सिटी में सत्र 2021-22 से अध्यापन कार्य भी प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो किस-किस संकाय में कितने कोर्स प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 279

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

चित्तौड़गढ़ की गोशालाओं को देय अनुदान

280. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

(1) जिला चितौड़गढ़ में कुल कितनी गोशालाएं संचालित हैं तथा उक्त को किस-किस पशु पर कितना अनुदान दिया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोशालाओं के विकास हेतु विधायक मद से दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) गोपालन विभाग द्वारा पंजीकृत गोशालाओं का रिकार्ड संधारित किया जाता है। रिकार्ड अनुसार जिला चित्तौडगढ़ में कुल 40 पंजीकृत गोशालाएं तथा एक कांजी हाउस है। उपरोक्त में से 22 गोशालाएं अनुदान की पात्रता रखती है। गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 संशोधित 2021 अन्तर्गत पात्र गोशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से वर्ष में 09 माह अनुदान राशि दी जाती है। पात्र गोशालाओं को दिये गये अनुदान की राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आदेश दिनांक 09.03.2019 द्वारा अनुदान राशि छोटे पशु की 16 रुपये से बढाकर 20 रुपये प्रतिदिन व बड़े पशु की 32 रुपये से बढा़कर 40 रुपये प्रतिदिन की गयी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इसी प्रकार आदेश दिनांक 10.06.2022 द्वारा अनुदान राशि की अवधि 06 माह से बढा़कर 09 माह की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

अनुदान राशि दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रथम चरण में 4 माह अर्थात् अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं द्वितीय चरण में 05 माह अर्थात् नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च हेतु भरण पोषण अनुदान का प्रावधान किया गया है।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 2.22 के अनुसार गोपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गोशाला के

(गोपालन मंत्री)

लिये टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसम्पत्तियों का सृजन निर्धारित शर्तों के अधीन कराया जा सकता है। प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। गोशालाओं के विकास हेतु विधायक मद से दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक मद से जो स्वीकृति होती है, वह प्रक्रिया जटिल है। इस पूरी प्रक्रिया को, जो विधायकों ने अनुशंसा की है और स्वीकृतियां निकलीं, उसमें जो समय निकला, उसको पूरा दिखवाकर प्रक्रिया सरल करने का विचार रखते हैं या नहीं?

दूसरा, विधायक मद से 10 लाख रुपये की सीलिंग है। अगर उस गोशाला में पहले वाले विधायक ने पैसा दे दिया है तो नया वाला नहीं दे सकता। इस राशि को गोशालाओं के विकास हेतु बढ़ाने का विचार सरकार रखती है या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी की भावना से सहमत हूं कि संस्थाओं को राशि देने की एम एल ए गाइडलाइन में जो प्रक्रिया है, उसमें शिथिलता की आवश्यकता है क्योंकि हमने भी गोपालन विभाग के माध्यम से अनुदान भरण-पोषण केस में जो-जो संस्थाओं का फीड-बैक आया है, हमने हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उसमें काफी शिथिलताएं प्रदान की हैं, उससे गोशालाओं को काफी लाभ हुआ है। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से विधायक जी की भावना को अवगत कराऊंगा। आपने दूसरी बात रखी कि 10 लाख रुपये तक का प्रोविजन है। अभी एक संस्था को एक बार में 10 लाख रुपये देने का ही प्रोविजन है। यह जनहित का कार्य है। गौ सेवा का कार्य है। मैं खुद भी गौ सेवक हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वास्तव में यह राशि बढ़नी चाहिए, ताकि जनहित के कार्य ज्यादा हो सकें। गोरक्षा के क्षेत्र में कार्य विधायक फंड से ज्यादा हो सकें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 281

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मोहन राम चौधरी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

वल्लभनगर पंचायत समिति का भवन निर्माण

282. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति वल्लभनगर के भवन निर्माण हेतु जमीन का आबंटन किया जा चुका है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त के भवन निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कब तक भवन निर्माण करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। पंचायत समिति, वल्लभनगर के भवन निर्माण हेतु जमीन का आबंटन हो चुका है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति, वल्लभनगर के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 1617 दिनांक 27-06-2022 द्वारा जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट-2)। विभागीय पत्रांक 185 दिनांक 17-02-2023 द्वारा राशि रुपये 98.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि पंचायत समिति, वल्लभनगर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है। (परिशिष्ट-3) पंचायत समिति, वल्लभनगर का भवन निर्माण दिनांक 30-11-2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति भवन की वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व पंचायत राज मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया में भाखड़ा नहर में पक्के खालों का निर्माण

283. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुरदीप सिंह)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया में IGNP एवं भाखड़ा नहर में पक्के खालों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): जी हां। संगरिया विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा नहर परियोजना के अंतर्गत 85,955.56 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में कुल 315 पक्के खालों का निर्माण किया जाना था, (परिशिष्ट-1) जिनमें से अब तक 46 चकों के 12,479.31 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में वर्ष 2019-20 तक पक्का खाला निर्माण कार्य किया जा चुका है (परिशिष्ट-2)। शेष रहे 269 चकों (परिशिष्ट-3) सीसीए 73,476 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 173 VII के अन्तर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है।

संगरिया विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 14,111 हैक्टेयर में 97 खालों का निर्माण वर्ष 2010 से पूर्व किया गया था (परिशिष्ट-4)। उनमें से जर्जर हो चुके खालों में से प्रथम चरण में 49 चकों जिनका सीसीए 6379.95 हैक्टेयर है, को बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 174 (III) के अन्तर्गत पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है (परिशिष्ट-5)।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): भाखड़ा के अंदर और आई जी एन पी के अंदर जो बजट 2023-24 के अंदर घोषणा हुई है, उनका काम कब तक चालू हो जाएगा?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा की है, जिसकी हम अभी डी पी आर तैयार कर रहे हैं और तीन सालों में इसका काम पूर्ण हो जाएगा।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निजी सुझाव किसान होने के नाते है। जो खाले बनते हैं, इसकी मियाद 10-12 साल होती है और पैसा बर्बाद हो जाता है। पंजाब व हरियाणा के अंदर इसको अंडरग्राउण्ड पाइप डालकर पाइप द्वारा पानी दिया जाता है। इसकी कम से कम मियाद 50 साल है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खालों की जगह अगर आप पाइप

(श्री गुरदीप सिंह)

लाइन ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जगह-जगह लोग बाद में खाले तोड़कर पक्का बना लेते हैं। उससे भी हमारी लाइनिंग कमजोर हो जाती है। आप पाइप पर विचार करें तो बहुत बढ़िया होगा और सरकार का पैसा भी बचेगा।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आपको तो धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि भारत सरकार ने तो पूरी भाखड़ा परियोजना के प्रथम फेज 2017-18 का जो काम था, वह पूरा बंद कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने हैड से पैसा दे रही है। आपके सौ प्रतिशत क्षेत्र में पूरे के पूरे में खाले बन जाएंगे। इसमें आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं दे दें। उसमें इंस्पेक्शन करवा देंगे कि किस प्रकार से पाइप ले सकते हैं या नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री रीटा चौधरी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ करने की कार्ययोजना

284. सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा) (श्रीमती इन्द्रा (बामनवास) के स्थान पर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के किसानों के बकाया किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) ऋण माफ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त बैंकों द्वारा किसानों को देय दो लाख रुपयों तक के बकाया किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयोजना मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के लिये दिनांक 02.01.2019 को माननीय प्रधान मंत्री को, 15.06.2019 को वित्त मंत्री, भारत सरकार को, 21.12.2020, 27.12.2021 को पुनः माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.09.2022 को मुख्य सचिव की ओर से सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर उक्त बैंकों की ऋण माफी में आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(आयोजना मंत्री)

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के केवल एक पत्र दिनांक 21.12.2020 का जवाब पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को दिया, जिसमें कृषक ऋण माफी हेतु आर्थिक सहायता देने से मना किया गया है। वर्तमान में ऋण माफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। राज्य सरकार अपने आदेश दिनांक 19.12.2018 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का विचार रखती है।

राज्य सरकार ने अन्तर्विभागीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति की अनुशंषा पर सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तथा उक्त बैंकों की ऋण माफी के लिए One Time Settlement Scheme (OTS) लाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे हैं।

इन पत्रों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से पूर्ववर्ती केन्द्र की यू पी ए की सरकार द्वारा 2008 में करीब 72 हजार करोड़ की देशव्यापी कर्ज माफी की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी की ओ टी एस लाने हेतु निर्देशित कराने का आग्रह किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 09.11.2021 को ओ टी एस एकमुश्त ऋण माफी योजना के तहत 90:10 का ऋण माफी का प्रस्ताव वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्पोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया, लेकिन किसी भी बैंक प्रबन्धन ने इस प्रस्ताव पर अब तक सहमति नही दी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 17 फरवरी, 2023)

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति

198. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अथवा अन्य आर्थिक सहायता दी जा रही है? उक्त

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता देने की क्या पात्रता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में उक्त वर्ग के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता दी गई? उक्त पर कितना व्यय हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त वर्ग के छात्र-छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति राशि, अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है एवं अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास/भोजन इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजनाओं की पात्रता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजना प्रारम्भ कर राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश पत्र परिशिष्ट-2 संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-3 संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा से प्राप्त सूचना के अनुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की छात्राओं को स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विभाग द्वारा संचालित डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 (जनवरी 23) तक वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2021-22 से 2022-23 (13 फरवरी, 2023) तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

अम्बेडकर डी बी टी वाउचर योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आर्थिक कमजोर वर्ग के 75 छात्रों को लाभान्वित किया जाकर 7.50 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विगत तीन वर्षों मे देय आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की छात्राओं को स्कूटी वर्ष 2020-21 से दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में 573 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई है। वर्ष 2020-21 में स्कूटियों पर 302.92 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के आवेदनों की जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।

(3) डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूर्व में आय सीमा 1.00 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 से 2.50 लाख रुपये वार्षिक की गई है एवं उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। अब वर्ष 2022-23 से निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाना प्रारम्भ किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2021-22 में 1,000 अभ्यर्थियों का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 1,499 किया गया है एवं वर्ष 2023-24 के बजट में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी करने के फलस्वरूप लक्ष्य बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 55 की अनुपालना में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों के लिये आर्थिक कमजोर वर्ग कोष का गठन क्रमांक 593 दिनांक 06.04.2022 किया गया है (परिशिष्ट-9)। उक्त कोष में छात्र-छात्राओं का शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिये 07 संभाग स्तर पर बालिका छात्रावास, आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिये स्कूटी वितरण, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना प्रारम्भ की हुई है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो जवाब आया, उस जवाब में और इस बार के जवाब में कोई खास अन्तर नहीं है। आज भी मुझे जो डेटा मिला है वह 2020 का मिला है कि 2020 में हमने यह-यह वितरण किये हैं। मुझे डेटा चाहिए था कि आज तक, विगत तीन वर्षों में हमने कितने वितरण किये? जिसका जवाब आपने बोला कि अभी भी बहुत सारे आवेदन हैं। मैं समझ सकती हूं क्योंकि मैं जब वेबसाइट पर गई तो करीबन 1,200 पेजेज की यह पूरी डेटा थी, जिसमें बच्चों ने आवेदन कर रखा है। एक पेज पर 30 बच्चे हैं। करीबन 36 हजार अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह यह देखना चाह रहे हैं कि हमें स्कूटी कब मिलेगी। कोई बात नहीं, आपने डेटा प्रोवाइड नहीं किया। आपका डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है कि लेटेस्ट डेटा क्या है। क्या अभी टेंडर हो गये हैं उन स्कूटियों के वितरण के?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, आप भी मेरे राजसमन्द ज़िले से ही आते हैं। मेरा कन्सर्न यह है कि इसमें कालीबाई भील स्कूटी वितरण की योजना के अन्तर्गत आपने लिखा है कि 51 स्कूटियां हम प्रति ज़िले में देंगे। उसके बाद आप जैसे-जैसे डेटा को देखेंगे तो कोई रेशो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिलावाइज। मैं आपसे क्या यह पूछ सकती हूं कि राजसमन्द में ढंग से रेशो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 50 परसेंट से भी कम है, मैं क्या आपकी तरफ से आश्वस्त हो सकूं कि आप सब ज़िलों में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? एस सी, अनुसूचित जाति की छात्राएं हमारे यहां भी होती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, समाज कल्याण से शिक्षा में चले जाएंगे तो फिर प्रश्न पोस्टपोन करना पड़ेगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर...

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी क्लियर करना चाहूंगा, उस दिन भी डेटा यही था और आज भी डेटा यही है। मैंने कोई डेटा छिपाया नहीं है। 2020-21 का लक्ष्य 600 था, उसमें से 573 एप्लीकेशंस आई थीं, हमने उनको वितरण कर दिया। 2021-22 व 2022-23 की स्कूटी अभी प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन रहने का कारण, हमारी तरफ से कमी नहीं है। बच्चों के द्वारा हमारे पास पोर्टल की, आगे तारीख बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आई 03 जनवरी, 2022; 15 फरवरी, 2022; 15 मार्च, 2022; 15.07.2022; 06.09.2022; 31 जनवरी, 2023 तथा अभी लेटेस्ट 18 फरवरी, 2023, इसमें हमने बढ़ाई। उसके बाद प्रक्रिया पूरी कर दी, इसमें कोई तारीख नहीं बढ़ेगी।

इस साल 2022-23 में भी 20.10.2022 को, 30.11.2022, 21.12.2022 को, 15 जनवरी, 2023 व 15 फरवरी, 2023 को। हम दो साल पहले की बात करें, उस समय कोविड भी था। मार्क्स-शीट वगैरह नहीं आ रही थी। पेपर आगे-पीछे हुए थे। उसके बाद हमने तारीख बढ़ा दी है। अब टेंडर हो गये हैं। 2021-22 की पोर्टल की हमने कट आफ अस्थायी सूची जारी कर दी है। 2022-23 की भी पोर्टल की लास्ट डेट 15 फरवरी थी, उसकी अस्थायी सूची हम 30 अप्रैल तक जारी कर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों वर्षों की स्कूटी बांट देंगे। इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में स्कूटी की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी है। आने वाला साल है, उसमें भी अच्छी संख्या में बच्चों को स्कूटी मिल पाएगी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): टेंडर कितनी स्कूटी के हुए हैं? आपने मुझे उस दिन भी कहा था कि यह आपके डिपार्टमेंट का डायरेक्टली आंसर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया। प्लीज। अगला प्रश्न। बार-बार शिक्षा में जाएंगे तो प्रश्न अलग लगाना पड़ेगा। Anything if you want to ask specifically for social welfare department, आपका कन्सर्न था,

(श्री अध्यक्ष)

उसको एड्रेस किया है। दो साल की स्क्रूटी प्रोसेस में है। डेट बता दी उन्होंने। अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक फोरलेन सड़क का निर्माण

285 श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री हाकम अली खां (फतेहपुर) के स्थान पर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गोकुलपुरा चौराहे से बढ़ाढर तक व सीकर शहर के बाईपास सड़क पर यातायात का भारी दबाव रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को फोरलेन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक यातायात के भारी दबाव को देखते हुए फोरलेन सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) गोकुलपुरा चौराहे से बढ़ाढर तक सीकर बाईपास सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का भाग है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 एवं 11 के सीकर-फतेहपुर-बीकानेर खण्ड को दो-लेन मय पेव्ड शोल्डर से चार-लेन बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के कार्य की स्वीकृति दिनांक 08.03.2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का कार्य प्रगतिरत है। इस सड़क को फोर-लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा ही जारी की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर खण्ड को दो-लेन मय पेव्ड शोल्डर से चार-लेन बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के कार्य की स्वीकृति दिनांक 08.03.2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने का कार्य प्रगतिरत है। इस

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क को फोर-लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा ही जारी की जायेगी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। यह जो बाईपास है, यह ग्रामीण क्षेत्र से भी मिलता हुआ है, बहुत भारी दबाव ट्रैफिक का है। क्या भारत सरकार के ध्यान में इसकी स्थिति रखते हुए इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए, उनसे निवेदन करेंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे है और पी पी पी माडल पर है। जब इसकी डी.पी.आर. तैयार हो जाएगी, डी.पी.आर. 31.05.2022 को कार्य पूर्ण की तिथि है, परन्तु इसकी निर्धारित तिथि के आधार पर नहीं हो पाई, महीना-दो महीना आगे पीछे होकर, जैसे ही डी.पी.आर. तैयार हो जाएगी, डी.पी.आर. को हम लोग भारत सरकार को भेज देंगे। भारत सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जेलों की सुरक्षा की कार्ययोजना

286. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की जेलों से विगत दो वर्षों में कितने कैदी फरार हुए तथा उक्त में से कितनों को गिरफ्तार किया गया व कितने फरार हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कैदियों के फरार होने की जांच के पश्चात् किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही सामने आयी एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार जेलों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जेल मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) प्रदेश के कारागृहों से विगत दो वर्षों में कुल 27 बंदी कारागृह से फरार हुए, जिनमें से 25 बंदियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं 2 बंदी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जेल मंत्री)

(2) विगत दो वर्षों में कारागृह से फरार हुए बंदियों के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी व उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) कारागृहों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं:-

1. जेलों की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु आर.ए.सी की एक बटालियन जेलों पर तैनात की गई है।
2. प्रहरियों के 527 एवं 276 पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3. कारागृहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये गये हैं।
4. कारागृहों की बाहरी सुरक्षा हेतु वॉच टावरों का निर्माण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बंदी जेलों से फरार होते हैं, उसका मुख्य कारण प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना है? फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे, क्या उस समय 17 की क्षमता के विरुद्ध वहां 60 कैदी थे? यदि हां, तो क्या प्रदेश की जेलों की क्षमता बढ़ाये जाने का विचार सरकार रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

मेरा दूसरा प्रश्न है, जेलों में प्रहरियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, यह आपने खण्ड-3 में बताया है। यह भर्ती कब तक कर दी जाएगी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्ती प्रक्रिया, हमारे पदों की थोड़ी विसंगति है, इसलिए अटकी हुई है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही, इस वर्ष तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा खुली जेल, नई बैरक, महिला बैरक अलग से बनाने की घोषणा की गई है। इसके अन्दर 20-20 की 8 घोषणाएं हैं, तो उसके अन्दर भी हमारी संख्या बढ़ेगी। साथ ही तीन नई जेल, सालावास दौसा हमारी शुरू हो गई है। अकलेरा झालावाड़ की रेडी है, बहुत ही जल्दी, एक सप्ताह-दस दिन के अन्दर-अन्दर उसको शुरू कर रहे हैं। डूंगरपुर जेल का काम

(श्री टीकाराम जूली)

भी बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाला है। मैं समझता हूं कि इससे इसके अन्दर काफी फर्क पड़ेगा। कैदी तो आपके समय भी भागे थे। हमारे समय में तो 8 वारदातें हुईं आपके समय में 11 हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर की प्याज मण्डी में सुविधाएं

287. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की एकमात्र प्याज मण्डी अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित है? यदि हां, तो उक्त मण्डी कब स्थापित की गई एवं उक्त में किसानों व आढ़तियों के लिए किन सुविधाओं का प्रावधान रखा गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लाखों का राजस्व प्राप्त करने वाली उक्त प्याज मण्डी में सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्याज मण्डी में मण्डी अनुरूप बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) अलवर में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.04.2005 के द्वारा प्याज की विशिष्ट मण्डी की स्वीकृति प्रदान की जाकर गौण मण्डी यार्ड प्याज, अलवर के लिए अधिसूचना दिनांक 22.06.2006 जारी की गई थी। (प्रति संलग्न) इसके अतिरिक्त रसीदपुरा (सीकर) में भी प्याज के विपणन हेतु दिनांक 22.12.2017 द्वारा विशिष्ट जिन्स प्याज मण्डी की स्वीकृति प्रदान की जाकर गौण मण्डी रसीदपुरा के लिए अधिसूचना दिनांक 19.02.2018 जारी की गई थी। (प्रति संलग्न) कृषि उपज मण्डी समितियों के मुख्य एवं गौण मण्डी प्रांगणों में आधारभूत संरचनाएं विकसित करने एवं इनकी प्राथमिकता के संबंध में जारी दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विशिष्ट मण्डी प्याज गौण मण्डी यार्ड में कार्यालय भवन, दो चैकपोस्ट, दो गेट तथा कृषि जिन्सों की नीलामी हेतु कामन प्लेटफार्म, शौचालय, प्याऊ, बोरवेल, विश्राम हेतु रेस्ट शैड, जलपान हेतु

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कियोस्क तथा सी.सी. रोड का निर्माण मण्डी समिति द्वारा कराया गया है। मण्डी समिति में सुरक्षा हेतु चौकीदार, पीने के पानी, सफाई एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

(3) प्याज मण्डी, अलवर में उपर्युक्तानुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधारभूत संरचना विकसित करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के क्रम में मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं आवश्यकता के आकलन के आधार पर परीक्षणोपरान्त शेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 2006 में स्थापना होने पर विभाग द्वारा आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था? साथ ही साथ उस वक्त प्याज मण्डी में दुकानों के आबंटन हेतु कितने लाइसेंसधारी आढ़तियों व व्यापारियों ने आवेदन किये एवं कितनी दुकानों को आबंटित किया गया एवं कितने आवेदन अभी लम्बित हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्याज मण्डी के अन्दर 286 लाइसेंस हैं और आप जो पूछ रहे हैं कि उस टाइम कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने पैंडिंग हैं, इसकी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है, उसके अनुसार वहां पर एक भी दुकान अभी तक नहीं खुली है। साढ़े सोलह साल गुजर जाने के बाद भी एक भी आढ़तिये को दुकान नहीं दी गयी है। उस वक्त आवेदन लिये गये थे, 15 हजार रुपये की धरोहर राशि ली गयी थी और दुकान नहीं लेने के कारण धरोहर राशि वापस की जा रही है। कुछ आढ़तियों ने दुकान के पैसे भी वापस ले लिये हैं और कुछ इस विवाद में उलझे हुए हैं कि हमें ब्याज सहित उस राशि को लौटाया जाये।

खण्ड-2 में आपने जो बताया कि वहां विकास पूरा हुआ है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि आप एक बार अलवर शहर में पधारें और स्वयं उस मण्डी का

(श्री संजय शर्मा)

निरीक्षण कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जिन अधिकारियों ने यह गलत जवाब आपके श्रीमुख से कहलवाया है, निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को करनी चाहिए।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डवलपमेंट के काम हैं, वह मण्डी समिति से जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर किये जाते हैं और मण्डी समिति, अलवर में फाइनेंशियल स्थिति हमारी ठीक है। आज की तारीख में हमारे स्तर पर डवलपमेंट का कोई भी प्रस्ताव पैंडिंग नहीं है। यदि आप ऐसा बता रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि कोई जरूरत की चीज है, उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजे तो हम उसको दिखवाएंगे, उसको आप भी मेरी जानकारी में लाना, उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे कि जब हमारे पास में बजट उपलब्ध है, वहां पर लोगों को, आढ़तियों को प्लस किसानों को उन चीजों की आवश्यकता है तो क्यों नहीं उन्होंने प्रस्ताव भिजवाये। वर्तमान में हमारे पास में कोई भी प्रस्ताव पैंडिंग नहीं है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में आपने यह स्वीकार किया है कि वहां पर विश्राम हेतु रेस्ट शैड, जलपान हेतु कियोस्क तथा सी.सी. रोड बनी हुई है, यह बिलकुल सही है। निर्माण मण्डी समिति द्वारा करवाया गया है लेकिन मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि न तो वहां पर मण्डी कार्यालय है, न कैंटीन है, न किसानों के लिए कोई विश्रामालय है, न शौचालय है, न सुविधाएं हैं। हमारे अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य जो कि मंत्री महोदय हैं, वे स्वयं वहां पर गये थे और आढ़तियों ने इस भाव से इनका स्वागत किया था कि वहां पर विकास होगा, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। मैं बारम्बार आपसे यह आग्रह कर रहा हूं, मंत्री महोदय, आप समय दें और वहां पर एक बार खुद पहुंचकर निरीक्षण कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से हमारे हायर आफिसर्स को और प्लस मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा कि एक बार उस मण्डी का निरीक्षण करके आऊंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप माननीय सदस्य को सूचित करके इनको साथ लेकर जाकर निरीक्षण करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

डूंगरपुर के होम गार्ड स्वयंसेवकों का बकाया मानदेय

288. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़) (श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर) के स्थान पर): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में माह जून, 2021 में बाल श्रमिक पलायन रोकने हेतु नियुक्त 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों को मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त स्वयंसेवकों के बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) जिला डूंगरपुर में माह जून, 2021 में बाल श्रमिक पलायन रोकने हेतु नियुक्त 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों को जिले में स्थापित विभिन्न चैक पोस्टों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिये जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर की मांग के अनुसार स्वयंसेवकों को नियोजित किया गया था।

उक्त नियोजन में स्वयंसेवकों के बकाया मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। गृह रक्षा विभाग द्वारा प्रेषित उक्त स्वयंसेवकों का बकाया मानदेय भुगतान के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु गृह विभाग में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जून को दो साल हो जायेंगे तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि इनका भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, यह सही है। 2021 में पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर ने 72 होमगार्ड को ड्यूटी पर लगा लिया था और उनके 34

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

लाख 32 हजार रुपये आज तक बकाया हैं, ये उनको मिलने चाहिए थे। यह जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), डूंगरपुर की थी और वे ही भुगतान करते। हम तो सिर्फ होमगार्ड को उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर भिजवाते हैं और उनके पास पैसा नहीं था या यह काम डूंगरपुर एस.पी. की गलती की वजह से वह उनको भुगतान दो साल तक नहीं हुआ, होमगार्ड भटकते फिरे। अब हम इस मामले को वित्त विभाग की स्वीकृति से वह राशि हम देने के लिए प्रक्रिया चला रहे हैं और दो महीने में उनका भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 289

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा में पंचकर्म केन्द्र की स्थापना

290. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नवीन आयुर्वेद औषधालय एवं पंचकर्म केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): नवीन औषधालय खोलने संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयुष नीति-2021 के मानदण्डों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में 72 चिकित्सालयों में पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र तिजारा में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय, तिजारा में भी पंचकर्म की सुविधा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें आपने जो कहा है कि मानदण्डों की अगर पूर्ति हो जाती है तो कब तक नवीन औषधालय खोलने का विचार है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि नवीन औषधालय का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उसके मानदण्डों के आधार पर विचार करेंगे। आप औषधालय का प्रस्ताव भेज दीजिए। पंचकर्म की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान में टोटल 3783 हमारे चिकित्सालय/औषधालय चल रहे हैं। सैकण्ड नम्बर पर अलवर है। फर्स्ट नम्बर पर मैं यह बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा है और उसके बाद सैकण्ड पर अलवर है, जहां पर 192 आलरेडी यह चल रहे हैं और तिजारा के बारे में भी मैं यह बताना चाहूंगा कि तिजारा विधान सभा में 14 चिकित्सालय और औषधालय हैं जो आलरेडी हैं, फिर भी आपके इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): थैंक यू, सर।

श्री अध्यक्ष: सारे प्रश्न समाप्त हो गये अब क्योंकि माननीय सदस्य आ गये हैं इसलिए माननीय श्री रामस्वरूप लाम्बा। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। प्रश्न पूछने दें उनको।

विधायक कोष से विद्यालयों में कक्षों की मरम्मत

270. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोष से विद्यालयों के कक्षों की मरम्मत एवं चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने हेतु स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है?

(2) क्या सरकार विधायक कोष से विद्यालयों एवं अन्य राजकीय भवनों एवं चारदीवारी मरम्मत करने की स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: रामलालजी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (ग्रामीण विकास मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। राजकीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 2.5 एवं योजना में अनुमत कार्यों की सूची के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार स्वीकृत किये जा सकते हैं।

योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 2.5 एवं अनुमत कार्य बिन्दु संख्या 17 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री रामलाल जाट)

(2) जी नहीं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 2.5 एवं योजना में अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार सामुदायिक उपयोग की राजकीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/नवीनीकरण करवाने के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं। उक्त संबंधी नवीन नियम बनाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि मरम्मत का प्रावधान होने के बावजूद मैंने जब यह लैटर राशि की स्वीकृति के साथ जिला परिषद् में भेजा तो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरिपुरा है, उसके लिए उन्होंने यह जवाब दिया कि यह बहुत अत्यधिक जीर्णशीर्ण अवस्था में है और इसकी मरम्मत सम्भव नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर उसी भवन में विद्यालय संचालित हो रहा है और अभी कुछ दिनों पहले छत का एक हिस्सा टूटकर गिर भी गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के कारण कोई बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ तो ऐसे भवन जिनकी मरम्मत सम्भव नहीं है, क्या राज्य सरकार ऐसे भवनों को गिराकर उनकी जगह नये भवन बनाने का विचार रखती है? ऐसी जगह जहां पर बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जहां भवन सुरक्षित नहीं है तो ऐसे भवनों की बजाय क्या दूसरे भवनों में क्या स्कूल संचालित किये जा सकते हैं?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि मरम्मत के लिए वार्षिक आबंटन की 20 प्रतिशत है, क्या राज्य सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: दो का जवाब आने दो।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का प्रश्न था, नियम है या नहीं? नियम तो है, उसमें बना सकते हैं।

इनका दूसरा प्रश्न आया कि बिल्डिंग नष्ट हो रही है, ज्यादा जीर्णशीर्ण अवस्था में है, इसलिए अधिकारियों ने मना किया। पी डब्ल्यू डी के ए ईएन या एक्स ईएन को चिट्ठी लिखें, भले ही हम लिख देंगे, आपके क्वेश्चन के माध्यम से। उसको डिस्ट्राय करके, नया भवन बनाने की प्रक्रिया में विधायक कोष के लिए 20 परसेंट, 5 करोड़ के 1 करोड़ रुपये वैसे ही होते हैं। फिर भी बढ़ाने की अभिशंषा है तो सभी माननीय सदस्यों की राय के आधार पर, डिपार्टमेंट करता है। जहां तक मैं समझता हूं, सभी की राय के हिसाब से

(श्री रामलाल जाट)

20 प्रतिशत ठीक है। फिर भी आप डिमांड पर बात रखना, हम इस पर विचार करेंगे। बिल्डिंग, हम ए ईएन साहेबान को लेकर, उसकी रिपोर्ट लेकर, रमसा या समसा के आधार पर जो स्वीकृति आती है, उसके अन्तर्गत कर देंगे। अजमेर में डी एम एफ टी फण्ड भी है, उसके आधार पर करवा देंगे। विधायक कोष में शामिल करके, अन्य योजनाओं में, जैसे नरेगा में बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है, तो उससे जोइंट करके हम बनवा सकते हैं। यह एक रिपोर्ट दे दें, उसके आधार पर जिला कलेक्टर को कह कर उस बिल्डिंग को करेंगे।

दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है, अगर कोई बिल्डिंग है या स्कूल है, तो हम उसमें कर देंगे। तत्कालीन उस कमरे में, जहां दिक्कत आ रही है, उसको बंद करवा देंगे, ताकि बच्चों को कोई जनहानि नहीं हो।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): बिन्दु संख्या 2.11 में आपने कहा है-ज़िले में सामुदायिक महत्व के कार्य, जिनसे सम्पूर्ण ज़िले की जनता लाभान्वित होती है, इन कार्यों के लिए ज़िले के निर्वाचित सभी विधायकगण अपने हिस्से की राशि में से अभिशंसा कर सकेंगे। अपनी विधान सभा के अलावा, कितने प्रतिशत या कितनी राशि, विधायक सामुदायिक कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकेंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 पर लिख रखा है, विधायक द्वारा उनके वार्षिक आबंटन की 20 प्रतिशत राशि तक के कार्य सामुदायिक उपयोग के राजकीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तावित किये जा सकेंगे। विभाग के आदेश एफ/14(40) एमएलए/ ग्रुप-6/2015, दिनांक 07.10.2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। सामुदायिक एवं राजकीय परिसम्पत्तियों का नवीनीकरण, मरम्मत दे रखा है आलरेडी। फिर भी 2.11 के अन्दर विधायक अपने हिस्से की राशि की अभिशंसा कर सकेंगे, भले ही उक्त कार्य उनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं आ रहे हों। इस प्रकार के कार्यों की जिला परिषद् ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ स्तर पर स्वीकृति के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। 2.11 में, अगर आप अपने विधान सभा क्षेत्र से कोई दूसरी जगह करवाना चाहते हैं, तो 2.11 में प्रावधान है। 2.5 में तो क्लियर है। आपकी विधान सभा में नवीनीकरण कराओ, सामुदायिक भवन है, परिसम्पत्तियां हैं, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग है, उसमें आप करवा सकते हो। क्लियर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आये तो आप मुझसे मिल लेना, मैं आपकी समस्या का हल करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अनुपस्थित थे, अब उपस्थित हो गये। जब्बर सिंह सांखला।

आसींद में समाधि हेतु भूमि आवंटन

279. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नाथ (योगी) समाज में मृत्यु होने पर समाधि देने का प्रचलन है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसींद के नाथ (योगी) बहुल क्षेत्रों में पृथक् से श्मशान भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): जी हां। नाथ (योगी) समाज में मृत्यु होने पर समाधि देने का प्रचलन है। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नाथ (योगी) बहुल क्षेत्रों में ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा निवेदन/आवेदन किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक (समाधि स्थल) श्मशान के लिए भूमि आरक्षित की गई है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने जवाब दिया उसमें चार की सूची आई है। मेरा निवेदन है विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां नाथ, योगी समाज के चार-चार, पांच-पांच परिवार रहते हैं। वहां समाधि स्थल के लिए दिक्कत आती है। क्या सरकार आसीन्द-हुरड़ा विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में, जहां नाथ, योगी समाज के लोग रहते हैं, वहां सर्वे कराकर, इस समाज को श्मशान भूमि समाधि स्थल के लिए देने का विचार रखती है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार की नहीं, पांच की सूची है। दौलतगढ़, बग्ता का खेडा, चाडो का खेडा, राजपुरा, राजपुरा। हमने 'प्रशासन गांवों के संग 'अभियान' में सरकार ने डायरेक्शन दिये, कोई भी श्मशान हो, कब्रिस्तान हो, समाधि स्थल हो, ग्राम पंचायत की मांग के आधार पर हम जमीन आबंटित करते हैं। जहां-जहां इनकी मांग आई, वहां हमने कर दी। अगर फिर भी कोई बाकी है, क्लियर आदेश है, आपकी ग्राम पंचायत मांगेगी या समाज के और भी कोई लोग मांगेंगे तो पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर हम अलाट नहीं करते हैं, आप हमें दे दें, हम आपकी अलाट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामनिवास गावड़िया की जगह श्रीमती सफिया।

नागौर ज़िले में श्रमिक कार्ड के लम्बित आवेदन

289. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़) (श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर) के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? विधान सभा क्षेत्र परबतसर का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक श्रमिक कार्ड बनाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उक्त में से कितने श्रमिक कार्ड बन गये व कितने शेष हैं? सरकार द्वारा उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जिला नागौर में कुल 1,74,937 श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 12,619 है।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में श्रमिक कार्ड बनाने हेतु प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त एवं शेष लम्बित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। लम्बित पंजीयन आवेदनों का 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि इतना लम्बित रहने का क्या कारण है? इसमें जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, वे ही आवेदन करते हैं। वे लाइन में खड़े रहते हैं, आफिस के दस चक्कर काटते हैं। हमारे देश में बड़े-बडे सेठ अडानी, अम्बानी के तो एक दिन में घर बैठे, उनके लोन पास हो जाते हैं और माफ भी हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या खाली फोर्स डिपार्टमेंट में इसका कारण हो सकता है क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। इंस्पेक्टर को खुद मौक़े पर जाकर जांच करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। नियोजक को आनलाइन या एस एम एस के जरिए इत्तिला की जाती है कि आपकी यह कमी है, पूर्ति की जाए। कमी की समय पर पूर्ति नहीं करने से पेंडिंग रहती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल का समय बचा हुआ है। जो सदस्य नहीं हैं मैं पूछ रहा हूं। राजस्व मंत्री जी। प्रश्न संख्या 268, कैलाश जी मेघवाल का प्रश्न है।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पटवारियों के स्वीकृत पद

268 श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) (श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा) के स्थान पर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? पटवार हलकावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी पटवार मण्डलों में पटवारियों के पदस्थापन किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ पटवारियों को एक से अधिक पटवार मण्डलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने पटवारी हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाडा) के अन्तर्गत 03 तहसीलें (शाहपुरा, फुलिया कलां एवं बनेड़ा) आती हैं जिनमें पटवारियों के 95 पद स्वीकृत हैं। पटवार हलकावार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में कुल 85 पटवार मण्डल हैं जिनमें से 71 पटवार मण्डलों पर पटवारियों का पदस्थापन किया हुआ है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में 12 पटवारियों को एक-एक पटवार मण्डल का तथा 01 पटवारी को 02 पटवार मण्डलों का (कुल 13 पटवारियों को 14 पटवार मण्डल) अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह है कि बाकी जो पटवार मण्डल खाली है, उनको कब तक भर देंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने जो नई भर्ती की, उसमें हमने सारे पटवारी लगाए, जिसमें 5 पटवारियों ने जोइन नहीं किया। बाद में, और पढ़ाई के लिए 6 महीने का टाइम होता है, स्वीकृति ली और वह अभी आये हैं। फिर हमने वेटिंग लिस्ट जारी की, उसमें 18 पटवारियों को नई नियुक्ति दी है। जिसमें 13 पटवारियों ने जोइन किया और 5 पटवारी अभी पेंडिंग हैं। हाईकोर्ट की डी.बी. का स्टे आ गया, तो यह ट्रेनिंग में है। कुछ पटवारी खाली हैं, वे एलआरसी आफिस के पद हैं, उन पदों

(श्री रामलाल जाट)

पर लगाने की वजह से, लीव रिजर्व, एलआरसी, वह बैठे हुए हैं तो हम तुरंत ही भर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-12 परसेंट के आस-पास हमारी वैकेन्सी अभी खाली है पूरे राजस्थान में। बाकी पटवारी हम भर चुके हैं। पहली बार ऐसी स्थिति ज़िलों में आई।

माननीय, जहां से आप पधारते हैं वहां 78 परसेंट पटवारी राजसमन्द जिले में खाली थे। आज 10 परसेंट से ज्यादा वहां खाली नहीं हैं। पूरे राजस्थान में, हर जिले में, वैकेन्सी के आधार पर पूरे किये। आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए, अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, जल्दी ही और पूर्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 274, वेद प्रकाश जी का है। सामाजिक न्याय मंत्री।

दिव्यांगों को गैर सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण

274. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) (श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू) के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिव्यांगों को गैर-सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा दिव्यांगों की दी जाने वाली पेंशन में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा बजट में गई थी? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त की वृद्धि कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पंचायती राज चुनाव एवं शहरी निकाय चुनावों में दिव्यांग को आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) प्रदेश में राजकीय सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र मे दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण एवं सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करवाया जा रहा है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 21.03.2022 को की गई घोषणा संख्या 32 में ऐसे विशेष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

योग्यजन जिन्हें अपने दैनिक कार्य करने के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त एक हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की गई है। निदेशालय, विशेष योग्यजन के पत्र क्रमांक 29015 दिनांक 30.12.2022 द्वारा अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों के लिये पेंशन राशि के अतिरिक्त मासिक आर्थिक सहायता योजना संबंधित दिशा-निर्देश 2022 जारी किये जा चुके हैं। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, दिसम्बर माह से इनकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, आदेश जारी हो गये, बिल ट्रेजरी में चले गए।

(3) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायती राज चुनाव में दिव्यांग को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास एव पंचायती राज विभाग, राजस्थान की सूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 के अन्तर्गत वार्डों के आरक्षण का प्रावधान है। उक्त आरक्षण वार्डों की संख्या के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः नियमानुसार दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

रमेश चन्द मीना, श्री, मंत्री, को 01 मार्च, 2023 से 12 मार्च, 2023 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रमेश चन्द मीना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपनी माताजी का निधन हो जाने के कारण दिनांक 01 मार्च, 2023 से 12 मार्च, 2023 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कैलाश चन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में क्षतिग्रस्त एवं खराब सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(3) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने के संबंध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जल-जीवन-मिशन की स्वीकृत योजनाओं की पूर्ण रूप से क्रियान्विति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर, जोधपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से कोटपूतली जयपुर में हुई हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से कोटा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रकरणों में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत लाछुडा में संचालित अवैध खानों को अविलम्ब बन्द किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से मावली पंचायत समिति में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में क्रमोन्नत 33 के वी लाइन को जी एस एस 132 के वी से जोड़कर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने के संबंध में।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में शुगर मिल को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में।

(14) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ब्लाक सराड़ा में नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास विद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(15) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे नं. 67 पाली हेमावास से नाडोल तक की अवाप्त की गई भूमि का किसानों व आमजन को मुआवजा दिलाने के संबंध में।

(16) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर विधान सभा क्षेत्र में बुडारामा जोड चौराहा पर परिवहन निगम की बसों का ठहराव न होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

(17) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से कतिपय व्यक्तियों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के कतिपय लाभार्थियों की किस्त अन्य बचत खातों में जमा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्टाम्प विक्रय हेतु पायलट प्रोजेक्ट मोबाइल एप लागू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से भादरा-नोहर के हिस्से के पानी में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में रावत समाज हेतु सम्राट पृथ्वीराज चौहान कल्याण बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री निर्मल

(श्री अध्यक्ष)

कुमावत, श्री सतीश पूनियां, श्री ललित कुमार ओस्तवाल एवं श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।

(2) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर आमजन को राहत दिलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम मवड़ी में हुई संदिग्ध मौतों की स्वतन्त्र एजेन्सी से जांच करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में चंबल सागरपाड़ा चैक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश में टैक्सियों हेतु स्थायी टैक्सी स्टैण्ड आबंटन करने के संबंध में।

(8) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से मण्डावर को पंचायत समिति बनाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति किये जाने के संबंध में।

(9) श्री कैलाश चन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का राजकीय सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने के संबंध में।

(10) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर-नापासर-जसरासर स्टेट हाईवे-20 बी के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारम्भ करवाने के संबंध में।

(11) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से डा. एस. एन. मेडिकल

(श्री अध्यक्ष)

कालेज, जोधपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(12) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से रेडियोग्राफर संवर्ग का पदनाम परिवर्तित कर रेडियोलोजी आफिसर करने के संबंध में।

(13) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के सर्विस लेन एवं शहर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में बदहाल सिंचाई व्यवस्था के संबंध में।

(15) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से नगरपालिका पिण्डवाड़ा में स्थित सामुदायिक भवनों का समुचित रखरखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यगण, आज मेडिकल की चर्चा है इसलिए 295 के जितने भी प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा हुआ माना गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

माननीय सदस्यों से पुन: निवेदन है कि हमारी डिबेट सारगर्भित हो, पालिसी के बारे में चर्चा हो। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम समय में पालिसी के बारे में ज्यादा चर्चा करें और कट-मोशन का जवाब दें तो हम क्वालिटी आफ डिबेट को ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। डिबेट को हम 9 बजे तक वाइंड अप कर दें including reply of the Minister तब तो हम इफेक्टिव ढंग से कर पायेंगे, क्योंकि कल भी हमारा हाउस चलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब कोआपरेट करें और डिबेट को हम अच्छे तरीके से सम्पादित कर सकें। श्री रामलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बेरोजगारों पर लाठीचार्ज

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर इंगित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अन्दर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संसदीय कार्य मंत्रीजी बात कर रहे हैं, गम्भीर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी आपके मित्र हैं। आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यहां तक आवाज आ रही है। हमारी चिन्ता मत करो, आपकी खुद की चिन्ता करो। बैठे-बैठे हमारे लिए टिप्पणियां ठोक रहे हो। कल यह है, कल यह है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो यह कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कल उपस्थिति कम होगी। मेरा निवेदन यह है कि उपस्थिति कल कम होगी, क्योंकि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। एक तरफ वर्षगांठ और दूसरी जुलूसबाजी। मैं यही कह रहा हूं, साहब, इनसे।

श्री अध्यक्ष: मैंने यही कहने के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया था। धन्यवाद। श्री रामलाल शर्माजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अन्दर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास करे। 07 फरवरी को राजस्थान के अन्दर पेपर लीक, भर्ती और भर्ती के परिणामों के मामलों को लेकर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में एक डेलिगेशन आर पी एस सी के अधिकारियों से मिलने के लिए आता है और 07 फरवरी को जैसे ही डेलिगेशन, जिसमें 35-40 लड़के थे, वे आर पी एस सी के कार्यालय पर पहुंचते हैं तो 8-10 पुलिसकर्मी तैनात दिखाई देते हैं। आपस में वार्ता होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय रामलालजी, आपके मित्र मदन दिलावरजी आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं इसमें। वह बोल रहे हैं माननीय मदनजी कि आप दोनों का फोटो जायेगा, आपका और धारीवाल साहब का। रामलालजी बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम एक ही जिले के हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को तो आप बोलने दें। श्री रामलालजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): साहब, मैं क्या बताऊं, कभी ओम शांति होती है, कभी कुछ।

श्री अध्यक्ष: जो भी शांति है, आप दोनों की शांति रखना। बोलो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब डेलिगेशन आर पी एस सी कार्यालय के बाहर पहुंचा तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके पांच सदस्यों की हम आर पी एस सी के सेक्रेटरी से मुलाकात करवा देते हैं। इस बात पर सहमति बन गयी। वहां कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई अभद्रता नहीं थी, कोई रास्ता रोका नहीं गया था। तब मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि आपका डेलिगेशन अन्दर जाए उससे पहले आप मीडिया को बाइट दे दो। उपेन यादव जब बाइट दे रहे थे तब वहां के सिविल लाइन एस एच ओ मौके पर आते हैं, बिना कोई वार्ता के लाठीचार्ज करते हैं और उपेन यादव की गिरेबान पकड़ कर उनको गाड़ी में डालने की कार्यवाही करते हैं और थाने में ले जाकर उनके साथ अभद्रता करते हैं। उनके बाल नोंचने का काम करते हैं और बाल उखाड़कर डस्टबिन में डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का दुर्व्यवहार करने के बाद उसको कहते हैं कि तेरी नेतागीरी जयपुर में जाकर करना। दुबारा अजमेर में आकर नेतागीरी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से इतना ही निवेदन है कि इस पूरे मामले के अंदर SHO के खिलाफ कार्यवाही करके इस पूरे मामले की जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें और निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि इसने 22 दिन से अन्न त्याग कर रखा है और आज उसने जल त्याग करने की भी घोषणा की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है, सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

सूरसागर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज पुलिस के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी। मैं उनकी निन्दा तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी तो रग-रग के अंदर पुलिस है, मगर इनकी कार्यशैली बदलनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। जब तक कार्यशैली नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट एक अनुशासित डिपार्टमेंट है और हर वक्त इसको काम में लेना भी जरूरी होता है। जुलूस निकलेगा या कोई भी कार्य होगा तो पुलिस पहले आयेगी, मगर इनके पास ऐसी कोई नफरी नहीं है, जितनी कि वह काम में ले सकें और आपको दे सकें। फिर भी इसके ऊपर कुछ विचार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सूरसागर क्षेत्र के अंदर आये दिन चोरियां होती हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता, जब चोरी नहीं हुई हो और एक भी चोरी खुलती नहीं है। पुलिस वालों से कोई भी ऐसा व्यक्ति छिपा नहीं है जिससे कि यह पता चले कि यह चोर है। अभी तो मैं थानों के अंदर कम जाती हूं, परंतु एक जमाने के अंदर बदमाशों की वहां पर एक लिस्ट लगी हुई होती है, इसके साथ ही फोटो लगी होती है कि वह आज कितने दिन से गायब है, आज वह कहां है। अब यह लिस्ट और फोटो लगती है या नहीं, इसकी जानकारी मैंने की नहीं। मगर फिर भी अपने को इस बात के लिए तो देखना ही पड़ेगा कि आये दिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं और क्यों होती हैं? इनका भी कसूर मैं नहीं बतला सकती और, न और कोई बतला सकता है, क्योंकि इनके पास नफरी नहीं है। थानों के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर जितने लोग होने चाहिये, मेरे हिसाब से थानों के अंदर कम से कम 50-60 आदमी तो होने चाहिए, आज की तारीख में किसी भी थाने में 50 आदमी भी नहीं हैं। बहुत कम आदमी हैं और नफरी नहीं होने से काफी असुविधा रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं चूंकि सदन के नेता गृह मंत्री भी हैं, तो उनको इसके लिए सोचना चाहिये। कोई भी जोधपुर का थाना और कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची जहां मैं नहीं गयी हूं। मैं खुद एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं और मैं तो पुलिस वालों को देखती हूं तो बड़ा गर्व होता है। मगर आजकल का जमाना ऐसा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर राज किया है तो कांग्रेस ने किया है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, आपका हो गया।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मेरी बात को कहने दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नियम 50 में निश्चित समय होता है। यह जनरल डिमांड नहीं है। राजेन्द्र जी ने आपको पुलिस की डिमांड पर नहीं बुलाया।

श्रीमती सूर्चकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पांच मिनट दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो मैं मेरी बात कहती हूं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): पांच मिनट दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समझो, मैंने आपको अलाउ किया है आपके कहने से। आज पुलिस की डिमांड नहीं है। इसमें आप खाली निश्चित समय में अपनी बात कह दें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर तीन थाने ऐसे हैं जिनको जमीन भी उपलब्ध नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हर थाने के अंदर स्वागत कक्ष होना चाहिये। यह जरूरी है, होना भी चाहिये। इज्जत होनी चाहिये, कोई भी आवे तो उसकी इज्जत तो होनी चाहिये, मगर बनावें कहां? जहां थाने थे एक-दो मैंने बना दिये। मैंने पुलिस चौकी बनवा दी, मैंने थाने बनवा दिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज हेल्थ पर डिबेट है, आप अपनी बात को समाप्त करें प्लीज।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मेरी मांग यह है कि जो तीन थाने हैं, वे किराये के भवनों में चल रहे हैं, उनके लिए जमीन उपलब्ध करायी जाये। अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करवायेगी तो थाना कैसे बनेगा? एक-एक कमरे में थाना चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि इनकी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात समझो। आप पुराने सदस्य हैं, बात समझें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इनको भत्ता देवें। इनके मैस में खाना अच्छा देवें। आप मैस का खाना तो देखिये, साहब, आप कभी जोधपुर आकर देखो तो सही, मैस का खाना कैसा है?

श्री अध्यक्ष: मैं मुख्य मंत्रीजी को कहूंगा आपको साथ लेकर जावें। धन्यवाद। श्री निर्मल कुमावत।

कोटपूतली (जयपुर) में हुई हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत बोलने की अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान कोटपूतली की एक घटना की ओर आकर्षित करता हूं। 04 नवम्बर, 2022 को विकास प्रजापत पुत्र प्रकाश प्रजापत, निवासी बड़ाबास मोहल्ला, कोटपूतली अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में शादी समारोह में गया और दूसरे दिन सुबह 7.00 बजे इसके पिताजी प्रकाश प्रजापत को लोगों ने सूचना दी कि आपका बेटा अचेत अवस्था में सड़क पर मिला है और उसको BDM अस्पताल, कोटपूतली में भर्ती कराया गया है, आप तत्काल वहां पहुंचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि गृह राज्य मंत्रीजी, कोटपूतली से ही आते हैं, उनके खुद के क्षेत्र का मामला है। 05 तारीख को बाकायदा इन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया और तब से आज तक लगभग 4 माह हो गये, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। वह जगह-जगह दर-दर भटक चुके हैं और 21.12.2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर वहां बैठे हैं, मगर आज तक सरकार की ओर से कोई भी सुनवाई नहीं हुई और मजे की बात तो यह है कि FSL की टीम पांच दिन बाद मौके पर पहुंची। परिवारजनों की मांग है कि इसकी CBI से जांच हो। पूरे प्रजापत समाज में इसका आक्रोश है। मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस पीड़ित परिवार से भेंटकर उनकी मांगों को मानें और पूरे समाज को न्याय दिलायें। यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

कोटा के कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के बढ़ते आत्महत्या प्रकरण

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वह राजस्थान के नौजवानों के लिये बड़ा गम्भीर मुद्दा है। कोटा इस समय कोचिंग और एजुकेशन का हब है, लेकिन पिछले चार वर्षों के आंकड़े देखें तो चौंकाने वाले हैं और इस वर्ष का देखेंगे तो पूरे राजस्थान के लिए चिंता का विषय है। 10 हजार नौजवान आत्महत्याएं करते हैं, जिसमें 2,442 विद्यार्थी हैं। अकेले कोटा सम्भाग में 55 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और 2022 में 16 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। यह कोचिंग के कारण जो तनाव है बच्चों के बीच में, उसमें मुझे लगता है कि पूरे देश भर के बच्चे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के और राजस्थान में

(श्री सतीश पूनियां)

भी उस कोटा सम्भाग के बच्चों में लगातार एक के बाद एक आत्महत्याओं का सिलसिला है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिये, क्योंकि इस तरीके से उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। उनके लिए एक अच्छी काउंसलिंग की व्यवस्था हो। कोई जिम्मेवारी उसकी तय हो, क्योंकि एक दार्शनिक ने कहा है कि चिंतित मनुष्य अपने जीवन का महत्व खो देता है। वह इस प्रदेश का नागरिक है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करके कोई न कोई नीति अपनाकर उन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होने से रोकने के लिए सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

प्रधानमंत्री आवास योजना के कतिपय लाभार्थियों की किस्त अन्य बचत खातों में जमा होना

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत आपने और मेरी पार्टी के नेताओं ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिये आप सबका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: पार्टी के नेता, राजेन्द्र जी का नाम आप जबरदस्ती ले रहे हैं। बोलो आप।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, डूंगला में शांतिबाई पिता लक्ष्मण मीणा, कालीबाई पिता प्यारा भील, हरलाल पिता भैरा मेघवाल, अम्बाबाई पिता सोहनलाल मीणा, भैंरूलाल पिता कालू मीणा, मगना, भवानीशंकर, दुर्गाशंकर, भूरीबाई, ये 9 व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं। इनको प्रथम किस्त मिल भी गयी है और इन्होंने काम प्रारम्भ भी कर दिया है। इनका जो पुराना छोटा-मोटा मकान होगा, कच्चा-पक्का या छपरे का, उसको गिराकर पक्का मकान बनाने के लिए इन्होंने काम भी प्रारम्भ कर दिया। इनको प्रथम किस्त भी मिल गयी, लेकिन किसी को दूसरी किस्त और किसी को तीसरी किस्त, किसी अपराधी द्वारा या विभागीय गलती से दूसरे के खातों में चली गयी। ये गरीब व्यक्ति हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिलाया जाये। उनसे तो पता नहीं कब वसूली होगी पर मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को सरकार की तरफ से जो दूसरी और तीसरी किस्त की बकाया है, इनको इस राशि में से दूसरी और तीसरी किस्त दिलायी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

भादरा-नोहर के हिस्से के पानी में कटौती

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 स्थगन प्रस्ताव में भादरा-नोहर के हिस्से के पानी में कटौती पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

भादरा-नोहर के हिस्से का पानी 400 क्यूसेक्स प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे नहरी क्षेत्र की फसल, जो पकाव पर आयी हुई फसल है, उनको पानी नहीं मिलेगा और इलाके में खड़ी फसलें बर्बाद हो जायेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारी खर्चे और मेहनत के बाद किसानों को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। विधान सभा क्षेत्र के किसानों की मांग है कि 15 अप्रैल तक 600 क्यूसेक्स पानी अमरसिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर यानी भादरा-नोहर के हिस्से का पानी तय करवाया जाये तथा BBMB की बैठक में स्थायी तौर पर जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये, ताकि क्षेत्र की मांग को वहां अच्छे से रख सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गंगनहर के किसान भी इसी तरह पानी के लिये आन्दोलनरत हैं। मेरी मांग है कि हमारा 15 अप्रैल तक पानी 600 क्यूसेक्स करवाया जाये, ताकि हमारी फसलों को आखिरी पानी मिल जाये और फसल पक जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण, 131, श्री वासुदेव देवनानी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर शहर में अपंजीकृत ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अजमेर शहर में बिना रजिस्ट्रेशन सरपट दौड़ रहे ई-रिक्शा के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ई-रिक्शा चालकों को नियमित लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, ई-रिक्शा के लाइसेंस व पंजीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार पंजीयन व लाइसेंस बनाये जा रहे हैं। अजमेर शहर में 1672 यात्री ई-रिक्शा व 153 वाहन ई-कार्ट कार्यालय में पंजीकृत हैं। कार्यालय द्वारा दिनांक 01.01.2015 से 28.02.2023 तक ई-रिक्शा के 125 स्थायी लाइसेंस जारी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

किये जा चुके हैं तथा 1,357 व्यक्तियों के लर्निंग लाइसेंस जारी किये गये हैं।

अजमेर शहर में यातायात नियंत्रण की कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा की जाती है। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा 01.01.2021 से 28.02.2023 तक कुल 5,019 चालान बनाये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। जिला परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, अजमेर को उक्त संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर एक पर्यटक एवं धार्मिक स्थल है, जहां हजारों देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ई-रिक्शा का उपयोग भी करते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में वे पंजीकृत नहीं हैं। जैसा आपने कहा कि 1,672 पंजीकृत हैं, तो उनको चलाने वालों के पास लाइसेंस भी नहीं हैं। आपने अपने उत्तर में कहा है कि केवल 87 स्थायी लाइसेंस हैं, इसका मतलब बाकी के पास लाइसेंस नहीं हैं। साथ में अभी आपने कहा कि 1,260 लर्निंग लाइसेंस हैं। लर्निंग लाइसेंस तो एक महीने के लिए होता है और आपने अभी-अभी किया है। इसका मतलब है कि पिछले वर्षों में लगातार बिना लाइसेंस के हजारों ई-रिक्शा चल रहे थे। यदि मैं शब्द कहूं तो अनाड़ी, नाबालिग, कथित खानाबदोश, नशेड़ी, नौसिखिये उनको चला रहे हैं। इसके कारण वह कई बार जितनी ई-रिक्शा की कैपेसिटी है, उससे दुगुने लोग उसमें भर देते हैं, जिसके कारण वे कई बार पलट भी जाते हैं। पर्यटक भी घायल हो रहे हैं। स्थायी निवासी भी इनसे घायल हो रहे हैं। इस समय परिवहन अधिकारी व यातायात पुलिस उनको देखते भी हैं लेकिन वह अंगूठा दिखाते हुए चल रहे हैं। कोई कार्यवाही वहां पर नहीं हो रही है, इतना मैं आपके सामने कह रहा हूं। मेरी मांग है कि वहां पर परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस दोनों के जितने चल रहे हैं, मुझे आप बतायें कि कितने समय में सबके लाइसेंस बना देंगे? आपने ही कहा है कि हमने इतने लर्निंग दिये, इतने वह दिये। कब तक आप सारे लाइसेंस बना देंगे? इनको आप निर्देशित करें कि बिना लाइसेंस के या नाबालिग 18 वर्ष से कम का कोई भी बालक ई-रिक्शा को नहीं चलायेगा, यह सुनिश्चित करें, ताकि पर्यटक एवं स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके। कोई घायल नहीं हो।

अजमेर का विषय तो नहीं है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड अप नहीं कर सकते? बार-बार रिपीट कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, मैं उसको गंभीरता से लूंगा। इसी महीने हम पुलिस और परिवहन विभाग दोनों से सामंजस्य करके कैंप लगाकर उनके लाइसेंस बनवायेंगे। सघन जांच करने के लिए पुलिस के ए डी जी, ट्रैफिक और हमारे अधिकारियों को निर्देशित करके इस पर प्रभावी कार्यवाही कराऊंगा। जांच करायेंगे और कोशिश यह करेंगे कि बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी ई-रिक्शा नहीं चले। जो लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं, पहले उनको लर्निंग लाइसेंस के लिए अवसर देंगे कि उस कैंप का फायदा उठायें और लाइसेंस बनवायें, अगर नहीं बनायेंगे तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। समस्या के लिये थोड़े ही है, तरीका है उसके लिये। बैठे-बैठे नहीं बोलें। बैठें, प्लीज। समस्या ऐसे थोड़े ही होती है।

श्री अविनाश।

जैतारण में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत जैतारण विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत किये जाने के संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ब्लाक जैतारण में 10 वर्ष से पूर्व निर्मित तथा क्षतिग्रस्त कुल 33 सड़कों में से 11 सड़कों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें से 4 सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 7 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है। शेष क्षतिग्रस्त 22 सड़कों के नवीनीकरण की लागत रुपये 18.51 करोड़ रुपये होगी, जिसकी स्वीकृति किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। ब्लाक जैतारण की सूचना विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उप खण्ड बर, के रायपुर ब्लाक में 10 वर्ष से पूर्व निर्मित एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या 20 है, जिनमें से 4 सड़कों

(श्री भजनलाल जाटव)

की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 16 सड़कों के नवीनीकरण की लागत रुपये 16.80 करोड होगी, जिसकी स्वीकृति किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने लगातार विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में ध्यानाकर्षित कराया है। लेटेस्ट 24.06.2022 को मैंने माननीय मंत्री महोदय के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण और बर उपखण्ड के अंतर्गत आने वाली वे सड़कें जो नोन-पेचेबल हैं, उनको 10 साल तो कम से कम हो गये, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 17 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है। उनकी सूची मैंने माननीय मंत्री जी को दी है। इसमें कुल 22 सड़कें थीं। उसमें से कुछ सड़कें तो पी एम जी एस वाई में अभी हाल ही में स्वीकृत हुई हैं। एक-दो सड़कें बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी हैं। इतनी लम्बी लिस्ट मैं लगातार विभाग को दे रहा हूं।

माननीय मंत्री महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट वर्ष 2023 के बजट पैरा 93 में जिले की प्रमुख सड़कों के लिए साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। उसके अलावा पैरा नंबर 97 में पेज 71, 72 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है कि मानसून के कारण अच्छी खेती तो हुई लेकिन सड़कों का अत्यधिक नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो सरकार बजट में कह रही है..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। बी ब्रीफ। ध्यान रखें।

श्री अविनाश (जैतारण): बजट के अंदर जब यह बात है कि सड़कों की दशा को सुधारेंगे तो जो यह मेरे उत्तर में दिया है कि जैतारण ब्लाक की 22 सड़कें हैं, जिनकी लागत 18.51 करोड़ तथा बर ब्लाक की 16 सड़कों की लागत 16.80 करोड़ है, कुल मिलाकर के मात्र 35 करोड़ रुपये ही है। यह जो सड़कों की लिस्ट आपको अपने विभाग से प्राप्त हुई है, इनका नवीनीकरण कब तक कर देंगे? ये 15 साल पुरानी सड़कें हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय मंत्री महोदय, यह कब तक कर देंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में इन 4 सालों में तकरीबन 117.85 करोड़ के कार्य कराये गये हैं। यह 2023-24 का बजट है वह अलग है। मैंने आपको बोल ही दिया कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। हम चरणबद्ध तरीके से अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब 5 साल आपकी सरकार थी, तो वहां कुछ काम नहीं हुए। उसके उपरांत भी 117.85 करोड़ के कार्य आपके करा दिये गये हैं। मैंने कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते जायेंगे तो हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री टीकाराम जूली।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत निम्न 2 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा (वर्ष 2021-22)

(1) खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा वर्ष 2021-22 एवं

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा (वर्ष 2021-22)

(2) जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रीको) का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय लेखा वर्ष 2021-22.

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री परसादी लाल जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,07,40,89,000/- (उनचास अरब सात करोड़ चालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक और है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक और है। एक सैकण्ड।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,74,40,00,000/- (एक सौ एक अरब चौहत्तर करोड़ चालीस लाख) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर चर्चा हो रही है। यह राजस्थान का सबसे संवेदनशील विभाग है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी पूरे देश और दुनिया में जगह-जगह जाकर राजस्थान माडल की बात करते हैं, चाहे वो कोरोना का माडल हो, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का माडल हो, चाहे और हो। मैं समझता हूं कि राजस्थान के पूरे आठ करोड़ लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित विभाग है। हर व्यक्ति को इस विभाग से कहीं न कहीं कोई न कोई काम पड़ता है।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना तो देखो कि मंत्रीजी के पास दो विभाग हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक विभाग आबकारी है और दूसरा विभाग स्वास्थ्य है। एक विभाग दूसरे का स्वास्थ्य खराब करने वाला है और एक विभाग यह करता है। मैं यह समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या क्वालिटी है मंत्रीजी में कि आबकारी और स्वास्थ्य दोनों का कोई काम्बिनेशन ही नहीं और ये दोनों विभाग आपको दे रखे हैं। एक विभाग दूसरे के मूल रूप से खिलाफ है। एक विभाग दूसरे विभाग के लिए पूरा का पूरा खिलाफ और आपके पास ये दोनों विभाग हैं। इस विभाग की क्या स्थिति है यह देखो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूज पेपर्स में हम लगातार पढ़ते हैं, कल ही सब लोगों ने राजस्थान को शर्मसार करने वाली एक न्यूज पढ़ी, यह पहली भी नहीं है, लगातार इतनी बड़ी मानवीय संवेदना की कैसे भूल हुई कि यह लगातार आठवीं-दसवीं बार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक आर्टिकल छपा राजस्थान पत्रिका में और लिखा 'क्रूरता की हद', उन्होंने अंदर इसके जो शब्द लिखे, कि यह क्रूरता केवल किसी पेशेंट के साथ नहीं है, यह क्रूरता केवल उस अबोध बालक के साथ नहीं थी जिसके साथ यह घटना हुई, यह क्रूरता उस राजस्थान की जनता के साथ है, जिसके साथ यह घटना हुई। यह दुर्भाग्य है हमारा कि जब भी इस तरह की कोई बात सदन में हम करते हैं तो हम उसको हमेशा पक्ष और विपक्ष में ले जाते हैं। मंत्रीजी जब जवाब देते हैं तो साढ़े चार साल बाद भी पिछली सरकारों का रोना रोते हैं। ये हम किस बात का यहां पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो आज जो बातें, माननीय मंत्रीजी, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूं, मैं प्रथम बार का आया हुआ सदस्य हूं, मैं किसी प्रकार के बायस्डनेस की बात नहीं कर रहा हूं। यह राजस्थान के आठ करोड़ लोगों की बात है। हम राजस्थान को क्या देना चाहते हैं कि राजस्थान में हास्पिटल में एक बच्चा सो रहा हो और उसको श्वान उठाकर ले जाए, कोई कुत्ता ले जाए, उसको नोंच दे और वह खतम हो जाए। मैं समझता हूं कि शायद इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती।

(समय: 12.32 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सिरोही में 29 दिन के नवजात को अस्पताल में नोंच-नोंचकर मार डाला। जोधपुर में दर्द से तड़पती महिला को लेबर रूम से बाहर निकाल दिया और सड़क पर प्रसव हुआ, यह हमारा

(श्री अशोक लाहोटी)

राजस्थान का चिकित्सा माडल है। अस्पताल में कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला, यह राजधानी जयपुर के सांगानेरी गेट हास्पिटल में मिला। आई सी यू में लकवाग्रस्त महिला की पलक चूहे कुतर गए। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी एक मिनट में पल्ला झाड़ देंगे, कह देंगे कि ये श्वान तो धारीवालजी के विभाग के हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। धारीवालजी कहेंगे कि ये हास्पिटल इनके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों के आपसी विवाद में राजस्थान की जनता के साथ में जिस प्रकार का मजाक हो रहा है, मैं समझता हूं कि पूरे चिकित्सा विभाग का मजाक है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा में पहले नवजात शिशुओं की मौत का विषय चला राजस्थान में। आखिर इस विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील विभाग है?

माननीय सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी ने लगातार बात की और राजस्थान विधान सभा के हर सदस्य ने चिरंजीवी पर बात की, मैं इस चिरंजीवी पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूंगा। इस चिरंजीवी में आप जाओ कि यह चिरंजीवी है क्या? ये चिरंजीवी राजस्थान सरकार का एक स्टार्टअप है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कैसे स्टार्टअप है, यह पहली बार इस चिरंजीवी में, आप देखो बनाने वाले ने बड़ी अच्छी योजना बनाई हो, मैं धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन इस योजना का हश्र क्या हो रहा है? इस विभाग में राजस्थान में केन्द्र सरकार की इंश्योरेंस कम्पनियों को लूटने की यह योजना है। कैसे है? आज से पहले भी सरकारी हास्पिटल में फ्री इलाज होता था, नि:शुल्क दवाएं मिलती थीं, सारे टेस्ट फ्री होते थे और मुख्य मंत्रीजी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तब भी उन्होंने किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है? इस बार, पहली बार सरकारी हास्पिटल को भी इलाज का वो पैसा मिल रहा है जो प्राइवेट हास्पिटल को मिल रहा है, यह कमाई का जरिया इन्होंने चिरंजीवी के माध्यम से सरकारी हास्पिटलों को बनाया है। आज एस एम एस अस्पताल में जो इलाज हो रहा है उसका वो का वो पैकेज मिल रहा है जो प्राइवेट हास्पिटल को मिल रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में जो इलाज हो रहा है उसको भी वही पैसा मिल रहा है जो प्राइवेट हास्पिटल को मिल रहा है, तो इलाज की क्वालिटी कैसे मिलेगी? इलाज की क्वालिटी भी है तो, मंत्रीजी, आप जरूर जवाब देना। आज हालात क्या हैं? मैं यदि यह कहूं कि आज हास्पिटल में मुफ्त इलाज के लिए भी अगर बात करें तो केन्द्र सरकार की इंश्योरेंस कम्पनियों से आज पैसे ले ही

(श्री अशोक लाहोटी)

रहे हो, चलो लो आप, लेकिन आपके पैकेज क्या हैं? आप जिम्मेदारी के साथ बताना कि जब चिरंजीवी योजना पांच लाख रुपये की थी, आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम बदला, पांच लाख रुपये भी आज तक राजस्थान में कितने लोगों को मिले हैं? राजस्थान में कुल 33 लाख लोगों ने अब तक क्लेम लिया है, 33 लाख लोगों में से पूरे पांच लाख रुपये अभी तक कितने लोगों को मिले हैं? यदि 100 लोगों को भी मिला हो तो उनके नाम की लिस्ट को यहां आप टेबल जरूर करें, मैं बिलकुल आपसे पूछूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए नहीं मिल सकता कि यदि कोई भी सदस्य, कोई भी राजस्थान का व्यक्ति यदि उसको हार्ट की बीमारी हो जाए, वो एडमिट होने जाता हो, हार्ट के साथ उसको नेफ्रो की प्रोब्लम हो जाए, गेस्ट्रो की हो जाए, उसको कोई और लीवर की प्रोब्लम हो जाए, कुछ भी प्रोब्लम हो जाए, उसको पांच-छह बीमारियां भी एक साथ हो जाये और वो पूरा एक महीना भी एडमिट रहे तो उसका पूरा खर्चा 3 लाख 67 हजार रुपये से एक रुपया ऊपर नहीं आएगा। आप पांच बीमारियों का एक साथ जोड़ लो, 3 लाख 67 हजार रुपये से ऊपर उसका खर्चा नहीं आएगा। आप उसको 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 25 लाख कर दो, जब पैसा होना ही नहीं है खर्च, उसका इलाज ही नहीं होना तो आप 5 करो, 10 करो, 25 लाख करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पैकेज की रेट देखो, जो इन्होंने पैकेज बनाये हैं, उन पैकेज की रेट में कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट हास्पिटल में आपको कार्डियोलॉजी का इलाज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कार्डियोलॉजी की रेट है, उस रेट पर इलाज नहीं होगा। आर्थो सर्जरी नहीं होगी, न्यूरो सर्जरी नहीं होगी, गेस्ट्रो सर्जरी नहीं होगी, न्यू-गेस्ट्रो सर्जरी नहीं होगी, आन्कोलॉजी सर्जरी नहीं होगी, ये किसी भी प्राइवेट हास्पिटल में जाकर आप करवा लो, यदि वो करते हैं तो उन्होंने पास में किराये पर कोई हास्पिटल ले रखा है, जहां पर भेड़-बकरियों की तरह मरीजों को डालते हैं। चिरंजीवी योजना और आर जी एच एस वाले लोगों के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि यह योजना अच्छी है, इस योजना पर आप ध्यान देकर इस योजना को ठीक करें, इसके पैकेज की रेट ठीक करें, इसमें आपके घर से कुछ नहीं लग रहा है, पैसा इंश्योरेंस कम्पनी दे रही है आपको, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने कंजूस क्यों हो रहे हो?

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि किसी प्राइवेट हास्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी और मोतियाबिन्द और ई एन टी के आपरेशन भी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? अधिकांश हास्पिटल तो कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने मना ही कर दिया। जयपुर शहर में आप बता दें, सैकड़ों हास्पिटल, 70 प्रतिशत हास्पिटल इलाज नहीं कर रहे हैं। आपने पिछले तीन सालों में किस हास्पिटल पर क्या कार्यवाही की? जगह आपने फ्री दी, अभी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में धमकाया भी, अभी आपने हास्पिटलों की बिल्डिंग का ले-आउट प्लान नापा, धारीवालजी के डिपार्टमेंट से, उनको धमकाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? इलाज तो अभी भी नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप कोई भी व्यक्ति भेजकर देख लो, किसी भी विधान सभा क्षेत्र में प्राइवेट हास्पिटल इलाज नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक रुपये की चीज है और आप कहें कि 25 पैसे में दें, तो वह कैसे देगा? आप एस एम एस हास्पिटल में तो उस रेट पर इलाज नहीं कर सकते उस व्यक्ति का और आप कह रहे हो कि प्राइवेट हास्पिटल उसका इलाज कर दे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा मजाक आज के दिन यह है कि किसी प्राइवेट हास्पिटल में पेसमेकर लगवाकर बता दो, आप बोन कैंसर का इलाज करवा दो, इम्प्लांट का करवा दो। क्यों? क्योंकि इनकी आपने जो रेट रिवाइज की है वो आपने 01 लाख 30 हजार रुपये की है। मैं इस सदन में कह रहा हूं कि, माननीय मंत्रीजी, आप इसकी रेट मंगवा लो, इस दुनिया में इन इक्विपमेंट की रेट 01 लाख 30 हजार रुपये में उपलब्ध हैं क्या? ये आपके बुद्धिमान अधिकारी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो। जब आपकी कम्पनी आर एम आर एस खुद ही इस रेट से ज्यादा में इसको खरीद रही है तो प्राइवेट हास्पिटल उसका इलाज इससे कम रेट में कैसे कर देंगे? वो तो इलाज भी इससे कम में कर दे और आपकी कम्पनी उसको उससे कम खरीद ही नहीं सकती, तो यह पैकेज कौन बनाता है? ऐसे बुद्धिमान, चतुर लोग कौन हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं कि प्राइवेट हास्पिटलों ने पास में छोटे-छोटे हास्पिटल किराये पर ले रखे हैं और मंत्रीजी, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भी जयपुर में ही रहते हो। क्यों उन पर कार्यवाही नहीं हो रही? आपके लालसोट के लोग भी जाते हैं तो आपको फोन करना पड़ता है,

(श्री अशोक लाहोटी)

फिर भी किसी बड़े हास्पिटल में उनका इलाज नहीं होगा, पास में जहां भेड़-बकरियों की तरह पेशेंट भरे जाते हैं, उस प्राइवेट चिकित्सालय में वहां पर किराये पर ली हुई दुकान में उनका इलाज होता है। क्यों? क्योंकि आपने उनका गला घोट रखा है। इसीलिए आप राइट-टू-हेल्थ बिल ला नहीं पा रहे हो। प्रवर समिति की दो महीने से आप मीटिंग नहीं कर पाये। क्यों? क्योंकि आपने इसका ट्रैक ही गलत पकड़ लिया। आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। इसके पैकेज की रेटों को सबसे पहले रिवाइज करने की जरूरत है वरना यह चिरंजीवी योजना राजस्थान में औंधे मुंह पड़ चुकी है और आप किसी व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाओगे।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी में यदि पहले कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले तो उसको कहते हैं कि ट्रायल है, पोर्टल चला तो ठीक है, वरना नकद में इलाज कराओ। फिर यदि उसको एक से ज्यादा डाक्टरों को दिखाना है तो उसको कहते हैं कि अलग-अलग दिन आओ। फिर यदि वो करता है, सरकार का दावा है कि अस्पतालों में जांचें फ्री होंगी और हकीकत क्या है? पैकेज समेत 280 तरह की जांचें ही बंद कर रखी हैं।

आज हालात क्या हैं? कैंसर जैसी बीमारियों के इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, जो चिरंजीवी योजना में लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। 11 लाख कर्मचारी पेंशनर्स की हार्ट, बीपी, समेत 30 से ज्यादा फ्री दवाएं बन्द पड़ी हैं और 33 में से 25 जिलों में स्पेशलाइज्ड डाक्टर्स ही नहीं हैं। यदि हों तो आप चैक करवाकर लिस्ट मंगवा लें। आप जवाब दे दीजियेगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहूंगा, थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप केवल लालसोट के ही नहीं, पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, आपको चिन्ता सता रही है, पर इस लालसोट की दुनिया से बाहर भी निकलें, पूरे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बनें। पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है। यह सबसे बड़ा महकमा है, जिसे आप लेकर बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जवाब देते समय आप इन सब चीजों को इन्कारपोरेट करके इस पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना में देखें, आज तक राजस्थान में कुल 01 लाख 94 हजार परिवार हैं। चिरंजीवी योजना में 1 लाख 38 हजार परिवार कवर्ड हैं। उनमें से 01 करोड़ 04 लाख एन एफ एस ए वाले परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना में केन्द्र सरकार 05 लाख रुपये दे रही है। वे 05 लाख रुपये भी आपके खर्च नहीं हो रहे हैं। 01 करोड़ 4 लाख वे परिवार हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

15 लाख छोटे किसान हैं। 02 से 03 लाख कान्ट्रैक्चुअल एम्प्लायीज हैं। 15 लाख आर जी एच एस वाले कर्मचारी हैं। 02 से 03 लाख वे हैं, जिन्हें कोविड-19 में ग्रांट मिली थी। ऐसे करके 01 लाख 38 हजार परिवार हैं। यानी कुल 05 करोड़ लोग। चलिये, मैंने यह मान लिया, केन्द्र सरकार जो पैसा दे रही है, वह भी आपका है, सब है, 850 करोड़ रुपये तो जनता आपको दे रही है और 850 करोड़ रुपये सरकार उसमें मिला रही है। चिरंजीवी योजना, जिसका इतना बड़ा प्रचार किया जा रहा है, राजस्थान के 03 लाख करोड़ के बजट में मात्र 1,700 करोड़ की पूरी योजना है, जिसका पैसा इंश्योरेंस कम्पनियों के माध्यम से आपको मिल रहा है। सभापति महोदय, आप कल्पना करें कि राजस्थान की 08 करोड़ जनता में से जो 05 करोड़ लोग चिरंजीवी योजना में इलाज ले रहे हैं, उनका केवल और केवल 1,700 करोड़ रुपये का बजट है। यानी प्रति व्यक्ति में निकालूं तो 324 रुपये का खर्चा आता है। इससे पहले यदि प्रति व्यक्ति राजस्थान का आप देखें तो जो खर्चा आता था, वह आता था 2,496 रुपये। आज इस चिरंजीवी योजना के आने के बाद राजस्थान में 340 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आ रहा है।

सभापति महोदय, आप इस चिरंजीवी के बजट में राजस्थान का भला नहीं कर रहे हैं। आप यह देखें कि इतने कम बजट में आप 8 करोड़ लोगों को जो झुनझुना पकड़ा रहे हैं, मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह योजना आपको फायदा नहीं, नुकसान देकर जायेगी, क्योंकि जो इलाज लेने जा रहा है, उसे इलाज के स्थान पर ताने मिल रहे हैं, उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, वह नेताओं के यहां घूम रहा है, फोन करवा रहा है, उसके बाद भी उसे इलाज नहीं मिल रहा है। यह सच्चाई है राजस्थान की, चाहे आप सर्वे करवाकर देख लें। आपके पास तो बड़ी-बड़ी सर्वे एजेंसियां हैं ही, जो अभी डी ओ आई टी के माध्यम से काम कर रही हैं। उनके माध्यम से सर्वे करवाकर देख लें, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी।

सभापति महोदय, नि:शुल्क दवाओं की बात मुख्य मंत्री जी लम्बे समय से कर रहे हैं। आपने कुल 824 दवाओं को नि:शुल्क कर रखा है। उनमें से 26 तो आपने पहले हटा दीं, 798 दवाएं आप दे रहे हैं। अभी राजस्थान में 18.02.2001 को आपने एक आदेश निकाला विभाग से, जिसमें आपने यह लिखा कि 268 दवाओं के लिए टेंडर्स नहीं होंगे। इन दवाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। वह क्यों लिखा और किनके टेंडर हुए यह आप

(श्री अशोक लाहोटी)

भी जरा ध्यान दें अधिकारीगण। केवल उन दवाओं के टैंडर हुए हैं जिनकी एम आर पी 1,500 रुपये लिखी हुई थी, लेकिन वे दवाएं बाजार में 500-600 रुपये में मिल रही हैं। उस घपले के लिए, उस भ्रष्टाचार के लिए टेंडर लगाये गये हैं।

268 वे दवाएं हटा दीं जो सस्ती मिल रही थीं, जिन पर कमीशन नहीं था तो पहले घोषणा क्यों हुई? 824 में से 798 दवाएं बचीं और 268 दवाओं के लिए लिखित आदेश निकाल दिया कि इनकी जरूरत ही नहीं है राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान में जब मरीज इलाज कराने जाता है तो उसे पर्ची दे दी जाती है कि दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, बाजार से ले आएं। सभापति महोदय, केवल टेंडर होने के 6-8 महीने के भीतर दवाएं चोरी हो जाती हैं। कितनी बार एस एम एस हास्पिटल में आग लगी? कितनी बार राजस्थान में आग लगी? क्या आज तक उसकी जांच हुई? एक मंत्री जी पहले थे, उनके समय भी मैंने कहा, जांच कराएं। जब भी कोई न कोई बड़ा मामला विधान सभा में उठता है या विधान सभा का सत्र शुरू होने वाला होता है तो इनके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल या एस एम एस हास्पिटल में आग लग जाती है और वे दस्तावेज जल जाते हैं।

10 करोड़ के मास्क कोविड में चोरी हुए थे। कहां गये वे मास्क? दिल्ली में पकड़े गये थे, चंडीगढ़ में पकड़े गये थे। उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? मंत्री जी, आप जवाब दें आज। कितनी बार राजस्थान में एस एम एस हास्पिटल सहित आपके डिपार्टमेंट में चोरियां हुईं उन चोरियों का क्या हुआ? कौन-कौन चोर पकड़े गये? कितनों पर कार्रवाई हुई? इस विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान में केवल और केवल एक भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बनाया है।

सभापति महोदय, अभी स्टेट कैंसर सेंटर की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। बहुत बड़ा सेंटर खुला। पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इनका बस नहीं चल रहा है। तीन दिन ओ पी डी वहां लगेगी और तीन दिन एस एम एस में लगेगी। इसका क्या कारण है? जब आपने करोड़ों रुपये की स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग बना दी, फिर भी तीन दिन तो ओ पी डी वहां लगेगी और तीन दिन एस एम एस हास्पिटल में लगेगी। क्यों? क्योंकि इनका अपने अधिकारियों पर, डाक्टरों पर, कर्मचारियों पर बस नहीं चलता। सोमवार को मरीज वहां आयेगा। यदि मंगलवार को चला गया तो एस एम एस जाओ। छुट्टी होगी तो दो दिन तक इन्तजार करो, क्योंकि आज ओ पी डी नहीं है, डाक्टर साहब नहीं आएंगे। यदि नहीं है तो आप चैक करवा लें। फिर क्या हुआ?

अभी एक बड़ा टेंडर हुआ। दुनिया में पहला टेंडर है। अभी इन्होंने एक लीनियर एक्सीलरेटर मशीन खरीदी 54 करोड़ रुपये में। 40 करोड़ रुपये केन्द्र

(श्री अशोक लाहोटी)

सरकार ने इनको भेजे। चलिये, आपने इसका कहीं प्रचार नहीं किया, कहीं नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इसमें 40 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के हैं या नहीं, यह बता दें। 40 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये। उसके बाद आपने टेंडर किये। तीन बार टेंडर हुए। दो बार रिजेक्ट हुए उसके कारण भी बताएं। दुनिया में पहला ऐसा टेंडर है, महंगी जमीन, महंगी जगह, महंगी मशीन, सब-कुछ सरकार का, केवल मशीन को चलाने के लिए जो एम्प्लायीज लगेंगे या जो एक -दो एक्सपर्ट्स लगेंगे, उनके लिए जो रेवेन्यू माडल बना है, वह 55 प्रतिशत कम्पनी को जायेगा और सब-कुछ देने के बाद भी केवल 45 प्रतिशत राजस्थान सरकार को मिलेगा। यह कौन-सा पी पी पी माडल है दुनिया का? पी पी पी में मेरी भी डाक्टरेट की हुई है। मेरी पीएच डी का सब्जेक्ट रहा है पी पी पी। ऐसा पी पी पी माडल मैं पहली बार देख रहा हूं, जिसमें रेवेन्यू का सरप्लस माडल प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है और लैस माडल राजस्थान गवर्नमेंट खुद रख रही है।

सभापति महोदय, सरकार सड़क का भी 10-20 लाख का टेंडर करती है तो उसमें 3-3 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, 10 साल की ओ एंड एम होती है। इसमें क्या हुआ? 3 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खतम करके केवल एक साल कर दिया और वह क्यों कर दिया? ताकि आपके इंस्टालेशन, कमीशनिंग और ट्रायल में ही एक साल निकल जायेगा। यदि नहीं हो तो आप आज शपथ पेश कर दें कि इस एक साल से पहले आप ट्रायल करके मशीन चालू कर देंगे। इस मशीन को लैंड करवाने, इंस्टालेशन करने, कमीशनिंग करने, ट्रायल करने में एक साल लग जायेगा। उसके बाद जब तक आपके यहां यह मशीन चालू होगी, तब तक उस कम्पनी की जिम्मेदारी खतम हो जायेगी। वाह रे संवेदनशील सरकार। सभापति महोदय, इनकी संवेदनशीलता किसके प्रति है, यह तय कर लें। डिपार्टमेंट के प्रति, अधिकारियों के प्रति, जनता के प्रति या कम्पनियों के प्रति?

सभापति महोदय, रोबोटिक मशीन की बड़ी-बड़ी बातें हुईं हम रोबोटिक सर्जरी पर जा रहे हैं। एक रोबोट खरीदा। जिस रोबोट की कीमत पूरी दुनिया में 16 करोड़ रुपये है, उसे इन्होंने 25 करोड़ रुपये में खरीदा। कुछ डाक्टर्स ने उस पर यह लिखा कि इस रोबोट की जरूरत ही नहीं है। रोबोट हमारे पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर रहा। फिर भी उसके 8-9 करोड़ रुपये इन्होंने ज्यादा दिये। वह कौन-सा लास्ट डाक्टर था, जिसने रिपोर्ट दी। बाकी सब डाक्टर्स ने नोटशीट पर

(श्री अशोक लाहोटी)

लिखा है कि यह रोबोट हमारे लिए काम का नहीं है। उस एक लास्ट डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 16 करोड़ का वह रोबोट आपने 9 करोड़ रुपये महंगा खरीदा। इसका क्या कारण रहा, वह भी आप जवाब दें।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा माडल की बात हुई, कोविड की बात हुई। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चलिये, पहले वाले मंत्री जी के समय हुआ होगा। भीलवाड़ा माडल की बात हुई। वे सब सी एम एच ओज कहां हैं, जो उस माडल में लगे हुए थे? वे सारे अधिकारी कहां गये जो उस माडल में लगे हुए थे? ऐसा क्या हुआ कि आपके मंत्री बनने के तीन महीने के अन्दर-अन्दर राजस्थान के सारे सी एम एच ओज बदल गये? वह एक विज्ञापन आता था न, "पूरे घर के बदल दूंगा"। आपने पूरे राजस्थान के सी एम एच ओज बदल दिये, पूरे राजस्थान के अधिकारी बदल दिये। उस पर से आप कह रहे हैं, हमारा कोविड माडल सक्सेसफुल था। या तो वह माडल सक्सेसफुल नहीं था या फिर दाल में कुछ न कुछ काला है। एक बदलते, दो बदलते, सारे ही बदल दिये? इतना द्वेष? मैं सोच रहा था, कांग्रेस में केवल दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, यहां तो गली-गली में झगड़ा चल रहा है।

सभापति महोदय, एक विषय मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, कोविड के टाइम में ब्लैक फंगस इंजेक्शन, आप राजस्थान के बराबर के सब स्टेट की तुलना करवा लें, राजस्थान ने 220 करोड़ रुपये की खरीद की थी और हमारे बराबर के सारे स्टेट्स ने कितने करोड़ रुपये के इंजेक्शन खरीदे हैं, यह आंकड़ा सामने आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीन-चार घंटे का टाइम है, फोन करवाकर ले लो। गुजरात का ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, हरियाणा का ले लो, पंजाब का ले लो। उत्तर प्रदेश तो हमसे चार गुना बड़ा है। 220 करोड़ रुपये के ब्लैक फंगस के इंजेक्शन खरीदे और हमारे बराबर के स्टेट ने कितने खरीदे? 600 करोड़ रुपये के रेमडेसिविर इंजेक्शन राजस्थान ने खरीदे। हमारे बराबर के सभी स्टेट में कोविड एक जैसा ही हुआ था, राजस्थान में तो अलग नहीं हुआ। बाकी स्टेट्स में कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गये, उसका भी डाटा आप मंगाओ, उसका डाटा भी आप यहां सदन में रखना। जब रेमडेसिविर बन्द करने की लास्ट गाइडलाइन आयी उस दिन कितना बड़ा टेंडर लगा, यह फिगर भी आप इसमें रखना। जब भारत सरकार ने, डब्ल्यू एच ओ ने गाइडलाइन दी कि अब रेमडेसिविर को बन्द किया जाए, उस दिन कितने का टेंडर आपके यहां पर लगा? उसकी भी जानकारी आप यहां सदन में उपलब्ध करायें।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, यह जो डिपार्टमेंट चलाने का तरीका है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ यह धोखा है और मैं जिम्मेदारी से यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिपार्टमेंट बेलगाम हो गया है। इसी सदन में सबसे पहली, सबसे बड़ी इस चिकित्सा विभाग की घोषणा हुई थी निरोगी राजस्थान के नाम से और उसके बाद जनता क्लिनिक की बात हुई। वह जनता क्लिनिक जनता से दूर है। कम से कम दस सवालों के जवाब में आ गया कि अब तक कितने खुले हैं। जोधपुर में 4 खुले हैं, माननीय सदस्या, आपके यहां पर केवल 4 खुले हैं और यह रिपोर्ट में आया हुआ है। जयपुर में 9 खुले हैं और वे भी केन्द्र सरकार के पैसे के हैं। पूरे राजस्थान में कितने खुले हैं? राजस्थान के 9 हजार के लगभग वार्ड हैं, 10 हजार पंचायतें हैं।

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज। बीच में नहीं बोलें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपके यहां खुल गया तो चुनाव में जनता जवाब मांग लेगी, इसकी चिन्ता मत करो आप। सभापति महोदय, यदि खुले हैं तो आंकड़ा दे दें। केन्द्र सरकार पैसे दे रही है फिर भी इनसे नहीं खुल रहे हैं। जनता क्लिनिक जनता से दूर हैं। हर गली-मोहल्ले में खुलना था, हर पंचायत में खुलना था, शहरों में हर वार्ड में खुलना था और अकेले जयपुर में 250 वार्ड हैं और केवल 9 खुले हैं।

सभापति महोदय, कहां गया वह निरोगी राजस्थान का जो संकल्प था? सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबन्ध कोष का गठन किया था, उसमें कितना खर्चा हुआ, यह मंत्री जी बताना। 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय की पहली घोषणा थी, 2022 में 18 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कालेज की घोषणा थी। वे क्यों नहीं खुल पा रहे? उनमें क्या घालमेल है, यह भी बताना। इसमें क्या मजबूरी है, यह भी बताना। सांगानेर, जयपुर में एक सेटेलाइट हास्पिटल की घोषणा की गयी थी पर आज तक वह कागजों में भी नहीं बना। यदि कागजों में बना हो तो कागज पेश करें। उसके बाद जब ट्रोमा सेंटर बनने वाला था, उस ट्रोमा सेंटर के साथ आपने यह कहा कि जयपुर में चारों दिशाओं में चार ट्रोमा सेंटर और खोले जाएंगे, वे कहां हैं चार ट्रोमा सेंटर? अगर जगह चिह्नित हो गयी तो वह भी बताना, उसका कोई नक्शा बन गया हो तो यहां टेबल करवाना, पेश करना। केवल और केवल इस सदन में घोषणा कर देना और वापस चले जाना। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह ऐसा विभाग नहीं है इस विभाग की

(श्री अशोक लाहोटी)

घोषणा प्रत्येक मानव जीवन से जुड़ी हुई है इस विभाग की घोषणा हर व्यक्ति की सेहत के साथ जुड़ी हुई है इस विभाग में इस प्रकार की असंवेदनशीलता, मैं समझता हूं कि राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय, एक हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा। जनता क्लिनिक तो खोल ही दिये आपने? फिर उसके बाद घोषणा हुई थी एक हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की। प्रदेश में 19 ब्लाकों में आयुष चिकित्सालय। कहां-कहां खुला, वह भी बताना। अगर खुले हैं तो यहां टेबल कराओ न कि इतने खुल गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में नहीं, प्लीज। इनको टोकिये मत, बोलने दें। बोलने दीजिये, आपका टर्न आएगा तब आप बोल देना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, ये जो माननीय सदस्या कह रही हैं कि खुल गयी, तो इनके नाम से ही टेबल कराओ, ताकि इनके यहां पर भी आये।

सभापति महोदय, राजस्थान में यह सब क्यों नहीं हो रहा क्योंकि आप राजस्थान का चिकित्सा का बजट देखो। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने इतना बजट बढ़ाया। बजट आपने बढ़ाया और लास्ट ईयर के बजट से आपने 2,500 करोड़ रुपये ज्यादा बढ़ाकर आपने कहा कि हमने बजट 18,038 करोड़ कर दिया। आपने हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर का बजट 18,038 करोड़ किया, लेकिन किसमें किया? लास्ट ईयर का आपका बी.ई. देखो, आपने 16,974 करोड़ रुपये बी.ई. में रखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपकी सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट का जो आप 15 हजार करोड़ ही खर्च कर पाये। उसके बाद आप कह रहे हो 18 हजार करोड़, यानी आपने 2,500 करोड़ रुपये केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो। आपने जो आर ई में 4,495 करोड़ किया था उसको आपने 450 करोड़ रुपये कम करके 4,026 करोड़ ही कर दिया। आप कह रहे हो कि हम तीन मेडिकल कालेज खोलेंगे, इतनी सब चीजें खोलेंगे और बजट आप कम कर रहे हो। यह राजस्थान में किसको बेवकूफ बना रहे हो, मंत्री महोदय? आप एक बार बजट के अधिकारियों से पूछो। उन्होंने आपके डिपार्टमेंट की नसबंदी कर दी। आपके डिपार्टमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना है, जिससे खरीद करनी है, मशीनें खरीदनी हैं, नये डवलपमेंट करने हैं, नये भवन बनाने हैं, नये चिकित्सालय बनाने हैं, नये कालेज

(श्री अशोक लाहोटी)

बनाने हैं, नये नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं, तीन-तीन मेडिकल कालेज बनाने हैं, उसमें आपका बजट 450 करोड़ रुपये कम करके 4 हजार करोड़ पर ले आये जो आपने आरई में 4,495 करोड़ रुपये रखा था। यानी आपने माना कि हमारा 2,500 करोड़ रुपये सैलरी, पेंशन पर तो बढ़ेगा पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने कम किया है। यह आपका हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर का पूरा बजट है। इसमें केवल हेल्थ का करोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चार मिनट में आप अपना कम्प्लीट करिये। फोर मिनट्स।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, अभी टाइम है। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, एक रिपोर्ट में भी आया है कि राजस्थान की सरकार सड़क और स्कूल, दोनों का कम्बाइंड आया है कि जितने बजट की इन्होंने घोषणा की, उसका इस मार्च तक केवल 16 प्रतिशत बजट खर्च कर पाये। केवल 16 प्रतिशत बजट आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं बात करूं तो आपने 44 हजार संविदाकर्मियों की बात की थी। मंत्री जी, आप जो कह रहे हो वह मुझे पता है, आप कहोगे कि यह ऐसी ही बातें हो रही हैं, तो आप इनको आंकड़ों सहित टेबल कर दें। 44 हजार संविदाकर्मियों को नियमित करने की बात थी और आपने यहां मुख्य मंत्री जी के मुंह से बुलवाया कि आप घोषणा करो। कैसे करोगे? वह ठेकाकर्मी 15 वर्षों से लगातार काम कर रहा हो, यह पहली शर्त लिखी है, दूसरी शर्त लिखी है कि उसकी सर्विस ब्रेक नहीं हो यानी वह ठेकाकर्मी बीच में कभी छोड़कर नहीं गया हो और तीसरा उसको डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हैड से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए वह दर-दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहा है। यानी आप उसको नियमित नहीं कर पाओगे, यह आपने पक्का मान लिया।

सभापति महोदय, ठीक ऐसे ही यदि राजस्थान में मिलावट की बात करूं तो आज राजस्थान का हाल क्या है? मुख्य मंत्री जी की फोटो लगायी और फोटो लगाकर आपने जो यह मिलावट का लिया, इस मिलावट में आपने 'शुद्ध के लिए युद्ध' चलाया, आपने 34,500 फूड सैम्पल लिये, कहां गये? पूरे देश में यह पहला विभाग है जहां फूड डिपार्टमेंट के पास यह लैब नहीं होकर मेडिकल के पास है और मेडिकल के अधिकारियों को फुर्सत नहीं है, टेम्परेरी चार्ज देते हैं 'शुद्ध के लिए युद्ध' का। घोषणा करते हैं, मुख्य मंत्री जी की फोटो लगाते हैं और फिर उसके साथ मजाक करते हैं। 34,525 फूड सैम्पल लिये पर

(श्री अशोक लाहोटी)

एक भी चालान आज तक कोर्ट में पेश नहीं किया। पिछले 11 साल में केवल दो चालान कोर्ट में पेश हुए हैं, उसमें हमारी सरकार भी आयी है, लेकिन यह राजस्थान की जनता के साथ डिपार्टमेंट मजाक बना रहा है। फिर क्या होता है कि जिस मिठाई का सैम्पल लेते हो, जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक वह सैम्पल बाजार से खतम हो जाता है। जिस दवा का सैम्पल लेते हैं, जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक उस बैच की सारी की सारी दवा बाजार में बिक जाती है। एक भी अपराधी को राजस्थान में नकली दवाओं के मामले में सज़ा हुई हो, एक भी अपराधी को राजस्थान में नकली फूड के मामले में सज़ा हुई हो तो आप एफिडेविट के साथ, मंत्री जी, पेश कर दें या उसका नाम-पता सहित पेश कर दें कि इसको हमने सज़ा दी है। सभापति महोदय, आज हालात क्या हैं? राजस्थान के हालात अगर देखो तो आज मैं मांग करता हूं.....

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, जब रिप्लाई हो तब मौजूद रहना, आप चले जाते हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल रहूंगा, मैं जा थोड़े ही रहा हूं, यहीं पर रहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें। टाइम हो गया। एक मिनट में कर दें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, ऐसे आप बार-बार क्यों कहते हो, या तो आप कह दो कि मैं बैठ ही जाऊं, यह क्या बात हुई, साहब? ये दस-दस मिनट ज्यादा बोलते हैं न। ऐसे मत करो, सभापति महोदय। ऐसे मत करो।

श्री सभापति: दो मिनट में कर दीजिये आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यदि दो मिनट ऊपर नीचे हो गया तो ऐसे आप सैकण्ड सहित काउंट कर रहे हो तो फिर सबका हम भी करेंगे काउंट। ऐसे नहीं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप अपनी बात बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजस्थान में आपका सबसे बड़ा कैडर नर्सिंग का था, आज जो नर्सिंग ट्यूटर हैं उनको राजपत्रित अधिकारी बनाने में क्या दिक्कत है? उनको मान-सम्मान देने में कहां दिक्कत है? राजस्थान के जो नर्सिंग ट्यूटर हैं, 35

(श्री अशोक लाहोटी)

अन्य विभागों में समान पे के लोगों को आपने राजपत्रित अधिकारी बना दिया तो फिर इन नर्सिंग वालों ने आपके साथ क्या गुनाह किया है? क्या ये राजस्थान के मतदाता नहीं हैं? क्या ये राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं? मैं मांग करता हूं कि इनको भी राजपत्रित अधिकारी बनाया जाये।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है और मैं मंत्री जी से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, मंत्री जी, ऐसी कौनसी वो अदृश्य शक्तियां हैं जिनके कारण से आप परेशानी में हो? आप जब मंत्री बने थे तब तो राजस्थान में बड़ी चर्चा थी कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का कितना साफ-सुथरा कलर है। आपका कलर तो दिन-प्रतिदिन काला होता जा रहा है और सदन में चर्चा है कि यहां एक मंत्री जी जयपुर वाले हैं, प्रताप जी आज नहीं आये हैं, वे दिन-प्रतिदिन गोरे होते जा रहे हैं। यह स्वास्थ्य विभाग का क्या चक्कर है? इसकी भी अधिकारियों से जांच करवाकर बतायें। एक मंत्री काले हो रहे हैं और एक मंत्री गोरे हो रहे हैं। यह क्या चक्कर है?

(समय: 13.00 बजे)

स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कौन-सी अदृश्य शक्तियां हैं, जो वहां कुर्सी पर बैठकर सारे राजस्थान के अधिकारियों को निर्देश देती हैं। वे किस हैसियत से वहां पर बैठते हैं? कौन हैं वे लोग? इसकी जांच करके कौन सदन को बतायेगा? जो राजस्थान के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, वे कौन से राजपत्रित अधिकारी हैं? मंत्री महोदय, यह भी राजस्थान की जनता को बताना। मैं जवाब के समय यहीं रहूंगा। यह बात भी जवाब में बताना कि वहां स्वास्थ्य विभाग में कौन बैठते हैं?

श्री सभापति: थैंक यू, वैरी मच, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मंत्रीजी, डब्ल्यू एच ओ के एस डी जी होते हैं, जिसमें लिविंग स्टैण्डर्ड से लेकर नो पावर्टी और जीरो हंगर से लेकर लिविंग स्टैण्डर्ड तक के सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें राजस्थान कहां खड़ा है? एक बार इसको भी देख लेना। राजस्थान का एक और आंकड़ा है, राजस्थान में 6 लाख बच्चे कम जन्मे, इसमें आप क्या करोगे, लेकिन 5 लाख मौतें राजस्थान में बढ़ी हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? यह आपके विभाग की जिम्मेदारी है। यह भारत सरकार के सीआरएस-2020 की रिपोर्ट है, 2021-22 की बाकी है। सीआरएस की रिपोर्ट में राजस्थान में नवजात बच्चों की 5 लाख मौतें बढ़ी हैं। वह क्यों बढ़ी हैं? इसकी भी जांच करायें। एसडीजी में राजस्थान,

(श्री अशोक लाहोटी)

जहां देश का एवरेज 6.6 है, वहीं राजस्थान 3 से भी नीचे है, उसकी भी जांच करायें। तब हम इन पैरामीटर्स पर पूरा आयेंगे।

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी आज इन सब चीजों का जरूर जवाब देंगे।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह जी।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): आनरेबल सभापति महोदय, हेल्थ पर आज चर्चा हो रही है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, doctor is a half-god half-pagan लेकिन मेरी सभी आधुनिक डाक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए जो शब्द कहे हैं, वे उनकी अनुपालना करें।

सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटी के फील्ड में, I am alone doctor in this House और मेरा अपना पचास साल का तजुर्बा है। मैंने 1964 में एस एम एस मेडिकल कालेज जोइन किया था। उस समय डा. फारूक अब्दुल्ला फाइनल ईयर में थे जो कश्मीर के सी एम बने, केन्द्र में मिनिस्टर बने। एस एम एस अपने आप में कंट्री का, डब्ल्यू एच ओ का आइडेंटिफाइड हास्पिटल है। राजस्थान में करीब 725 सी एच सीज हैं, पी एच सी 2,500 हैं, more than 15,000 sub-centers, 30 मेडिकल कालेज बन रहे हैं, तीन का अभी प्रोसेस चल रहा है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर जिला हैड क्वार्टर पर एक मेडिकल कालेज एसेंशियल है। माननीय, 400 बेडेड हास्पिटल होना चाहिए। आपके स्वयं के झुंझुनूं में भी बन रहे हैं तो 400 बेडेड हास्पिटल जब बन जायेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सारी स्पेशलिटीज उन मेडिकल कालेज, हास्पिटल में आ जायेंगी। निश्चित रूप से, जिला लेवल पर, मैं नहीं समझता हूं कि भारत के किसी भी राज्य के अन्दर हर जिले में मेडिकल कालेज बने हैं, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक बहुत डवलप्ड हैं, वहां भी हर जिले में मेडिकल कालेजेज नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना का जिक्र बार-बार आयेगा। कोरोना जब पूरे देश में फैला तो अकल्पनीय था। जब हिरोशिमा पर 1945 में अमेरिकी पायलट ने परमाणु बम डाला और डालने के बाद जब वह सैकण्ड राउण्ड ले रहा था हिरोशिमा के ऊपर, तो उसने नीचे का नजारा देखा 70

(श्री जितेन्द्र सिंह)

परसेंट हिरोशिमा जमींदोज हो गया था। उस वक्त अमेरिकी पायलट ने एकदम स्टंड होकर कहा 'Oh God' what mistake I have done and he turned permanently in mental case. लेकिन परमाणु बम की तरह, कोरोना बुहान, चाइना से आया। पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। अकेले स्पेनिश फ्लू, 100 साल पहले आया था, 5 करोड़ लोग मरे थे।

सभापति महोदय, developed countries like United States मेरे दामाद यू एन ओ में सैक्रेटरी हैं। वे बता रहे थे, कोरोना से 65 लाख लोग अमेरिका और यूरोप में मर गये। भारत में करीब 4 लाख मौतें हुईं, राजस्थान में 7 हजार हुईं। John F. Kennedy की पोती कोरोना से मर गई। जिस तरह का मैनेजमेंट राजस्थान में हुआ, वह अपने आप में अद्वितीय है। आज राजस्थान में 95 परसेंट वैक्सीनेटेड हैं, हमारी मोर्टेलिटी का..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता, पर यह विधान सभा इन विधायक की ट्यूटोरियल क्लास बन गई है क्या? दर्शक दीघा में अधिकारियों को प्रताड़ित कीजिए। इनको इतना ही डेटा देना है, इतना ही पढ़ाना है, यह कोई तरीका है। यह विधान सभा का अपमान नहीं है? मैं देख रहा हूं आफिसर दीर्घा में बैठे हुए अधिकारी लगातार एम एल ए को बुला-बुलाकर आंकड़े दे रहे हैं। बात करनी है तो बाहर जाकर बात करिये। यह विधान सभा है, यह घर की बात नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना फैला। सभापति महोदय, राजस्थान में जो मैनेजमेंट हुआ, अपने आप में अद्वितीय था। सभापति महोदय, मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला था। जब मैं 1998 में मंत्री था। मैं म्यूनिख मेडिकल यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, देख रहा था तो मैं उनकी पैथोलोजिकल लैब के सामने से निकला तो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, 'Department of Charakology', मैं रुका और जो जर्मन लेडी थी उससे कहा, it should be corrected. It should not be the department of 'charakology'; it should be the department of 'serology'. वह हंसने लगी और उसने कहा, well Sir, Charak was a great physician of India and in an honor of 'Charak', we have named the department as department of 'Charakology'. मैं धन्यवाद दूंगा कि अब चरक भवन, धनवन्तरी भवन एस एम एस में बनने लग गये। उनसे कम से कम कुछ सीख रहे हैं।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनी, that should be appreciated. सभापति महोदय, पूरे भारत या विश्व में ही नहीं, अमेरिका जैसे कंट्री में एक बाईपास सर्जरी का 40 से 50 लाख रुपया लगता है। एस एम एस हास्पिटल में 65 हजार में बाईपास सर्जरी होती है। हमें पता है, 1993 में हम लोग रिक्वेस्ट किया करते थे चीफ मिनिस्टर साहब को कि हमारे एक वॉल्व लगेगा, साहब 10 हजार रुपये दीजिए। वॉल्व दो भी लगते हैं, उसके 20 हजार रुपये दीजिए, ये परिस्थितियां थीं।

ओबामा हेल्थ स्कीम यू एस ए में फेल हो गई, लेकिन जिस तरह से मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना बनाई, वह निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कोरोना बड़ा शाकिंग था। आज भी आप्टिकल हल्लुसिनेशन होता है, दृष्टि भ्रम होता है। हमारे चार साथी मास्टर भंवरलाल जी, गजेन्द्र सिंह जी शक्तावत साहब, किरण माहेश्वरी जी, कैलाश त्रिवेदी जी, वे नहीं रहे। मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा। सम्भवत: हमारे पोलिटिक्स में 1947 के बाद पहला ऐसा मुख्य मंत्री होगा, जिसने अपनों की चिरस्थाई याद बनाने के लिए वहां गर्ल्स कालेजेज का नाम एम एल एज के नाम पर किया। मैं धन्यवाद दूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने एम एल एज का नाम अमर करने के लिए किया। माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना फैला तो अलग से आर यू एच एस में 1000 बेड शिफ्ट किये गये।

सभापति महोदय, अब मैं एस एम एस हास्पिटल की बात पर आऊंगा। एस एम एस हास्पिटल में एशिया का सबसे ज्यादा आउटडोर है। 10 हजार आउटडोर पेशेंट वहां पर आते हैं और एट ए टाइम पचास हजार लोग उस कैम्पस में रहते हैं। मैं समझता हूं इंडिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है उनके पास और जिस तरह से एस एम एस हास्पिटल मैनेज हो रहा है उसमें बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं। मैं अलग-अलग डिपार्टमेंटवाइज आपसे बात करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हार्ट के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे करीब बारह हजार एंजियोग्राफी होती है और 6 हजार एंजियोप्लास्टी होती है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की पहली सीटी एंजियोग्राफी की थी वह डा. जगत नरूला जयपुर के थे, जिन्होंने वर्ल्ड की पहली सीटी एंजियोग्राफी की थी। आप कल्पना कर सकते हैं एमिनेन्ट डाक्टर्स

(श्री जितेन्द्र सिंह)

दिये हैं एस एम एस हास्पिटल में जिसने फर्स्ट बाईपास सर्जरी की इंडिया के अन्दर वे मण्डावा के डा. गिरधारी शर्मा थे। डा. बी.के. गोयल थे साम्भर के जो बोम्बे के मेयर रहे, डा. एस.आर. मेहता, डा. जी. नरेनन, डा. पी.के. सेठी। डा. पी.के. सेठी, आज भी अमेरिका में स्टील फुट है और मेरा सौभाग्य है कि मैं ओर्थोपेडिक्स में उनकी टीम का सदस्य था जिन्होंने रबर फुट बनाया, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला।

आज एस एम एस की ओर्थोपेडिक्स विंग वर्ल्ड की रिकग्नाइज्ड विंग्स में से है। डा. मेहता खुद यू एस ए के अन्दर बैठते हैं। अदर कंट्रीज को जयपुर फुट इराक, वियतनाम जहां एक्सीडेंट में बच्चे ब्लो कर देते हैं, फौजी ब्लो कर देते हैं, जयपुर फुट उनके लगता है।

सभापति महोदय, बहुत जवान-जवान लोग चले गये हार्ट अटैक से। डोसाइल हैबिट्स, हमारे न्यूरोलॉजी के एस एम एस के हैड आफ डिपार्टमेंट खुद ट्रेड मिल पर दौड़ते-दौड़ते कोलैप्स हो गये। What are the reasons of cancer and heart diseases? This is a docile habit and day-to-day हमारी हैबिट्स हैं और आवश्यकता है कि इन डे टू डे हैबिट्स को हम ठीक करें। मैं तो राय दूंगा, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं कि जो साठ साल का व्यक्ति है, उसकी सीटी एंजिग्राफी करना आप मेंडेटरी करें। यह इंश्योरेंस वालों को बोलें। पचास साल से ऊपर स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं। हमारे हार्ट की कोरोनरी वैसल्स के अन्दर फैट डिपोजिट हो रहा है तो यह मेंडेटरी करें। उन्होंने सब्जैक्ट में एक लिस्ट बना रखी है कि यह ई सी जी होनी चाहिए, यह यूरीन की होनी चाहिए, यह किडनी जांच होनी चाहिए, but why not heart? हार्ट एंजियोग्राफी को दुबारा से मैं आपसे कहना चाहूंगा, सीटी एंजियोग्राफी, यह जो हम कैमिकल इंजेक्ट करके जो एंजियोग्राफी करते हैं वह नहीं होती, CT angiography is an x-ray (CT x-ray), उसको मेंडेटरी करें। कम से कम उसको पता लग जायेगा कि 90 प्रतिशत ब्लाक है, जान बच जायेगी। मैं नहीं जानता क्यों इन लोगों ने नहीं कर रखा। CT angiography is essential. मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। मैंने खुद ने दो बार कराया हुआ है सीटी एंजियोग्राफी और आप लोगों से भी आग्रह है आप लोगों पर बर्डन है, whole of the Rajasthan is sitting here and हर एक विधान सभा क्षेत्र में आप रिप्रजेंट कर रहे हैं 8 करोड़ लोगों को, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है to all the legislators कि सीटी एंजियोग्राफी आप सब लोगों

(श्री जितेन्द्र सिंह)

को करानी चाहिये। पता लग जायेगा कि यह ब्लाक है 90 परसेंट। मैं डरा नहीं रहा हूं, I am just saying that it is a must, it should be done. डा. करण सिंह यादव, he is an eminent personality.

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गरीब इलाका है। बाहर से डा. त्रेहन को बुला-बुला कर उनको कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है आप सिखाओ हमारे डाक्टर्स को, हम तो आपको अच्छे होटल में रोक सकते हैं, हमारे पास देने को पैसा नहीं है। डा. त्रेहन आये and he developed a team of cardiothoracic surgeons और आज, सभापति महोदय, कार्डियो थोरोसिक सर्जरी में बहुत बड़ी संख्या में हमारी बाईपास सर्जरीज हो रही हैं।

सभापति महोदय, आज जिस एस एम एस हास्पिटल में शुरुआत हुई थी उसमें हार्ट के ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट छोटी बात नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। डा. क्रिश्चन बर्नार्ड ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था साउथ अफ्रीका में, दो दिन में मर गया वह और हमारे जो हार्ट ट्रांसप्लांट किये हुए हैं हमारे हास्पिटल में और डा स्वर्णकार को मैं एप्रिशियेट करूंगा, but I shouldn't name पर्टिकुलर मेडिकल कालेज को, लेकिन उन्होंने जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया दो-दो साल तक जिन्दा हैं तो हमारे इंडियन डाक्टर्स के पास उनकी कैपेसिटी है यह काम करने की बशर्ते कि उनको मौके मिले।

सभापति महोदय, मैं एस एम एस मेडिकल कालेज के हमारे नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगा। पूरे भारत में हमको करीब दो लाख बीस हजार लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है एवरी ईयर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं साढ़े सात हजार पूरे इंडिया में और हमारे 1997 से अभी तक 550 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं एस एम एस के अन्दर। उसका रीजन है डोनर नहीं है, लोगों में अवेकनिंग नहीं है कि वे अपने, जिनकी ब्रेन डैथ हो जाये वो डोनेट कर दें। सब डरते हैं कि इसकी चीर-फाड़ हो जायेगी। हमारे वहां खेतड़ी की महिला अध्यक्ष हैं, उसके भाई को जरूरत थी किडनी की। वह खुद 45-50 साल की थी, उसने खुद अपनी किडनी डोनेट की। हमारे शहर अध्यक्ष हैं कुमावत, वे खुद 55 साल के हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए खुद की किडनी दी। हमें आवश्यकता है कि जो हमारे कैडेवर डोनर, हमारे जो आने वाले लोग जिनकी डैथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उनको जागरूकता के लिए कुछ पर्क्स देना पड़ेगा। समझाना बहुत मुश्किल होता है सभापति महोदय, आप जानते हैं अमेरिका के अन्दर डोनर हैं 24 परसेंट तक और हमारे यहां डोनर हैं 2 परसेंट। स्पेन में नम्बर 2 आता है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

और उन डोनर्स को सबको डर लगता रहता है कि हमारे यह खतम भी हो गया और इसकी बॉडी को खराब कर देंगे, लेकिन अगर किसी की ब्रेन डैथ हो गयी तो अवेकनिंग करनी पड़ेगी, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, जो मर्जी आये गोली खा लेते हैं। मैं गया हमारे रोजड़ा गांव में, वहां 24 साल के लड़के की डैथ हो गयी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? तो बताया कि डाक्टर साहब, इसके घुटनों में दर्द रहता था और यह हरी पत्ती की गोली खा रहा था। सभापति महोदय, एक कोमन मेन को जानना चाहिये कि सिर दर्द की और पांव दर्द की गोली मर्जी आये जब ले ली, ये सीधी जाकर किडनी को खराब करती है। सिरम क्रेटिनिन लेवल और यूरिया बढ़ता है और किडनी किसी भी वक्त फेल हो सकती है तो इसलिये भगवान के लिए यह दर्द की गोली कि आज सिर दुख रहा है तो ले लो इसको, यह बहुत सावधानी से लें। It will damage your kidney. You should be aware of this thing. हमारे यहां की बहुत शानदार टीम है एस एम एस हास्पिटल की। हमारे किडनी डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी बहुत बेहतरीन टीम है and they are doing very good work. हमारे फ्री है डायलिसिस वगैरह, सारा बहुत शानदार हो रहा है उनके।

सभापति महोदय, हमारे जो सबसे बड़ा तीसरा रीजन है वह है सेरेब्रल स्ट्रोक, जिसको लकवा बोलते हैं। हमारे नितान्त आवश्यकता है पेशेंट बेड पर सारी जिन्दगी सड़ जाता है। चार घंटे तक, यह मैंने मंगाया था हमारा मेडिकल कालेज का लड़का है पी जी आई चंडीगढ़ में। हमारा थ्रोम्बोसिस है, साढ़े चार घंटे का वेल्युएबल वक्त मिलता है अगर किसी के लकवा हो गया तो। उसको इमीजिएटली अवेकनिंग करानी है कि साढ़े चार घंटे में लपको, पर साढ़े चार घंटे में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वे उसके ब्रेन में थ्रोम्बो खून पतला करने की दवा दे देंगे तो वह खुल जायेगा और उसके लकवा नहीं होगा और अगर हो गया तो उनको चार दिन मिलते हैं थ्रोम्बेक्टामी के लिए तो मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मंत्री महोदय से कि इंटरवेंशनल लैब सेरेब्रल स्ट्रोक के लिए एस एम एस में स्थापित करें। यह नितान्त आवश्यकता है। हमारा जो एस एम एस मेडिकल कालेज का न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट है, यह भी कंट्री में सबसे बड़े डिपार्टमेंट में से एक है तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है अलग से कि हमारा स्ट्रोक इंटरवेंशनल लैब स्थापित करें। सारी जिन्दगी, सभापति महोदय, लकवे वाले, आप तो स्वयं विधायक हैं वहां के और आप देखते हैं कि एक न एक बुजुर्गवार पड़ा मिलेगा खाट के ऊपर।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा, diabetes is a mother of every disease. 6.5 परसेंट जनरल पापुलेशन में डायबिटिक्स हैं और यह आवश्यकता है कि उनका समय के ऊपर उपचार हो। बच्चों में है, सभापति महोदय, जुवेनाइल डायबिटिज, बच्चों में हो रही है डायबिटीज।

मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एस एम एस मेडिकल कालेज की जो Endocrine Lab है, मंत्री महोदय, इंडिया की सबसे बड़ी Endocrine Lab हमारे एस एम एस हास्पिटल की है। उन्होंने अलग से जायका से, जापान से डिमांड की है, उनको और डवलपमेंट के लिये पैसा चाहिये। मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है कि आप उसमें उनकी मदद करें, उसमें यह नितांत आवश्यक है।

सभापति महोदय, काज आफ डैथ में कैंसर सबसे ज्यादा फैटल डिजीज है। एस एम एस की कैंसर की बहुत शानदार यूनिट है। Dr. Jasuja is doing very good! उन्होंने कैंसर के लिये अलग से यूनिट बना रखी है। सभापति महोदय, कैंसर आज इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, हमारे बीकानेर में तो खुद राजा गंगासिंह जी, he had malignancy. उन्होंने उस वक्त जर्मनी से अलग से रेडियो डाइग्नोसिस की लैब मंगवाई थी। आज गंगानगर से पूरी की पूरी कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन आती है। The cause of cancer is pesticides. वहां डे-टू-डे लाइफ में जितनी बड़ी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, सभापति महोदय, मेरे रूम मेट का भाई था, वह महाराजा कालेज में था, हम मेडिकल में थे। उसने कहा भाई बीमार हो रहा है। हम उसे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर पहुंचे। उसने एक्स-रे किया, एक्स-रे करके मुझे बुलाकर कहा कि जितेन्द्र, I am very sorry to say कि इस लड़के के तो लंग्स कैंसर है। मैंने कहा साहब, यह तो 19 साल का लड़का है। वह बोले, यह बहुत तगड़ा स्मोकर है। मैंने कहा कि इसने जिंदगी में एक सिगरेट नहीं पी। हमारे कुलश्रेष्ठ का भाई था, मैंने उससे पूछा कि तू चुपचाप सिगरेट तो नहीं पीता था? उसने कहा नहीं भाईसाहब, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, परंतु मेरा रूम पार्टनर रोज चार बंडल केवंडर के पी जाता था। सभापति महोदय, जो चार-चार सिगरेट के बंडल पी रहा था, वह तो आज तक जिंदा है और वह 19 साल का डाक्टर कुलश्रेष्ठ का भाई मर गया। इसलिए जगह-जगह लिखा रहता है कि यह स्मोकर जोन है, आप यहीं पर पीजिए, बाहर मत पीजिए नहीं तो दूसरों को दंड मिलेगा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने स्मोक फ्री राजस्थान की पहल की है।

सभापति महोदय, यहां के respiratory department में उनको अलग

(श्री जितेन्द्र सिंह)

से आवश्यकता है, वहां उनकी बहुत शानदार टीम है। उनके रहने के हॉस्टल नहीं हैं, टीबी हास्पिटल की छतें चू रही हैं। मेरा आग्रह है कि उनको अलग से बजट दिलवायें। माननीय मंत्री महोदय, जरा गौर करें, टीबी हास्पिटल में सीटी स्कैन नहीं है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको एस एम एस में भेजना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे इमरजेंसी में आपने सीटी स्केन बना रखा है, टीबी हास्पिटल में भी सीटी स्केन की और 2D ईको की सुविधा होनी चाहिये, क्योंकि स्मोकिंग हार्ट को भी डेमेज करता है, इन दोनों की आवश्यकता है। इसके लिये उन लोगों ने मुझसे आग्रह किया है।

सभापति महोदय, आर्थोपेडिक्स में एस एम एस हास्पिटल का वर्ल्ड में नाम है। मेरा सौभाग्य था अमेरिका में डाक्टर पी के सेठी हमारे टाइम में थे। जैसा मैंने पहले कहा स्टील फुट आता है, उन्होंने रबर फुट बनाया। मैं उनकी टीम में था और आज अमेरिका में भी यहां के डाक्टर मेहता बैठे हैं, वे देख रहे हैं कि रबर फुट किस तरह से बने। आर्थोपेडिक्स में बहुत शानदार तरीके से नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा काम आर्थोपेडिक में हो रहा है।

सभापति महोदय, चाइल्ड हास्पिटल में जे के लोन भी इंडिया का सबसे बड़ा बच्चों का हास्पिटल है, 1000 का आउटडोर है। सभापति महोदय, बच्चों में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनके pediatric cardiac surgeon नहीं हैं। छोटे बच्चे, दो साल के बच्चों के हार्ट में छेद हो जाता है, 'patent ductus arteriosus' उसको बोलते हैं, उनका कोई यहां सर्जन नहीं है। उनको बाहर भेजना पड़ता है। सभापति महोदय, हमारे बच्चों के हास्पिटल में अलग से pediatric cardiac surgeon होना चाहिये।

सभापति महोदय, मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है, सारे घर के लिये अभिशाप होता है। मैं एक दिन देखने गया, हमारे परिचित थे, उनका बच्चा मंदबुद्धि था, मैंने कहा कि आपका बच्चा कहां गया? उन्होंने कहा कि उसको हमने हरिद्वार आश्रम में डाल दिया। मैं बड़ा सिहर उठा कि अपने बेटे को वहां भेज दिया। सभापति महोदय, जब पेट में 6 वीक का बच्चा होता है तो para-centesis करके उसका amniotic fluid निकालकर जांच की जा सकती है कि बच्चा मंदबुद्धि है या नहीं है। उस समय मां का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, महिलाओं में सबसे बड़ा कैंसर सर्विक्स होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है और महिलाएं शर्म से बताती नहीं हैं। अभी आवश्यकता है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कि जो हमारे सब सेंटर पर ए एन एम, जी एन एम हैं, वे उनको जागरूक करें। कैंसर में जब डाक्टर के पास पहुंचते हैं तो वह हैंड्सअप कर देते हैं कि यह तो थर्ड स्टेज में आ गया, हम क्या करें? माननीय मंत्री जी बैठी थीं, उन्होंने उड़ान योजना शुरू की है, बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। सर्विक्स कैंसर के पेशेंट्स पर कंट्रोल होगा। ब्रेस्ट कैंसर में जरा सी भी गांठ होती है तो ए एन एम, जी एन एम बता देंगी कि तुरंत जांच कराओ। अभी एक पेशेंट थी, जांच की, malignant निकला, तुरंत आपरेट कराया इसको। इसलिए हमारे ए एन एम, जी एन एम को चाहिये कि वह उनको जागरूक करें।

सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना में 10 से 25 लाख रुपये कर दिया। मेरे अभी भी समझ में नहीं आता, सभापति महोदय, आपके सामने भी प्रोब्लम आ रही होगी। मेरे पास एक पेशेंट आया, डाक्टर साहब, बच्चे के 50 लाख खर्च हो गये। मैंने कहा किस में हो गये? साहब, मैं उसको गवर्नमेंट हास्पिटल में कहां ले जाऊं, प्राइवेट हास्पिटल में ले गया। प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग जा रहे हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपको बताने का रीजन है कि इन प्राइवेट हास्पिटल में डाक्टरों के सामने समस्या हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बच्चे जा रहे हैं। हमारे इतने सीनियर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ, सर्जरी के केसेज मिलना कम हो गये, क्योंकि सब प्राइवेट हास्पिटल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, उनका भरोसा है, विश्वास है। इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना के प्रचार के लिये पंचायती राज से शुरू करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि चिरंजीवी योजना कलेक्टर देख लेंगे। हरेक बीमार की कलेक्टर से बात करने की हिम्मत नहीं है। हमारी आवश्यकता है कि चिरंजीवी योजना का, पंचायत समिति से हमारे सरपंच लेवल पर उसका प्रचार करें, पंचायत समिति प्रचार करे, ए एन एम, जी एन एम उनका प्रचार करें, तब जाकर लोग चिरंजीवी योजना समझेंगे, इसमें अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप 25-25 लाख रुपया दे रहे हो और लोगों को अभी भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में अवेकनिंग की और आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बहुत लंबी बात नहीं करनी है। अंत में मैं हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा। आर यू एच एस हमारे कंट्री की बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। सभापति महोदय, वहां अभी उन्होंने 1,800 डाक्टर और नर्सेज को भर्ती किया है और हमारे सभी डिपार्टमेंट को

(श्री जितेन्द्र सिंह)
चालू किया है। सभापति महोदय, कोरोना का आफ्टर इफेक्ट यह हो रहा है, एस एम एस का एक गार्ड कुर्सी पर बैठा-बैठा नीचे गिर गया। सडन कार्डियेक अरेस्ट हो गया, कोरोना हुआ था। Respiratory distress हो रहा है, bronchopneumonia - COPD सांस के बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है। इस तरह के रोग पोस्ट कोरोना हो रहे हैं। सभापति महोदय, मेंटल केस हो गये। हमारे आर यू एच एस में कोरोना के आफ्टर इफेक्ट पेशेंट के लिये अलग से यूनिट बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डाक्टर सुधीर भंडारी, he is doing well! जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया था, पोस्ट कोरोना के पेशेंट को जिस तरह से वह मैनेज कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो किया है वह अद्वितीय है। अंत में 'Nostradamus' की भविष्यवाणी बताना चाहूंगा- I am seeing the Earth like a fireball. There will be III World War! Whether it may be a nuclear war or bacterial war! But, when the situation will appear in the World, a man with blue turban will take birth in Central Asia, probably in India and he will restore the peace in the World. उन्होंने तो सारी बात कही, लेकिन मैं मेरे तरीके से बोल रहा हूं। निश्चित रूप से नास्त्रेदमस ने कहा था, a man with a blue turban will come; I don't know whether a blue turban man will come or not, but a man with white Kurta and trouser with a black jacket, he will emerge and he will restore good health in the Rajasthan, none other than Shri Ashok Gehlot. Thank you!

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर चिकित्सा के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। माननीय सभापति महोदय, सोजत उप जिला चिकित्सालय में सोजत शहर सहित आसपास के दर्जनों गांववासी इलाज के इस अस्पताल में आते हैं। गम्भीर रोगी जब इस

(श्रीमती शोभा चौहान)

अस्पताल में आते हैं तो आवश्यक चिकित्सा संसाधनों एवं विशेषज्ञों के अभाव में मरीज को रैफर कर दिया जाता है। मेरे द्वारा सदन में बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी दो वर्ष पूर्व सोजत उप जिला चिकित्सालय में सरकार द्वारा ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह महज घोषणा मात्र ही रह गयी है। हाल ही में पाली जिले के प्रभारी मंत्री जी द्वारा भवन का शिलान्यास किया गया, लेकिन उस दिन के बाद एक भी पत्थर नहीं लगा है। सम्पूर्ण सोजतवासियों का यह इन्तजार कब खतम होगा, भगवान ही जाने। ट्रोमा सेन्टर निर्माण को क्या ग्रहण लग गया कि आज तक इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पाया है। महोदय, सोजत उप जिला चिकित्सालय का लगभग एक हजार से अधिक का आउटडोर है। समय की आवश्यकता के अनुसार इस उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया जाये तो आमजन को इलाज में काफी सुविधा मिल सकेगी।

अस्पताल की वर्तमान स्थिति की बात करें तो विगत सात-आठ साल से ई एन टी, नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर के पद रिक्त हैं। सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध है, लेकिन विशेषज्ञ नहीं होने के कारण मशीन धूल फांक रही है। मजबूरन मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर अपनी जेब कटवानी पड़ती है। इस अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 5 से 6 डिलीवरी होती हैं, लेकिन महिला गायनिक डाक्टर का टोटा ही है। अस्पताल आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं बिल्डिंग मरम्मत सहित एक करोड़ से अधिक का प्रस्ताव डी एम एफ टी फंड से स्वीकृति हेतु जिला प्रशासन को भिजवाया गया है, लेकिन इस अस्पताल को कुछ भी राहत नहीं मिल सकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से अनुरोध करती हूं कि ट्रोमा सेन्टर को राजनीति की भेंट न चढ़ाएं, शीघ्र ही भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये। साथ ही, आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर की भी नियुक्ति कराये जाने के आदेश जारी करें।

इसी तरह सोजत रोड सामुदायिक चिकित्सालय में हाल ही में एक डाक्टर की सेवानिवृत्ति के बाद कोई नये डाक्टर को पदस्थापित नहीं किया गया है। मगरा क्षेत्र से जुड़े इस अस्पताल में मरीजों का भारी जमावड़ा रहता है, लेकिन डाक्टर के अभाव में समय पर चिकित्सा नहीं मिल पा रही है।

महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायपुर, कुशालपुरा, देवलीकलां,

(श्रीमती शोभा चौहान)

पीपलिया कलां, सोजत रोड, बगड़ीनगर, चण्डावल नगर सी एच सी में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये, ताकि आमजन को इलाज के लिए स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा मिल सके। मगरा क्षेत्र से जुड़े रायपुर व बगड़ीनगर सामुदायिक चिकित्सालय को 30 रोगी शय्या से बढ़ाकर 75 में क्रमोन्नत किये जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रायपुर सामुदायिक चिकित्सालय में महिला गायनिक चिकित्सक की विगत कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। इससे मगरा व मैदानी क्षेत्र की महिलाओं को ब्यावर व सोजत जाना पड़ता है। कभी-कभी गम्भीर स्थिति होने पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। महिलाओं को जीवन-मरण की स्थिति से उबारने के लिए यहां महिला गायनिक चिकित्सक की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है।

महोदय जी, मेरी उक्त बातों पर सरकार द्वारा गंभीरता पूर्वक चिन्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से सोजत शहर की चिकित्सा के क्षेत्र में तस्वीर बदल जायेगी और आम नागरिकों को सरकारी खर्च पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। एक बार मैं पुन: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जितने डाक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरा जाये, ताकि जनता को राहत मिल सके। 2023-24 के बजट में जयपुर विकास प्राधिकरण की राजस्थान विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना, धावास, अजमेर रोड जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): एक सैकण्ड। आप इसमें हैमरेज और लकवे का भी जरूर रखें। सरकार इसका एक अभियान चलाये। बी पी के कारण लकवा बहुत हो रहा है और हम उसको अभियान में नहीं लेते हैं। लोग दवाई छोड़ते हैं। डाक्टर साहब, इससे डैथ के बहुत केसेज हैं। Dr. Sir, with your wisdom word it would have been better.

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27, जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उस पर आज चर्चा हो रही है। 'पहला सुख निरोगी काया', अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई खाना-पानी या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माननीय सभापति महोदय, इस सब्जेक्ट पर आज जो चर्चा हो रही है और विपक्ष के माननीय सदस्य कई तरह की खामियां निकाल रहे थे। डाक्टर साहब ने अभी

(श्री मेवाराम जैन)
विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से राजस्थान की सरकार, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी, सब मिलकर, चिकित्सा के क्षेत्र में जो राजस्थान में काम हो रहा है, राजस्थान के आम गरीब से लेकर सभी वर्गों के लिए जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, वह राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा कार्य किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। इतना शानदार काम राजस्थान के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत्बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अब इलाज फ्री। अब अपन बातें तो कई तरह की कर रहे हैं। इसमें वह कमी है, वह कमी है। कमी की बात कर रहे हैं पर यह कोई नहीं कह रहा है कि इलाज के लिए आज से दस साल पहले लोग हास्पिटल में जाने से पहले या तो गहने बेचते या किसी से पैसे लोन पर लेते या जमीन बेचते, तब जाकर अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते थे। आज उनका एक रुपया भी नहीं लग रहा है। राजस्थान की सरकार ने पूरा इलाज, जितने पैसे लगेंगे, वह राजस्थान की सरकार लगायेगी। उस परिवार को कोई चिन्ता नहीं है। चिन्ता है तो राजस्थान की सरकार को है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि निशुल्क दवा, नि:शुल्क जांचें और बड़े से बड़ा आपरेशन। अब 25 लाख तक की जो चिरंजीवी योजना शुरू की है, पहले 10 लाख की थी, अब उसको 25 लाख किया है। कहीं कितना भी खर्चा हो, राजस्थान की सरकार देगी। इलाज के लिए यहां राजस्थान से बाहर कोई दूसरे स्टेट में जाना भी चाह रहा है तो उसका खर्चा भी राजस्थान की सरकार देगी। क्या इससे भी बढ़िया कोई बात हो सकती है? पर उसका भी विरोध।

अब शानदार बजट आया। इस बजट में इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। अब बोलें तो बोलें क्या? हर क्षेत्र, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। आम गरीब से लेकर, मजदूर से लेकर, महिलाओं से लेकर, एससी-एसटी से लेकर, ओबीसी से लेकर, सभी वर्ग राजस्थान की 80 परसेंट जनता को कहीं न कहीं, किसी तरह का सभी को लाभ मिला है। अब ये बोलें तो बोलें क्या? जनता के सामने जायें, उनसे बात करें तो क्या खामियां निकालें? माननीय सभापति महोदय, अब इनको बोलना है, इसके लिए बोल रहे हैं। कोई कमी नहीं है, बाकी शानदार काम चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी, जिस तरह से ये योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना की बात की, उसके अन्दर दुर्घटना बीमा। आज इतनी

(श्री मेवाराम जैन)

शानदार सड़कें बनी हैं। आप अख़बार में, डेली न्यूज में पढ़ते होंगे कि ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें दिन के अन्दर कितने ही लोगों की जान जा रही है, उनका बीमा इस चिरंजीवी योजना में पहले पांच लाख तक का दुर्घटना बीमा था, अब उसमें 10 लाख रुपये कर दिये हैं। अगर दुर्घटना में कोई जीवन चला जाए तो उसके परिवार वालों को कैसे सम्बल मिले, उसके लिए उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता इस चिरंजीवी योजना के कारण मिलेगी। इसके कारण उस परिवार को कितना लाभ होगा, यह बात वह परिवार भी जानता है, इसलिए यह इतनी शानदार योजना है।

माननीय सभापति योजना, इस नि:शुल्क योजना में जो काम हुआ है, आप देखें कि पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों में मेडिकल कालेज, पहले तीन जिले बाकी थे, उसकी घोषणा इसमें कर दी। इससे बैटर क्या काम हो सकता था? खाली ये तो बातें ही कर रहे थे पर काम अगर किया है तो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूंगा कि आज से 12-13 साल पहले हास्पिटल में सिर्फ 12-13 डाक्टर होते थे। आज बाड़मेर मेडिकल कालेज के अंदर 200 डाक्टर्स हैं। डाक्टर वहां से बनकर दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि मेडिकल कालेज खुल गयी है वहां। डाक्टर वहां से बनकर दूसरी जगह जाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी?

पी एच सी की बात करें, सब-सेंटर की बात करें, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सब-सेंटर, हमने इसमें कोई राजनीति नहीं की। हर पंचायत पर, चाहे बी जे पी की पंचायत हो, चाहे कांग्रेस की पंचायत हो, सब पंचायत मुख्यालय पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र। पी एच सी कितनी खुली हैं? हिसाब लगाइए। मेरे ख्याल से आपने जो 5 साल में खोली, उससे कई गुना ज्यादा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने पी एच सी खोल दीं, सी एच सी खोल दीं, जिला उप-चिकित्सालय खोल दिया, चिकित्सालय खोल दिये, सिटी डिस्पेंसरी खोल दी। इसमें स्टाफ की आप बात कीजिए। कहां स्टाफ था? इन चार साल में डाक्टर्स की भर्ती की, जी एन एम, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की और अब कल ही आपने लिस्ट में देखा होगा कि खाली पी एच सी थी, उनमें भी स्टाफ की कमी थी तो 1,700 डाक्टर्स की उन्होंने नियुक्ति भी दे दी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है, एक ऐतिहासक कार्य हो रहा है। मैं जांचों की बात करूं, नि:शुल्क जांच, सभी प्रकार की जांचें जिला अस्पताल में होना और सीटी

(श्री मेवाराम जैन)

स्कैन से लगाकर, पी एच सी और सी एच सी के अंदर भी जांच शुरू कर दी। जो पहले सिर्फ जिला मुख्यालय पर जांच होती थी, अब वहां भी इसकी व्यवस्था हो गयी। मैं उदाहरण देना चाहता हं कि कोविड के अंदर कितना शानदार कार्य हुआ। सब बैठे हैं, सबको पता है, इतना शानदार काम। बाड़मेर का उदाहरण देना चाहता हूं कि सिर्फ 200-250 बेड अस्पताल में थे, 800 बेड लगे। एक्स्ट्रा बेड लगाते गये। आक्सीजन व इंजेक्शनों की कमी नहीं आयी। कोविड के अंदर जिस तरह की शानदार व्यवस्था की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बाड़मेर एक उदाहरण था। आसपास के जिले वाले मरीज बाड़मेर के अंदर आकर भर्ती हुए थे। शानदार इलाज हुआ, जिसमें सभी ने सहयोग किया। भामाशाह, डाक्टर, स्टाफ, पुलिस प्रशासन, सभी ने इसमें सहयोग किया। जन-प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के अंदर राजस्थान में जैसा काम हुआ, किसी प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण की बात करूंगा। बाड़मेर के अंदर जिला अस्पताल है, वहां जाकर देखें। उसमें आई सी यू बेड, भामाशाह ने 25 बेड का आई सी यू बनाकर दिया। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपके जयपुर के अंदर एस एम एस में ऐसे आई सी यू बेड नहीं मिलेंगे, जितने वहां बाड़मेर में दूर-दराज एरिया में हैं। आई सी यू पूरे, 25 बेड का कोटेज वार्ड। आप वहां जाकर उनकी व्यवस्था देखिए। जो व्यवस्था है वेंटिलेटर से लगाकर, डायलिसिस से लगाकर पूरी जांचें और पूरी तरह से उनकी शानदार व्यवस्था। अगर कोई वहां से रेफर होकर बाहर जाता है, अहमदाबाद जाता है तो दिन में एक लाख रुपये देने पड़ते थे और वापस आकर कहते हैं कि वहां की सुविधा और बाड़मेर की सुविधा तो एक जैसी है। हमने वहां जाकर गलती की है। इस तरह की शानदार व्यवस्था है। गायनिक के अंदर बाड़मेर में सारे प्राइवेट अस्पताल थे। कम से कम 15 अस्पताल खुले हुए थे। एकदो या तीन रहे हैं, सारे बंद हो गये, इतनी शानदार गायनिक की व्यवस्था। बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट, शानदार व्यवस्था बाड़मेर की हो रही है। मेडिकल कालेज बाड़मेर में, जिला अस्पताल 200 करोड़ का बनना है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अस्पताल तो दिया ही दिया, उसके साथ-साथ नर्सिंग कालेज बाड़मेर में दी और चौहटन में उप-जिला चिकित्सालय दिया। चौहटन में ट्रोमा सेंटर दिया। ट्रोमा सेंटर बाड़मेर

(श्री मेवाराम जैन)

में दिया, सिटी डिस्पेंसरी बाड़मेर में दी, आयुर्वेद चिकित्सालय बाड़मेर में दिया। मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय है। वहां आपने कार्डियोलोजी न्यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी, ये चार जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, माननीय मंत्री जी ने उनकी स्वीकृति भी दे दी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसमें स्टाफ भर दे। यह महत्वपूर्ण विषय है, विभाग है, इसके लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 500 नई 108 और 104 एम्बुलेंस की व्यवस्था की इस बजट के अंदर। ये राजस्थान के अस्पतालों में शानदार काम आनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बाड़मेर रेगिस्तानी एरिया है। उस एरिया में दूर-दराज में गांव और ढाणियां बसी हुई हैं। वहां हमारे सब्सेंटर और पी एच सी वगैरह में हमें कुछ छूट दें, ताकि इनको दूर इलाज के लिए जाना नहीं पड़े। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें, ताकि ग्रामीण एरिया में चिकित्सा अच्छी मिल सके।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मुफ्त दवाइयों से लेकर सारी व्यवस्था और जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था की गयी है, पूरे भारत में इसको सराहा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतनी सारी घोषणाएं की हैं, अब इनको पता नहीं वह पचेगी भी कैसे? अब इलाज फ्री, विधवा, विकलांग, असहाय, पालनहार योजना, गैस सिलेण्डर 1,200 में दे रहे थे, खाली झुनझुना पकड़ा रखा था। अब 500 में सिलेण्डर, बिजली फ्री, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 की भर्ती में जो ए एन एम की भर्ती थी, वह अधूरी रही, क्योंकि उसमें पहले तो सलेक्शन कर दिया गया, बाद में सरकार बदली तो पद इन्होंने काट दिये तो वे उसमें वंचित रह गयीं। ये ओवरएज भी हो रही हैं। कैसे भी करके आप उनको भर्ती में जोड़ें, ताकि उनको राहत मिल सके। सी एच ए हैं, उनके लिए भी और अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार कर रही है। और भी उनकी कोई डिमांड है तो आप

(श्री मेवाराम जैन)

इसमें पूरी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य राजस्थान की सरकार कर रही है। लोग धन्यवाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास।

सूचना

रावणा राजपूत समाज व ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों का धरना

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, हजारों की संख्या में रावणा राजपूत समाज और ओ.बी.सी. के लोग धरने पर बैठे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि उनसे बात करके उनकी वाजिब मांगों पर न्याय दिलायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: राज्य सरकार के ध्यान में है। श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व 28-चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूंगी। आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर तीन बड़े-बड़े अस्पताल हैं, एम.डी.एम. हास्पिटल, उम्मेद हास्पिटल, टीबी हास्पिटल। ये सारे ही बड़े हास्पिटल्स हैं। जब एम.डी.एम. हास्पिटल बना तो महाराज उम्मेद सिंहजी की महारानी भटियाणी ने यह कहा कि औरतों ने आपका क्या गुनाह किया है तो, माननीय सभापति महोदय, उस समय महाराजा उम्मेद सिंहजी ने उम्मेद हास्पिटल बनवाया, आज वह उम्मेद हास्पिटल के नाम से जाना जाता है। उस उम्मेद हास्पिटल के अन्दर सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और वह बच्चों का है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

है कि लेबर रूम के अन्दर एक-एक पलंग के ऊपर दो-दो महिलाएं सो रही हैं, इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। आज जब अपन चिकित्सा के ऊपर विचार कर रहे हैं, मंत्रीजी सामने विराजमान हैं, मुख्य मंत्री स्वयं जोधपुर के हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस हास्पिटल का भी सुधार करें। काफी सुधार वे कर भी रहे हैं लेकिन फिर इसका भी सुधार करें। इसका सुधार करने से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।

एम.डी.एम. हास्पिटल है, उसके अन्दर सारी व्यवस्था है, जब मशीनें खराब होती हैं तो डाक्टर्स यह कहते हैं कि आप बाहर से जांच करवा लो तो गरीब आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी, बाहर जाने में उनको कितनी असुविधा रहती है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो कोई भी मशीन खराब हो जाये तो एक समय तो बंधना चाहिए कि 24 घंटे में ठीक हो, तीन दिन में ठीक हो, चार दिन में ठीक हो, आप ऐसा कोई समय बांधें कि उसको तुरंत ठीक करवाया जाये, ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि एम.डी.एम. हास्पिटल के पास एक टीबी हास्पिटल खुला था और वह किसने खोला? एक सेठ थे रघुनाथजी परिहार, रघुनाथ सेठ थे, उनका क्या सोच था, कहां के वे रहने वाले थे और कहां आकर उन्होंने यह हास्पिटल खोला, क्योंकि लोगों को टीबी बहुत होती है तो यह हास्पिटल खोला और वह हास्पिटल बना कितनी राशि के अन्दर? 46 हजार रुपये के अन्दर वह हास्पिटल बना और आज भी वह कायम है और एक भी मरम्मत कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बढ़िया उन्होंने हास्पिटल बनाया, ऐसी उनकी सोच थी तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस हास्पिटल के अन्दर जो कोई भी मशीनें वगैरह खराब हों तो तुरंत दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि सूरसागर के अन्दर सेटेलाइट हास्पिटल है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और प्रताप नगर। प्रताप नगर के अन्दर मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत्तबहुत आभार और धन्यवाद करूंगी कि वहां पर उन्होंने जिला अस्पताल की घोषणा की है और जो वहां पर सेटेलाइट अस्पताल चल रहा है, वह दीनदयाल उपाध्याय पार्क के अन्दर चल रहा है। यह जब जिला हास्पिटल बनेगा तो चलो कोई बात नहीं, इधर आ जायेगा मगर इनके अन्दर सेटेलाइट हास्पिटल जो है, इनके अन्दर डाक्टर्स, नर्सेज पूरे बराबर नहीं हैं तो उनको भरें। वे क्षमता के

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

अनुसार पूरे होने चाहिए, क्षमता के अनुसार पूरी मशीनें होनी चाहिए, क्योंकि ये सेटेलाइट हास्पिटल ऐसे होते हैं कि वहां पर बहुत मरीज आते हैं और यह 24 घंटे खुले रहने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इनको बराबर 24 घंटे खोलें और वहां पर सारा स्टाफ मौजूद रहे। ऐसा न हो कि कहीं पर स्टाफ की कमी रहे, जिससे वहां के लोगों को असुविधा न हो।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर, चांदपोल के अन्दर मास्टर खींवराज कछवाह अस्पताल है, उसको सेटेलाइट करने के लिए मैं मेरी मांग रख रही हूं, इस मांग को स्वीकार करें।

इसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, सूरसागर के अन्दर एडपोस्ट है कालीबैरी, इसको अपग्रेड करने के लिए मेरी मांग है। मसूरिया के अन्दर भी क्रमोन्नत करें, वहां पर भी एडपोस्ट है, तो उसको क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं। इसी तरीके से सूरज राज चिकित्सालय, राजबाग जो कि सूरसागर के अन्दर है, उसको भी मैं क्रमोन्नत करने की मांग कर रही हूं, ताकि वहां के लोगों को सहूलियत मिले और जनता के हित की बात हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 एवं 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। भिवाड़ी, जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर पांच लाख की आबादी में मात्र पचास बेड का एक हास्पिटल चल रहा था और उसमें भी तीस ही बेड संचालित अभी तक थे, पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले उसको उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया और इस बजट में उसको जिला हास्पिटल में क्रमोन्नत किया तो यह भिवाड़ी के लिए, भिवाड़ी में देश के प्रत्येक हिस्से के जो लोग रहते हैं, उनके लिए चिकित्सा सुविधा मुख्य मंत्रीजी ने दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्री संदीप कुमार)

तिजारा जो हमारा हैडक्वार्टर है, विधान सभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, वहां पर भी जो 2013 में यह घोषणा हुई थी, 50 बेड से 100 बेड स्वीकृत हुए थे तो वह लम्बे समय से पेंडिंग था। 2013-14 से 2018-19 तक उसकी क्रियान्विति भी नहीं हो पायी थी तो मैं यह धन्यवाद करता हूं मुख्य मंत्रीजी का कि वहां पर भी उन्होंने 50 से 100 बेड का हास्पिटल हमारे यहां पर क्रमोन्नत कर दिया और उसमें डाक्टर्स भी आ गये हैं और साथ में हास्पिटल में विंग भी उसमें तैयार हो रही है, जिसमें उसके लिए अलग से वार्ड बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सी.एच.सी., पी.एच.सी., चार तो मेरे यहां पर सी.एच.सी. खुली हैं और तीन पी.एच.सी. खुली हैं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से, उसमें हमारा मेवात अंचल भी है तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।

कोविड के समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे देश में एक माडल राजस्थान हमारे प्रदेश को यहां पर घोषित करवाया। राजस्थान स्टेट को पूरे देश भर में ख्याति मिली और उसमें हमारी चिकित्सा सुविधाओं का भी बहुत विस्तार हुआ। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमने विभिन्न, हमारे वहां पर स्वयंसेवी संस्थाओं से, हमारे भामाशाहों से सहयोग लेकर सभी हास्पिटल्स में आक्सीजन की पाइप लाइन की हमारे यहां पर व्यवस्था हो गयी है। करीबन 30-30, 40-40 बेड की हमारी जो सी.एच.सीज. हैं, उनमें आक्सीजन पाइप लाइन की व्यवस्था हो गयी, उनमें एक्स-रे मशीन की व्यवस्था हो गयी और चिकित्सा सुविधाओं में जांच के लिए जो मशीनें हैं, उन सबकी भी व्यवस्था हमारे यहां पर हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं जो वहां की चिकित्सा सुविधा के लिए जरूरी है। एक तो हमारे टपूकड़ा में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर खुशखेड़ा और चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र नये विकसित हुए हैं। वहां पर भी हजारों की संख्या में हमारे देश भर के मजदूर साथी रह रहे हैं, तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए टपूकड़ा में हमारे मात्र 30 बेड का हास्पिटल है जबकि वहां पर हमारा उप खण्ड कार्यालय है, हमारे वहां पर तहसील है और नगरपालिका टपूकड़ा, कस्बे में भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और साथ में मेवात का क्षेत्र भी लगता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह मांग करूंगा कि हमारा टपूकड़ा का जो हास्पिटल है, उसको तीस बेड से

(श्री संदीप कुमार)

बढ़ाकर पचास बेड का कर दिया जाये और उसमें सैटेलाइट हास्पिटल की सुविधा हमारे टपूकड़ा हास्पिटल में हो।

साथ ही साथ, हमारा तिजारा हैडक्वार्टर का जो हास्पिटल है, वहां पर 800 से 1000 की ओ.पी.डी. लगातार हमारे वहां पर है और वहां पर बड़ी संख्या में अलग-अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। हरियाणा हमारे यहां से नजदीक है, वहां के लोग भी काफी बड़ी संख्या में आते हैं तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि तिजारा हास्पिटल में भी हमारे यहां पर जनाना हास्पिटल की मांग है तो एक महिला विंग वहां पर तिजारा के हास्पिटल में खोली जाये। साथ ही साथ जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. नई खुली है तो मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उनके भवन का निर्माण भी जल्दी हो, ताकि लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल सके।

(समय: 14.00 बजे)

मेरा विधान सभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और वहां पर बड़ी संख्या में इण्डस्ट्रीज हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सी एस आर का काफी पैसा इण्डस्ट्रीज की तरफ से आता है, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि सी एस आर का पैसा सही जगह पर लगे। हास्पिटल्स की सुविधाओं का विस्तार हो। हमारे वहां पर इण्डस्ट्रीज प्रदूषण फैला रही हैं। वहां का पानी दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गयी। यदि हम इंडेक्स को देखते हैं तो एशिया के मानकों में पोल्यूशन में सबसे टॉप में भिवाड़ी आता है जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इण्डस्ट्रीज को पाबन्द किया जाये कि सी एस आर का पैसा स्थानीय क्षेत्र में चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधाओं के लिए लगे। वह देश भर की विभिन्न जगहों पर एन जी ओ के माध्यम से पैसा लगाते हैं। सी एस आर का पैसा सही जगह पर लगे।

तिजारा में सोनोग्राफी की मशीन की आवश्यकता है। पहले सोनोग्राफी की मशीन लगी थी। उसमें ट्रेकर नहीं है इस कारण वह मशीन ऐसे ही धरी की धरी रह गयी। दस साल पहले वह मशीन आयी थी।

(समय: 14.01 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पहले तो हमारे वहां पर सोनोलॉजिस्ट नहीं था। सोनोलॉजिस्ट आया तो बताया गया कि उस मशीन में ट्रेकर नहीं होने की

(श्री संदीप कुमार)

वजह से वह मशीन कामयाब नहीं है। वहां पर एक अन्य सोनोग्राफी की मशीन लगे। हमारे यहां पर सारी व्यवस्था है। सर्जरी के लिए विधायक कोष और भामाशाहों की मदद से हमने सर्जरी वार्ड वहां तैयार करवा दिया है, लेकिन तिजारा में सर्जन नहीं है इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर डाक्टर्स लगाये जायें। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का कि अभी कल ही 1,700 डाक्टर्स की सूची आयी है, भर्ती कर दी गयी है, हमारे यहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की मेरे यहां पर मांग है तो मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे यहां पर डाक्टर्स लगाये जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करता हूं। सभी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर मेडिकल कालेज खुले हैं। भिवाड़ी में जिला स्तर की सारी सुविधाएं हैं। वहां पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाया। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल वहां पर चल रहा है और सभी जिला स्तरीय कार्यालय वहां पर स्थापित हैं। भिवाड़ी में भी मेडिकल कालेज खुलाने की व्यवस्था करावें। हमारा क्षेत्र एन सी आर में आने से कोई फायदा तो हुआ नहीं है पर हमें बड़ी परेशानी होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार से एन सी आर का हमारे हक का पैसा मिले और हमारे यहां पर मेडिकल कालेज की स्थापना हो।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या है। यह सभी जगह की समस्या होगी शायद। मैंने मेरे यहां पर विधायक कोष से बड़ी सी एच सी में तीन एम्बुलेंस दी हैं लेकिन उनको चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए डीजल और ड्राइवर की व्यवस्था करें। यह पूरे राजस्थान की समस्या है। हमने विधायक कोष से एम्बुलेंस दे दी, लेकिन हमारे लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो चिकित्सक मना कर देते हैं। हर बार यही कह देते हैं कि हमारे पास चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग सभी जगहों पर ज्यादातर विधायकों ने एम्बुलेंस दी हैं, लेकिन कहीं पर भी न तो डीजल की व्यवस्था का प्रावधान है और न ही ड्राइवर है। एम आर एस में इतना फण्ड नहीं होता है। आपको सबको ध्यान है कि आजकल ओ पी डी भी फ्री हो गयी। जो थोड़ा बहुत पैसा पर्चियों से आता था वह भी नहीं आ पा रहा है। वह बड़ी समस्या है। जब एम्बुलेंस खड़ी हुई है तो मंत्रीजी से निवेदन है कि उनके लिए आपके विभाग से ड्राइवर मिल जाये और डीजल की भी व्यवस्था हो जाये, तब जाकर ही लोगों

(श्री संदीप कुमार)

को फायदा मिलेगा वरना एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह जायेगी। मेरे क्षेत्र की जो मांगें हैं उनके लिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सभी मांगों को पूरा करेंगे, मुझे भरोसा है। मुझे बोलने का मौका दिया, पुन: आपका आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान में वर्तमान में चिकित्सा को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं, बड़ी-बड़ी बातें की गयीं। बहुत सब्जबाग राजस्थान की जनता को दिखाये गये और भ्रम का मायाजाल फैलाने में पूरे के पूरे चिकित्सा प्रशासन ने बहुत मेहनत की, मशक्कत की। मेरा मानना है कि यदि यह मशक्कत राजस्थान की जमीन पर होती, धरातल पर होती तो निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान के आम-अवाम को मिल पाता परन्तु जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी डिस्पेंसरीज और मेडिकल कालेज के जो हाल हैं, वास्तव में वे चिन्ताजनक हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा में निरोगी राजस्थान के संकल्प से शुरू होकर यूनिवर्सल केयर, हेल्थ केयर तक आप गये, परन्तु इन चार सालों में राजस्थान की जनता को कोई विशेष लाभ आपके द्वारा नहीं मिल पाया। आपकी अधिकांश घोषणाएं आपने जो कीं इन चार सालों में, वे फलीभूत ही नहीं हुईं। चिकित्सा जैसे संवेदनशील मामले में तो कम से कम ईमानदारी से बात करें और पूरी तत्परता के साथ यहां पर सिर्फ अपनी प्रशंसा कराने के लिए काम करें। मैं समझता हूं कि यह एक संवेदनशील विषय है जिसमें गरीब, मरीज, पीड़ित, रोगी अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाता है और वहां पर सिर्फ हम प्रशंसा को लेकर आतुर रहें और उनको काम के नाम पर लाभ हम नहीं दे पायें तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है।

माननीय सभापति महोदय, आपने तमाम सी एच सी, पी एच सी की घोषणाओं का अम्बार लगा दिया, परन्तु उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर और डवलपमेंट के विषय में आपने नहीं सोचा। हर विधायक का कहना है कि आज नर्सिंग स्टाफ की कमी से हर पी एच सी, सी एच सी जूझ रही हैं। इसके लिए आपको योजना बनाने की आवश्यकता थी। आप निरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक गरीब मरीज लाइन में खड़ा होकर पर्ची का इन्तजार करता हुआ दवाई के काउंटर तक पहुंचता है तो दवाई नहीं मिलती, जांच नहीं

(श्री संदीप शर्मा)

हो पाती। उसको मजबूर होकर मेडिकल की दुकान से दवाई खरीदनी पड़ती है और प्राइवेट लैब में जाकर उसको जांच करवानी पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इसी सत्र के एक प्रश्न के उत्तर में देखा था तो चिकित्सा मंत्रीजी ने बताया था कि आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के 50 प्रतिशत से भी अधिक पद रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार चिकित्सा विभाग तथा राजमेस एवं चिकित्सा शिक्षा के शिक्षक, नर्सिंग संवर्ग, पैरा मेडिकल कैडर व अन्य कैडर के भी कुल स्वीकृत 05 हजार 785 में से 3 हजार 623 पद रिक्त पड़े हैं। यह जबाव आपने अपने उत्तर में दिया है। इस प्रकार की स्थिति होगी तो किस प्रकार से हम निरोगी राजस्थान की बात कर सकते हैं? प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि हम देखें तो हमारे राजस्थान में चिकित्सकों की उपलब्धता सबसे कम है। भारतीय चिकित्सा, डब्ल्यू एच ओ के मापदण्ड के अनुसार एक हजार पर एक डाक्टर होना चाहिए। आज हम किस स्थिति में खड़े हैं, इसका आकलन आप स्वयं करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा कर दी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत। क्या वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर पाये हो? क्या वहां स्टाफ नियुक्त करा पाये हो? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्षों में जो चिकित्सा शिक्षक की भर्ती निकली थी, वह आज तक नहीं हुई। दिल्ली की तर्ज पर आप जनता क्लिनिक खोलना चाह रहे थे केजरीवाल की तरह, जिसका पूरा देश मजाक उड़ाता है, उसकी बराबरी हम नहीं कर पाये। एक जनता क्लिनिक हम राजस्थान में नहीं खोल पाये।

माननीय सभापति महोदय, संविदाकर्मियों के साथ आपने धोखा किया। आपका चुनावी वादा आप पूरा कर पाये? एन आर एच एम, एन यू एच एम और आर एम आर एस के कम्प्यूटर आपरेटर्स, लैब असिस्टेंट, सहायक कर्मचारी और आशा सहयोगिनी आज भी स्थायी होने का इन्तजार कर रहे हैं। आपने उन्हें गुमराह करने के लिए पृथक् से कोई कमेटी बना दी। सी एच ए कोविड में अपनी जान को जोखिम में डाल कर लगे रहे। 27 हजार 427 कोविड सहायकों को आपने भर्ती किया था पर उन्होंने अल्प वेतन पर काम किया था। आपने उनको हटाकर बेरोजगार कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा की बात करना चाहता हूं। न्यू

(श्री संदीप शर्मा)

मेडिकल कालेज, कोटा में प्रतिदिन 05 हजार से 07 हजार का आउटडोर है और वहां यह स्थिति है कि 30 करोड़ की लागत से द्वितीय तल का निर्माण हो चुका पर तीन साल से वह बेकार पड़ा हुआ है और वह भूत बंगला बन रहा है। वहां पर अगर थोड़ा स्टाफ और थोड़े बेड लगा देते तो मैं समझता हूं, कोविड के टाइम तक भी अगर यह काम हो जाता तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा देते। बिना बेड के लोगों को तड़पते-तड़पते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, पीडियाट्रिक का वहां उपचार नहीं हो रहा है। वहां पीडियाट्रिक के सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर बैठते हैं, लेकिन वहां भर्ती करने के संसाधन नहीं हैं। वहां नीकू, पीकू चालू नहीं हैं। वेंटिलेटर नहीं हैं नीकू, पीकू में। न्यू चिकित्सालय जहां पर 05 से 07 हजार ओ पी डी की संख्या है, वहां पर 15 किलोमीटर दूर जाकर जे.के. लॉन में भर्ती बच्चा होता है तो यह कितने दु:ख की बात है और हम बात करते हैं निरोगी राजस्थान की। न्यू मेडिकल कालेज में रीजनल कैंसर सेंटर नहीं है। वहां दो ओंकोलॉजिस्ट सर्जन को लगाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, कैंसर रोगी किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आप बहुत भले आदमी हैं लेकिन भले होने से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्रीजी, हम आपके प्रशंसक हैं, परंतु जमीन पर आकर इन समस्याओं को देखने की आवश्यकता है, जिससे आज आम आदमी जूझ रहा है।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 150 करोड़ रुपये की लागत से खड़ा हुआ है और वहां सिर्फ आपको कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर लगाने हैं। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट लगाने हैं, जी.आई. सर्जन लगाना है, कोई भी डाक्टर वहां पदस्थापित नहीं हैं। या तो इनको आप यू टी बी पर लगायें या पदस्थापन के द्वारा भेजें, वह भी आपने रोक रखे हैं। अगर यह चालू हो जाये तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इतना शानदार बना हुआ है कि निश्चित रूप से उसका लाभ लोग ले पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाला दूसरा हमारे कोटा शहर का मेडिकल कालेज है। वहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ढंग से हो सके, इसके लिये रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता है। वहां पर रोबोट आ जाये तो कैंसर के जो यूरोलॉजी वाले मरीज हैं, उनको हम लाभ दे सकें। हालात यह हैं कि सीटी स्कैन और एम आर आई कराने वालों की वहां लाइन लगती है। वहां पर सीटी स्कैन मशीन तो है नहीं, एम आर आई की लाइन लगती है। वहां पर मरीज का 15

(श्री संदीप शर्मा)

दिन में नंबर आता है तो एक सीटी स्कैन और एम आर आई आप दे दें तो राहत मिल जायेगी। आर्गन ट्रांसप्लांट की वहां आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, नर्सिंग आफिसर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टैक्निशियन, ECG टैक्निशियन आदि के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि वहां की जनता को लाभ मिले। वर्तमान में जो कैथ लैब लगी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अभी तो कितना समय हुआ है। आपने 10 मिनट का समय दिया था। मरीजों को देखते हुए कम से कम हृदय रोगियों के लिये तो हम एक कैथ लैब और दो कार्डियोथोरेसिक सर्जन और एक नर्सिंग स्टाफ आप दें। कोविड के बाद तेजी के साथ, अभी माननीय सदस्य भी बता रहे थे, माननीय सभापति महोदय, तेजी के साथ हृदयाघात से लोग मरने लगे हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता है। हर CHC पर कम से कम एक ECG मशीन हो तो कम से कम उसको प्राथमिक उपचार मिल जाये और वह अस्पताल तक पहुंच जाये, उसको बीमारी का मालूम पड़ जाये।

आपकी गलत नीतियों से प्रदेश के प्राइवेट चिकित्सा संस्थान नाराज हो गये। लगभग 70 प्रतिशत काम हमारे प्राइवेट चिकित्सा संस्थान करते थे। इनको बुलाकर इनकी संवेदनाओं के साथ इनको संवेदनशील बनाया जाता, इनको इनके दायित्वों को बताया जाता और निश्चित रूप से इनकी सलाह के अनुरूप हम काम लेते तो निश्चित रूप से आपके सहयोगी बनकर निरोगी राजस्थान बनाने में आपकी मदद करते।

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 आपका ऐसा रहा, जिसके कारण हम खुद समझ रहे हैं कि किस तरीके की तकलीफ में आप भी रहे हो और पूरे राजस्थानवासी भी रहे हैं।

आपके द्वारा गत दो वर्ष पूर्व जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा की गयी थी, वह नहीं हुआ। CHC विज्ञान नगर में भवन तैयार खड़ा हुआ है, वहां कुछ डाक्टर लगाने हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में तलवंडी, दादाबाड़ी शापिंग सेंटर, सुभाष नगर में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। वहां अगर यह स्टाफ दे दें तो लोगों को राहत प्राप्त हो। मंत्रीजी, आप वास्तव में बहुत संज्ञान लेने वाले हैं, परंतु आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

(श्री संदीप शर्मा)

आयुर्वेद और होम्योपैथी हमारे लिये कितनी मददगार रही कोरोना के टाइम में पर कोटा में आयुर्वेद कालेज का यह हाल है कि जो आपने बजट में हमको दिया, 20 किलोमीटर दूर एक कमरे में आयुर्वेदिक कालेज चल रहा है।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समय और मिलेगा। ऐसे ही होम्योपैथी में मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) मैं बैठ रहा हूं साहब।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बहुत भारी अच्छे समर्थन के साथ प्रशंसा करना चाहूंगा कि राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का जो सिस्टम है, वह गत चार सालों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। हमारे यहां राजस्थान का सिस्टम, राजस्थान का माडल न केवल अपने स्टेट में एप्रिशियेट किया गया है, बल्कि अन्य राज्यों में भी और देश के प्रधान मंत्रीजी ने भी इस सिस्टम को एप्रिशियेट किया है चाहे वह कोरोना के रूप में किया हो, चाहे वह अन्य शब्दों से किया हो, but fact remains that the system has been appreciated by the Hon. Prime Minister of India. इसका मतलब पूरे देश में हमारे प्रदेश को सराहा है। सराहना ऐसे ही नहीं होती, माननीय सभापति महोदय, कोई कार्य करके दिखाते हैं और कोई एप्रिशियेबल कार्य करते हैं, कोई अच्छा नवाचार करते हैं तब ही प्रशंसा हुआ करती है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता क्लिनिक सिस्टम स्टेट में आया और मेरे झुन्झुनूं जिले में चार जनता क्लिनिक आपने दिये। उसमें से दो जनता क्लिनिक मैं ले गया और मैं आपको जानकारी देता हूं कि दोनों के दोनों मैंने शुरू करा दिये हैं। बहुत अच्छे चल रहे हैं। कम से कम 100-100 पेशेंट का आउटडोर दोनों में है। एक जनता क्लिनिक मैंने पिलानी में चालू किया और दूसरा मैंने चिड़ावा में शुरू किया। CHC चिड़ावा और CHC पिलानी और CHC मंड्रेला, तीन CHC मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। PHC भी जगह-जगह पर हैं, लेकिन CHC चिड़ावा में आउटडोर बहुत भारी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जो बेड संख्या है, वह मात्र 75 आपने कर रखी है

(श्री जे.पी. चन्देलिया)
और मैं आपको कई पत्र लिख चुका हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी पत्र लिख चुका हूं और मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं उनके नोटिस में भी यह बात ला चुका हूं कि कम से कम, मांगना तो मुझे ज्यादा चाहिये, लेकिन कम से कम 100 बेडेड हास्पिटल तो इस CHC को बना दें। अनेकों गांवों के लोग इस हास्पिटल में आते हैं और आवश्यकता है कि इसे 100 बेडेड बनाकर चिड़ावा CHC को उप-जिला हास्पिटल का दर्जा आप दीजिये। मैं यह उम्मीद करता हूं और मानकर चलता हूं कि जब आप उत्तर देंगे तो मुझे इस मामले में आप निराश नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैंने CHC मांगी अपने डिमांड में। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं नई PHC नहीं मांग रहा, मैं यह कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाम्बा गोठड़ा में, डुलानिया में, बेरी में, बंदगोठडी में जो सब-सेंटर चल रहे हैं, उनका अप-ग्रेडेशन मांग रहा हूं माननीय मंत्री महोदय। लाम्बा गोठड़ा की बात कर रहा हूं। लाम्बा गोठड़ा एक बहुत बड़ा कस्बा टाइप है और उसमें बिल्डिंग भी हमने एक भामाशाह से बनवा दी। आपको वहां पर भवन नहीं बनाना। आज मुझे एप्रिशियेट करना चाहिये सुआबाई पत्नी श्री रामेश्वर लाल जी का, जिन्होंने अपने एक मात्र पुत्र की याद में, क्योंकि पुत्र का स्वर्गवास हो गया, उसकी याद में उन्होंने 50 लाख रुपये का भवन PHC बनाने के लिये हमें दे दिया। वह पंचायत को हैंडओवर भी हो गया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां के लोग भी इंतजार कर रहे हैं चालू होने का। वहां पर अनेकों गांव हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि कौन-कौनसे गांव हैं, जिनको PHC बनानी है। लाम्बा गोठड़ा और डुलानिया को खाली अपग्रेड करना है। वहां पर भवन वगैरह सब कुछ है। लोग इंतजार कर रहे हैं। वहां पर आपने जो सब-सेंटर बना रखा है, उससे काम नहीं चल रहा है। लोगों में असंतोष का लेवल बढ़ रहा है। एक तरफ तो हम एप्रिशियेट कर रहे हैं कि मेडिकल और हेल्थ की सर्विसेज हमारी स्टेट में बहुत अच्छी हैं और दूसरा जो बड़े-बड़े गांव हैं, आस-पास 10-10 गांव हैं, उनके बीच में भी अगर हम एक PHC नहीं देवें तो वह ठीक नहीं है। लाम्बा गोठड़ा के मामले में एक चिट्ठी भूल से मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिख दी, जो प्लान का काम देखते हैं। उनका जवाब मेरे पास आ गया कि साहब, जो नोर्म्स हैं, उनके अनुसार इतनी PHC होनी चाहिये और इसलिये नई PHC नहीं खोल सकते। मैं नई PHC नहीं मांग रहा हूं, मैं तो सब-सेंटर का अपग्रेडेशन मांग रहा हूं। अपग्रेडेशन में और नई में

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बहुत अंतर है। इसलिये आफिसर लॉबी में जो हमारे सीनियर आफिसर्स बैठे हैं, उनके नोटिस में भी डालना चाहता हूं। लाम्बा गोठड़ा में और आसपास पांच हजार की आबादी है, अलीपुर है, खुडिया है, इस्माइलपुर है, भोमपुरा है, शेखपुरा है, हरिपुरा है, अजीतपुरा है, कुलाड़ियों का वास है, इतने गांव और वहां पर एक PHC नहीं, और उसमें भी हमने वहां पर भवन बनाकर दे दिया। वहां पर शानदार भवन बनाया है। लेडी भामाशाह है, उसका एकमात्र बेटा था, उसकी डैथ हो गयी और उन्होंने वहां पर उसकी याद में भवन बनाकर दे दिया और खुद एक छोटे-से कमरे में रहती है। इतना बड़ा त्याग उसने कर दिया। मेरे विचार से we must honour, हमें आनर करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैने डुलानिया का अपग्रेडेशन मांगा। डुलानिया में सब-सेंटर चल रहा है, कई सालों से वह चल रहा है और मेरे से पूर्व जो भी विधायक रहे होंगे, उन्होंने भी मांगा होगा, लेकिन जब से मैं विधायक बना हूं, तब से मैं डुलानिया का अपग्रेडेशन चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं 12 गांवों को फायदा मिलेगा डुलानिया के अपग्रेडेशन से।

लीखवा, हसासियों की ढाणी, खालवा की ढाणी, गाडोली, हमीनपुर, मोरवा, भोजा का बास, भगीना, बास तोखा, सेढू की ढाणी, फरट और श्योसिंहपुरा। मैं खाली अनफाउंडेड बात नहीं कर रहा हूं। मैं फाउंडेड बात कर रहा हूं, which is based on the actual status in the Assembly Constituency. अगर एक सेंटर को आप अपग्रेड करते हो तो यह 12 गांवों को फायदा होता है। मेरा निवेदन है कि यह दोनों लांबा गोठड़ा और डुलानिया, बेरी आलरेडी सब सेंटर है, बनगोठडी आलरेडी सब सेंटर है। इनको आप अगर अपग्रेड कर दें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल हेल्थ का और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का जो सिस्टम है, वह काफी अच्छा हो जायेगा।

दूसरा, मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूं क्योंकि लांबा पी एच सी आपने पिछली बार एक सब सेंटर को अपग्रेड करके दी थी लेकिन वहां के भवन के लिये अभी तक पैसा मुझे नहीं मिला है। निवेदन है कि इस बजट प्रोविजन में भवन बनाने के लिये आप हमें जरूर पैसा उपलब्ध करायें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि 2013 का जो नर्सिंग भर्ती वाला मामला है, यह मैं ही नहीं बल्कि मेरे अनेक साथियों ने बार-बार परश्यू किया है। हम

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

लोगों ने पत्र भी लिखा है। मैं झुंझुनूं जिले का रहने वाला हूं। पिलानी विधान सभा क्षेत्र को रिप्रजेंट करता हूं। हमारे यहां की बच्चियां और बच्चे मैक्सिमम संख्या में उससे हिट हो रहे हैं। कृपया उस मसले को करें। राज उधर का था, वे लोग इधर बैठते थे। उन्होंने भारी संख्या में वैकेंसी निकाली। बाद में उनमें कटौती कर दी। वो बच्चे जो एग्जाम में अपीयर हुए, उनका क्या दोष है? बड़े उत्साह के साथ, बड़े हौसले के साथ वह अपीयर हुए। वह वैकेंसी उन्होंने कम कर दी। अब कम से कम उनकी गलती को हम सुधारें, ताकि जो युवा युवक, युवतियां हैं, उनमें से कई लोग तो ओवरएज हो जायेंगे इसलिए यह 2013 का जो नर्सिंग भर्ती वाला मामला है, माननीय महोदय, बड़े दिल के साथ इसको आप सुलटायें। सी एच ओ वाला मामला है, इसको सुलटायें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यहां कहने की बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि ट्रांसफर पालिसी का जो सिस्टम डिजाइन किया हुआ है आपके सेक्रेटेरिएट में, आपके डिपार्टमेंट में या मेडिकल हेल्थ के डायरेक्ट्रेट में, कई बार कई जिनाइन ट्रांसफर्स की भी डिनाई हो जाती है। उसको अगर आप थोड़ा पर्सनली देख लें और विधायक को सुन लें कि यह बार-बार रिपीट कर रहा है तो कुछ कारण तो होगा। उसको आप जरूर देखिये।

बाकी ओवरआल मैं वापस एप्रिशएट करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं, वे बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल हैं। मैं एप्रिशिएट करता हूं। मैं ही क्या पूरा देश एप्रिशिएट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की डायनेमिक लीडरशिप में और आपकी लीडरशिप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में और ज्यादा प्रगति करेंगी। माननीय सभापति महोदय, आपने इतना समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्य स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और माननीय चिकित्सा मंत्री भी इस विषय को लेकर गम्भीर नजर आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आहोर की बात कर रहा हूं, आहोर में 2 सी एच सी थीं आहोर और सियाणा। उसमें से आहोर में आज सुबह की लिस्ट देखी है तो

(श्री छगनसिंह)

उसमें 3 डाक्टर लगाये हैं, लेकिन सी एच सी सियाणा में तो आज भी एक डाक्टर है। वहां कंपाउंडर्स के भी पूरे 4 पद रिक्त हैं और डाक्टर्स के भी पद रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सी एच सी सियाणा में भी आप डाक्टर की नियुक्ति करें। मैं आशा करूंगा कि जो पोस्टिंग आपने दी है, वह डाक्टर इस सत्र तक ही नहीं रहे, वह अपना प्रोबेशन पीरियड तो पूरा निकालें। अन्य जगह न जाकर वह जोइन करें। जोइन भी करें और वहां पर रहें, नहीं तो हमारे क्षेत्र में पी एच सी हमेशा खाली रहती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो डाक्टर की नियुक्ति की है, वे पहले तो वहां पर रहें।

मैं ज्यादा लम्बी चर्चा नहीं करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण मेरे क्षेत्र के 2-3 विषयों को लेकर करना चाहूंगा। विषय छोटे-छोटे हैं। 2 गांव हैं रसियावास खुर्द और सुमेरगढ़ खेड़ा। वे ग्राम पंचायत स्तर के गांव हैं। माननीय मंत्री जी, जो ग्राम पंचायत स्तर के गांव हैं, उनकी आबादी करीब 3-3 हजार है। वहां पर सब सेंटर्स के भवन भी गवर्नमेंट द्वारा बनाये गये हैं, लेकिन वहां सब सेंटर्स हैं नहीं। रसियावास खुर्द और सुमेरगढ़ खेड़ा में भवन बने हुए हैं खाली सब सेंटर्स की घोषणा करें। दोनों बड़े गांव हैं। ग्राम पंचायत स्तर के गांव हैं, लेकिन वहां ग्राम पंचायत की घोषणा नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं परिसीमन में हमारे को अनदेखा किया था, लेकिन इस रसियावास खुर्द और सुमेरगढ़ खेड़ा में अगर सब सेंटर होगा तो ठीक होगा। वहां बिल्डिंग बनी हुई है। गुढ़ारामा और पलासिया खुर्द ऐसे गांव हैं जहां पी एच सी बहुत लंबी-लंबी दूरी पर है। गांव बड़े-बड़े हैं, इनमें सब सेंटर्स की घोषणा करावें।

मैं आपसे 3-4 बार मिला हूं। आपसे मैंने शंखवाली की पी एच सी को लेकर बार-बार चर्चा भी की है। मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया कि मैं शंखवाली में पी एच सी की घोषणा करूंगा, क्योंकि वहां पर चूंडा, कांबा और वलदरा, ऐसी 3 बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं। सबमें आजू-बाजू 7-7 गांव हैं। वहां पर 15 से 20 किलोमीटर तक कहीं पर भी एक भी पी एच सी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि शंखवाली की जो मैं बार-बार चर्चा कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप मुझे हताश नहीं करेंगे। आपने मुझे आश्वस्त भी किया कि शंखवाली में पी एच सी आप मुझे देंगे। ऐसा मुझे विश्वास भी है।

मैंने एक भाद्राजून सी एच सी, भंवरानी की सी एच सी, गुढ़ाबालोता

(श्री छगनसिंह)

और चांदराई की सी एच सी के लिये भी मांग की है। भाद्राजून तहसील मुख्यालय है। वहां पर 50 किलोमीटर के रेडियस में एक भी सी एच सी नहीं है। भाद्राजून एक तहसील मुख्यालय भी है। वहां पर सी एच सी की सख्त आवश्यकता है। जैसे कि अभी माननीय सदस्य पूर्व में बोल रहे थे कि नियमों में आये तो करें। वह नियमों में भी आ रहा है, उन नियमों के तहत अगर भाद्राजून में भी सी एच सी हो जाये तो अच्छा रहेगा।

मेरे क्षेत्र में टोटल 3 सी एच सी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां आवश्यकता है, आपके पास प्रपोजल भी आये हुए हैं। मैं चाहूंगा कि भाद्राजून, भंवरानी, चांदराई और गुढ़ाबालोता जैसे बड़े कस्बों के साथ में आजू-बाजू में जनता का जिस प्रकार का स्तर है, जिस प्रकार से आपने योजनाएं निकाली हैं, अगर हास्पिटल्स नहीं होंगे तो वे योजनाएं फलीभूत नहीं होंगी।

माननीय सभापति महोदय, आप चिरंजीवी की कह रहे हैं। मैं चिरंजीवी की चर्चा करना चाहूंगा कि भीनमाल के हास्पिटल में, वहां पर जब पेशेंट एडमिट होने जाते हैं, वे चिरंजीवी में हैं, उनको एडमिट तो कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं नेट नहीं है, इलाज होने के बाद में वह बड़े-बड़े बिल देते हैं। उसके बाद कंप्रोमाइज में वह आधा बिल करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एडमिट करते वक्त तो बोलते हैं कि हां, चिरंजीवी में हैं, लेकिन जब आधा घंटे बाद में इलाज शुरू हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि नेट शुरू नहीं है, आपको तो सीधा प्राइवेट इलाज लेना पड़ेगा। उसमें पेशेंट की और उसके परिवार की मजबूरी होती है कि वह वहां पर इलाज करवाते हैं। वह बड़ा बिल देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करें या फिर वह नेट की प्रोब्लम बता रहे हैं, वह वास्तव में है या नहीं है वह देखें। चिरंजीवी योजना में इस प्रकार की धांधली चल रही है। आप जरूर मुझे इस बारे में बतायेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, एक आर जी एच एस में सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, उनकी भी मांग है कि 25 लाख रुपये किये जायें। जब चिरंजीवी में 25 लाख हैं तो आर जी एच एस में जो सेवानिवृत्त हैं, उनके भी 25 लाख के इलाज की आवश्यकता है। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हर जगह विधायकों से भी मिले हैं। उनकी भी स्वास्थ्य को लेकर कुछ मांग है, क्योंकि जब उम्र ज्यादा होती है, तब इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, उस समय ही बीमारियां लगती हैं।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें आप उनकी जरूर मदद करें। आर जी एच एस में 25 लाख तक के इलाज की उनको भी छूट दी जाये।

मैं विशेषकर जो मेरी मुख्य मांग है, मैं आपसे हमेशा मिला हूं, मेरे यहां शंखवाली पी एच सी की महती आवश्यकता है, उसे आप जरूर स्वीकृत करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जय हिन्द। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री गिर्राज सिंह (अनुपस्थित)। श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चिकित्सा की मांग पर बोलने का अवसर दिया। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और मरीज को दवा, सबसे बड़ी सेवा है। उसी के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री और जन कल्याणकारी सरकार ने इन 4 वर्षों में यह कार्य किया है।

माननीय सभापति महोदय, हम सबने कोरोना का मंजर भी देखा। हम सबने कोरोना का एक ऐसा मंजर भी देखा जो देश ही नहीं पूरे विश्व में छाया। किस तरह से सरकारें उसमें असफल रहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को, चिकित्सा मंत्रीजी को और चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और धरती के भगवान कहे जाने वाले डाक्टरों को कि उन्होंने पूरे राजस्थान में ऐसी माकूल व्यवस्था की कि पूरे देश में उदाहरण और राजस्थान की जनता में आत्मविश्वास को पैदा करने का काम किया। आज इस विषय पर हमारे विपक्ष के साथी सरकार के खिलाफ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि कम से कम वो अपने गिरेबान में तो झांकें, वो यह तो देखें कि आपको राजस्थान की जनता ने पांच साल के लिए अवसर दिया था, मौका दिया था, केन्द्र में आपकी सरकार थी तो आपने उन पांच वर्षों में क्या काम किए। आप पहले तुलना कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और फिर इस सदन में आकर बोलें कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ, भाजपा के शासनकाल में क्या हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को आईना दिखाना चाहता हूं कि आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में क्या किया और हमारी इस सरकार ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में, केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, भाजपा के शासनकाल में मात्र 7 सब-सेंटर खुले, जबकि हमारे कार्यकाल में 500 सब-सेंटर खोले गए। भाजपा के शासनकाल में 7 पी एच सी बनाई गईं, जबकि हमारे कार्यकाल में 363 पी एच सी बनाई गईं। भाजपा के शासनकाल में उप जिला चिकित्सालय 'जीरो' थे, जबकि हमारे इस कार्यकाल में 41 उप जिला चिकित्सालय बनाये गये। भाजपा के शासनकाल में मात्र 565 बेड्स को बढ़ाया गया, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में 6 हजार 700 बेड को बढ़ाया गया। भाजपा के कार्यकाल में मात्र 2 नर्सिंग कालेज खुले, जबकि हमारे कार्यकाल में 25 नर्सिंग कालेज खुलने जा रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में मात्र 150 एम बी बी एस की सीटें बढ़ाई गईं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में 1,380 एम बी बी एस की सीटें बढ़ाई गईं। भाजपा के शासनकाल में 50 पी जी की सीटें बढ़ाई गईं, जबकि हमारे कार्यकाल में 558 पी जी की सीटें बढ़ाई गई हैं। ये वो आईना है जो जनता को भी पता चलता है और भाजपा के हमारे साथियों को भी आईना दिखाता है कि आपने पांच वर्ष के कार्यकाल में क्या किया और कांग्रेस की जन-कल्याणकारी सरकार ने काम क्या किया। कोरोना की वैश्विक महामारी में पूरा देश उसके अंदर कराह रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदीजी ने हमारे सांसदों का जो सांसद कोटा था उसको फ्रीज करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने विधायक कोष का पैसा 2 करोड़ 25 लाख रुपये था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का काम किया, ताकि राजस्थान के विधायक अपने क्षेत्र की जनता के पास जाकर, उन मरीजों के पास जाकर उनको ढांढस बंधाने का काम कर सकें। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सांसद असत्य घोषणाएं करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे। आज जिस तरह से पूरे देश में राजस्थान में एक उदाहरण पेश हुआ कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आये। पूर्व में 10 लाख रुपये थे, उसको बढ़ाकर मुख्य मंत्रीजी ने 25 लाख रुपये करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, आज चाहे कोई गरीब परिवार हो, मध्यम परिवार हो, उस परिवार में कोई बीमारी आती है तो उस परिवार को पता चलता है कि उस बीमारी का दर्द क्या होता है। जमीन, जायदाद और गहने, सब उस परिवार के बिक जाते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने उस गरीब और मध्यम परिवार के दर्द को समझने का काम किया जिसके तहत उन्होंने अपने हर कार्यकाल में चाहे वो नि:शुल्क दवा योजना की

(श्री अमित चाचाण)

बात करें, चाहे वो नि:शुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे उसका दायरा बढ़ाने की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना को लाने का काम किया है, उसकी हम बात करें, आज पूरे देश में यह एक उदाहरण बना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज जिस तरह से हमारे राजकीय चिकित्सालयों में जो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जो मरीजों का इलाज नि:शुल्क किया जा रहा है, वह हम सबके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। चालीस वर्ष हो गये, बहुत-सी सरकारें आईं, बहुत से वहां से विधायक चुने गये। बिहाणी परिवार के द्वारा नोहर के राजकीय चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया था, उसके बाद कोई सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे चिकित्सालय के डाक्टरों की मैंने मीटिंग ली, मैंने उनको यह कहा कि हमें एक वेंटिलेटर का शुभारम्भ करना है, कोरोना मरीजों का इलाज करना है, उनके हाथ-पांच फूल गये और वो कहते हैं कि नोहर जैसी सी एच सी में हम कोरोना का इलाज करेंगे, वेंटिलेटर चलाएंगे, सिलेंडर कहां से आएंगे, व्यवस्था कहां से होगी? मैंने उनको एक ही शब्द कहा आपके आगे मैं खड़ा हूं, जो आपको व्यवस्था चाहिए, मैं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में पांच दिनों में हमारे दानदाता, भामाशाहों ने 50 लाख रुपये के आक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर दिये। जहां दो मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था, वहां हमने 65-65 मरीजों का कोरोना काल में इलाज करवाया। 18 से 20 जिनका सीटी स्कोर था उनका इलाज करवाया। आज वही राजकीय चिकित्सालय जो 30 वर्षों से क्रमोन्नति की बाट जोह रहा था, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को जिन्होंने इसे 100 बेड में क्रमोन्नत करने का काम किया। ट्रोमा सेंटर की हमें सौगात दी, उप जिला चिकित्सालय का हमें दर्जा दिया। मैंने विधायक कोटे से 50 लाख रुपये का वहां आक्सीजन प्लांट भी लगाया। दानदाता, भामाशाह और डी एम एफ टी के सहयोग से एक शानदार आई सी यू वार्ड का निर्माण करवाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सी एच सी लेवल पर राजस्थान में कोई सरकारी अस्पताल में इस तरह का आई सी यू वार्ड नहीं होगा। हमने दानदाताओं, भामाशाहों और डी एम एफ टी फंड के द्वारा डायलिसिस मशीन का शुभारम्भ करवाया, जिससे भी वहां मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणाजी को कि इसी बजट

(श्री अमित चाचाण)

में जो हमारी लम्बे समय से मांग चली आ रही थी ब्लड बैंक की, उसकी सौगात भी नोहर के उप जिला चिकित्सालय को दी। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांगें आपके सामने रखना चाहता हूं। नर्सिंग भर्ती 2013 के बारे में सभी विधायक आज अपनी बात उठा रहे हैं, मैं भी उनका समर्थन करते हुए कह रहा हूं कि इस भर्ती को जल्दी किया जाए। प्रयोगशाला सहायकों की सूची से जो वंचित रह गये थे, उसका भी शीघ्र हल निकाला जाए। सी एच ओ की जो मांग थी, कोरोना काल में उन्होंने जो कार्य किया, मदद की, उसकी भी मैं आपके द्वारा मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा संविदाकर्मियों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा कर राहत देने का काम किया। 1 लाख 10 हजार जो संविदाकर्मी हैं, जिनका अनुभव पुराना 3 साल का है उसको एक साल का माना है। मेरी यह मांग है कि एक साल को एक साल मानते हुए 5 साल पूर्व से जो लगे हुए हैं उनको स्वीकृत करने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा नोहर क्षेत्र में पी एच सी से सी एच सी को क्रमोन्नत करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। खइया, मंदरपुरा, टोपरिया, धानसिया को सब-सेंटर से पी एच सी में क्रमोन्नत किया जाए। मालासर, मोटेर, सीरासर, जबरासर, दलपतपुरा के लिए मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी मरम्मत करने और जहां लेबर रूम नहीं है वहां उसको भी बनाने की मांग करता हूं। इसके अलावा हमारे उप जिला चिकित्सालय में आंखों के डाक्टर तो हैं, लेकिन उनके पास कोई उपकरण नहीं हैं। पिछले काफी दिनों से मैं कह रहा हूं, आर एम एस सी एल से पर्चेज नहीं हुए हैं, मैं मांग करता हूं कि जल्द जिला चिकित्सालय में उसकी भी सप्लाई की जाए। हमने डी एम एफ टी फंड से सी आर एम मशीन 15 लाख रुपये की लगाई और हमने 40 लाख रुपये की लागत से अलग से आर्थो आपरेशन थियेटर का निर्माण करवाया। पूर्व में दो डाक्टर वहां पर कार्यरत थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद वो ओटी बंद है। हमारे विकलांगों के जो प्रमाण पत्र बनते हैं, वह व्यवस्था भी वहां पर बंद हो गई है, यह भी शुरू करवाने की मांग है मंत्री महोदय से कि आने वाले समय में हमें आर्थो के डाक्टर दिए जाएं। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केन्द्र 14 बारानी, बालासर, चैनपुरा, बांगासर, सांखिया, 6 आरपीएफ और असरजाना में खोले जाने की मैं मांग करता हूं।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, हमारे दानदाताओं के द्वारा सेठ फकीरचंद-लालचंद कंदोई के द्वारा स्वयं के भवन जो 2 करोड़ रुपये की लागत से 1995 में बना था, उन्होंने बेशकीमती जमीन भी इस विभाग को दी थी। शुरू में यह कंडीशन थी कि इस चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जाएगा, लेकिन वह भारत सरकार के बंद करने के बाद आज वह मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है और वहां पर केवल टीकाकरण का ही काम हो रहा है। आज हम अगर उसको देखते हैं तो भामाशाह और दानदाताओं के मान और सम्मान के लिए मैं यह विशेष तौर से मांग करता हूं कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे हमारे राजकीय चिकित्सालय का भार कम हो सके और दानदाताओं और भामाशाहों का भी मान और सम्मान कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े हास्पिटल हैं वे उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। आज ही मेरे पास एक श्रवण कुमार गुरड़ा जो मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र से है, एच सी जी जो कैंसर हास्पिटल मानसरोवर, जयपुर में है, उसमें एडमिट हुआ। जब एडमिट हुआ तो उसको कहा कि तमाम इलाज निःशुल्क किया जाएगा, उसका आपरेशन हुआ नहीं और दो दिन से वे छुट्टी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उनका पैसा जमा कराएं। वो एकदम गरीब परिवार से है। मेरी यह भी मांग है कि जो भी बड़े हास्पिटल हैं, जिनको निःशुल्क या रियायती दर पर जमीन भी दी हैं, उनकी जांच करवाई जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सारा तो दानदाताओं ने किया है, सरकार ने क्या किया है? (व्यवधान)

श्री अमित चाचाण (नोहर): पैसे दानदाता ऐसे ही नहीं देते हैं, जन-प्रतिनिधि ईमानदार हो तभी दानदाता पैसे देते हैं। आप ईमानदारी से काम कीजिए, दानदाता आपको भी पैसे देंगे। मैं नोहर में पांच करोड़ रुपये की बिल्डिंग भी दानदाताओं से करवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एमएलए साहब, इतनी देर तो वाहवाही कर रहे थे, अब जांच कराने लग गए। वाहवाही करते-करते जांच करवाने लग गए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन मांग संख्या 27 और 28 पर विचार कर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके लिए 5 मिनट निर्धारित किये गए हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): जी, माननीय। अभी जो आपस में वाद-विवाद कर रहे थे वो समय तो शामिल नहीं है न इन 5 मिनट में?

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28, चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। वैसे तो हमारे चिकित्सा मंत्रीजी इतने सभ्य, शालीन और खूबसूरत हैं कि इनको देखकर ही आधी बीमारियां तो सबकी दूर हो जाती हैं, आपका गेट-अप ही इतना बढ़िया है, मगर फिर भी मैं सदन का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है पहले भी कई बजट पेश किए। 2019-20 में आपने छोटे मोहल्लों और ग्रामीण एरिया के लिए विशेष तौर से जनता क्लिनिक का बहुत बड़ा वादा किया था। माननीय मंत्री महोदय, मेरे यहां फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में एक जनता क्लिनिक की घोषणा अभी दो महीने पहले हुई है, मगर उसका अब क्या होगा, यह आप ही जानें। आप अपने रिप्लाई में जरूर बताएं कि अब तक साढ़े चार साल में आपने कितने खोले।

2021-22 में आपने एक बहुत बड़ी घोषणा कोविड काल में की थी कि सभी विधायक एक-एक माडल सी एच सी गोद लें। सबने उसे गोद तो ले लिया, लेकिन आप यह भी बताएं कि सरकार उसमें क्या करेगी? अगर माननीय सदस्यों को ही करना है तो वह तो वैसे भी सभी लोग अपना-अपना सहयोग करते हैं। सरकार ने बजट में ये चीजें अनाउंस की हैं। दोनों चीजें बजट में की हैं। इसलिए बजट का पार्ट है, कोई अन्य आय का पार्ट नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, जब आप घोषणा करें तो अपने श्रीमुख से बताएं। हालांकि, मैंने अपने यहां किशनगढ़-रेनवाल को उसमें चयनित किया था और आपका पत्र मुझे मई, 2022 में मिला था कि आप पैसे स्वीकृत करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने नवम्बर, 2021 में ही 1.5 करोड रुपये स्वीकृत करके निर्माण भी पूरा करवा दिया। अब सरकार उसमें क्या करेगी, यह आप जरूर बताइयेगा। उसे उप-जिला अस्पताल बनाएंगे या अन्य कोई सुविधाएं देंगे?

(श्री निर्मल कुमावत)

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी तकलीफ जो हमारे सामने है, वह यह है कि गांवों में तेजी से हार्ट अटैक और कैंसर फैल रहा है। किसी व्यक्ति को यह पता ही नहीं पड़ता कि वह किस स्टेज पर है और कब उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मैं विशेष तौर से जयपुर जिले की ही बात कर रहा हूं, दूर-दराज की तो बात ही अलग हो गयी। इसके लिए पी एच सी-सी एच सी में आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्राथमिक स्तर पर लोगों को कैसे इसकी जानकारी लगे। आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, स्वास्थ्य में जांच फ्री है। आप जांच करवाकर बताएं। दो-चार जांचों के लिए तो हमें फोन करने पड़ते हैं, तब जांचें होती हैं। बताइये। साथ ही, वह जांच सही है, उसकी गुणवत्ता सही है, यह हम कैसे ट्रस्ट करें? आपने लगभग 700 दवाएं फ्री कर रखी हैं, बहुत अच्छी योजना है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, मगर जो पैरासिटामोल बाजार में 100 रुपये की मिल रही है और आपको सप्लायर 15 रुपये में दे रहा है तो उसकी गुणवत्ता को हम कैसे मानें? कहीं मुफ्त की दवाइयों के चक्कर में रोगी अधिक बीमार तो नहीं होते जा रहे हैं, हमें यह सोचने की आवश्यकता है।

आप में से और हम में से कितने लोग मुफ्त दवाएं काम में लेते हैं, यह भी कृपया आज बताएं। केवल कहने से नहीं होता। आम जनता परेशान होकर हास्पिटल आती है, बार-बार उसे चक्कर काटने पड़ते हैं। आज की तारीख में जयपुर जिले में एक भी सी एच सी नहीं होगा, जिसमें हजार से कम ओ पी डी हो। ओ पी डी की हालत यह है, मुख्य मंत्री जी ने मुफ्त कर दी, कुछ 10 रुपये लेते थे, आप केवल एक काउंटर पर पर्ची चालू करते हैं, उसमें सैकड़ों आदमियों की भीड़ होती है, महिलाएं भी उसमें रहती हैं, बड़े-बुजुर्ग भी रहते हैं। कम से कम दो-दो, तीन-तीन काउंटरों पर पर्ची कटवाने की व्यवस्था तो हो। एम आर सी की मीटिंग औपचारिकता हो गयी है। आपका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है उसमें।

हम सभी जन-प्रतिनिधि हजार बार कहते हैं कि व्यवस्था ठीक करें। एक भी सी एच सी में दो काउंटर, तीन काउंटर, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जयपुर की बात नहीं कर रहा। हमारे गांव की बात कर रहा हूं, आप बताइये, एक-एक लाइन के लिए 200-300 आदमी रहते हैं और 1000 का ओ पी डी आपके 9 से 3 के समय में होता है। कैसे लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा? पहले तो वह डाक्टर के पास जाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, फिर डाक्टर के पास भीड़ रहे, फिर बाद में जांच कराकर मुफ्त की जो दवा लेकर आये, वह काम करेगी कि नहीं, भगवान भरोसे है।

(श्री निर्मल कुमावत)

अब आप यह बताइये। ग्रामीण क्षेत्र में 9 से 3 के बाद कोई डाक्टर, अगर सात डाक्टरों की पोस्ट है तो 2-3 तो छुट्टी पर रहते हैं। एक का आफ रहता है, एक कोई ड्यूटी पर रहता है। 3 बजे बाद आदमी कहां जाये? या तो उसके क्वार्टर पर जाये। आपकी क्या व्यवस्था है पी एच सी, सी एच सी पर? जहां सिंगल पी एच सी है, वहां तो अगले दिन ही खुलेगा 9 बजे। सी एच सी में आन कॉल की फैसिलिटी आप लोग देते हैं, सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, बता दें, रात को एक भी कोई डाक्टर, इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाये, कोई डिलीवरी आ जाये तो परेशान होकर लोग हमें कॉल नहीं करते तो बता दें आप।

मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा, व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। कहीं क्वार्टर्स दूर हैं, कहीं हास्पिटल के अन्दर हैं। यह जो 9 से 3 का टाइम है, थोड़े दिन बाद आप समय बदल देंगे, उसके बाद इतनी बड़ी सी एच सी या उप-जिला अस्पताल होता है, उसमें कोई स्थायी डाक्टर हर समय वहां मिले, उसके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? आप क्या करना चाहते हैं, अपनी मंशा बताएं।

मेरा दूसरा निवेदन है, मोबाइल सर्जिकल यूनिट आपकी चलती है। उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता है, जयपुर जिले में भी पांच-छह कैम्प लगते हैं। इस साल भी जो कैम्प लगे हैं, 500-500 आंखों के आपरेशंस हुए हैं। वे लोग उनमें आते हैं, जो किसी योजना में नहीं आते। न कोई चिरंजीवी उन पर लागू होती है, न कुछ। ज्यादातर बड़े-बुजुर्ग आते हैं 80-90 साल के, जो या तो इलाज करवा नहीं सकते या अपने लोगों द्वारा ठुकराये हुए होते हैं। यह जो इतनी बढ़िया यूनिट है, माननीय आंजना साहब भी कैम्प लगाते हैं, आप स्वयं भी गये हुए हैं, आपके अंता से आने वाले माननीय मंत्री महोदय भी कैम्प लगवाते है, हम भी लगवाते हैं यहां जयपुर में बंधे के बालाजी, तो इस यूनिट को आप जिन्दा रखें। पूरे एशिया की एकमात्र यूनिट है। जितने काम यह कर सकती है, मैं यह नहीं कहता कि दूसरे नहीं कर सकते, पर यह भी एक व्यवस्था है कि आज जो यह परम्परा चलती आ रही है, गांवों में जाकर आप सुविधा दे रहे हैं, वह चालू रहे। अत: मोबाइल सर्जिकल यूनिट के लिए मेरा निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग को आपने सेटेलाइट हास्पिटल बनाया, अच्छी बात है, मगर यूनिट खतम न करें। यह मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे यहां एक भी उप जिला अस्पताल नहीं है। चार-चार सी एच सीज हैं। क्या कोई नाराजगी है हम

(श्री निर्मल कुमावत)

से? आप चार में से किसी एक में तो खोलें कम से कम। जिसमें ज्यादा ओ पी डी होती है, वहां खोलें। कोई उप-खण्ड मुख्यालय पर है, वहां खोलें। कोई बिल्डिंग अवेलेबल है, वहां खोलें।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह (अनुपस्थित), श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित), श्री जितेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)। श्री लाखन सिंह।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरा इतना ही कहना है कि मेरे यहां हिरनोदा, बन्धे के बालाजी और पचकोड़िया में नयी पी एच सी आप खोलें। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी पधारे थे मूर्ति अनावरण में। एक अणतपुरा का छोटा-सा मैटर देना चाहूंगा आपको। आपके यहां से एन आर एच एम से 41 लाख रुपये का नया पी एच सी सेंटर, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति निकली। जमीन उपलब्ध नहीं थी। बार-बार सरपंच और आपकी ए एन एम ने पत्राचार करके भामाशाह से जमीन दान करवायी। रजिस्ट्री करा ली, नामान्तरण खुल गया। फिर बाद में उस जगह निर्माण न करके दूसरी जगह निर्माण करा दिया। मैंने आपके तत्कालीन प्रिंसिपल सैक्रेटरी से सम्पर्क किया, आपसे किया, आप भारत जोड़ो यात्रा में पधारे हुए थे, सी एम एच ओ को कहा, ब्लाक सी एम एच ओ को कहा, कोई सुनवाई नहीं। मतलब कौन जमीन देगा? आप घर जाकर किसी को जमीन के लिए तैयार करते हैं, फिर उसी को मना कर देते हैं कि अब तेरी जमीन नहीं लेंगे, लेकिन आपने जमीन भी ले ली गरीब किसान की। उसकी क्या गलती? बताइये। विभाग कैसे काम करता है, यह आपके सोचने की बात है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए पिछली सरकार में बोर्ड का गठन हो गया, आप उसे मान्यता देंगे अथवा नहीं? यह भी तय करें।

माननीय सभापति महोदय, बजट की बात करना चाहूंगा, केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। यह पिछले बजट का प्रगति प्रतिवेदन है। केवल 40 परसेंट खर्चा किया आपने दिसम्बर तक। आप कैसे आगे काम करेंगे? मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी मांगें हैं फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की, नयी पी एच सी और उप-जिला अस्पताल आप खोलें। जो 9 से 3 के बाद की हास्पिटलों की व्यवस्था है, उसे कैसे ठीक करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी जरूर सुनेंगे। मैंने आपकी तारीफ भी खूब की है, अब तो सुनेंगे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 एवं मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाह रहा हूं कि आपके लिए 8 मिनट निश्चित किये हैं और आपके लिए 7 मिनट निर्धारित किये हैं। कृपया समय का ध्यान रखें। वक्ता बहुत ज्यादा हैं।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है, पहले भी तीन बजट दिये हैं, ये बहुत शानदार हैं। उन्होंने गरीब, पिछड़ी जनता की सोच को ध्यान में रखकर यह बजट दिया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र करौली डांग क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। यह 70 सालों से ऐसा क्षेत्र था, जहां 50 किलोमीटर के बीच कहीं पी एच सी नहीं थी, कहीं सी एच सी नहीं थी, किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो वहां पर मुझे सी एच सी दी और दो पी एच सी दीं जो मासलपुर क्षेत्र में आती हैं। दूसरी जगह भी मुझे चार पी एच सी दीं और तीन सी एच सी दीं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि पिछड़ा हुआ है, उसमें मेडिकल सुविधाओं के लिए जहां-जहां हमने जो मांगा, वह हमें दिया। जिस तरह से गरीब के लिए चिरंजीवी बीमा योजना चालू की है, वह बहुत ही शानदार है। जब मैं कई बार जाता था तो दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में। अब वे सिर्फ जाते हैं और जाने के बाद में उनका कम्प्लीट इलाज हो जाता है। अभी मुझसे पूर्व माननीय सदस्य कह रहे थे कि जांचें नहीं होतीं। आप जांच कराने गये ही नहीं कि आपको पता चले। आप जाएं किसी भी अस्पताल में। आपको जांचें फ्री मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं है। दवाएं भी फ्री हैं। जो गरीब है, उसकी जांच भी फ्री है, दवा भी फ्री है और इलाज भी फ्री है। सबसे बड़ी बात, यह जो चिरंजीवी बीमा योजना है, इसमें कितने लोगों को फायदा हो गया। जो गम्भीर बीमारी हुआ करती थी, उसका तो गरीब आदमी इलाज ही नहीं करा सकता था। वह तड़प-तड़पकर ही अपनी जान दे देता था। मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरह की योजना लाकर गरीब की जान बचाने का काम किया है। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, उसका इलाज फ्री है। पहले 10 लाख थे, अब 25 लाख कर दिये। 10 लाख एक्सीडेंट में कर दिये। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह की योजना जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी लाये हैं, यह गरीब के लिए है। चाहे 8 रुपये में इन्दिरा रसोई योजना हो, एक रुपये किलो गेहूं हो, जिस

(श्री लाखन सिंह)

तरह की सोच और योजना है, चाहे पेंशन की योजना हो, इस तरह की जो योजनाएं हैं, ये सब गरीबों के लिए हैं, न कि ये कोई पैसे वालों के लिए योजनाएं हैं। जितनी भी योजनाएं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने, सरकार ने चला रखी हैं वे अधिकतर गरीबों के लिए है। केन्द्र की सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं वे अधिकतर पैसे वालों के लिए है चाहे अडानी के लिए हो, चाहे अम्बानी के लिए हो। मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह की योजनाएं हैं ये बहुत शानदार योजनाएं हैं।

मेरी एक मांग है कि हमारे यहां करौली शहर में एक पुराना अस्पताल है जिसको अब बन्द कर जो नया अस्पताल बनाया गया है वह शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और उसी में कालेज बनाया गया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उस अस्पताल को सेटेलाइट अस्पताल किया जाये। उसमें बेड की सुविधा है, आक्सीजन की सुविधा है, सारी तरह की सुविधाएं उसमें हैं इसलिए उस अस्पताल को सेटेलाइट अस्पताल किया जाये।

कुछ मुझे पी एच सी की और भी आवश्यकता है जिसमें एक तो झगर नवीन पी एच सी के लिए है और एक शहर में ढोलीखार है। इन दोनों में पी एच सी की आवश्यकता है। जो डाक्टर हैं उनकी वैसे भर्ती भी की गई है, काफी जगह डाक्टर लगाये गये हैं, लेकिन कुछ जगह डाक्टर्स की और भी आवश्यकता है इसलिए डाक्टर भी लगाये जाएं। जो नर्सिंग स्टाफ की कमी है वह भर्ती की जाए। इसके अलावा जो पहले से नर्सिंग संविदाकर्मी हैं उन सबकी भी मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए। जो टेक्निकल स्टाफ है इसकी भी बड़ी कमी आती है। जो नई पी एच सी, सी एच सी खुली हैं उनमें जांचों की दिक्कत है, इसलिए टेक्निकल स्टाफ की भी पूर्ति की जाये।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 चिकित्सा पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे पर थोड़ा रहम रखना, क्योंकि मैं धीमी गति का हूं।

सभापति महोदय, वर्षों से इस हाउस में चिकित्सा पर बहस चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

गांव और शहर का भेद कब खतम होगा, क्योंकि गांवों के अन्दर पी एच सी है उसमें डाक्टर नहीं हैं, ए एन एम नहीं हैं, जी एन एम नहीं हैं और सारे पद रिक्त हैं। अगर कोई लगा हुआ है तो वह एक महीने के अन्दर सिर्फ 5-6 दिन हाज़िरी लगाकर अपने घर आ जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है। मुफ्त दवा का प्रचार सरकार खूब जमकर कर रही है। आप गांवों के अन्दर जाकर पूछो, किसी भी उप स्वास्थ्य केन्द्र में, पी एच सी के अन्दर आपको दवा नहीं मिलेगी, यह हकीकत है। लगातार प्रशंसा की जाती है पर सच्चाई के ऊपर कोई भी व्यक्ति ध्यान तो दे। मानते हैं कि यह योजना बहुत फायदेमन्द है पर जो आपने घोषणा कर रखी है, उसके मुताबिक ग्रामीण व्यक्ति को इलाज मिले, समय पर दवा मिले, यह व्यवस्था सरकार करे।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाहवाही मुख्य मंत्री जी की हो रही है पर केन्द्र का भी इसमें हिस्सा है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं पर केन्द्र का भी 45 परसेंट इसमें बताया गया है तो केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अरबों रुपये खर्च करती जा रही है। पहली बात तो यह है कि एलोपैथिक दवाइयां फेल होती जा रही हैं, काम करने से रह गयीं, यह हकीकत है। सर्जरी कामयाब है। बाकी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद हमारे देश की सबसे पुरानी इलाज की पद्धति है पर आयुर्वेद को तो हमने इस तरह से कर दिया जैसे कोई बिना मां-बाप की सन्तान हो। पहली बात तो भवन नहीं है, भवन है तो जाले लगे हुए हैं, स्टाफ नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद इतनी बुरी चीज नहीं है। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, उप वैद्य हैं उनकी तनख्वाह और टी ए, डी ए वगैरह जो भी सुविधा है वह आप एलोपैथिक के समान रूप से दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार कहां है? सरकार तो गयी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सरकार तो है न, सरकार की बात कर रहे हो आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अपने को पूछता कौन है? मैं निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं है। एलोपैथी पर जितना पैसा खर्च होता है उससे आधा पैसा भी अगर आयुर्वेद में रिसर्च पर खर्च करो तो जनता को हर हालत में लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक दवाई साइड इफेक्ट नहीं करती। मैं प्रेक्टिकली बता रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि यह हर बार ऐसे ही बोलता है। मेरे गैस की प्रोब्लम थी और एलोपैथिक में जा-जाकर दस बार दवाई ले ली पर ठीक नहीं हुई।

श्री सभापति: बीड़ी काम करती है क्या आपके? बीड़ी पीने से गैस निकलती है आपकी, बीड़ी छोड़ दो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बीड़ी कम करे तो हल्ला ही क्यों हो। यही तो रोग है। कुल मिलाकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय रहते आयुर्वेद की तरफ ध्यान दे और आयुर्वेद को रिसर्च के लिए बजट दे तो कम से कम आयुर्वेद की दवाई खाने से दूसरी बीमारी तो नहीं लगेगी। एलोपैथी के अन्दर, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है कि एक बीमारी ठीक होती है और दस बीमारियां और पैदा हो जाती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जितने भी पद रिक्त हैं वे भरे जाएं। जहां भवन नहीं हैं उन भवनों के लिए बजट दिया जाए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जो अनदेखी हो रही है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। पद इतने रिक्त पड़े हैं जिनकी संख्या मैं बताऊं कि जहां 100 पद हैं वहां मौके पर सिर्फ 30 ही कार्यरत हैं, 70 पद रिक्त हैं। यह हालत है ग्रामीण क्षेत्र की। इसके अन्दर सुधार करने के लिए सरकार कब व्यवस्था करेगी? सरकार इधर की भी आ गयी, उधर की भी आ गयी पर ग्रामीण क्षेत्र में आज दिन तक न तो कोई नि:शुल्क दवा योजना का लाभ मिला और न ही कोई भवन मिला, न डाक्टर मिला, न नर्स मिली और बहुत बुरी हालत है।

सभापति महोदय, सरकारी हास्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो प्रथम बार तो उसको कह दिया जाता है कि आपके तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और हमारे यहां तो मशीन खराब है, आपको गंगानगर जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना पड़ेगा। ये बहानेबाजी कब रुकेगी? जब तक यह बहानेबाजी नहीं रुकेगी तब तक गरीब व्यक्ति को इलाज नहीं मिलेगा। यह बात मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इतना बड़ा बजट सरकार खर्च कर रही है और धरातल पर सुविधा नहीं मिल रही है। एलोपैथिक विभाग एक ओर प्रचार कर रहा है कि ये जो सरकारी दवाइयां हैं, ये काम तो करती नहीं, चाहे कितनी ही लें, यह प्रचार पूरे राजस्थान के अन्दर है। जो सरकारी दवा हैं, उसकी तरफ लोगों का रुझान ऐसा हो गया है कि ये बिलकुल ही काम नहीं करती हैं।

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समाप्त ही है। सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप समय रहते आयुर्वेदिक पद्धति पर पुन:

(श्री रामप्रताप कासनियां)

विचार करें। अगर इस देश को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है तो एलोपैथिक दवाइयों से पीछा छुड़ाओ।

अभी कितने हार्ट अटैक हुए हैं। यह कोरोना का असर है। कोरोना की बीमारी का असर है या वह जो वैक्सीन लगाई, उसका असर है, यह एलोपैथिक विभाग बताये। हार्ट अटैक दुनियाभर के हो रहे हैं, जिनके कोरोना हुआ है। शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में, सब जगह हो रहा है। एलोपैथिक के पास रिसर्च है तो एलोपैथिक वाले यह क्यों नहीं बताते कि जो वैक्सीन लगाई है, उसका अवगुण है या फिर कोरोना बीमारी का कारण है। बातें बहुत बड़ीबड़ी, अरबों रुपये का बजट खर्च करने के बावजूद भी, आयुर्वेदिक देशी दवाएं हैं, वे हमारे वन की जड़ी, बूटियां हैं। भगवान राम के समय में संजीवनी बूटी पहाड़ी क्षेत्र में थी। सभापति महोदय, उसकी रिसर्च करें, जीवन बूटी ढूंढो, तब जाकर यह राजस्थान बचेगा।

श्री सभापति: आप तो च्यवनप्राश की डिमांड करें। सारे एम एल एज को च्यवनप्राश दिलवाओ।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): च्यवनप्राश, आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे तो आपको फ्री में मिलेगा। सरकार बजट तो दे, मैं हकीकत में बता रहा हूं।

श्री सभापति: वैक्सीन का तो नाम ही मत लो। वैक्सीन में तो मोदी जी का भी नाम आ जायेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आने वाले समय में आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समय रहते अपना लेंगे तो जनता को कुछ लाभ होगा और समय निकल जायेगा तो जनता इस एलोपैथी से बर्बाद हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: यह वैक्सीन का नाम तो हटवा दें। इसमें तो नरेन्द्र मोदी साहब का भी नाम आ रहा है। वैक्सीन तो प्रधान मंत्री जी ने भेजी थी। उनका भी नाम आ जायेगा, हटवाऊं इसको?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): प्रधान मंत्री भेजे, कोई भी भेजे। इनके पास हिम्मत है तो जांच करके बताये ना, वैक्सीन का चक्कर है या कोरोना बीमारी का है?

श्री सभापति: ठीक है। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): धन्यवाद, सभापति महोदय,

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

आपने मुझे मांग संख्या-28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या-27 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था, जो कि हर व्यक्ति की जरूरत है, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है। जिस प्रदेश में, जिस देश में चिकित्सा व्यवस्था शानदार है, उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था कोई हो नहीं सकती है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले गांव में मध्यमवर्गीय परिवार में, गरीब परिवार में, कोई व्यक्ति बीमार होता था, किसी का परिजन बीमार होता था तो सबसे पहले किसी साहूकार के पास भागते थे। भाई, पैसे उधार दो, मरीज को दिखाकर लाना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि 2008 से 2013 के बीच में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पूरे देश में पहली बार 02 अक्टूबर, 2011 को महात्मा गांधी की जयन्ती के दिन मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। उस योजना का धीरे-धीरे दायरा बढ़ाया। उसमें दवाइयों की संख्या बढ़ायी। फिर, जांचें नि:शुल्क कीं। इस बार तो इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए, हमारी सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि पूरे देश में उस निर्णय की चर्चा है। पहले 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री किया। अब इसी बजट में उसको बढ़ाते हुए 25 लाख रुपये तक का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क करने का काम किया। यह कोई छोटा-मोटा निर्णय नहीं है।

सभापति महोदय, एक आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, साधारण परिवार के लिए, अगर उसकी बीमारी में लाख, दो लाख, पांच लाख रुपये का सहारा मिलता है। वह दो रुपये सैकड़े में कहीं से ब्याज पर रुपये उठाकर लाता है, उससे बचता है। वह हमारी पार्टी को दुआएं देते हुए घर पर जाता है।

सभापति महोदय, हास्पिटल के बाहर दुनिया भर की प्राइवेट लैब्स होती थीं, लूट मचा रखी थी, छोटी-छोटी जांचों के हजारों रुपये लगते थे। मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, गांव में रहता हूं। हम देखते थे, जब जयपुर मरीज आता था तो हर जांच के पांच हजार रुपये, कोई दस हजार रुपये, कोई हजार रुपये और वह मरीज रोता हुआ वापस घर पर जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने सभी जांचों को नि:शुल्क करने का काम किया। इससे अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय कोई हो नहीं सकता है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

यह बात सही है कि पक्ष और विपक्ष, निश्चित रूप से विपक्ष का काम हर काम में कमियां निकालना है। लोकतंत्र में, राजनीति में शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। जिस सिस्टम में कमी हो, विपक्ष का अधिकार भी बनता है कि उन कमियों को जरूर बताने का काम करे। सरकार का यह फर्ज बनता है कि उन कमियों को ठीक करने का काम करे। इस देश में यही शुद्ध लोकतंत्र है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम एक घर भी बनाते हैं तो उसको भी सही तरीके से पूरा करने में पांच से दस साल का समय लगता है। कभी किसी चीज की कमी है, कभी किसी चीज की कमी रह जाती है, लेकिन हम सब लोगों का एक उद्देश्य जीवन में होना चाहिए। इस लोकतंत्र की असली परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसको हम लोग कैसे लागू करें।

आम आदमी को, गरीब आदमी को किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का काम करें। निश्चित रूप से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पूरे देश में एक ऐतिहासिक योजना है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने डाक्टर्स की कमी बताई है। आपको ध्यान होगा, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि एक भी पी एच सी और एक भी सी एच सी में डाक्टर की पोस्ट रिक्त नहीं है। कल की डेट में, जो डाक्टर्स की पोस्टिंग हुई है। राजस्थान की कम्प्लीट पी एच सीज भर दी गई हैं। सी एच सीज में सिर्फ तीन पोस्ट खाली बची हैं। अभी सैक्रेटरी साहब कह रहे थे कि वे भी आज भर देंगे। कितना ऐतिहासिक निर्णय है।

जब आपकी सरकार थी। 2018 में मुझे सौभाग्य मिला, विराटनगर की जनता का प्रतिनिधित्व करने का। नहीं-नहीं, एक भी पी एच सी, एक भी सी एच सी खाली नहीं है। निश्चित रूप से, कल जो पोस्टिंग हुई है, आप लिस्ट उठाकर देखिये, कम्प्लीट पद, एक भी पी एच सी और सी एच सी खाली नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन से। व्यक्तिगत वार्ता नहीं।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): निश्चित रूप से, सिर्फ तीन सी एच सी खाली हैं। उनकी पोस्टिंग भी आज हो जायेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय है, छोटा निर्णय नहीं है। मैं जब 2018 में चुनाव जीतकर आया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 44 डाक्टर की पोस्ट थीं, जिसमें से सिर्फ 18 भरी हुई

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

थीं। सारी पी एच सीज खाली पड़ी थीं, सारी सी एच सीज खाली पड़ी थीं। आज चार हजार डाक्टर्स की भर्ती की है। उनकी पोस्टिंग करने का काम किया है। यह कोई छोटा-मोटा निर्णय नहीं है।

पहले गांवों में डाक्टर मिलते नहीं थे, कम्पाउंडर इलाज करते थे यह हम सब लोगों ने देखा है। आज गांव की पी एच सी पर एम बी बी एस डाक्टर बैठा है, पी जी डाक्टर बैठा है। सी एच सीज में डाक्टर बैठा है। आप सब लोगों को, कम से कम सारे पद भर दिये, अब तो सारे मिलकर एक बार ताली बजा दो। अब तो कम से कम टेबल बजाकर के सरकार का स्वागत आप लोगों को करना चाहिए कि सारे डाक्टर्स के पद भरने का काम किया।

सभापति महोदय, मेडिकल कालेज, आज से पांच-दस साल पहले, क्या हालात थे? डाक्टर्स की कमी रहती थी। विदेशों से एम बी बी एस करके आते थे, अन्य स्टेट्स से करके आते थे। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिला स्तर पर मेडिकल कालेज खोले। आज हमारे पास डाक्टर्स की कमी नहीं है, पी.जी डाक्टर्स की भी कमी नहीं है। सभापति महोदय, यह कोई छोटा निर्णय नहीं है। कितना शानदार काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जो जिला स्तरीय अस्पताल है, अभी डाक्टर्स की और भी आवश्यकता हम लोगों को होनी है। जिला स्तरीय हास्पिटल हैं जो तीन सौ बेडेड हैं जो मेडिकल कालेज के नोर्म्स पूरे करते हैं, जिलों के अलावा वहां भी मेडिकल कालेज खोलने चाहिये। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे कोटपूतली में तीन सौ बेड का बीडीएम हास्पिटल है, अगर उसमें मेडिकल कालेज खोल दिया जाये तो आपके एस एम एस के ऊपर जो भार आता है, हरियाणा तक का पेशेंट यहां पर आता है निश्चित रूप से उस पेशेंट को वहां पर रिलीफ मिलेगी, क्योंकि सरकार की यह मंशा है कि एस एम एस की ब्रांच आस-पास के पचास-सौ किलोमीटर के एरिया में हम लोग खोलें, ताकि एस एम एस के ऊपर भार कम रहे। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से, आप अचरोल में जगह देख रहे हैं, जे डी ए एरिया में देख रहे हैं, अचरोल में और जयपुर में क्या फर्क है? क्यों नहीं आप इसको सौ किलोमीटर दूर कोटपूतली के आस-पास खोलें, ताकि आस-पास के कम से कम तीन-चार जिलों को इसका फायदा मिले।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के आप भी पड़ोसी जिले के हो। हमारे पदमश्री से अवार्डेड महाराज नारायणदास जी महाराज का स्थान है त्रिवेणी धाम। मेरे वहां साईवाड़ पंचायत पड़ती है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): मैं लगातार पिछले एक महीने से इस बात का बजट में भी प्रयास कर रहा हूं कि महाराज श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहता है, पूरे इलाके पर रहता है। जयपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, हमारे चिमनपुरा कालेज हो, सब हमारे महाराज श्री की देन है। उनकी ग्राम पंचायत में हजारों साधु मन्दिर में रहते हैं। उस पी एच सी को मैं सी एच सी करने की मांग मैं कई दिनों से कर रहा हूं कि उस पी एच सी को सी एच सी किया जाये, ताकि चौबीस घंटे वहां डाक्टर्स उपलब्ध रहें। साधु-सन्त हजारों की संख्या में वहां पर रहते हैं, यात्री भी हजारों की संख्या में वहां पर आते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंढा, पालड़ी व बड़ोदिया में मैं पी एच सी खोलने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में दस लाख रुपये तक का बीमा हमारी सरकार ने नि:शुल्क किया है, लेकिन इसमें कमी रही है उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। हमने उसमें एक लाइन जोड़ दी दुर्घटना बीमा। सभापति महोदय, पहले बी पी एल परिवार के मुखिया की डैथ के ऊपर 75 हजार रुपये उस परिवार को दिये जाते थे, क्योंकि बी पी एल परिवार के हालात अच्छे नहीं होते तो अगर यह एक लाइन उसमें जोड़ दी जाये कि मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना में जो परिवार बी पी एल परिवार में शामिल है और उसके मुखिया की डैथ होती है तो निश्चित रूप से उसको भी बीमा का लाभ मिलना चाहिये, ताकि उन गरीब परिवारों को आने वाले समय में सम्बल मिलने का काम हो सके।

सभापति महोदय, इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ई डब्ल्यू एस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ नि:शुल्क दिया जाना प्रस्तावित किया है कि ई डब्ल्यू एस के सभी परिवारों को मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना का नि:शुल्क लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जब ई डब्ल्यू एस को आप दे रहे हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिये कि गरीब सवर्ण को उसका हक मिलना चाहिये तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि एम बी सी वर्ग को भी उसमें जोड़ा जाये। एम बी सी एक बड़ा समुदाय राजस्थान में है, गरीब तबके के लोग हैं, किसान परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, उनको भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क रूप से शामिल किया जाये। सभापति

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

महोदय, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है पूरे राजस्थान के कोने-कोने में फैला हुआ है उनको भी अगर इसमें शामिल किया जाये तो सब एम बी सी वर्ग के लोग सरकार के प्रति आभारी भी रहेंगे। निश्चित रूप से हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि गांव के गरीब तबके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना में हम लोग जोड़ें, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार कि अचानक आदमी बीमार हो जाता है और वह इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। उसमें तीन महीने का प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस को भी थोड़ा जल्दी किया जाये तो इसका भी फायदा हम सब लोगों को मिलेगा।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोग सब-सेन्टर खोल रहे हैं, लेकिन एक-एक ग्राम पंचायत के गांव में पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर का डिफरेंस है तो अगर बड़े राजस्व गांवों में भी हम लोग सब-सेन्टर खोलने का काम करें तो उन गांवों को भी इसका फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सूचना

बाड़मेर में होली के त्योहार पर धारा 144 लागू किया जाना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। सभापति महोदय, होली का त्योहार रंग-बिरंगा त्योहार, सद्भाव का त्योहार है और कल के बाद हम सब लोग भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में होली मनाने जायेंगे। बाड़मेर कलेक्टर साहब का एक आदेश मेरे हाथ में है। आदेश क्रमांक प.16/147/न्यायिक/2023/1005, इन्होंने बाड़मेर में 2 मार्च के रात्रि बारह बजे से 12 मार्च के रात्रि बारह बजे तक धारा 144 लगायी है। होली पर धारा 144 लगाना, बाड़मेर जिला कलेक्टर का यह कृत्य होली का त्योहार जो रंग-बिरंगा त्योहार है, यह हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। आप आसन पर विराजे हैं और सर्व धर्म सद्भाव के आप प्रतीक हैं। आप सरकार को कहिये कि जवाब दे। अगर इस प्रकार धारा 144 लगेगी हमारे त्योहार पर तो हम किस प्रकार अपने धार्मिक आचरणों को पूरा कर पायेंगे? इसलिये मैं आपके संज्ञान के माध्यम से मंत्री महोदय, यहां हैं नहीं पर ये वन मंत्री जी बैठे हैं उसी इलाके से आते हैं, यह धारा 144 कलंक है इस सरकार पर।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर मैं मेरी बात रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान की कल्पना की। राजस्थान के तमाम निवासी निरोगी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां विराजे हुए नहीं हैं, जब हमारे अस्पताल सारे खाली रहेंगे, डाक्टर्स खाली रहेंगे, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी सी एच सी, पी एच सी सभी भर दी गयी हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की यदि बात करूं तो वहां सी एच सी, राजलदेसर के अन्दर चार पद आज भी खाली पड़े हैं। छापर सी एच सी की घोषणा हो गयी पर वहां पर एक भी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गयी है। दो डाक्टर्स के सहारे...

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): कर दी। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): नहीं हुई है भाई इन्द्राज जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। आप आसन को बतायें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, कैसे हम इस राजस्थान की निरोगी राजस्थान की कल्पना कर सकेंगे, जब आपके पास में बार-बार हम मिलते हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय से मिलते हैं, मुख्य मंत्री जी से मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि डाक्टर बता दो कौन-सा कहां से डाक्टर लगायें। हमारे पास में डाक्टर थोड़े ही हैं? डाक्टर्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है।

चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं गईं। इसमें केन्द्र के पैसे के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, आप मत करो आपकी सत्ता यहां पर है, आप जैसे भी आपका ध्यान जिस तरह भी जाये, करो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? चिरंजीवी योजना की मॉनिटरिंग में राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हो गयी है। जिस उद्देश्य के साथ में यह योजना लागू की गयी है, यह पूरी तरह से फेल है।

प्राइवेट हास्पिटल वाले चिरंजीवी योजना वालों का इलाज करने से कतराते हैं। प्राइवेट हास्पिटल्स के ऊपर एक तलवार लटका दी गयी है। प्रवर

(श्री अभिनेश महर्षि)

समिति के अन्दर वह मसला है। ऐसी स्थिति में जब तक उसका निर्णय करके आप लोग प्राइवेट हास्पिटल्स को कान्फिडेंस में भी नहीं लोगे, वे वहां पर जाते हैं, मेरे से पूर्व कई वक्ता बता भी रहे थे, जाने के बाद उनको भर्ती करने के बाद में धीरे-धीरे उनके साथ में वह हाल किया जाता है कि दुबारा कभी प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य कोई योजना, हो वह व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है। सरकारी अस्पतालों के हालात के तो मैं जिक्र करूं तो यह इतना लम्बा-चौड़ा पुलिन्दा है जो बार-बार समय-समय पर चाहे वह राजस्थान पत्रिका हो, चाहे भास्कर अख़बार हो, उन सब बड़े पेपर्स में इस सरकार की पोल, कलई कई बार खोली है। अख़बार ही इस सरकार की कलई नहीं खोल रहे हैं, बल्कि मेरे सामने बैठे हुए सत्ता पक्ष के अनेक विधायक साथियों ने भी चाहे वह दबी जुबान के अन्दर खोली हो, चाहे डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी हों और चाहे हमारे सभापति पैनल के माननीय चन्देलिया साहब हों, सबने इस सरकार की कलई खोलने की बात की है और इनके ऊपर उनकी भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक साल में जनता क्लिनिक की बात की थी। तीन साल में एक भी जनता क्लिनिक नहीं। मैं मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, अभी हमारी माननीय मनीषा जी यहां पर बैठी हुई नहीं हैं मनीषा जी, अच्छा होता आप बात करतीं, आपके हाईफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की जो हमने पाठ्यक्रम के अन्दर उनको शामिल किया था। वो हमारे हीरो थे। उनकी बात को इस सरकार ने आते ही पाठ्यक्रम से हटा दिया। अच्छा होता, आप जोधपुर की वह बात करतीं। अच्छा होता, रावणा राजपूत समाज जिस समाज से आप भी आती हैं, आज सड़क के ऊपर इस सरकार को रो रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनकी मांगों पर सुन कर उनके ऊपर फैसला करवाती, तब तो मैं समझता कि आप न्याय कर रही हैं, नहीं तो निश्चित रूप से आप सरकार को बचाने के लिए जिस तरह से बातें कर रही थीं, ये सब असत्य बातें थीं।

जनता क्लिनिक की बात हम लोगों ने की। पचास करोड़ रुपये का घोटाला हो जाता है और सरकार आंख बंद करके बैठी रहती है। पी बी एम हास्पिटल का, यह अख़बार के अन्दर कटिंग है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जिसमें रेडिएशन थैरेपिस्ट नहीं 6 महीने से, मशीनें लगा दीं। मेरे रतनगढ़ में ट्रोमा सेन्टर बनाया, मशीनें लगा दीं, लेकिन उसके बाद में डाक्टर्स नहीं। उसके ऊपर

(श्री अभिनेश महर्षि)

ताला लगा दिया और जो मशीनें थीं, लाखों-करोड़ों रुपये की मशीनें धूल फांक रही हैं। यह पत्रिका और नवज्योति की खबर है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन फिजिशियन नहीं, 6 महीने से गामा मशीन धूल फांक रही है। यह सरकार का नमूना है। इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मेडिसिन और वायरोलॉजी कागजों में रह गई। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि समय कम रहता है। राठौड़ साहब, बड़े आपरेशन में चीरा लगाने वाली 14 लाख की मशीन ओ टी से चोरी हो गई। बच्चों को कुत्ते उठा कर ले जाएं, नोच-नोच कर खा जाएं और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाये। करीब 2/3 घोषणाएं अभी अधूरी हैं। ये सारी खबरें हैं। मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। ये वे खबरें हैं जो अखबारों में और प्रेस मीडिया में आई हैं। यदि मैं यह सब बताने लगूं तो एक घंटा लगेगा।

आर जी एच एस में दवाओं की बात करें, आज आर जी एच एस में कोई व्यक्ति दवा लेने जाता है तो वे कहते हैं एक दवा तो हमारे पास है, बाकी दवाई नहीं है। क्यों नहीं है? वह धीरे से कहते हैं एम एल ए साहब, आप हमारी बात उठाओ, हमारा तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है। 9-9, 10-10 लाख रुपये उनका बाकी पड़ा रहता है, इसलिए वहां पर दवा नहीं मिलती है। मरीज इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।

मंत्री महोदय, रतनगढ़ में जिला अस्पताल तो खोल दिया, लेकिन जिला अस्पताल खोलने के बाद उसमें सारे पद खाली पड़े हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, मेरे यहां 5 स्पेशलिस्ट डाक्टर के पद खाली हैं। 40 में से 25 पद खाली हैं। अन्य चिकित्साकर्मियों के 50 पद खाली पड़े हैं। सब सी एच सी, पी एच सी खाली पड़ी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रेम नगर और छाबडी मीठी ढाकावाली में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाये। बहुत महती आवश्यकता है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पी एच सी में क्रमोन्नत किया जाये। गोरीसर, जेगणिया बिदावतान, परसनेऊ को पी एच सी में क्रमोन्नत किया जाये। लाडसर को सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाये और राजकीय अस्पताल और आदर्श सी एच सी राजलदेसर, अब आदर्श सी एच सी की बात करें, निश्चित रूप से आदर्श सी एच सी खोलने के लिये सरकार ने दिशा-निर्देश दिये। आदर्श सी एच सी खोल तो दी, हमने भी अनुशंसा कर दी कि

(श्री अभिनेश महर्षि)

राजलदेसर को आदर्श सी एच सी बनाओ। पिछले दिनों मैं वहां पर जाकर आया था, आप लोगों को अखबारों में भी पढ़ने को मिला होगा, वहां पर एक डाक्टर के सहारे उस आदर्श सी एच सी में सारा काम चलता है। पानी भर गया, मशीनें खराब हो गईं, यह आदर्श सी एच सी है इस सरकार में। दाउदसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक और चिकित्साकर्मियों के खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिये।

सभापति महोदय, कोरोना काल में सी एच ए ने अपनी जान जोखिम में डाल कर काम किया था, उनके बारे में भी सरकार जल्दी से जल्दी फैसला लेकर उनका भी निदान करे।

कोरोना काल का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आप लोगों को पेश करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मैं स्वयं कोरोना से ग्रस्त हो गया था। सीतापुरा के आर यू एच एस अस्पताल में मैं 17 दिन तक भर्ती रहा। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता +++ का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बढ़िया डाक्टर हैं। मैं +++ की एक बानगी जो मेरे साथ घटित हुई है, वह बताना चाहता हूं। विधायक था, रात को डेढ़-दो बजे टीम के साथ आते थे। How are you MLA Sahab? I am fine. चले जाते थे। एक दिन अचानक सुबह-सुबह 15-20 डाक्टर के साथ मेरे बेड पर पहुंचे। मैं डर गया, क्या हो गया, उन्होंने पूछा ठीक हो? मैंने कहा बिलकुल ठीक हूं। रिपोर्ट पर उन्होंने लाल गोला कर रखा। मैंने कहा कि क्या हो गया, आप इतने घबराये हुए क्यों हो? मेरे घर वालों को सूचित कर दिया, सबके फोन आने लग गये। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मुझे क्या है? दो इंजेक्शन उन्होंने ठोक दिये, सारी डोज देने के बाद दो इंजेक्शन और लगाये। मैंने कहा, कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा रुकिए, रुकिए आप बोलिए मत एम एल ए साहब। +++ 15 फीट दूर खड़े हो गये, उसके बाद बोले Tocilizumab लाओ। एक Tocilizumab ठोक दिया। दोनों हाथ में लगा दिये। मैंने पूछा क्या हो गया, सब ठीकठाक तो है? मंत्री महोदय, उस डाक्टर की बानगी बताता हूं। उन्होंने उसके बाद इतनी दवाएं दीं कि मेरा जी घबराने लगा, मैंने कहा कि हो क्या गया? थोड़ी देर के बाद दो डाक्टर की निगरानी में छोड़ कर चले गये। नर्सिंगकर्मी से मैंने मेरी शीट मंगवाई। उसके ऊपर एक अभिषेक नाम के व्यक्ति की रिपोर्ट थी। जिसमें डी-डाइमर 700 था, उस डी-डाइमर को देख कर +++ ने, मैं इस पवित्र सदन में कह रहा हूं, उसने मेरे साथ इतना अन्याय किया, इतने इंजेक्शन ठोक दिये जिसको मेरा शरीर आज

(श्री अभिनेश महर्षि)

तक झेल रहा है। उसके बाद मैंने +++ को फोन किया। मैंने कहा, where are you +++? सर, मैं यहां पर हूं। मैंने कहा come fast. तुरंत आए। आने के बाद मैंने कहा +++ क्या मतलब? मैंने कहा... (व्यवधान) आप ठहरिए, मैं बिलकुल सही कह रहा हूं... (व्यवधान) मैं नाम लेकर कह रहा हूं... (व्यवधान) सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो... (व्यवधान) सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए, ...(व्यवधान) विराजिए। जो रेलेवेंट पार्ट है, उसको हटा दें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ...(व्यवधान) आप सुनिए, सच्चाई स्वीकार करो आप।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए, प्लीज परम्पराओं का निर्वहन करें। विराजिए, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जिसके साथ हुआ है, वह जानता है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आसन पैरों पर है। विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। जो भी रेलेवेंट पार्ट है, सब विलोपित कर दो और माननीय सदस्य, अब आप सब्जेक्ट पर बात करें। आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, यह बताने की जरूरत नहीं है। सारा विलोपित करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सारा विलोपित कैसे कर सकते हैं आप?

श्री सभापति: मैंने कर दिया विलोपित।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आपने कर दिया, क्या मतलब हुआ? आप तो सब कुछ कर दीजिए।

श्री सभापति: बिलकुल नहीं, आसन के साथ ऐसा व्यवहार कतई निंदनीय है। आपको अपनी बात रखनी है ...(व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ जी... (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जिसके साथ घटना होती है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। +++ ने यह कह दिया, +++ ने वह कह दिया, क्या मतलब है इन सब बातों का? कोई छोटी-मोटी बात आपके साथ हो गई, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपने संज्ञान में ला दिया। मंत्री जी इस बात की जानकारी ले लेंगे। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आसन सर्वोपरि है, आसन को सब अधिकार प्राप्त है। सभापति महोदय, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। सभापति महोदय, आप उस मानसिकता को नहीं जानते, जब इनके परिवार के लोगों ने वहां पहुंचने से पहले मुझे टेलीफोन किया तो मेरी आंखों में आंसू इसलिए निकल पड़े कि उन्होंने कहा कि अब आपका साथी जाने वाला है। इन्होंने यह आपबीती सुनाई, इस पर उत्तेजित होने की क्या बात है? डाक्टर ने दूसरे की शीट के आधार पर इनके इंजेक्शन लगा दिये... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): दूसरे की रिपोर्ट देखकर। लापरवाही डाक्टर की है। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ...(व्यवधान) इन्होंने कहा +++ के कहने पर, यह क्या बात कर रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज आप विराजिए, विराजिए। आपने अपनी बात संज्ञान में ला दी, मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं। मंत्री जी ने सुन लिया, अपने आप इस बात पर कार्यवाही करेंगे। मैं इससे ज्यादा आपको इस मामले में चर्चा करने की इजाजत नहीं देता। आप अपनी बात रखें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वह मंजर मैंने देखा है, इसलिए मैंने कहा और मेरे ऊपर जो घटना घटी, किसी और दूसरे के साथ घटती, मैं डाक्टर की लापरवाही बता रहा हूं कि किसी दूसरे की रिपोर्ट देखकर..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया, अब आपको आगे कोई बात करनी है या इसी पर डिबेट होगी? समय की सीमा है, 50 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि इसी तरह से आप हाउस को हाईजैक करेंगे तो अपनी बात रख नहीं पायेंगे। आप अपनी बात रखें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सी एच सी और पी एच सी के भवन हैं उनके लिए बजट में घोषणा की गयी थी तो उनमें जो भवन बनने हैं, उन भवनों को तुरन्त बनाया जाना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार की बाकी सब चीजों, चूंकि यह लम्बा काम हो गया, लेकिन एक बात कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा कि ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन का एक पत्र मुझे मिला है। इसके अन्दर व्याख्याता, टीचिंग स्कूल और बाकी सारे लोगों को ये गजेटेड आफिसर मानते हैं और इन नर्सिंग ट्यूटर्स को नहीं मानते हैं। ये भी समान वेतनमान में काम करते हैं, बाकी सारी चीजें हैं। इनके साथ में यह अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए भी इनको गजेटेड के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें, जो कि मैंने पहले भी रखी हैं, सीटी स्कैन और सी आर एम मशीनरी। रतनगढ़ का जिला अस्पताल है, उनके अन्दर ये लगायी जानी चाहिए। डायलिसिस के लिए सरकार की भावना और मंशा है कि रतनगढ़ अस्पताल में, छापर सी एच सी, राजलदेसर के अन्दर और जो सी एच सी हैं, उनके अन्दर सरकार की भावना के अनुसार वहां पर डायलिसिस मशीन लगाकर डायलिसिस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहां पर निश्चेतन की व्यवस्था नहीं है। जहां पर आपरेशंस नहीं होते हैं, जरूरत नहीं है, वहां पर डाक्टर है। वहां से उनको हटाकर जहां पर आपरेशन थियेटर हैं, वहां पर डाक्टर्स लगाये जाने की मांग करता हूं।

ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक, 2008 तक के जो संविदाकर्मी हैं, आज तक कैडर में दर्ज नहीं हुए हैं, प्रमोशन नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं मांग करता हूं। 2013 की भर्ती की बात मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने भी कही है। उन सबको भी मैं शामिल करते हुए, माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2013 के बाद चाहे सरकार हमारी रही हो, लेकिन अब तो चार साल से आपकी सरकार है तो उसके ऊपर निर्णय करें। सी एच सी स्तर पर होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा भी यदि आप उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें तो यह पद्धति भी कारगर है। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री वीरेंदर सिंह।

श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आज की अनुदान की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस बजट में एक उप

(श्री वीरेंदर सिंह)

जिला अस्पताल, दो पी एच सी, दो सी एच सी स्वीकृत करने के लिए मैं मेरी और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। खाटूश्याम जी का जो विश्व प्रसिद्ध मन्दिर है उस ग्राम में उप जिला अस्पताल जो कि सरकार ने दिया है, उससे आसपास के ग्रामीणजनों के अलावा देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। पिछले बजट में पलसाना में ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की थी, जिसका कार्य जल्द आरम्भ होने वाला है, उसके लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज लोगों के मन में जो भय था कि इतना महंगा इलाज किस तरह से अपने परिवार के जनों के लिए करा पायेंगे, उसके लिए चिरंजीवी योजना में 10 लाख के इलाज को बढ़ाकर 25 लाख की जो नजीर मुख्य मंत्री महोदय ने पेश की है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इसमें मेरा एक सुझाव है कि हड्डी रोग विभाग, नाक-कान-गला विभाग और सर्जरी विभाग में एम आर आई पैकेज नहीं होने के कारण चिकित्सक दवाइयों के पैकेज लगाते हैं, जिसके कारण पैकेज निरस्त हो जाते हैं। एम आर आई पैकेज को शामिल करने से यह असुविधा दूर हो सकती है। चिरंजीवी योजना में कुछ कमियां हैं, उनके लिए लोगों के सुझाव हैं कि 1 फरवरी से मरीजों के रिकार्ड को अपलोड करने के लिए नया पोर्टल चालू किया गया था, जिस पर बार-बार प्रयास करने पर भी क्लेम अपलोड नहीं किया जा सका। प्राइवेट अस्पतालों में योजना के तहत इलाज नहीं हो पाने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भार बढ़ गया है और मरीजों के अनुपात में चिरंजीवी काउंटर्स की संख्या कम होने कारण समय पर क्लेम सब्मिट नहीं हो पाते हैं। योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से मरीजों से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड पोर्टल पर सब्मिट किये जाने के बावजूद कोई न कोई कमी निकालकर क्वेरी बीमा कम्पनियों की तरफ से भेज दी जाती हैं। बहुत बार क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उपरोक्त समस्याओं के चलते मरीज समय पर डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, उसके कारण से अस्पतालों में मरीजों का दबाव रहता है। सरकारी अस्पतालों का क्लेम भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बीमा कम्पनियां सीधा-सीधा फायदा उठा रही हैं। इसके लिए हर वार्ड में चिरंजीवी का पृथक से काउंटर हो। पोर्टल 24 घंटे सुचारु रूप से चलाया जाये, जिससे मरीजों का सम्पूर्ण रिकार्ड सही वक्त पर अपलोड किया जा सके। बीमा कम्पनियों की

(श्री वीरेंदर सिंह)

प्रभावी मॉनिटरिंग हो, जिससे अनावश्यक आपत्ति न लगायी जाकर क्लेम को रद्द नहीं किया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाय कस्बा है। उसके आसपास 9 ग्राम पंचायतें लगती हैं। वहां पर वर्तमान में सिर्फ एक पी एच सी जो कि बाय में है, बाकी 8 पंचायतों में चिकित्सा के सब-सेन्टर ही हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी पी एच सी बाय है, उसको सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाये। यह मेरी आपसे मांग रहेगी। उसके साथ हमारे करड़ और भोजा की ढाणी में पी एच सी स्वीकृत करने की मेरी मांग रहेगी।

मैं सीकर जिले से आता हूं। सीकर जिला एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हुआ है। अभी विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अगर विराटनगर में मेडिकल कालेज हो तो जो दबाव आपके एस एम एस और जयपुर में है, वह दबाव कम होगा। निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूं। आज जयपुर में हरियाणा का काफी सारा इलाका जो कि हमारे राजस्थान से लगता है, जो हमारे सीकर जिले से लगता है। निश्चित रूप से अगर सीकर जिले में मेडिकल कालेज है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, उन्हें अगर अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छे सीनियर डाक्टर्स मिले और अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिले तो जैसे एजुकेशन हब सीकर बना है, उसी तरीके से सीकर मेडिकल हब भी बन सकता है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सरकार का आखिरी बजट है। इससे पूर्व सरकार ने चार बजट पेश किये हैं और आपसे पूर्व जो कि विभाग का कार्य देख रहे थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बराबर में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से माननीय सदस्य बोल रहे थे। पिछले चार बजट में जिले में मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में एक रुपये का भी बजट नहीं दिया है। हर बार मैं मेरे क्षेत्र के लिए मांग करता रहा हूं। पड़ोसी होने के नाते, मुझे कहते थे कि आपको जरूर कुछ न कुछ दूंगा। ट्रोमा हास्पिटल दूंगा, मैंने जो भी मांग की, वह दूंगा पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया।

(श्री कन्हैया लाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस विचारधारा के लोग भी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी रहते हैं। उन लोगों ने आपके विभाग में आकर कई बार यह मांग की। मैं आपसे कई मांगें करना चाहता हूं, उनमें से आप एक-दो मांग भी पूरी कर देंगे तो उन लोगों का भी मान-सम्मान रह जायेगा।

आप लोगों से मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से दो स्टेट हाईवे निकलते हैं। एक सांगानेर से भीलवाड़ा जाता है और एक दूदू से छाण जाता है। इन पर आये दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, खूब एक्सीडेंट होते रहते हैं। उनको इमरजेंसी में या तो टोंक ले जाना पड़ता है या जयपुर लाना पड़ता है। कई लोगों की डैथ हो गयी। अगर थाने से रिकार्ड निकालेंगे तो इतनी ज्यादा डैथ हुई हैं शायद कहीं भी नहीं हुई है। उनकी सुविधा के लिए मेरे मालपुरा में जिला अस्पताल नहीं तो ट्रोमा हास्पिटल और ब्लड बैंक हो जाये तो कम से कम उन लोगों की जान बचे।

इसके साथ-साथ बेड वृद्धि। आज डेली एक हजार से ज्यादा की ओ पी डी आती है। बेड्स के लिए कोई वार्ड नहीं है। करीब 50-75 बेड का हास्पिटल है और 50 एन आर एच एम के तहत। हमने कई बार प्रपोजल भेजे हैं। जब एक्स ईएन, एन आर एच एम से पूछता हूं कि हमारे प्रपोजल क्यों नहीं जा रहे हैं तो राज्य सरकार से केन्द्र में नहीं भिजवा पा रहे। उनमें भी पूरा भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कम से कम बेड तो बढायें। जो 75 बेड हैं, उनको 100 करें। टोडारायसिंह में जो 50 बेड हैं, पिछली हमारी सरकार में जो 30 बेड थे, उनको 50 बेड किया। वहां भी हास्पिटल जर्जर होने की स्थिति में है। उसको 75 बेड किया जाये। नवीन भवनों के निर्माण के लिए भी दोनों जगह पर न तो डाक्टर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स हैं, न वार्ड है। इसके साथ-साथ पिछली सरकार में डिग्गी में पी एच सी से सी एच सी किया था, वहां भी आज वही स्थिति है। बिल्डिंग का बजट आ गया, पांच साल में बिल्डिंग तो बन गयी पर उसके अन्दर सुविधा कुछ भी नहीं है। सी एच सी होने के बाद दो डाक्टर्स बैठते हैं। वहां पर जो भी पद हैं, उनको पूरा भरा जाये।

इसके साथ-साथ टोडारायसिंह स्वास्थ्य केन्द्र के अंदर सर्जन की पोस्ट नहीं है, न एनेस्थिसिया है। अगर ये दोनों पद भी सृजित किये जाएं तो ये उप खण्ड क्षेत्र का बड़ा हास्पिटल है, सब लोगों को फायदा मिलेगा। रिक्त पदों को भरा जाए। कलमंडा जो पहले मेरे पी एच सी थी, वह पी पी पी मोड पर चली

(श्री कन्हैया लाल)

गयी थी। अब वह पी पी पी मोड से हट गयी है। इस वजह से वहां पर जितने भी पद हैं, चाहे ए एन एम हों, चाहे जी एन एम हों, चाहे डाक्टर्स के हों, ये पद भी हमारे भरे जाएं।

सभापति महोदय, टोडारायसिंह का हमारा 50 बेड का जो हास्पिटल किया, उसके साथ-साथ डाक्टर्स के पद तो बढ़ा दिए, लेकिन राज्य सरकार की जांचें करने के लिए जो भी पद थे, जांच करने वाले लगभग 07 पद थे, उनको विलोपित कर दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो पद थे, उनको वापस किया जाए, ताकि राज्य सरकार की जो भी जांचें होती हैं, वे उनको समय पर मिले।

अभी जो बात आयी थी कि विधायक मद से हम एम्बुलेंस देते हैं, एम्बुलेंस तो हमने दे दी, लेकिन उसको चलाने के लिए ड्राइवर की कहां से व्यवस्था करें? कहां से उनकी सैलेरी दें? मंत्री महोदय, इसकी व्यवस्था भी करें। विभिन्न जांचों को करने के लिए जो मशीनों की आवश्यकता है, जैसे आज टोडारायसिंह और मालपुरा के अंदर सोनोग्राफी मशीन नहीं है। उप खण्ड के काफी बड़े हास्पिटल हैं। 100-100 बेड के हास्पिटल हैं, उनके पास सोनोग्राफी मशीन नहीं है।

सभापति महोदय, डिग्गी जो सी एच सी खोली है, उसके अंदर डिजिटल एक्स-रे मशीन भी देनी चाहिए। पिछले कोरोना के बाद में हमने विधायक मद से करीब 3 करोड़ रुपये के उपकरण मेरे पी एच सी व सी एच सी पर और हर जगह पर चाहे जनरेटर लगाने का हो या जो भी उनकी डिमांड थी, वह कर दी। बड़ी जो मशीनें हैं, वह राज्य सरकार के द्वारा कराई जाए। मालपुरा हास्पिटल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहां 12 डाक्टर के पद हैं। इनमें से 3 डाक्टर परमानेंट डेपुटेशन पर कैम्पों के हिसाब से टोंक में लगा रखे हैं। वहां डेली 1000 के आसपास ओ पी डी आती है तो या तो नये पद बढ़ाए जाएं या उन तीनों पदों के डाक्टर्स का जो टोंक में डेपुटेशन कर रखा है, वह कैंसिल किया जाए, ताकि समय पर मरीजों का उपचार किया जा सके।

इसके साथ-साथ बिजली के बिलों के लिए आज पी एच सी पर अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह पर तो कनेक्शन काट दिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिए अलग से कोई बजट दिया जाए जिससे बिजली के बिल जमा करवाकर उनको वापस चालू किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर पिछले चार साल से जो मैं मांग कर रहा हूं, मेरे

(श्री कन्हैया लाल)

काफी बड़े गांव हैं, जैसे पारली है, उनियारा खुर्द है, मोर है, इन गांवों के अंदर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, कई ऐसे बड़े कस्बे हैं, जिनकी 15 से 20 हजार के आसपास आबादी है, उनके अंदर अभी पी एच सी है। अगर इनके आसपास के गांवों की, पंचायतों की आबादी जोड़ें, जैसे लांबा हरिसिंह है, पचेवर है, लावा है, डिग्गी है, नगर है। मांदोलाई आज लगभग तीस साल पुरानी पी एच सी है, इसके आसपास भी काफी ग्राम पंचायतें हैं। इन जगहों को अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदला जाए तो फायदा मिलेगा। इनमें से कोई सी भी एक मांग भी आप पूरी करेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ 2008 के अंदर हमारे कई उप स्वास्थ्य केन्द्र थे, जो एडपोस्ट पर चल रहे थे, उनका पद तोड़ दिया गया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पद भर दिए जाएं। इनमें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अच्छी नयी बिल्डिंग्स हैं। सवारा है, पथराज कलां है, झाडरी है, बासेड़ा है, चैनपुरा पंचायत है, इनके अंदर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें तो उन लोगों को, काफी बड़ी आबादी की पंचायत है, इन लोगों को भी फायदा मिलेगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशा-सहयोगिनी वगैरह जो हैं, कुछ इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये महिलाएं बहुत सेवा करती हैं। जब भी हमारे पास आती हैं तो कहती हैं कि दो-चार हजार रुपयों के अंदर हम क्या करें? पूरा दिन हम घर से निकल जाते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं। राज्य सरकार इनके बारे में भी सोचे। ये काफी बड़ी संख्या के अंदर हैं। इनके घर का लालन-पालन इनसे होता है।

सभापति महोदय, नर्सिंग आफिसर, जी एन एम का पदनाम करने की जो बात थी, वह भी किया जाए। इनको भी एक मान-सम्मान मिलेगा। कोरोना के अंदर इन सबने मिलकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इनके आत्म सम्मान के लिए इनका पदनाम बदला जाए। पहले जो एल एच वी, ए एन एम वगैरह इनका जो पे-ग्रेड था, ये 3600 रुपये किया जाए, जैसे थर्ड ग्रेड के अध्यापक का है। बिहार, केरल, पंजाब और हरियाणा के अंदर कैडर के हिसाब से इनको मिलती है तो यहां पर भी इनका ये काम किया जाए।

मंत्री महोदय, मैं आपसे ये ही निवेदन करता हूं कि हमारे लोगों का मान रखने के लिए कोई भी एक मांग जो मैंने बताई, वह की जाए तो हमारे लोगों का बहुत भला होगा। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा की मांग के ऊपर मैं बोलता हूं। ये दोनों मांगें स्वीकृत की जाएं इसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में इतने बड़े ग्रामीण इलाकों में, दूर-दराज इलाकों में विस्तार आज से पहले कभी नहीं था। प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर तक सब-सेंटर को स्थापित करना। इसके अलावा कई बड़े-बड़े गांवों में भी सब-सेंटर खोले गये।

इसके साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान, जो रेगिस्तानी इलाका है, इसके साथ हमेशा से, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे बिजली हो, इसमें न्याय इनको नहीं मिलता है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से वह एरिया सबसे लंबा-चौड़ा है और आबादी उस एरिया में दूसरे एरियो से कम है। शिक्षा का स्तर वहां का कमजोर होने से डाक्टर, कम्पाउंडर, जी एन एम, ए एन एम भी उस एरिया के स्थानीय बहुत कम आते हैं। पूर्वी राजस्थान और जयपुर के आसपास के जिलों के लोग वहां तैनात होते हैं। ज्यों ही उनकी सर्विस कन्फर्म होती है, वे तबादला करवाकर वापस इस एरिया में आते हैं और वहां खाली स्थानों की यथास्थिति रहती है। ये वहां के लोगों के साथ न्याय नहीं है। इसके लिए सरकार को या तो कानून में ये परिवर्तन करके स्थानीय लोगों के कोई बोनस नम्बर दिए जाएं जिससे वहां के लोग तैनात किये जा सकें या फिर तबादलों पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। वहां पर अध्यापक, डाक्टर, कम्पाउंडर, जी एन एम, ए एन एम के तबादले न हों तो लोगों को राहत मिल सकती है, नहीं तो हमेशा की तरह वहां की खाली स्थिति का लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा।

इसके साथ मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की छोटी-सी दो बातें रखता हूं। मंत्री जी, आप कृपा करके उनको स्वीकार करें। एक तो तहसील गडरारोड में हरसानी पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करें और दूसरी खरीफा की बावड़ी पी एच सी को सी एच सी की जाए। दूसरा, ये आयुर्वेद विभाग के जो डाक्टर्स हैं, शुरू से वैद्य और डाक्टर आते रहते हैं और वहां रहे हैं। आजकल आयुर्वेद और होम्योपैथिक डाक्टर्स की वहां बहुत कमी है। कमी क्या, उनका नंबर करीब-करीब जीरो है। इसलिए इन दो संस्थाओं के भी वैद्य, हकीम या डाक्टरों की तैनातगी की जाए। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात खतम करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। आज प्रदेश के हर गरीब, किसान, दलित, वंचित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सुविधा चरमराई हुई है व्यवस्था सही नहीं है। सी एच सी और पी एच सी के अंदर डाक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है।

भोपालगढ़ विधान सभा के अन्दर चार सी एच सी हैं, एक उप जिला हास्पिटल है। सी एच सी की बात करें, आसोप सी एच सी के अन्दर 5 स्वीकृत पोस्ट हैं, लेकिन एक भी डाक्टर नहीं है। सी एच सी, बावड़ी 8 पोस्ट है, 3 डाक्टर हैं, वे भी मेडिकल आफिसर है, बावड़ी के अन्दर एक भी विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है।

भोपालगढ़ मुख्यालय पर उप जिला हास्पिटल है, वहां बहुत ज्यादा मरीज आते हैं। भोपालगढ के अलावा एडजोइनिंग नागौर ज़िले के गांव हैं, वहां के मरीज भी भोपालगढ़ उप जिला हास्पिटल के अन्दर ही आते हैं। वहां भी स्वीकृत पोस्ट 28 हैं, लेकिन उनमें 8 डाक्टर हैं। किसी तरह की जांच की सुविधा नहीं है। बनाड़ सी एच सी, उप जिला हास्पिटल भोपालगढ़, इन दोनों हास्पिटल के अन्दर सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन आपरेट करने वाले डाक्टर नहीं हैं। सरकार की महत्वूपर्ण योजना, नि:शुल्क जांच योजना के अन्दर मरीज आते हैं। इसमें आपरेट करने वाले डाक्टर नहीं हैं, जिससे लोगों को इस सोनोग्राफी मशीन की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लोग भटक रहे हैं। प्राइवेट हास्पिटल में जाकर 1,500 से 2,000 रुपये तक में सोनोग्राफी करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि सी एच सी बनाड़ उप जिला हास्पिटल भोपालगढ़ में सोनोग्राफी मशीन तो है लेकिन आपरेट करने वाले डाक्टर नहीं हैं। अत: वहां डाक्टर लगाने की व्यवस्था करवाएं।

सभापति महोदय, नई क्रमोन्नत सी एच सी, रतकुडिया में भवन निर्माण की जल्दी स्वीकृति दिलाएं। वहां भी डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ लगाकर, सी एच सी स्तर के संसाधन हैं, वह प्रोवाइड कराएं तथा उसको शुरू कराएं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सालवा कलां पी एच सी है। बड़ी ग्राम पंचायत है। सालवा कलां के 25 किलोमीटर एरिया के अन्दर कोई दूसरी सी

(श्री पुखराज)

एच सी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सालवा कलां पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत कराएं।

बनाड़ सी एच सी, तीन नेशनल हाईवे से जुडी है। जयपुर नेशनल हाईवे, बनाड़, कुचेरा नेशनल हाईवे, जोधपुर-नागौर नेशनल हाईवे। एक रिंग रोड से जुड़े हुए हैं। वहां पर ट्रोमा सेंटर नहीं है। आये दिन नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं, मरीज बनाड़ सी एच सी में प्राथमिक उपचार हेतु लाए जाते हैं। ट्रोमा सेंटर नहीं होने से, लोगों को वहां दिक्कत होती है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि बनाड़ सी एच सी के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोला जाए।

पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बावड़ी में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की, लेकिन वहां अभी किसी तरह का कार्य चालू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ट्रोमा सेंटर का कार्य शुरू करवाया जाए। नेशनल हाईवे जोधपुर-नागौर है, उसमें जोधपुर से 75 किलोमीटर तक दूसरी कोई सी एच सी या चिकित्सा सुविधा नहीं है। इस रोड पर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो प्राथमिक उपचार के लिए बावड़ी सी एच सी पर लेकर आते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की काफी ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन नजदीक में पी एच सी नहीं है। वहां सब-सेंटर है। ग्राम पंचायत साथिन, ग्राम पंचायत बुडकिया, ग्राम पंचायत रूधिया और ग्राम पंचायत हीरादेसर, इसमें सब सेंटर को क्रमोन्नत करके पी एच सी बनाने के लिए मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, सरकार का संकल्प है, निरोगी राजस्थान। सरकार राइट-टू-हेल्थ लाने की बात कर रही है। ये दोनों सरकार के संकल्प हैं। इनको धरातल पर लाने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोगों को इसका फायदा मिले, इसकी सुविधा मिले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा। हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर, दूर-दराज एरिया के अन्दर ग्राम पंचायत है, उस हैडक्वार्टर पर, सब सेंटर खोलने के लिए मंत्री जी से मांग करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

(श्री गिरधारीलाल)

महोदय, पूर्व बजट में सरकार ने डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की, इसके लिए सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीडूंगरगढ़ मुख्यालय पर सी एच सी संचालित है, सी एच सी को क्रमोन्नत करके उप चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए। मंत्री जी अगर इसको लेकर सदन में आश्वस्त करे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकार को केवल स्वीकृति प्रदान करनी है। उप चिकित्सालय, ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु भामाशाह तैयार हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम दुलचासर में पी एच सी संचालित है। इस क्षेत्र के आस-पास के 30 गांवों के मरीज, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के लिए जाते हैं। प्रतिदिन 17 हजार से अधिक ओ पी डी आईपीडी हैं। अगर दुलचासर पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाता है तो इन गांवों के हज़ारों मरीजों को फायदा मिलेगा। मेरी सरकार से मांग है कि दुलचासर पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाए। गांव के हज़ारों मरीजों को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पी एच सी, बेरासर व सेवरणा में लम्बे समय से चिकित्सक के पद रिक्त पड़े हैं। श्री डूंगरगढ़ सी एच सी में फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त चल रहा है। इसमें फिजिशियन व स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है, क्योंकि यहां प्रतिदिन 1,000-1,500 से ज्यादा ओ पी डी रहती है। डिलीवरी के समय आने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ सी एच सी में पूर्व में कार्यरत डा. प्रीति अग्रवाल 2 जुलाई, 2022 से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रही हैं। विभाग के निर्देशों के बावजूद उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जानकारी में आया है कि उन्होंने दूसरी जगह प्राइवेट जॉब ले लिया। चिकित्सा विभाग इस पर प्रसंज्ञान ले। सी एच सी में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति कराये। इसके अलावा क्षेत्र के चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त अन्य पदों को भी भरा जाए। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेहरासर, कल्याणसर, दुशारना, पडुसी उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन नहीं है तो भवन निर्माण करवाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बहुत ही अच्छी है। भारत में अगर राजस्थान की तुलना करें आमजन, गरीब को, इस योजना का लाभ मिलता है।

(श्री गिरधारीलाल)

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, यहां अगर एक भी पद रिक्त नहीं हो, जहां पर ए.एन.एम., डाक्टर्स हैं, थोड़ी-सी मॉनिटरिंग अच्छी हो तो निश्चित रूप से आमजन, गरीब और गांव में रहने वाले आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ में गांवों में आयुर्वेदिक पद्धति थोड़ी कमजोर हुई है। अभी चार सालों में जैसे ही हमारे गर्ग साहब ने यह विभाग सम्भाला है तो गांवों में इसका प्रचलन बढ़ा है। हर गांव में हर ब्लाक स्तर पर एक बड़ा औषधालय खोलने की घोषणा की है हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आयुर्वेदिक पद्धति पर भी ध्यान दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांग मेरे इलाके की ओर से रखना चाहूंगा। विशेष मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ में नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाये। साथ ही, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां पर पद खाली हैं, अपनी मॉनिटरिंग से सारे पद, चाहे वह नर्सेज के हों, डाक्टर्स के हों, आयुर्वेदिक चिकित्सक के हों, वे पद भरे जायें।

माननीय सभापति महोदय, आने वाला समय इतना खतरनाक होगा आने वाली पीढ़ी के लिए और अगर हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी किसी भी बीमारी से बच नहीं पायेगी, महामारी की ओर जायेगी। चाहे कोरोना काल हो, जो कोरोना काल का समय रहा हो, जिसमें कोरोना काल में किसी की भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबने मन लगाकर कोरोना काल का मुकाबला किया है।

इसी प्रकार जब स्वास्थ्य की बात होती है तो उस सूरत में नशे पर रोक लगनी चाहिए। जहां नशा बिकता है, अवैध रूप से बिकता है, आप चाहे कहीं पर भी जाओ, तो उस पर भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि जो पद हमारी सरकार ने चार साल में नर्सिंग के, डाक्टर्स के, संविदा कर्मियों के भरने के लिए जो घोषणा की है, जो संविदा कर्मी हैं उनको स्थायी करने की बात कही है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार यह काम कर देती है तो आने वाले समय में यह हमारा बड़ा काम होगा, बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की होगी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका और मेरी पार्टी का, नेताओं का मैं बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट 2019, बिंदु संख्या 99 में आपने यह कहा कि नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली सभी नवजात बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट दिये जायेंगे। कितने दिये? इसका अवलोकन जरूर करें। आपने एक घोषणा की कि जनता क्लिनिक खोले जायेंगे, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो अभी तक एक भी जनता क्लिनिक नहीं खुला है। चिरंजीवी योजना, आपने दस लाख रुपये से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपये किये, पिछले समय से जब से यह योजना प्रारम्भ की गयी है तब से अभी तक के लाभार्थियों के इलाज में व्यय राशि का अवलोकन आपको करना चाहिए कि कितने मरीजों का, कितने प्रतिशत मरीजों के इलाज का खर्चा दस लाख के आसपास आया। बहुत कम ऐसे लाभार्थी होंगे।

आर.जी.एच.एस., राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जिसका लाभ हमें भी दिया जाता है। किसी भी मरीज का इलाज हो जाता है, आपरेशन हो जाता है तो उसके बाद में वह डाक्टर को दिखाकर उसकी दवाई नियमित रूप से घर पर चलती है। डाक्टर को दिखा दिया, डाक्टर ने कहा कि दो महीने, चार महीने या छह महीने तक इस कोर्स को लें और उसके बाद वापस दिखाना, लेकिन आर.जी.एच.एस. में दवाई एक महीने की ही दी जाती है। उसके बाद फिर या तो वह मरीज वापस डाक्टर के पास जाये, फिर दिखाये और यहां गांव से शहर जाये तो शहर जाने का किराया लगेगा, गाड़ी का किराया लगेगा, तो यह दवाई उसको जितने महीने की डाक्टर ने लिखी है, उतने महीने की दी जाये।

(समय: 16.05 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

राज्य सरकार ने एक उड़ान योजना चलाई, जिसमें महिलाओं और स्कूली छात्राओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन दिये जाते हैं। एक वर्ष के पश्चात् भी आधे जिलों में भी वितरित नहीं हुए हैं और जहां पर यह वितरित किये गये हैं वहां पर भी उनकी क्वालिटी पर बालिकाओं ने भी सवाल उठाये। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, अत: उच्च गुणवत्तायुक्त सेनेटरी नैपकिन वितरित किये जायें।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

आयुर्वेद अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। बहुत कम अस्पतालों में वैद्य हैं। कहीं पर कम्पाउंडर्स के भरोसे पर है और कहीं-कहीं पर तो चपरासी ही चला रहे हैं। कुल स्वीकृत पद मेरे बड़ी सादड़ी और डुंगला में 172 हैं, उनमें से केवल 56 कर्मचारी ही कार्यरत हैं और बाकी रिक्त है, तो इन्हें अविलम्ब भरा जाये।

आशा सहयोगिनी, जो अभी पूरी तरह से अस्पताल में ही काम करती हैं और कई सारे काम वे करती हैं, तो उनका मानदेय बढ़ाया जाये, क्योंकि उनके जिम्मे बहुत काम है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा पर मशीन विद मैन कम्प्यूटर आपरेटर जो वर्षों से कार्यरत है, जिनका मानदेय अभी भी बहुत कम है जबकि इस योजना को सफल बनाने के लिए ये कार्मिक जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो इन्हें नियमित किया जाये। नियमित हो तब तक इनका मानदेय बढ़ाया जाये।

सी.एच.ए., कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोरोना काल में अपनी जान की चिंता किये बिना कोरोना पीड़ितों की मात्र 7,900 रुपये मानदेय प्रति माह में मन से सेवा की, इनमें से किसी ने 9 महीने और कइयों ने 11 महीने तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन इनको सरकार ने निकाल दिया। अत: इन सभी सी.एच.ए. को किसी न किसी पद पर वापस लिया जाये, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ कोरोना महामारी और लम्पी बीमारी में भी कारगर सिद्ध हुआ है। अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। राजस्थान में होम्योपैथिक में रजिस्टर्ड चिकित्सकों की संख्या 10 हजार के लगभग है, लेकिन स्वीकृत पद मात्र 303 ही हैं जो कि 3.3 प्रतिशत ही है। होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा सभी 656 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव 28.09.2021 को भेजा गया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ। 14 फरवरी, 2022 से होम्योपैथिक निदेशालय के सामने धरने पर बैठे थे, आयुष मंत्रीजी के आश्वासन पर 127 दिन बाद धरना स्थगित किया था, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी 02 फरवरी, 2023 से पुन: धरने पर बैठे हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इनके पद सृजित करके इन्हें नियमित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, वे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के सामने रख रहा हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी, एफ.आर.यू.बी. सिजेरियन को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये, क्योंकि यह नगरपालिका क्षेत्र है, काफी आबादी है और आसपास का इलाका भी इस पर बहुत निर्भर है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुंगला उप खण्ड मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है। सी.एच.सी. को एफ.आर.यू.बी. 75 बेडेड या मदर चाइल्ड हेल्थ विंग में क्रमोन्नत किया जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराबरदा, थड़ा, निकुम्भ, बोहेड़ा को क्रमोन्नत किया जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलवाड़ जो कि सिक्स लेन पर स्थित है, नेशनल हाईवे पर स्थित है, आये दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और इस हास्पिटल में हमेशा कोई न कोई चिकित्सक की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें और चिकारड़ा, बान्सी, धमोत्तार, ग्यासपुर, आसावरा, देवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र टीला, पाल, खरदेवला, सांगरिया, रठांजना, खोड़ी, नकोर, मधुरातालाब, जोलर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। नालवा, मंगलवाड़ गांव, बलालिया, रणा, उठेल, ओरवाड़िया, जन्तोई, रतनपुर, चिकारड़ा, बान्सी गांव में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें और जितने भी रिक्त पद हैं, उन सभी को भरा जाये।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ समय के अखबारों में यह अस्पतालों के जो हालचाल आये हैं, वह थोड़ा-सा आपके सामने मैं रख रहा हूं। 'ताले में अस्पताल, जननी हो रही शर्मसार, भटक रहे तीमारदार', 11 लाख कर्मचारी पेंशनर्स की हार्ट, बी.पी. समेत 30 फ्री दवा बंद। 'कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टैक्निशियन नहीं, दिल के मरीजों की जान संकट में और उपकरणों की मॉनिटरिंग में भी दिक्कत।' 'लाल रक्त का काला कारोबार। हर दिन मौत के मुंह में जा रहे बच्चे, परिजन लगा रहे इलाज की गुहार।' 'बीएमडी बीमारी से ग्रसित बच्चों ने परिजनों के साथ दिया धरना।' करीब दो-तिहाई घोषणाएं अधूरी।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

सभापति महोदय, मेरे इलाके में सीतामाता अभयारण्य है, उसमें दो पंचायतें अन्दर बसी हुई हैं वहां सड़क का भी कोई साधन नहीं है। दोनों पंचायतों में मिलाकर तीन उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, तीनों में एक भी कर्मचारी नहीं है। अभी 13 फरवरी को, गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर साधन लेकर आए, फिर उस महिला को लेकर गये, लेकिन हास्पिटल जाते वक्त पथरीले रास्तों पर ही हो गया प्रसव। मूलभूत सुविधाओं से वंचित पाल ग्राम पंचायत का मामला, मोबाइल, टार्च और गाड़ी की रोशनी में करवाना पड़ा प्रसव। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन पंचायतों में भी चिकित्सा की सुविधा की जाए। उप स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदला जाए। चार अस्पताल तीन माह से बंद, यह आयुर्वेद का है। 20 को कम्पाउण्डर व 2 को चपरासी चला रहे हैं, 20 बंद होने के कगार पर हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में बहुत जोर शोर से ये बातें कही गईं कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान अव्वल रहा, लेकिन इसमें सिर्फ आपका सहयोग हो, ऐसा नहीं है...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): हम लोगों का भी सहयोग है। देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी का भी सहयोग है। हम लोगों में से करीबन सबके वैक्सीन दो-दो डोज लग गई। उसके बाद बूस्टर डोज भी लग गई। तीन-तीन डोज लग गई। 220 करोड़ वैक्सीन डोज, केन्द्र सरकार ने नि:शुल्क उपलब्ध कराई। आक्सीजन की मात्रा 800 टन से 9 हजार टन तक बढ़ाई। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज कोरोना काल से मुफ्त दिया जा रहा है, जो अभी भी दिया जा रहा है। आप सेवा के काम देखिये, गांवों में जाएं वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकता, सेवा भारती का कार्यकर्ता मिला।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू वैरी मच।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): इन सबने भी सेवा की। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय राजस्थान। जय चित्तौड़।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वस्थ राजस्थान बनाने की दिशा में, आम आदमी के स्वस्थ जीवन के लिए, इस बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की राशि की तथा दुर्घटना बीमा की राशि भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है, जो कि राजस्थानवासियों के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय है। वहीं EWS परिवारों को भी अब नि:शुल्क चिरंजीवी योजना में लाभ मिल सकेगा।

विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। इनको लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने यह नहीं चलाया। माननीय मुख्य मंत्री ने ग़रीबों का मसीहा बनकर चिरंजीवी योजना बनाई।

मैं स्वास्थ्य पर गौतम बुद्ध जी की लाइनें कहना चाहती हूं कि हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बडा उपहार है, स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी सम्पत्ति है।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है। आज राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक कारगर साबित हुई। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से मांग करती हूं कि राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि आमजन ऐलोपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ-साथ होम्योपैथिक चिकित्सा का भी लाभ उठा सके।

कोरोना जैसी महामारी के समय राज्य में लगाये गये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को वर्तमान में नर्स ग्रेड-द्वितीय के ग्रेड कैडर में रखा है। मैं चिकित्सा मंत्री जी से उक्त स्वास्थ्य अधिकारियों को ग्रेड-प्रथम में रखकर, वेतन इन्सेंटिव के साथ, वेतन वृद्धि देने की मांग करती हूं।

मैं आपका ध्यान चिकित्सा विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार (यू टी बी) पर लगे संविदा कार्मिकों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। चिकित्सा

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

विभाग में कोरोना काल सहित पिछले कई वर्षों से आवश्यक अस्थायी आधार (यू टी बी) पर संविदा कार्मिकों की लगातार भर्तियां की गई हैं, लेकिन इन कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है जबकि इनकी नियुक्ति भी राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियमावली, 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही हुई है। यू टी बी संविदा कार्मिकों का मानदेय एन एच एम द्वारा निर्धारित दर अनुसार देय है जो कि पे-मैनेजर के माध्यम से सीधे सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्लेसमेंट एजेन्सी की कोई भूमिका नहीं होती है। अतः मैं चिकित्सा मंत्री जी से आवश्यक अस्थायी आधार (यू टी बी) पर लगे संविदा कार्मिकों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियमावली में एडोप्ट करवाने की मांग करती हूं, ताकि इन कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से उप स्वास्थ्य केन्द्र नाथडियास, माझावास एवं सांगवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं।

मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को तहेदिल से कह रही हूं। हमारी उप चुनाव में मांग रखी गई थी कि कारोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाए। साथ ही, रायपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सेटेलाइट अस्पताल तथा गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत की मांग करती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के मासिंगपुरा (मोखून्दा), रामपुरिया (अरनिया), तिलोली (सांगवा), अबरकिया (सोनियाणा), कोटडी (दरीबा), खजूरिया श्याम (गोवलिया), भैसाकुण्डल (देवली), कालीमंगरी (डेलाणा) तथा मोमी (गुरला) में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग करती हूं, ताकि आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना सहित चिकित्सा विभाग की चल रही अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि हाल ही में जारी नवीन चिकित्सकों के पदस्थापन आदेश में से 15 चिकित्सकों के सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नवीन पदस्थापन के आदेश जारी किये हैं। मेरे गृह क्षेत्र रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिसन, सर्जन सहित कई चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं, इस कारण आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

हैं। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र, सहाड़ा में नर्सिंग स्टाफ के भी पद काफी रिक्त चल रहे है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत रेडियोलोजिस्ट सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को दूसरे विधान सभा क्षेत्र में डेपुटेशन पर लगाया जा रहा है। एक तरफ मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्साकर्मियों की कमी है वहीं दूसरी ओर मेरे यहां पर कार्यरत स्टाफ को दूसरे विधान सभा क्षेत्र में लगाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से ही स्टाफ को इधर-उधर किया जा रहा है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करती हूं कि मेरे यहां पर कार्यरत चिकित्साकर्मियों को बेवजह इधर-उधर नहीं किया जाये।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के सम्मान में दो लाइनें कहना चाहूंगी कि-

'जब भी तुम्हारा हौंसला आसमान तक जायेगा,
याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आयेगा।'

जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 व 28 पर चर्चा हो रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हर सरकार चाहती है कि आमजन स्वस्थ रहे क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा कई प्रकार के वेरिएंट आ जाते हैं। सुनते हैं कि कोरोना के दस प्रकार के वेरिएंट और अलग-अलग प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, उसके अनुरूप प्रशिक्षित डाक्टर, विशेषज्ञ स्टाफ, आधुनिक उपकरण, संसाधन, बजट, कार्य का वातावरण होना चाहिए, जो आज लगता है कि वर्तमान में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज आप सी एच सी, पी एच सी खोलते गये, सब एम एल एज को खुश करते गये कि ले जाओ, आप जरूर खोलो लेकिन केवल जन-प्रतिनिधियों को खुश रखने के लिए ही नहीं, वहां पर आप स्टाफ भी दीजिए, सुविधाएं भी दीजिए, दवाइयां भी रखिए। इस समय इनमें से कुछ भी नहीं है। हाल बेहाल हैं। आज मरीज बहुत परेशान हैं। वैसे तो मरीजों के अनुपात में नये-नये पद आपको स्वीकृत करने चाहिए, साथ ही पुराने भी पूरे करने चाहिए, लेकिन न तो पुराने भर रहे हो और न नये स्वीकृत कर रहे हो। आज हालत पूरी तरह चरमराई हुई है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेडिकल कालेजों की बात करूं तो मैं कहूंगा कि यह तो माननीय मोदीजी के सपने के आधार पर हर जिले के अन्दर बन रहे हैं। उसी आधार पर राजस्थान में भी मेडिकल कालेज बन रहे हैं। आपको बनाने होते तो पहले बनाते। किसने रोका था यू पी ए के समय? बने हैं तो मोदीजी के कार्यकाल में बने हैं। भले ही वाहवाही चिकित्सा मंत्रीजी ले रहे हों, पर वास्तव में बधाई के पात्र तो प्रधान मंत्री मोदीजी ही है जिन्होंने कहा कि हर जिले में आप मेडिकल कालेज खोलिए। इतना ही नहीं, वर्तमान में 30 मेडिकल कालेज हैं। 07 सरकारी हैं, 12 राजमेस के अन्तर्गत हैं, 09 प्राइवेट हैं, 16 डेन्टल कालेज में से केवल एक सरकारी है और 15 प्राइवेट हैं। इस कारण सीटें भी बढ़ीं 5,105 यूजी की, 2,693 पीजी की और 300 सुपर स्पेशियलिटी की सीटें हैं और इतने सारे खुलने के बावजूद भी बजट आपने 450 करोड़ रुपये कम किया है। मोदीजी ने आपको हर कालेज के लिए 325 करोड़ रुपये सैंक्शन किये। यानी 60 परसेंट सेन्टर का है और आपका 40 परसेंट है, लेकिन आप तो कई जगह जमीन भी उपलब्ध नहीं करवा पाये। रात-दिन आप और आपके मुख्य मंत्रीजी केवल मोदीजी को कोसते रहे पर वहां से पैसा जो आ रहा है, वह ही आप खर्च नहीं कर पा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। 2020-21 में आपको 1,863 करोड़ रुपये मिले और आपने खर्च कितने किये, 646.28 करोड़। 2021-22 में आपको मिले 2,613 करोड़ और आपने खर्च कितने किये, 854 करोड़। बाकी पैसे पड़े हैं। 2022-23 में फिर आपको 2,613 करोड़ मिले और आपने खर्च किये अभी तक सिर्फ 1,334 करोड़। यानी पैसा तो आपके पास केन्द्र का और आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। आप केवल उनको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हो। आप तो उनको बधाइयां दो, उनके गीत गाओ कि आपने हमको मेडिकल कालेज दिये जिसके आधार पर सीटें भी बढ़ीं। आपने बजट को उलटा कम कर दिया, 450 करोड़ रुपये कम कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, आप बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हो। हम लोग विधान सभा में खूब तालियां ठोक रहे हैं पर इनको संभालेगा कौन? इसकी चिन्ता कौन करेगा? आपको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है। मेडिकल कालेज को एम सी आई से परमिशन लेनी आवश्यक होती है। आप क्या करते हो, हर कालेज से दो-दो, चार-चार आदमी डेपुटेशन पर वहां लगा देते हो। एम सी आई के सामने प्रदर्शित कर दिया कि यहां काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एम सी

(श्री वासुदेव देवनानी)

आई गयी वह मेडिकल कालेज खाली, सारे अपने-अपने स्थान पर पहुंच गये। यानी इस प्रकार की हालत है। आप स्टाफ को भी नियुक्त नहीं करते हो। केवल घोषणाएं करते रहते हो, उससे जनता कभी भी आपको माफ करने वाली नहीं है, जनता परेशान है। जनता कहती है केवल अख़बार में पढ़ने से, विधान सभा में घोषणा करने से वाहवाही लूटने नहीं देंगे। बड़े-बड़े होर्डिंग्स से भी जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। जनता को तो चाहिए कि मरीज का इलाज हो और वह सही होकर घर जाये, लेकिन आपको उसकी कोई फिक्र है नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे ध्यान है 2019-20 में तत्कालीन चिकित्सा मंत्रीजी ने बहुत जनता क्लिनिक की घोषणाएं कीं, जिससे लगा कि सारा राजस्थान स्वर्ग हो जायेगा, हर गली मोहल्ले में जनता क्लिनिक खुलेगा और उसके आधार पर जनता का इलाज होगा। खूब वाहवाही आपने लूटी लेकिन आपने क्या किया? 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तक कुल 38 खोले हैं। पूरे चार साल में पूरे राजस्थान के अन्दर केवल 38 खोले हैं। किस बात की वाहवाही लूट रहे हो? आपने खूब कहा कि हर घनी बस्ती में, हर गरीब बस्ती में हम चिकित्सा सुविधाएं देंगे, लेकिन रिजल्ट ढाक के तीन पात। अजमेर शहर में पहले 10 खोलने की घोषणा हुई थी। इस बजट में आपने 10 को 20 कर दिया, लेकिन वे 10 भी कहां हैं? मैं तो मोमबत्ती लेकर ढूंढ रहा हूं, किसी मोहल्ले में एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, केवल घोषणा ही नहीं, विचार करो कि घोषणा करते हो तो उसको निभाओ। आपने उस समय 100 के लिए कहा था, यानी चार सालों में तीन सौ, चार सौ खुल जाते। आज राजस्थान का भला होता, लेकिन यहां पर अपने समर्थकों से केवल टेबल बजवाना, जनता को भ्रमित करने का काम चलेगा नहीं।

मैं अजमेर की बात करूं। वहां के लिए स्थान भी तय हो गये। लोंगिया कम्पाउण्ड परिसर में कम्युनिटी हॉल में, घूघरा घाटी में, महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेन्टर पर, मदार की टेकरी में, प्रकाश नगर, फायसागर रोड पर, कोटड़ा, बैरवा बस्ती में, सोनी नगर में, कहीं भी एक भी नहीं है। हम जाते हैं तो जनता पूछती है कि मंत्रीजी ने, सरकार ने घोषणा की है, खुलवाओ तो सही। हम किसके सामने जाकर रोयें? किसको कहें? कोई सुनने वाला हो तब तो कहें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह बड़ी वाहवाही लूटते हैं कि कोरोना का हमने बहुत अच्छा इलाज किया, राजस्थान माडल को सब अपनाओ। गुजरात में क्या हुआ? आपके राजस्थान माडल को नकार करके

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपको 16 तक सीमित कर दिया। वहां तो फिर भी 16 मिल गये, यहां तो आप दहाई के अंक से भी पीछे रह जाओगे। जरा सोच लेना।

इसी तरह कोरोना को रोकने के लिए बधाई देनी है तो आप मोदीजी को दीजिए जिन्होंने दो स्वदेशी वैक्सीन बनवायीं। एक बूस्टर डोज दिया। वर्ल्ड रिकार्ड, शायद गिनीज बुक में रिकार्ड होगा कि किसी देश के अन्दर 220 करोड़ डोज लगाये हैं। वह भी निःशुल्क। आप उनको धन्यवाद नहीं दोगे, आप केवल क्रिटिसाइज करते रहोगे। उन्होंने आपको वेंटिलेटर भेजे, आक्सीजन सिलेण्डर भेजे, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे, लेकिन कुछ नहीं। वाहवाही करनी है तो मोदीजी की करो। वह उस समय मदद नहीं करते तो आप इतने सारे हास्पिटल्स नहीं खोल पाते, क्योंकि कोई जिन्दा ही नहीं रहता तो इलाज कौन करवाता? इसके बारे में जरा आप सोचना।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा की कि हम महिलाओं और छात्राओं को उड़ान योजना के अन्तर्गत सेनेटरी नैपकिन देंगे, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था है क्या? महिलाएं परेशान हैं, ढूंढती हैं कि कहां मिलेंगे नैपकिन? केवल घोषणा पर घोषणा, ताली पर ताली, इससे गाड़ी नहीं चलेगी माननीय मंत्रीजी। आपके समर्थकों से केवल डेस्क बजवा लो, उससे जनता तो आपको वोट देने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करता हूं। आपने बड़ेबड़े होर्डिंग्स लगवाये, हर गली मोहल्ले में लगवाये कि 10 लाख से 25 लाख रुपये कर दिये। जैसे कोई आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आप पता करें कि इसकी शुरुआत किसने की। शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी 2014-15 में स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में। फिर उसको भामाशाह बीमा योजना के रूप में लाये। 01 सितम्बर, 2019 को आयुष्मान बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भामाशाह योजना तीनों मिलकर चले। आपने चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपया जो किया, उसमें केन्द्र की आयुष्मान योजना भी शामिल है, इसलिए 05 लाख तो आप वहीं से ले रहे हो, केवल 05 लाख ही तो आप दे रहे हो। आज मैं पूछता हूं कि आपने 10 लाख रुपये किसको क्लेम दिया है? पूरे एक प्रतिशत लोग भी 10 लाख रुपये के नजदीक नहीं आये। चिरंजीवी योजना के अंदर बात करूं तो 100 लोगों को भी 10 लाख का लाभ नहीं मिला है और आज फिर 25 लाख रुपयों का क्या मतलब है? केवल वाहवाही लूटना मकसद है। चिरंजीवी योजना में यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

सम्मिलित है और इस योजना के अंदर हास्पिटल्स की हालत क्या है? 15 से 20 दिन तो जांचों के लिए इंतजार करना पड़ता है। यदि मरीज 15 से 20 दिन तक इंतजार करेगा जांच के लिये, तब तक तो वह मर जायेगा, वह जिंदा कहां रहेगा? आपके हास्पिटल्स में व्यवस्थाएं ही नहीं हैं, आप कैसे करोगे?

माननीय सभापति महोदय, कुल 30 लाख का आपने बताया है प्रारूप में, 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया, जबकि 100 लोगों को भी पूरा क्लेम नहीं मिला है। अगर मैं गलत हूं तो आप अपने भाषण में इसको करेक्ट कर देना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 लोगों को भी पूरा क्लेम नहीं मिला और एक प्रतिशत से कम के मरीज हैं तो 25 लाख रुपये किसको दोगे? आपको तो केवल आंकड़ा देना है 25 लाख का, ताकि जनता भ्रमित होकर आपको वोट दे दे। आज के जमाने में जनता भी बेवकूफ नहीं है, आज वह समझदार हो गयी है। यह 1947 की जनता नहीं है, यह 2023 की है, क्योंकि मोदीजी का उसके सामने नेतृत्व है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना में मैंने पता किया, प्रति मरीज व्यय केवल 11,328 रुपये हुआ है और सबसे अधिक व्यय होता है ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी पर। 159 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी की है। यह होते हैं 5.50 करोड तो कितना हुआ एक का, 5.78 लाख में हुआ। आप 25 लाख दोगे किसको?

माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सक नहीं हैं, आपकी चिरंजीवी योजना कैसे चलेगी? मैंने पूरा देखा, मेरे अजमेर के अंदर 370 पद चिकित्सकों के खाली हैं। चिकित्सक नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं हैं, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है, आप इलाज करेंगे क्या? हम किसको रोयें, किसको बतायें?

आज ट्रोमा सेंटर की बात करूं तो हमारे यहां बने हुए 10 वर्ष हो गये। ट्रोमा सेंटर से केवल रेफर करने का काम हुआ है, आगे के हास्पिटल में रेफर कर दो। वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रात में एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर लोग आते हैं, रात में वहां पर कोई डाक्टर नहीं रहता। सीटी स्कैन के लिए दूसरी जगह रेफर होते हैं। इस समय यदि आप वास्तव में संवेदनशील हैं, परसादी लाल जी, मंत्री महोदय, आप संवेदनशील तो हैं, लेकिन या तो आपकी आगे चलती नहीं या मुख्य मंत्रीजी आपकी सुनते नहीं या आपके नीचे के अधिकारी नहीं सुनते। प्रतिवर्ष 25 हजार दुर्घटनाएं होती हैं और उसके अंदर 11 हजार मौतें होती हैं, जिसमें से 2 हजार 500 लोग तो बिना उपचार के भगवान

(श्री वासुदेव देवनानी)

को प्यारे हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं केवल एन.एच. पर होती हैं। आपने घोषणा की 6 डेडिकेटेड ट्रोमा सेंटर शुरू करेंगे, एक वर्ष हो गया, अभी तक शुरू ही नहीं हुए। कहीं न्यूरोलोजिस्ट नहीं है, कहीं एक्स-रे मशीन बंद पड़ी हैं। हर सेंटर पर 60 प्रतिशत से अधिक केसेज केवल रेफर हो रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी, आपने बड़ी घोषणा की थी कि जिला अस्पतालों में हम ICU खोलेंगे। आपने 27 करोड़ का बजट भी रखा। जिस कंपनी को आपने दिया, उसने मात्र औपचारिकताएं पूरी कीं। आज तक 90 प्रतिशत ICU जिला अस्पतालों में शुरू ही नहीं हुए। आप अपने अधिकारियों से पता करिये, शुरू हुए हों तो अपन चर्चा कर लेंगे। कहां हैं, उनको ढूंढेंगे अपन। बाकी जो 10 प्रतिशत ICU शुरू भी हुए उनमें न तो पर्याप्त स्टाफ है, न उपकरण हैं और टपकते हुए कमरों में उपकरण कबाड़ जैसे पड़े हैं। फंगस लगी हुई है। आपको देखना है तो आप गंगापुर चले जाइये। गंगापुर के हास्पिटल का दौरा करिये, वहां आपको सारी स्थिति का पता चल जायेगा। यानी इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। हमारे सामने राजस्थान का चित्र है। केवल वाहवाही लूटने के लिए कि बहुत अच्छा बजट है, आपकी घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं, इसको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जमीन पर कहां है, उसको तो दिखाओ।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह यदि मैं बात करूं अस्पताल SMS का हो, चाहे अजमेर का या दूसरे हास्पिटल्स हैं, आज कैंसर पीड़ितों के लिए एटीजी इंजेक्शन कहीं नहीं है। कहां जायेंगे वे? नि:शुल्क इलाज के बदले केवल उनको दर्द मिलता है। नि:शुल्क इलाज तो नहीं होता। माननीय मंत्रीजी, आप एटीजी इंजेक्शन तो उपलब्ध कराओ, ताकि कैंसर का मरीज तो बचे, लेकिन नहीं, इस प्रकार की दयनीय स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी अस्पतालों की थोड़ी और चर्चा करूं। पूरे सरकारी अस्पतालों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप SMS चले जाओ। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर भर्ती हुए उन्होंने क्या कहा था, मेरा शर्म से सिर झुक गया। यानी स्टेट का मुख्य मंत्री, वह भी राजस्थान का, जो इस प्रकार की घोषणाएं करता हो, यदि उसका सिर अव्यवस्थाएं देखकर शर्म से झुक जाये तो इससे बड़ा हमारे लिए पीड़ादायक दिन कोई हो नहीं सकता। आज उस अस्पताल में न तो टॉयलेट साफ होते हैं, दीवारें गंदी पड़ी हैं, वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं हैं, गार्ड नहीं हैं और बाथरूम से लेकर वार्ड तक गंदगी अटी पड़ी है। कोई एडमिट होता है तो उसके जो अटेंडेंट हैं, वे भी बीमार

(श्री वासुदेव देवनानी)

हो रहे हैं। क्या बीमारों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है? वहां अस्पतालों में व्हीलचेयर नहीं है। यह हाल केवल SMS का नहीं है, मेरे JLN अस्पताल का भी है और बाकी हास्पिटल्स में भी है। इस प्रकार की स्थिति बनी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कम से कम सफाई की ओर तो ध्यान दो। बिना सफाई के तो संक्रमण बढ़ेगा। आपने SMS हास्पिटल को 9 करोड़ का बजट भी दिया, आज मार्च आ गया, आपने उसमें से कितने खर्च किये? पैसा पड़ा हुआ है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि उस पैसे का हम उपयोग भी करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ बात करूं तो जो अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वे गैलरी और रैम्प पर सोते हैं। वहां पर उनके लिये कोई कमरा नहीं है, हॉल नहीं है। वे वार्डों के बाहर सोते हैं, खुले में खाना खाते हैं। आज इस कारण वहां पर संक्रमण फैल रहा है। मरीज तो ठीक नहीं होते, आप उनको और बीमार कर दो। यानी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यही हाल अजमेर में, यही हाल SMS अस्पताल में, यही हाल उदयपुर में है। माननीय मंत्रीजी, आप दौरे करिये। इन हास्पिटल्स की मीटिंग लीजिये। आप अचानक पहुंचिए, पहले से पता चलेगा तो सबको हटाकर आपके लिए अच्छा रास्ता और गलीचा बिछा देंगे। आप अचानक जाओगे तो आपको दयनीय स्थिति दिखाई पड़ती है कि आखिर है क्या? इसलिये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप निरोगी राजस्थान बनायेंगे, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निरोगी राजस्थान प्रबन्ध कोष का गठन किया, उसमें 100 करोड़ का प्रावधान भी रखा, पर उसमें से आपने खर्च कितना किया? आज तक केवल 5 करोड़ खर्च किया है। तीन-चार साल के अंदर केवल 5 करोड़ खर्चा करोगे तो फिर कैसे उस कोष का प्रबन्ध होगा?

माननीय सभापति महोदय, आज प्राइवेट मेडिकल कालेजों की फीस नहीं घटी। MP सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट पर प्राइवेट कालेजों पर अंकुश लगाया है। उन्होंने वहां पर फीस को कम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके नसबंदी फेल हो गयी। पांच वर्षों में 25.5 करोड़ का हर्जाना दिया है। CMHO का आफिस तक कुर्क हो गया। झुंझुनूं और जालौर में देख लीजिये, यह हाल है। फिर वहां पर कर्मचारी कैसे काम करेंगे?

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय सभापति महोदय, आज संविदाकर्मी बहुत परेशान हैं। आपने उसके लिये राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स तो बनाये, मेडिकल विंग में 36 हजार 178 कर्मचारी हैं, वे आफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, उनको 28 मार्च तक पूरे डाक्यूमेंट देने हैं। वे किस-किस के चक्कर लगायेंगे? संस्थापन अधिकारी के लगायें, सहायक लेखाधिकारी के लगायें, SMO के लगायें, Dy.CMHO, CMHO, ज्वाइंट डायरेक्टर, स्वास्थ्य भवन, आखिर फिर भी गारंटी नहीं कि आप उसको स्क्रीनिंग में पास करोगे। एजेंसी के माध्यम से और जॉब बेसिस पर जो कार्यरत हैं, उनको तो आपने शामिल ही नहीं किया। आप नियमावली सरल करो। लोगों का भला करना है तो नियम ऐसे बनाओ जिनके आधार पर नोर्म्स पूरे कर सकें। केवल घोषणा करने से नहीं होगा, भला करो। उनकी दुआएं मिलेंगी। आपको दुआएं मिलेंगी तो आपका भी भला होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे निवेदन करूंगा राइट-टू-हेल्थ के बारे में। इसको आप आधा-अधूरा लाये हैं। यह पूरा बिल, जो अभी प्रवर समिति में है, अब पता नहीं आप कब लाओगे। आपने घोषणा तो की है कि इसी बजट में लायेंगे, लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि आप इस बजट में इसको ला पायेंगे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कहोगे तब ले आयेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लायेंगे तो अच्छा है, हम तो स्वागत करेंगे, अगर आप ढंग से लाओगे तो, लेकिन वह डाक्टर विरोधी है। आज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का तो आपने सुना नहीं, न डाक्टर को सुरक्षा दी, न बिल में सुनवाई की कोई व्यवस्था की, प्राधिकरण में डाक्टर की सुनवाई नहीं और इमरजेंसी में नि:शुल्क इलाज की कोई परिभाषा नहीं। रूरल एरिया में सरपंच और प्रधान के हवाले डाक्टरों को छोड़ दिया कि वह कोई भी कार्यवाही कर सकेंगे, चुनौती का उनको कोई अधिकार नहीं और 1,700 रुपये में प्रतिदिन भोजन सहित मरीज को भर्ती करना पड़ेगा। कौन करेगा? करोड़ों रुपये खर्च करके उन्होंने अस्पताल बनाया। आपको यदि वास्तव में राइट-टू-हेल्थ बिल को इम्प्लीमेंट करना है तो सरकारी हास्पिटल्स को सुधारो। सरकारी हास्पिटल्स अच्छे होंगे तो वहां जायेंगे नहीं। प्राइवेट में वहां जायेंगे तो कम जायेंगे, लेकिन आप यह नहीं करेंगे। आज तो एक ही बात है कि मुख्य मंत्रीजी

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपनी सरकार रिपीट करने के चक्कर में हैं और प्राइवेट अस्पताल लूटने के चक्कर में हैं। इन दोनों के चक्कर में जनता बुरी तरह पिस रही है। जरा उसको संभालो, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, हाल तो यह है कि महिला चिकित्सालय में कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला है। सिरोही का तो आपने स्वयं ने अख़बार में पढ़ा होगा कि कुत्ते ने बच्चे को किस तरह से नोंच दिया। आज यह हालत है, फिर आप कहते हो कि हम सबको स्वस्थ रखेंगे। पेंशनर के साथ क्यों धोखा कर रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पांच मिनट में, 20 मिनट हैं मेरे। मैं 16 मिनट ही बोला हूं, चार मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने जो समय दिया है, मैं उसमें अपनी बात खतम करूंगा। मेरे अजमेर के बारे में कहूंगा, पोल खोल रहा हूं। 11 लाख पेंशन कर्मचारियों की आपने RGHS में हार्ट और बी पी समेत 30 दवाइयां बंद कर दीं। सीटी स्कैन, एक्स-रे में आप 15 से 20 दिन का इंतजार कराएं और कह रहे हैं निरोगी राजस्थान। आपने 97 हजार स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किये, अब तीन वर्ष तो बीत गये, उनका कहीं पता-ठिकाना नहीं है। नर्सिंग कालेज खोलते जा रहे हो, दो वर्षों में एक भी भर्ती नहीं की।

अब मैं जरा अपने अजमेर क्षेत्र की कहकर चार मिनट में समाप्त करता हूं। अजमेर में 2015 में कार्डियक थोरेसिक सर्जरी तथा बाईपास सर्जरी शुरू हुई लेकिन 2016 आते ही तुरंत बंद हो गयी। 2017 से आज तक बंद है और करोड़ों की मशीनें कबाड़ हो रही हैं, केवल सर्जन नहीं है। एक-आध सर्जन तो भेज दो जिससे वे मशीनें तो काम आयें। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रो फिजिशियन नहीं है। गेस्ट्रोलॉजी विभाग विकसित नहीं कर पा रहे हैं। एम आर आई की मशीन नहीं है। अनुबंध पर सरकार खुद खरीदे तब जाकर के लोगों का भला होगा। चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारी नहीं हैं।

कैंसर विभाग आपने खोल तो रखा है लेकिन उसमें मेडिकल आन्कोलॉजी और सर्जिकल आन्कोलॉजी, जब तक सुपर स्पेशलिस्ट नहीं आयेंगे, तब तक किसी भी प्रकार के कैंसर वाले को लाभ नहीं होगा। अत: मेरी आपसे मांग है कि अजमेर में आप कैंसर का पूरा हास्पिटल खोलने की घोषणा करें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मेरे यहां 5 करोड से उस समय राठौड़ साहब ने पंचशील सी एच सी बनवाई थी, लेकिन स्टाफ नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी मांग है कि अजमेर उत्तर में सेटेलाइट हास्पिटल आप खोलिये। आज जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में सब जगह 5-5, 6-6, 12-12 चिकित्सालय हैं। अजमेर में केवल 3 हैं। आप अजमेर नोर्थ में सेटेलाइट हास्पिटल खोलकर उसको जोड़िये।

आपने गत वर्षों में घोषणा की थी कि जनता क्लिनिक खोलेंगे, पब्लिक हेल्थ कालेज खोलेंगे, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोलेंगे। हास्पिटल मैनेजमेंट कॉडर बनायेंगे, मल्टीपरपज इंडोर हॉल खोलेंगे। कहां गये? कहीं पता ठिकाना नहीं है। आज तक नहीं खुले।

मेरे क्षेत्र के 2 गांव हैं अजयसर और हाथीखेड़ा, उन गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं, इन्हें आप पी एच सी में कन्वर्ट करिये। मेरे यहां नर्सिंग स्टाफ की 370 वैकेंट पोस्टें हैं। सीनियर लैब टेक्निशियन 11, टेक्निकल असिस्टेंट 7, नर्सिंग श्रेणी फर्स्ट 32 और सेकण्ड के 93, इनका कोई पता नहीं है।

आक्सीजन प्लांट्स में उत्पादन, 11 आक्सीजन प्लांट खोले जिनमें हमने विधायक कोष से भी पैसे दिये, लेकिन आज तक वे बंद पड़े हैं। उन्हें न तो सरकार चालू कर रही है, न पी पी पी मोड पर और न निजी में दिये हैं। और तो और, वात्सल्य केन्द्र की बड़ी घोषणा की थी, वे पूरे कबाड़ में पड़े हैं। उनका ताला नहीं खुला। राजकीय बस स्टैंड के केन्द्र पर ताला लगा हुआ है। जे एल एन का गेट क्षतिग्रस्त है और न ही बैठने की व्यवस्था है।

आपने उम्मीदें तो जगाईं, लेकिन न डाक्टर है, न स्टाफ है और न बजट है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कैसे होगा? शायद ईश्वर ही मालिक है। सारी जनता भगवान भरोसे है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय मंत्री जी, इस बजट पर आप विचार करिये। इस बजट में जो कमियां हैं, सारा जोधपुर जा रहा है। अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। अजमेर में कुछ तो दो। एक भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

इंस्टीट्यूशन नहीं खोला है। आपने 2 साल से घोषणा कर रखी है, उसके अलावा आपने किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं की। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक सैकण्ड में, यदि मैं, मेरे हास्पिटल्स के बारे में कहूं तो साइकोलॉजी के 12 में से 6 पद खाली हैं, मेडिसिन में 24 में से 13 खाली हैं, स्किन के 5 में से 3 खाली हैं, पीडियाट्रिक, बच्चों का डाक्टर, 18 में से 10 खाली हैं, सर्जरी में 24 में से 9 और आर्थोपेडिक, जिसमें लोग घायल होते हैं वहां 15 में से 10 पोस्टें खाली हैं। गायनिक में 17 में से 8 खाली हैं।

श्री सभापति: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह। थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ट्रोमा में 6 में से 6 खाली हैं। यूरोलॉजी में 2 संकाय खोलिये।

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हास्पिटल में एक योग विशेषज्ञ बिठाइये तब जाकर लोगों का इलाज होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। अत: मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इनको शुरू करिये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये प्रबंधनों की सराहना देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। आज राजस्थान नि:शुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से 25 लाख रुपये करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

सभापति महोदय, चाहे कोई बताये या न बताये, विधान सभा में उपस्थित समस्त माननीय सदस्य और उनके परिवार में से किसी न किसी ने

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

जरूर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लिया है। उन्हें भली-भांति यह भी पता है कि यह योजना पूरे विश्व में एक शानदार योजना है। मैंने स्वयं बीमार होने पर अपना इलाज इस योजना के अंतर्गत करवाया। उन गरीब लोगों की खुशियों को भी अनुभव किया है जो पैसे की तंगी के कारण अच्छा इलाज नहीं करा सके, परंतु इस योजना के तहत वह अब नि:शुल्क इलाज का पूरा लाभ ले रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अनेक ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मरीज उदयपुर से अहमदाबाद और महाराष्ट्र इलाज के लिये जाते हैं, जहां उन्हें महंगा इलाज मिलता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

ऐसा ही एक उदाहरण मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का देना चाहूंगी कि एक मरीज मुम्बई में इलाज कराने गये थे लेकिन वहां उनके पास पैसे खतम हो गये। उन्होंने हमसे सम्पर्क किया और मैंने कलेक्टर साहब से बात करके उनका तुरंत चिरंजीवी कार्ड बनवाया। साथ ही उन्हें उदयपुर रैफर करवाकर उनका इलाज करवाया। बाद में एस एम एस चिकित्सालय, जयपुर में भर्ती कराया। यहां उनकी एक सफल ब्रेन सर्जरी हुई। अब वह विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अपने गांव में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राजस्थान आने पर इलाज में उनका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरा सभी सदस्यों से यह आग्रह है कि इस जन-कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार करें जिससे आमजन को इसका फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं अगर मेवाड़ की बात करूं तो बजट में उदयपुर के आर एन टी मेडिकल कालेज में सेंटर आफ एक्सीलेंस फोर स्किल सेल डिजीज और मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिये 30 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है। अब मेडिकल कालेज उदयपुर के लिये क्रिटिकल केयर ब्लाक्स स्थापित किये जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से कदम बढ़ाते हुए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से राजस्थान के समस्त जिलों में विभिन्न निर्माण कार्य कराने की घोषणा की है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

से आग्रह करना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में अनेक उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं, जिनके निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र धावड़िया, नया राजपुरा, बालाथल, कराकलां तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाठेड़ा कलां, तारावट, वाणा, पाणून, बम्बोरा एवं माडल हास्पिटल कानोड़ के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित होकर पट्टे जारी हो चुके हैं। यहां भवन के निर्माण के लिए अतिशीघ्र बजट जारी करना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट भाषण के जवाब में मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में उप स्वास्थ्य केन्द्र नवानियां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने की सौगात दी गयी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं सही सुचारु रूप से पहुंचें इसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उप स्वास्थ्य केन्द्र आकोला, गुडली, सालेड़ा, करणपुर को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगत को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही खोखरवास, भंदेसर, बीकावनियां, पिण्डोलिया, पाथलिया, जैतपुरा, टांक में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, राजकीय माडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड़ में एक महिला गायनिक चिकित्सक को पदस्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गांवों में महिलाओं को सी एच सी और पी एच सी में पुरुष चिकित्सक से इलाज कराने में झिझक रहती है, जिसके कारण उनका समय पर उपचार नहीं हो पाता है और छोटी-सी बीमारी एक जानलेवा रूप ले लेती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करती हूं कि प्रत्येक सी एच सी और पी एच सी पर महिला चिकित्सक को अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिससे महिलाएं बेझिझक अपना उपचार करा सकें। साथ ही, इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी अनुरोध किया गया था और मैं पुन: अपनी बात को दोहराती हूं कि इस विषय में चिकित्सा मंत्री जी ध्यान दें।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

सभापति महोदय, साथ ही, मैं राज्य की नर्सेज के लिए एक अलग से निदेशालय का गठन करने एवं नर्सिंग शिक्षा को अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने और नर्सेज को मेडिकल छात्रों की भांति आवास और शिक्षण संस्था की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग रखती हूं। साथ ही, मैं आशा सहयोगिनियों के मानदेय को बढ़ाने की भी मांग रखती हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं, राजसमन्द में राज्य सरकार के स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा का स्वागत करती हूं और मुख्य मंत्री जी को राजसमन्द की जनता की ओर से इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी ने, जब वह जीवित थीं तो उन्होंने, पिछले 4 सालों में बहुत बार प्रमुखता से यह मांग अलग-अलग माध्यमों से रखी थी। आज यह मांग पूरी हुई है तो इस बात के लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं लेकिन साथ में एक चिंता जरूर है, कि आपने यह बात अपने बजट घोषणा में की थी कि 22 जिलों में भारत सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय खोले हैं और 3 जिले जिनमें नहीं खोले हैं, उनमें हम चिकित्सा महाविद्यालय खोल रहे हैं। राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र जो कि जिला मुख्यालय भी है, यह आशा रखती हूं कि ये मेडिकल कालेज जो आपने राजसमन्द जिले के लिए घोषणा की है, ये वहां खोला जाए क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के बीचों-बीच आता है। इस पर बजट का आबंटन जल्दी से जल्दी हो। बजट के आबंटन में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिली है कि कितनी बजट की घोषणा है, यह जरूर घोषणा की गई है कि यह मेडिकल कालेज खोला जाएगा। 300 से 400 करोड़ रुपये लगभग हमें जरूरत होगी इस मेडिकल कालेज को खोलने के लिए, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि यह सिर्फ घोषणा न रह जाए और 300 से 400 करोड़ के बजट को जल्दी से जल्दी आबंटित करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घण्टे बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घण्टे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको आर.के. हास्पिटल, राजसमन्द, जो कि जिला मुख्यालय का अस्पताल है, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाना चाह रही हूं। वहां पर सुविधाओं के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अगर सोनोग्राफी करवानी होती है तो वहां पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता है, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स नहीं होते हैं। इसके बाद जब सोनोग्राफी बाहर से करवाती हैं 1,800 रुपये पेमेंट करके तो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक शाम हो जाती है और डाक्टर्स को प्राइवेटली जाकर दिखाना पड़ता है। हम यह कह तो रहे हैं कि सब कुछ फ्री है, हम उनकी सब-कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, पेशेंट्स की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, जनता की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो सुविधाएं हैं ही नहीं क्योंकि जब रिपोर्ट्स आती है तो कुछ ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि आनलाइन उनको मिल जाए ताकि वो फटाफट उस रिपोर्ट को डाक्टर को उस वक्त दिखा सके जब डाक्टर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो।

माननीय सभापति महोदय, वो सोनोग्राफी मशीन हमारे आर.के. हास्पिटल में हफ्ते में दो दिन चलती है और दो दिन भी दो-दो, तीन-तीन घंटे के लिए, वो भी हमने अगर कुछ हल्ला कर दिया, कहीं कुछ आम सभा में कर दिया, सी एम एच ओ को हम लोगों ने फोन करके बोला तो हमें खुश करने के लिए वो दो घंटे के लिए चला देते हैं कि देखो, हमने उस दिन चलाई थी, उसके अलावा वो सोनोग्राफी मशीन कभी चलती नहीं है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा गर्भवती महिला जब अस्पताल में जाती है डिलीवरी के लिए तो उसको यह बार-बार बोला जाता है कि आपको तो आपरेशन की जरूरत है, आप आपरेशन कराएं तभी बच्चा हो सकता है। कोई न कोई चीज उसको बताई जाती है और आपरेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, ताकि वो पैसे दे और बिना पैसे दिए आपरेशन नहीं होते हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि एक बार सर्विलांस टीम जो चुपचाप जाए, पेशेंट बनकर जाए और देखे कि अस्पतालों की क्या हालत है। ये दु:ख इस बात का नहीं है, आप इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता को सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। प्रोब्लम यह है कि जब जनता वहां पर अपनी सुविधा के लिए जाती है और आर.के. हास्पिटल एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि एक रैफरल हास्पिटल बन कर रह गया है।

माननीय सभापति महोदय, राजसमन्द जिला मुख्यालय है। छोटे-से गांव में कहीं भी कुछ भी होता है तो पेशेंट सीधा दौड़कर आर.के. हास्पिटल, राजसमन्द जिला मुख्यालय पर जाता है। सीधी एक पर्ची बना दी जाती है कि आपको हम रैफर कर रहे हैं, आप उदयपुर जाइए, एम बी हास्पिटल जाइए, अनन्ता हास्पिटल जाइए, कोई भी प्राइवेट हास्पिटल जाइए, चिरंजीवी से आपका उपचार हो जाएगा लेकिन यहां पर हम आपका उपचार नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, डिलीवरी का तो कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते पहले से या कोई इमरजेंसी होती है तो डाक्टर को देखना ही पड़ता है, अगर कोई आड आवर में चला जाए तो उसका क्या हाल होता होगा? मैंने स्वयं कॉल करके डाक्टर से निवेदन किया, प्लीज, आप इस महिला को देखिए, मुझे उसने साफ मना कर दिया। मुझे उस पेशेंट को उदयपुर के एम बी हास्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। जब उसका बच्चा हुआ तो उस बच्चे को ट्रोमा में, तीन महीने तक NICU में भर्ती रखना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, जब एक विधायक की बात भी डाक्टर्स नहीं मान रहे हैं तो जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा, यह हम नहीं सोच सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, तकलीफ यह है कि डाक्टर्स की भी कमी है, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की हमारे यहां राजस्थान में बहुत बड़ी कमी है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का गैप देखें तो एम पी डब्ल्यू के अकोर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स का जो रेशो होना चाहिए, जिसमें डाक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब होने चाहिए, 64 परसेंट का राजस्थान में गैप है। 64 परसेंट बहुत बड़ा

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

नम्बर होता है। हमें यह देखना चाहिए कि किस तरीके से यह गैप बढ़ा है। पिछले साल के आंकड़ों की तुलना मैं इस साल के आंकड़ों से करूं तो मुझे पता है कि वो आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन आज भी चार से पांच हजार डाक्टर्स की कमी है। करीबन 1,800 स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की राजस्थान में कमी है। इस कमी को हम पूरा करेंगे तो कहीं न कहीं जनता को सुविधा दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं कि इस योजना के तहत हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं सब कुछ फ्री में हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूं कि मैंने स्वयं ने, मेरे पास जो आते हैं लोग, वो कहते हैं कि मेरा चिरंजीवी का नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि, मैम, आप बोलेंगे तो वो चिरंजीवी के अंदर हमको एनरोल कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर की एक पार्षद हैं और उन्हीं के परिवार की एक सदस्य चिरंजीवी योजना में एक प्राइवेट हास्पिटल में एडमिट थी। 30 दिन तक उनको परमिशन नहीं मिली, आनलाइन पोर्टल से एक स्टेंट लगने के लिए। अगर 30 दिन में यदि हार्ट अटैक रिपीट हो जाता तो वो पेशेंट ही नहीं बचता। आनलाइन पोर्टल की स्थिति यह है कि परमिशन नहीं आ रही है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। बाईपास और ये तो आप इन्क्लूड नहीं करते, लेकिन ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को अलग-अलग भ्रमित करके कि हम एंजियोग्राफी करेंगे, लेकिन एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, लेकिन एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, अभी हमारे पास डाक्टर नहीं है, तो कुछ न कुछ बहाने बनाकर बार-बार भेज दिया जाता है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मुझे आठ मिनट ही हुए हैं, अभी तक तो मांग ही नहीं रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के लिए मांग रखना चाहती हूं कि सी एच सी, पी एच सी और सब-सेंटर्स खोले जाएं। फूटोल, राजावास, खटामला, जूमदा, चौकड़ी इनमें पी एच सी खोलने की मैं मांग रखती हूं। मेडिकल कालेज राजसमन्द में खोला जाए। नर्सिंग कालेज की बहुत ज्यादा जरूरत है जो राजसमन्द में खोला जाए। होम्योपैथिक क्लिनिक्स राजसमन्द में खोले जाएं। वहां पर 50 बेडेड हास्पिटल की मैं मांग रखती हूं।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जहां-जहां सी एच सी हैं वहां पर होम्योपैथिक क्लिनिक भी खोले जाएं, ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेदिक डाक्टर्स के हाल भी बहुत बुरे हैं, उसमें भी जरूर से जरूर और जल्द से जल्द और लोगों को लें, क्योंकि गांव के लोगों का बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास आयुर्वेदिक डाक्टर्स पर होता है। अगर वो डाक्टर्स भी रहें तो कहीं न कहीं एलोपैथिक डाक्टर्स को सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक आंकड़ा आपके सामने रखकर मैं अपनी बात फिनिश करूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, अपने समय में ही बात करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीब 6 हजार लोगों पर एक डाक्टर है, 250 लोगों पर एक नर्सिंग स्टाफ है, 33 हजार लोगों पर एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी या तो पी एच सी है, सब-सेंटर है, सी एच सी है या हास्पिटल है। 700 लोगों पर एक बेड है। जब यह स्थिति राजस्थान की है तो कोई भी मेडिकल फेसिलिटी को हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि जनता को यह सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात यही कह कर फिनिश करूंगी कि इन हालातों को देखकर, यह तय करना मुश्किल है कि मरीज ज्यादा बीमार है या चिकित्सा व्यवस्था ज्यादा बीमार है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इनका तो सिर्फ आरोप लगाने का ही एक काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, चिरंजीवी योजना चलाने के बाद में जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते थे 25 लाख रुपये तक का इलाज फ्री कर दिया। 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कर दिया। इसके बाद भी इन लोगों को कोई भी योजना अच्छी नहीं लगेगी। एक भी योजना की ये तारीफ नहीं कर सकते हैं। एम एल ए लैड के 05 करोड़ रुपये कर दिये मुख्य मंत्रीजी ने, वो भी इनको अच्छे नहीं लगे। इन्हें कोई भी काम इस सरकार का अच्छा नहीं लगता। एक भी काम के लिए इन्होंने आज तक यह नहीं कहा कि यह काम इस सरकार ने अच्छा किया। इन्हें तो हर काम में कानून लगाने का काम है। कमी निकालते रहेंगे। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय चिकित्सा

(श्री गिर्राज सिंह)

मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे बाड़ी में आपने 300 बेड का हास्पिटल स्वीकृत किया है अभी। बी जे पी के राज में एक भी बेड नहीं बढ़ाया गया अब तक। 53 बेड का हमारे यहां हास्पिटल चल रहा है, वही चला आ रहा था। इन्होंने एक भी काम नहीं किया, जबकि दो बार हमारे जिले की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी रह चुकी हैं।

(समय: 17.00 बजे)

न तो जिला लेवल पर कोई काम किया, न कोई विधान सभा लेवल पर काम किया, न कोई तहसील लेवल पर काम किया और न ही इन्हें चिरंजीवी योजना अच्छी लग रही है। इन्हें तो वह अच्छा लगेगा कि गरीब आदमी लुटते रहें। सभी बी जे पी के लोगों की पार्टनरशिप है बड़े-बड़े हास्पिटलों में। मेडिकल कालेजों में पार्टनरशिप है इन लोगों की। इन लोगों को तो सिर्फ लूटो-खाओ वाली योजना ही अच्छी लगती है। इनको कांग्रेस के राज की योजनाएं, जिनसे गरीब व्यक्तियों को फायदा मिलता है, वे पसन्द नहीं।

किसी का एक्सीडेंट हो जाये, उसका घर बर्बाद हो जाता है। भगवान करे किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यदि किसी के यहां कोई दुर्घटना हो जाये और उसके घर 10 लाख रुपये पहुंचें, यह भी इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाये, कोई मकान गिरवी रखकर नहीं आ रहा है, कोई खेत को गिरवी रखकर नहीं आ रहा है, कोई कर्जा लेकर नहीं आ रहा है, वह भी काम इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनका तो सिर्फ यही काम है कि हमें तो हर चीज में कमी निकालनी है। सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किये हैं। बहुत अच्छीअच्छी स्कीम्स हैं।

अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की है, मेरे यहां बाड़ी में 300 बेड का जिला लेवल का हास्पिटल किया है, उसके लिए काफी धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, मेरे यहां जो आपने 300 बेड का हास्पिटल खोलने की स्वीकृति दी है, वहां जमीन की कमी है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। हमारी मांग है कि बाजार के अन्दर हमारे यहां एक 55 बीघा की कृषि उपज मण्डी है, उसमें 8-10 बीघा में मण्डी चल रही है, बाकी जमीन खाली पड़ी है, तो हमारी बाड़ी की, बसेड़ी की, सरमथुरा की जनता की मांग यह है कि जो हास्पिटल खोला जाये, उसके लिए कृषि उपज मण्डी के अन्दर नयी बिल्डिंग बनायी जाये। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी बता दिया है।

(श्री गिर्राज सिंह)

मेरा आपसे निवेदन है कि उससे बढ़िया हमारे यहां कोई जगह नहीं है। बाजार के अन्दर बीच मार्केट में है। करीबन उससे 8-10 रोड्स लगी हुई हैं। बाईपास भी उससे लगता हुआ है। पुरानी रोड है, बसेड़ी रोड है, सरमथुरा रोड है, बाड़ी रोड है, वे सब इसे टच कर रही हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी कृषि उपज मण्डी में नयी बिल्डिंग आप बनाएं और वह थोड़ा समय पर चालू हो जाये। मंत्री जी, बाड़ी के पास बसेड़ी और सरमथुरा का लोड भी बाड़ी पर पड़ता है तो एक ट्रोमा सैंटर की यदि व्यवस्था हो जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। आपने कृपा तो काफी की है, पर एक कृपा और हो जाये तो हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी।

हमारे बाड़ी से धौलपुर की दूरी 33 किलोमीटर है। बोर्डर से लगाएं तो हमारे जिले की करीब 75 किलोमीटर की दूरी है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा यह ध्यान रखें।

सभापति महोदय, कुछ मांगें और हैं। समय ज्यादा नहीं लूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मेरी मांग है। एक हमारे यहां धनौरा गांव है, उसका नाम स्मार्ट सिटी रख दिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा भी गांव के लोगों को बुलाकर सम्मानित किया गया है। पूरे देश में यह पहला गांव है, जहां सीवर लाइन डली हुई है और साफ-सफाई और पेड़-पौधों से युक्त इतना अच्छा गांव बना हुआ है। हमारी मांग है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां हो जाये। एक डांग बसई है, एक सोहरई है, एक परउआ गांव है। ये हमारी चार मांगें हैं। आप जो भी कर सकते हैं, वह करें। हम मांग तो सभी रहे हैं, पर जो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, वह हमारे लिए देने की कृपा करें। वैसे आपने बहुत दिया है। हमारे लिए जो जिला लेवल का हास्पिटल मुख्य मंत्री जी और आपने कर दिया, मैं आप दोनों से पर्सनली मिला, आपने कहा कि हम आपके यहां कर देंगे, तो वह भी हो गया, पर मंत्री जी, समय पर थोड़ा यह काम चालू हो जाये। हमारे यहां जमीन नहीं है और बहुत परेशानी हो रही है हमें हास्पिटल की वजह से। यह काम हमारा समय पर हो जाये और कृषि उपज मण्डी में हमारा हास्पिटल बने, यह मेरी आपसे मांग है। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष जी पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी, मुझे आपने मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत

(श्री सुभाष पूनिया)

आभार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में कोविड की चर्चा भी आयी है। कोविड काल में पूरे विश्व में जब हाहाकार मचा, तब हमारे देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया और इस देश को बचाया। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। मैं इसी कड़ी में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डाक्टर्स और नर्सेज को भी, जब आदमी के पास आदमी, पड़ोसी के पास पड़ोसी नहीं जा रहा था, उस समय घर-घर जाकर कोविड काल में उन्होंने पेशेंट्स की सेवा की, उसके लिए निश्चित रूप से वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं मानता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सामने बैठे हैं, भले आदमी हैं, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इतनी हिम्मत की है। इस प्रदेश में कई सालों में किसी मंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं की, इन्होंने प्रतिनियुक्ति समाप्त कर जहां खाली पद थे, उन्हें भरने का काम किया। ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इस कोविड काल में भी, इस आपदा को भी लोगों ने जो अवसर मानकर काम किया, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से सेनिटाइजर, मास्क एन-95 और केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वेंटिलेटर्स को भी प्राइवेट हास्पिटल्स में देने का काम किया गया। बड़ी शर्म की बात है।

जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस थे, उनकी किस तरह से कालाबाजारी हुई, यह आम आदमी को मालूम है। जो आक्सीजन प्लांट्स लगे, उनमें भी खूब घाल-मेल हुई। अभी की ताजा घटना, जो हमें शर्मसार करने वाली है। बच्चे को अस्पताल से कुत्ता उठा ले जाये और उसे कुत्ता चबा जाये, निश्चित रूप से इस समय इस देश में इस प्रकार की घटना होना और वह भी राजस्थान प्रदेश में, बहुत ही निन्दनीय बात है। मेरे यहां आपने माडल सी एच सी बनायी, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन उस सी एच सी पर एक करोड़ रुपये हमारे विधायक कोटे से देने के बाद भी मेडिकल उपकरण धूल फांक रहे हैं। मैं धन्यवाद तो इसलिए दूंगा कि एक डाक्टर तो आपने लगाया है, लेकिन अब भी वहां डाक्टर्स की, टैक्निकल स्टाफ की बहुत कमी है। बेड के मामले में तो पता ही है, कई बार आपसे मैं आग्रह कर चुका हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी एच सीज हैं। तीनों सी एच सीज पर तीस-तीस बेड हैं। सूरजगढ़ म्युनिसिपैलिटी हैडक्वॉटर है, एस डी ओ हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। सन् 1957 से यहां म्युनिसिपैलिटी बनी हुई

(श्री सुभाष पूनिया)

है, उसके बावजूद 30 ही बेड हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे ऊपर सवा चार साल तक तो कोई उपकार नहीं किया है, लेकिन अब जब आप आये हैं तो आशा बंधी है कि निश्चित रूप से आप इन तीनों सी एच सी में बेड बढ़ायेंगे तो वहां की जनता का इलाज हो सकेगा।

सभापति जी, जनता क्लिनिक की घोषणा तो हो गई, लेकिन मेरे यहां तो जनता क्लिनिक का कहीं नाम नहीं है। जब यहां घोषणा हुई तो हमने भी जनता में जाकर कहा कि हमें बहुत जल्दी दो जनता क्लिनिक मिलेंगे, लेकिन अभी तक उनका कहीं नामोनिशान नहीं है। अब रही पांच-छह महीने की बात तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता क्लिनिक मेरे यहां खोल पाओगे। ठीक है, आगे सही। रही मेडिकल कालेज की बात तो झुन्झुनूं में तो बहुत पहले मेडिकल कालेज खुल चुकी थी और उसके बाद में जो मेडिकल कालेज खुलीं, वे बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन आज तक झुन्झुनूं कालेज का शिलान्यास तो नहीं हुआ पर बिल्डिंग बनने के काम का किसी से सुना है कि बिल्डिंग तो चालू हुआ है और उसको भी जल्दी बना दें, पर मुझे नहीं लगता कि आप अपने कार्यकाल में बना पायेंगे।

मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा। मैं राजस्थान आयुष चिकित्सा पद्धति विवरण आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इसमें सी एच सी के ऊपर आपने आयुर्वेद वाले तो 38.74 परसेंट ले लिये, लेकिन होम्योपैथी के डाक्टर हैं, उन एक-एक डाक्टर को सी एच सी पर लगा दें, क्योंकि उनकी संख्या भी आज 3.3 परसेंट ही है तो निश्चित रूप से ये जो होम्योपैथिक डाक्टर धरने पर बैठे हैं, ये भी लाभान्वित होंगे, उनको काम मिलेगा और जो अस्पताल में मरीजों का भार है, उन मरीजों को भी राहत मिलेगी।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ बात रखूं, उससे पहले मैं देख रहा था कि पी बी एम स्टोर फिजिकल वेरिफिकेशन में 50 करोड़ का घोटाला, तीन साल में एक भी जनता क्लिनिक शुरू नहीं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं है रेडियेशन फिजिशियन, छह महीने से धूल फांक रही है गामा मशीन, इस तरह के हालात इस प्रदेश में होंगे और इतना लम्बा चौड़ा आप खर्चा कर रहे हैं पर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता आज इस बात की है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो अपने इस प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वह चरमरा जाएगी।

(श्री सुभाष पूनिया)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऊपर आता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुहाड़वास में जो पी एच सी है, उसको आप सी एच सी में क्रमोन्नत करें। एक पचेरी में पी एच सी है, पचेरी भी कस्बा है, कुहाड़वास भी कस्बा है और पी एच सी बहुत पुराने समय से है तो उसको भी सी एच सी बनायें। बुहाना के लिए एक ट्रोमा सेंटर दें, क्योंकि बुहाना हरियाणा बोर्डर पर पड़ता है और वहां हर रोज दो-तीन एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वहां ट्रोमा सेंटर बन जाए तो जो भी एक्सीडेंट होते हैं उससे लोग वहां बच जाएंगे, नहीं तो झुन्झुनूं हमारे से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। बुहाना के लिए एक एम्बुलेंस की भी जरूरत है, वह भी मेरे यहां करने की आवश्यकता है। एक हासास गांव है, उसमें आप एक उप केन्द्र दें तो निश्चित रूप से वहां के लोगों की सेवा होगी। सूरजगढ़ सी एच सी में एक सर्जन व एनेस्थीसिया चिकित्सक का पद रिक्त है, जिनको भी भरें। बुहाना सी एच सी में एक सर्जन का पद रिक्त है तथा सूरजगढ़ व बुहाना सी एच सी में एक आर्थोपेडिक्स की जरूरत है जिसे भी जल्दी लगाने की आप कृपा करें। सिंघाना सी एच सी पर एक फिजिशियन का पद भी रिक्त है। मेरे विधायक कोष से दी गई एम्बुलेंस को 108 में शामिल करें, जिसके लिए मैं पहले भी आग्रह कर चुका हूं। वहां से सी एम एच ओ ने भी लिख दिया है, क्योंकि खड़े-खड़े उसके टायरों की तो हवा निकल गयी है और वे 20 लाख रुपये बेकार पड़े हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य अब शायद चले गये और वे कह रहे थे कि हमें तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे सवा चार साल में न तो एक बेड बढ़ाकर दिया, न कुछ किया है, इसलिए अब आपसे आशा करता हूं कि कम से कम बेड बढ़ाकर और जो डाक्टर्स की कमी है, उसके लिए मेरे ऊपर मेहरबानी करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री सुदर्शन सिंह जी रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने शानदार बजट दिया और लगातार 5वें साल चिकित्सा को लेकर बजट में बहुत स्थान मिला है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, जिसकी हमारे विपक्ष के

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

ज्यादातर साथी आलोचना करते नजर आ रहे हैं, यह चिरंजीवी योजना राजस्थान के लिए एक लाइफ लाइन बन गयी है और इसे 25 लाख रुपये तक किया। दुर्घटना बीमा का कवर बढ़ाकर 5 से 10 लाख किया और एक हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के फण्ड से लगाकर तीन मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की, जिसमें मेरे जिले राजसमन्द का मेडिकल कालेज भी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं। ई डब्ल्यू एस के लोगों को भी चिरंजीवी स्कीम में कवर करने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने रोडमैप बनाया है। आर यू एच एस, एस एम एस और तमाम जितने भी हमारे बड़े चिकित्सालय हैं, उनमें आधुनिकीकरण के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने विचार किया है। आउट साइड स्टेट, यानी राजस्थान से बाहर आर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो मुख्य मंत्री जी ने रिप्लाई में घोषणा की थी, वह बहुत स्वागत योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि कई सालों से जो पंचायत हैडक्वार्टर्स पर कोई सब-सेंटर्स नहीं थे, उनके लिए भी इस बार आपने अपाइंटमेंट की है, सब-सेंटर्स की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम घोषणाएं हमारे भीम विधान सभा क्षेत्र के लिए भी की हैं। चाहे भीम में एस डी एच बनाना हो, चाहे छापली में सी एच सी खोली हो, चाहे भीम में एम सी एच की घोषणा हो, मदारिया, शेखावास, अजीतगढ़ और सारोठ को पी एच सी बनायी है, सभी पंचायत हैडक्वार्टर्स पर सब-सेंटर की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। देवगढ़ में भी 50 से बढ़ाकर 75 बेड किये हैं और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना का जो दौर था उसमें सब लोग एक बड़े संकट से गुजर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पूरे देश में, राजस्थान में, सब तरफ मौत का ताण्डव मचा हुआ था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस जीवटता के साथ, जिस हिम्मत के साथ राजस्थान को सम्भाला, उसके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि

"जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है,

परन्तु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए होता है।"

अभिमन्यु बनकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की जनता

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

को इस कोरोना के चक्रव्यूह से निकालने की कोशिश की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने अपने भीलवाड़ा माडल से पूरे देश में राजस्थान को एक माडल बनाया। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने भी उन दिनों मेहनत करके दिन-रात काम किया और तमाम हमारे चिकित्साकर्मियों तथा सबने मिलकर राजस्थान को बचाने में पूरा योगदान किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे एम एल ए फण्ड को भी बढ़ाया और हेल्थ सेक्टर में हमारे सदन के सभी सदस्यों ने मिलकर एक 'टीम राजस्थान' के तौर पर काम किया और उस कोरोना पर हमने विजय हासिल की। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र की सरकार उस समय न तो फ्लाइट्स रोक पायी, न जल्दी लॉकडाउन लगा पाये, न सेंटर से कोई गाइडलाइंस टाइम पर दे पाये, जिसके कारण से पूरे देश में कोरोना आगे बढ़ता गया। और तो और एम पी फण्ड को भी रोक दिया गया, जिससे हमारे एम पीज गांवों में कुछ भी काम नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, उस कोरोना के दौर में हम उस सीन को नहीं भूल सकते, जब गंगा के तट पर लाशों के ढेर लगे हुए थे और ड्रोन पिक्चर्स में जो वीडियोज आपने और हमने देखे थे, वे इतने दर्दनाक थे कि जो हमारे विपक्ष के साथी यू पी को माडल स्टेट बताते हैं, उस माडल स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसमें फेल हो गये और हम सबको शर्मिन्दगी महसूस करनी पड़ी। पीएम केयर्स को लेकर बहुत आलोचनाएं हुईं। केन्द्र सरकार एक्टिव तो हुई पर बहुत लेट हुई और तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और देश के अन्दर कोरोना से बहुत लोग पीड़ित हो चुके थे।

माननीय सभापति महोदय, जब हेल्थ के बजट के ऊपर देखता हूं तो राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 2019-20 में 13 हजार करोड़, 2020-21 में 14 हजार 700 करोड़, 2021-22 में 16 हजार 270 करोड़, 2022-23 में 20 हजार 111 करोड़ और अब 2023-24 में 22 हजार 64 करोड़ दिये हैं तथा हेल्थ के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी का लगातार फोकस रहा है। और तो और केन्द्र सरकार और हमारी जो सेंट्रल काउंसिल है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसकी गाइडलाइन है कि 8 परसेंट के करीब राज्य के बजट का पैसा हेल्थ पर लगना चाहिए। उस दृष्टिकोण से भी माननीय मुख्य

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मंत्री जी ने पांचों सालों में राजस्थान के मुकाबले में, जो आल इंडिया रैंकिंग थी, 2019-20 में आल इंडिया स्टेट में 5.3 परसेंट, वहां हम लोग 6.2 परसेंट रहे हैं। जहां 2020-21 में साढ़े पांच परसेंट पूरे आल इंडिया हेल्थ एक्सपेंसेज, हम लोगों का 7.1 परसेंट था, 2021-22 में जहां 6 परसेंट आल इंडिया का था, वहां हम लोगों का 6.7 परसेंट था और 2022-23 में 6.3 परसेंट आल इंडिया का था, तो हम लोगों ने राजस्थान में 7.4 परसेंट बजटरी एक्सपेंसेज रखकर काम किया है। आगे भी 2023-24 में, हम लोग 7.4 के इस टारगेट से काम करना चाहते हैं।

एक ओर जहां राजस्थान भारत में हेल्थ सेट-अप के अन्दर सबसे आगे है, वहीं केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण, जिसे हम आउट आफ द पाकेट एक्सपेंसेज कहते हैं, एक टर्म होती है, ओओपीई हेल्थ आउट ले, यदि गवर्नमेंट का अच्छा होगा तो आम आदमी को अपनी जेब से हेल्थ पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, प्राइवेट हास्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा। जिस काम के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी संघर्ष कर रहे हैं।

भारत की जो रैंकिंग हैं, पांच देशों का ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका भी है। इन पांचों देशों के ब्रिक्स कंट्रीज के समूह में हम लोग सबसे नीचे हैं या यूं कहें कि आउट आफ द पाकेट एक्सपेंसेज सबसे ज्यादा अगर किसी का हो रहा है तो भारत के लोगों का हो रहा है, जिस पर केन्द्र सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। उसके कारण गरीब आदमी की गरीबी बढ़ रही है। केन्द्र सरकार जब तक तीन परसेंट जी डी पी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेगी, तब तक हमारे यहां माडल स्टेट, वेलफेयर स्टेट और हेल्थ के अन्दर अच्छा काम नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन-चार सालों के अन्दर तो हम इस तीन परसेंट के टार्गेट को टच नहीं कर पाये हैं। अब आगे जाकर क्या होगा, वह आपके सामने है। इस सेट-अप में ज्यादा पैसा नहीं लगाने के कारण ही, हमको कोरोना में बहुत परेशानी महसूस करनी पड़ी। सभापति महोदय, मैं पिछले पांच साल के बजट, यानी बी जे पी शासनकाल के हेल्थ के एक्सपेंसेज को जब देख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज, सुनिये। उनको डिस्टर्ब होता है। वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): आज सुबह से हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य सरकार की कमियां, खामियां निकाल रहे थे। निश्चित तौर पर, जब हम बड़ी योजनाएं लेकर आते हैं तो कहीं न कहीं कोई प्रोसिजरल प्रोब्लम्स होती हैं। उसको निश्चित तौर पर आप पाइंट आउट करें। हाल ही में, मैंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले पांच साल के शासनकाल के बजट को देखा तो बजट के पन्नों में हेल्थ को लेकर कुछ नहीं है। जब मैंने 2014-15 का हेल्थ का बजट देखा है तो न तो कोई पी एच सी, न कोई सी एच सी, न कोई सब-सेन्टर, न कोई डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, न कोई एक्सट्रा बेड। आप देखें, 2015-16 में भी यही हाल है, सिर्फ 50 एक्स्ट्रा बेड दिये हैं और बजट में कुछ नहीं दिया है। 2016-17 में 8 पी एच सी टू सी एच सी, नई पी एच सी 5 खोली और सब-सेन्टर टू पी एच सी 2 खोले और एक्स्ट्रा बेड 1170, आज हमारे विपक्ष के तमाम साथी बड़े जोर-शोर से बोल रहे हैं।

मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, हमारे विपक्ष के उप नेता यहां नहीं हैं, माननीय राठौड़ साहब से हम सब लोग बहुत सीखते हैं, परन्तु पिछले शासनकाल में 2013 से 2016 में चिकित्सा मंत्री थे, उस बजट के ये हालात हैं। आज जब भी वे विधान सभा में बोलते हैं, तमाम सदस्य उनको सुनते हैं। उनके विचारों को सुनते हैं, पर मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप सरकार में रहते हैं, तो आपके विचार कहां जाते हैं? क्या मुख्य मंत्रियों के सामने और प्रधान मंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बोलना मना है या फिर आप अपनी आवाज उठाते हो और आपकी आवाज उन लोगों को सुनाई नहीं देती है?

वर्ष 2017-18 का भी कमोबेश यही हाल रहा है। 6 पी एच सी टू सी एच सी, नई पी एच सी 4, सब-सेन्टर टू पी एच सी 2 और एक्स्ट्रा बेड 240. अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि जनता क्लिनिक सिर्फ 34 खुले हैं। आप पूरे शासनकाल में कुल मिलाकर 30 पी एच सी नहीं खोल पाये और आप जनता क्लिनिक की बात कर रहे हो। आप लोग जब अपने शासनकाल में होते हो तो काम क्यों नहीं करते हो या फिर यह सही है कि जनता आपको विपक्ष में बिठा रही है, विपक्ष में बैठकर किसी भी मुद्दे को उठाना, बेवजह उठाना, उसमें आपको जरूर महारत हासिल है। आप वह बड़े अच्छे तरीके से करते हो, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हो।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, कुछ सजेशंस हैं। सर, हमारे यहां पर एम्बुलेंस चल रही हैं। उनको एम एल ए फंड से या आर एम आर एस से नि:शुल्क किया जाये, क्योंकि जो एम्बुलेंसेज हमने कोरोना के समय डोनेट की थीं, उनके चार्जेज लगते हैं, उसके कारण तकलीफ होती है। निश्चित तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डाक्टर्स लगने चाहिए, क्योंकि गांव के इलाके में कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, उसके कारण तकलीफ होती है।

विपक्ष के साथियों की कई बातें अच्छी हैं। चिरंजीवी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। चिरंजीवी मुख्य मंत्री जी की ऐसी योजना है, जिसमें वे चाहते हैं कि गरीब आदमी की मदद हो। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो भी फ्लाज हैं, उनको दूर किया जाये। मुफ्त दवा और मुफ्त जांच में जिस किसी भी अस्पताल में नाकामी बरती जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये, ताकि सरकार का मोटिव डिफीट नहीं हो।

मेरी दो-तीन डिमांड हैं, वह मैं जरूर बोलूंगा। देवगढ़ के अन्दर, यह 35 पंचायतों का सेन्टर है। यहां पचास बेड का एक एम सी एच खोलने की कृपा करें। काच्यबली, लगेदखेड़ा, जैतगढ़ और ईसरमंड में नई पी एच सी और सब-सेन्टर देने की कृपा करें। देवगढ़ में एक ट्रोमा सेन्टर और नर्सिंग स्कूल देने की कृपा करें। आपने बोलने का अवसर दिया और हमारी विपक्ष के सभी साथियों को मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम सब लोगों को, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी से भी सीखना चाहिए। वे आपके लीडर थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री बने। उनको एक बार जब किडनी की प्रोब्लम हुई। माननीय सभापति महोदय, मैंने वीडियो में देखा था तो उन्होंने वर्णन किया कि राजीव जी को पता लगा कि मुझे किडनी की प्रोब्लम है और राजीव जी ने फिर उनको यू एन डेलिगेशन में भेजा, ताकि यू एस ए में उनका इलाज अच्छी तरह से हो पर यह साहस अटल बिहारी वाजपेयी रख सकता था, जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, राजीव जी ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आप लोगों को भी यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक जीवन में कोई भी अच्छा काम करें, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उसकी जरूर बात होनी चाहिए।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

अशोक गहलोत जैसा मुख्य मंत्री नहीं, जो सोशल सिक्योरिटी पर, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, प्रो-पुअर के ऊपर काम कर सके। ऐसा कोई मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान में नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने भी एक बहुत अच्छा काम किया है। उसकी मैं प्रशंसा करूंगा कि सेल डिजीज को लेकर के 2037 के लिए टारगेट लिया है। उसकी हम प्रशंसा करते हैं। विपक्ष के सभी साथियों को, जो अच्छा काम करें, उसकी जरूर प्रशंसा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: देखिये, 23 लोग अभी बोलने शेष हैं। जो अलाटेड टाइम है आपके इधर और उधर के सचेतक महोदय द्वारा, उस टाइम पर आसन पूरा ध्यान रखेगा। दो मिनट पहले, 8 मिनट हैं तो 6 मिनट पर घन्टी बजेगी, 2 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है, वह जरूर कह दीजिए। जिसके 7 मिनट हैं, 5 मिनट पर घन्टी बजेगी। आसन से घन्टी बज गई, इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। थैंक यू, वैरी मच। श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से मांग पर सभी वक्ताओं ने जोर-शोर से बड़ाई की, सच्चाई कहने वालों की वास्तव में वाहवाही करनी चाहिए, वे मानते हैं। आपकी सरकार के अन्दर हेल्थ में, आपने कौन-सी ऐसी पी एच सी और सी एच सी खोली? मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, तीन सी एच सी पहले से थीं। उन्होंने कई बार कहा कि हम सी एच सी खोलेंगे, आप हमें लैटर भेजो। एक भी सी एच सी नहीं खोली। हमारी पूर्व सरकार को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि तीन-तीन पी एच सी और उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे, लेकिन आपने एक भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला, पी एच सी की तो बात ही अलग है, लेकिन वाहवाही करते हैं, अच्छा काम करो तो धन्यवाद तो कम से कम दो। किस बात का धन्यवाद?

आपने जिस प्रकार से कोरोना के अन्दर भामाशाह स्कीम को बन्द किया, क्या आपको किसी ने मना कर रखा था कि दो साल तक भामाशाह योजना बन्द करें? अगर लागू करते तो उसी समय कर देते। लोग भागे-फिरे और प्राइवेट हास्पिटल्स ने लूटने का काम किया। उस समय आपको किसी ने रोका नहीं था। आदिवासी क्षेत्र से मुझे एम एल ए बनाकर विधान सभा में

(श्री समाराम गरासिया)

भेजते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में अगर भामाशाह चालू होती तो यह दशा नहीं बनती।

आप तो चुनाव को देखते हुए चिरंजीवी, चिरंजीवी से क्या मतलब है? आपने चिरंजीवी को धरातल पर लागू किया है क्या? आपके कई माननीय सदस्य हास्पिटल्स में धरना देते हैं कि चिरंजीवी सही ढंग से चालू नहीं थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक माननीय सदस्य श्री प्रताप भाई भील, जो गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र से सदस्य हैं, 25 तारीख को जब अकस्मात 8.00 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और जब वे हास्पिटल गये तो उनको एक पर्ची दी और एक भी दवाई अवेलेबल नहीं थी, तो क्या यह चिरंजीवी है? एक सदस्य है विधान सभा का और अखबारों में ऐसा आया था, सबको ध्यान होगा और आप कहते हैं कि हम मुफ्त दवाई देते हैं। क्या मुफ्त दवाई देते हो, एक भी मेडिसिन आपके पास अवेलेवल है क्या? एक भी कहीं मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है और हास्पिटल्स के अन्दर डाक्टर आप लोगों ने एक भी लगाया क्या?

हमारे माननीय चौधरी साहब सिरोही जिले के प्रभारी हैं। कई मीटिंग्स में मैंने इस आवाज को उठाया है कि हमने जब पी एच सी इतनी सारी बनाई हैं, हमारे पिण्डवाड़ा, स्वरूपगंज, भूला, रोहिड़ा, नितोड़ा जितनी भी बनी हैं ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, वहां पर आपने कोई डाक्टर नहीं लगाया है। ए एन एम खाली हैं, क्या आपने व्यवस्था की? इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? हम एम एल ए फंड से सोनोग्राफी, जनरेटर, सारे एम एल ए फंड से लगाते हैं। सिरोही जिला मुख्यालय पर देख लो, मुख्यालय पर एक भी कहीं किसी ने बड़ा काम किया? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्रदेश की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिला दिया।

सभापति महोदय, सारे के सारे लोग गुजरात में जाते हैं, वहां इलाज कराते हैं। क्या राजस्थान प्रदेश में ऐसे अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर सकते? एक भी सी एच सी पर अगर कोई मामूली सा आपरेशन किया हो तो बता दें यहां पर आपके सी एम एच ओ साहब को पूछ कर कि आबू-पिंडवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक भी कहीं आपरेशन हुआ हो। चार साल में इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है और जिस प्रकार आप कहते हैं, पूर्व में एक घटना हुई थी, जब पूर्व भाजपा सरकार द्वारा एक डा. पंकज शर्मा को 2018 में

(श्री समाराम गरासिया)

मुख्य आरोपी मान कर सी आई डी सी बी ने धारा 420, 468, 467, 471 और 120 के तहत मानसरोवर थाने में एफ आई आर दर्ज है और सरकार बदलते ही उसकी जमानत हुई। उसको डीन के पद पर आप द्वारा नियुक्त किया गया और वर्तमान में वह विश्वविद्यालय को संचालित कर रहा है, जबकि उसका लाइसेंस भी निरस्त है। क्या आप व्यवस्था कर पाओगे?

मैं सीधा आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार में पूर्व सरकार की भांति आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया है? चिरंजीवी में कहां व्यवस्था हुई है? आपने चुनावों को देखते हुए और जनता सब समझती है भले ही जोर-शोर से वाहवाही करो। बाकी है क्या आपके पास में? कुछ भी सामान नहीं है और आपको सबको पता है कि अपने को इस साइड में बैठना है। 2023 का इंतजार करना है, बाकी कहीं कोई नहीं है, कोई मामला नहीं है। मतलब आप जिस प्रकार से वाहवाही लेते हो, आपको पता है कि वाहवाही करना है और फिर मांग किस बात की करते हो, मांग क्यों करते हो? आपके सारे काम तो हो जाते हैं।

हम भी सरकार में रहे हैं, लेकिन हमने कभी मांग की ही नहीं। बिना मांग से सारा काम होता था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व मंत्रियों को, सरकार को, बाकी मैं तो यही आलोचना करता हूं और वास्तविकता कहता हूं और किस बात का धन्यवाद? बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय सभापति जी, आज आपने मांग संख्या 27, 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। यहां पर समस्त जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम बहुत कठिन था, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनसंख्या को जीवनदान देने जैसा काम किया है। मैं समस्त राजस्थानवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्य मंत्री जी का। कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, जिसमें गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, बुजुर्गों की सभी परेशानियों को सरकार ने एड्रेस किया है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा सभी परेशानियों को दूर किया गया है।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

सभापति महोदय, मैं बात करूं रामगढ़ विधान सभा की, तो पिछले सवा चार सालों में बहुत अधिक काम हमारे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। 27 तो सब-सेन्टर खुले और 4 पी एच सी खुली हैं, एक पी एच सी, सी एच सी हो गयी है। इसके अलावा कई एक्स-रे मशीन्स, सोनोग्राफी मशीन्स, एक्स्ट्रा बेड्स, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है और जो पिछला कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक भी सब-सेन्टर रामगढ़ में नहीं खोला गया था, यह आन रिकार्ड है। अभी हमारे साथी विधायक कह रहे थे बिन मांगे मिलता था, लेकिन रामगढ़ के विधायक तो मांगते-मांगते थक गये, पर उनको एक सब-सेन्टर भी नसीब नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं बात करूं रामगढ़ की, तो हमारे यहां एक नर्सिंग कालेज है जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन चूंकि वह किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच नहीं है तो वह रनिंग में नहीं है। मैं तो मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां पोस्ट सैंक्शन की जाये और रामगढ़ के हॉस्पिटल को हण्ड्रेड बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाये जो इस नर्सिंग कालेज से अटेच होगा और यह नर्सिंग कालेज चल पायेगा। देखने में आया है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत हमारे नर्सिंग स्टाफ ने की थी, डाक्टर्स ने की थी, तो मैं तो राजस्थान के समस्त मेडिकल विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में भी बहुत मेहनत की और हजारों की संख्या में लोगों की जान बचाई थी।

सभापति महोदय, अगर हम महिला स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का स्वास्थ्य एक मेजर इश्यू है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है क्योंकि उनके हीमोग्लोबिन 4-5 या 6 होता है। लेडी डाक्टर्स नहीं होती हैं, नर्सेज भी 24 आवर्स वहां नहीं रहती है। डिलीवरी कैसेज इतने अधिक आते हैं और सरकार जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर इतना फोकस कर रही है तो मुझे लगता है कि लेडी डाक्टर्स की संख्या हमें बढ़ानी चाहिये और यह तभी बढ़ सकती है, जब कालेजेज में आप लड़कियों की संख्या बढ़ायेंगे, उनके लिए सीट एक्स्ट्रा करेंगे। जब तक आप लेडी डाक्टर्स बनायेंगे नहीं तो लेडी डाक्टर्स को हम ग्रामीण इलाकों में लगायेंगे कैसे तो इनकी सीट्स बढ़ानी चाहिये, ताकि ये जाकर आगे ग्रामीण इलाकों में हमारी महिलाओं का ध्यान रख सकें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारी महिलाएं जेन्ट्स डाक्टर्स के पास जाना पसन्द नहीं करती हैं। यह बहुत मेजर इश्यू है गांवों में, जिसकी

(श्रीमती सफिया जुबेर)

वजह से महिलाएं दाइयों के पास भी चली जाती हैं, बच्चों की डैथ भी हो जाती है, मां की डैथ हो जाती है। ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन इसको एड्रेस करने की हमें बहुत अधिक जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी पूरी दुनिया में आपने देखा है कि स्पेशली गुड़गांव जैसे शहर में मेडिकल ट्यूरिज्म बहुत चल रहा है। जहां अच्छे हास्पिटल्स हैं, अच्छे डाक्टर्स हैं, फैसेलिटीज अच्छी हैं तो वहां विदेशी लोग आकर अपने आपरेशंस कराते हैं और एक मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से वहां किया गया, यहां भी अगर हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ये बड़े-बड़े जो शहर हैं अगर हमारे हास्पिटल्स अच्छे हो जायेंगे, सभी फैसेलिटीज आयेंगी तो काफी ट्यूरिस्ट का ट्रेफिक राजस्थान में भी आयेगा और वह यहां की आर्थिक व्यवस्था को और भी मजबूत करेगा।

सभापति महोदय, अगर जनसंख्या के आधार पर सरकार सब-सेन्टर्स, पी एच सी और सी एच सी खोले तो मुझे लगता है कि कहीं कोई विसंगति नहीं होगी, क्योंकि देखने में आया है कि बीस-बीस किलोमीटर में एक भी पी एच सी नहीं होती है। पचास हजार की जनसंख्या है इतने इलाके में और एक पी एच सी नहीं है जो नोर्म्स के खिलाफ है तो मुझे लगता है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है जनसंख्या की तो, जहां पांच सौ की आबादी है उधर एक सब सेन्टर तो आप लोगों को खोलना ही चाहिये और पन्द्रह हजार की आबादी पर आपको पी एच सी खोलनी चाहिये, ताकि वहां रहने वाले लोगों को हम मेडिकल फैसेलिटीज दे पायें। सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि सब-सेन्टर्स को हमें और स्ट्रेन्थन करना चाहिये या नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने चाहिये। चौबीस घंटे नर्सेज वहां रहें, प्लस यहां सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड हो और जो सरकार ने जांच वगैरह फ्री की है, उसका पूरा रिकार्ड सब-सेन्टर्स पर होना चाहिये और कम्प्यूटराइज्ड होना चाहिये। इससे एक तो आपके पास आंकड़े आ जायेंगे कि कौन से इलाके में क्या किस तरह की प्रोब्लम्स आ सकती है, क्या कमियां हैं, ताकि उसके हिसाब से वहां उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाये या उनकी काउन्सलिंग की जाये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुझे लगता है प्रिवेन्शन इज बैटर देन क्योर।

सभापति महोदय, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो हण्ड्रेड परसेंट होने चाहिये, लेकिन ये नहीं हो पाते हैं। मैं बात करूंगी अलवर की तो यहां 96-97

(श्रीमती सफिया जुबेर)

परसेंट और जो बचे 3-4 परसेंट रहते हैं, उनमें गलघोंटू जैसी बीमारियों से भी बच्चे मर रहे हैं। कुपोषित बच्चे भी हैं, एनेमिक महिलाएं भी हैं, तो इसका कहीं न कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम इस व्यवस्था को कैसे ठीक करें, ताकि कुपोषित बच्चों की हम पूरी सार-सम्भाल कर सकें। अगर एनेमिक हैं, महिलाएं कमजोर हैं, आदमी कमजोर हैं तो कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे टीबी और एड्स, ये भी बहुत चल रही हैं ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि इन पेशेन्ट्स को शर्म आती है वे बताते नहीं हैं परिवार को, वे चुपचाप दवाई खाते हैं, कभी छोड़ देते हैं तो उनका पूरा इलाज भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती रहती हैं तो मुझे लगता है इसकी भी बहुत जरूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे और गांव-गांव जाकर इनकी काउंसलिंग करे, ताकि ये बीमारियां न फैलें।

एक बहुत बड़ी बीमारी जो आजकल निकलकर आई है, खासतौर से कोरोना के बाद, वह है डिप्रेशन। मुझे लगता है कि सी एच सी पर कम से कम एक साइकॉलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तो होना ही चाहिये, क्योंकि हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। सभी स्ट्रेस में जी रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, क्योंकि वर्कलोड इतना है और हर तरीके की परेशानियां कहीं न कहीं होती हैं। आपने देखा स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए यह बहुत मेजर इश्यू है, जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिये। स्पेशली महिलाओं में तो आफ्टर 40 मेनोपाज के दौरान हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से कई सारी परेशानियां आती हैं। इसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये। विटामिन सी, डी, बी-12, जिंक, पता नहीं क्या-क्या कमियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से महिलाएं डिप्रेशन की पेशेंट हो जाती हैं, लेकिन गांव में तो यही नहीं पता महिलाओं को कि डिप्रेशन होता क्या है।

अब हम बात करें 'शुद्ध के लिये युद्ध' की, तो मैं कहना चाहूंगी खाद्य पदार्थों में इतनी ज्यादा मिलावट है कि लीवर डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे कि लीवर डैमेज केसेज बहुत बढ़ गये हैं। खास तौर पर दूध तो लगभग 50 परसेंट नकली आता है। उसमें कोई पाम आयल मिलाता है, कोई डिटर्जेंट मिलाता है, काली मिर्च में पपीते के बीज भी मिला देते हैं, दालों में भी कुछ-कुछ मिक्स कर देते हैं, जिसका असर दिमाग तक होता है। नकली दवाइयों पर कंट्रोल मुझे नहीं लगता है, हम कर पाये हैं। आपके ड्रग इंस्पेक्टर क्या इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी क्या रिपोर्ट आती

(श्रीमती सफिया जुबेर)

है, कौनसी नकली दवाई पकड़ी, इसका किसी को कुछ पता नहीं रहता है। मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

नशे के लिये नौजवान पता नहीं कैसी-कैसी दवाइयां लेते हैं, और उनको यह ईजीली मेडिकल शाप पर अवेलेबल है। मेडिकल शाप को भी आपको डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लिंक करना पड़ेगा। रोज उसकी रिपोर्ट जायेगी कि कौनसे डाक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब की और उसके स्टाक में से वह दवाई निकली। मैं यह पूछना चाहूंगी कि जब सरकार ने दवाइयां फ्री कर दी हैं, इलाज फ्री कर दिया है, जांच फ्री है, फिर भी हास्पिटल के बाहर इतनी दवाइयों की दुकानों में भीड़ लगी रहती है। ऐसी कौनसी स्पेशल दवाइयां दे रही हैं ये दवाइयों की दुकानें जो हम सरकार में नहीं दे पा रहे हैं। सरकार 1,600 के करीब दवाइयां फ्री दे रही हैं तो ये स्पेशल कौनसी दवाइयां हैं? अगर वे अच्छी दवाइयां हैं तो उनको क्यों नहीं लिस्ट में जोड़ लेते? आप एस एम एस के बाहर देखिये, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। इन दवाइयों की वजह से गरीबों पर तो मार अभी भी पड़ रही है और यह कौन डाक्टर्स हैं जो ऐसी दवाइयां लिख रहे हैं जो अंदर तो मिलती नहीं हैं, लेकिन बाहर मिल रही हैं।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी, हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, बीमारियां हो क्यों रही हैं, इसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप यूरिया, डी ए पी इतना अधिक किसानों को देते हो, जिनको कुछ आइडिया नहीं है और यह यूरिया, डी ए पी और इंजेक्शन वाली हम सब्जियां खा रहे हैं। इसका भी बहुत ज्यादा असर हम लोगों की हेल्थ पर हो रहा है, इसको सरकार को एड्रेस करना चाहिये।

अब हम बात करें आबकारी की, दवा की बात कर ली अब हम करेंगे दारू की...

श्री सभापति: थैंक यू मैडम।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): आठ बजे तक दुकानें खुली होती हैं और साढ़े आठ बजे पुलिस, जो दारू पीते हैं, उनको पकड़कर ले जाती है और बंद कर देती है। मुझे लगता है इस पर सोचना पड़ेगा, इससे महिलाओं का शोषण होता है। पीता तो कोई है और उसको झेलना किसी और को पड़ता है। मुझे लगता है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 और मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे संगरिया में डाक्टरों के पद खाली हैं, इसके लिये मैं बार-बार मांग करता रहा हूं। चिकित्सा अधिकारी के 7 पद स्वीकृत हैं, मौके पर 3 हैं; नर्स ग्रेड प्रथम के 7 हैं, मौके पर 4 हैं; एल एच वी के 6 पद हैं, मौके पर 1 है; प्रसाविका (ए एन एम) के 39 पद हैं, मौके पर 37 हैं। मेरे दो पी एच सी, जो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चल रहे हैं, उनके भवन नहीं हैं, पी एच सी, नुकेरा और पी एच सी, चक हीरासिंह वाला। ढाबां में दो साल पहले उप स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर हुआ था, उसका भी भवन नहीं है। ढाबां सी एच सी में 21 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी वहां 8 ही हैं, डाक्टर सिर्फ एक है, बाकी सब पद खाली पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि इनके पद जल्द से जल्द भरे जायें, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

मेरी टिब्बी सी एच सी में भी रिक्त पद पड़े हैं। हमारे वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का पद खाली है। दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली हैं। एक एल डी सी, एक यू डी सी, दो सहायक रेडियोग्राफर, 3 स्वीपर, 3 वार्ड बॉय एवं 3 क्लिनिकल रिकार्ड कीपर के पद खाली हैं। हमारे टिब्बी में पांच सी एच सी हैं, जिनमें मेहरवाला में पिछले साल पी एच सी मंजूरी हुई थी, उसका भवन नहीं है, अभी वह उप स्वास्थ्य केन्द्र में चल रही है। टिब्बी में 51 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें से 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन नहीं हैं। 2 एमजेडडब्ल्यू (मिर्जावालीमेर), 4 एमजेडडब्ल्यू (मिर्जावालीमेर), 7 एमजेडडब्ल्यू (डबली कलां), 13 डीबीएल (डबली कलां), 4 आरपी (डबली कलां), सिलवाला कलां (बेहरवाला कलां), 6 एसएलडब्ल्यू (सिलवालाखुर्द), 4-5 आरडब्ल्यूबी (मसीतावाली), 5 जीजीआर (2केएसपी), 11 एसएलडब्ल्यू (2केएसपी), 2 एमएसटीएसएम (डबलीखुर्द), 13 सीडीआर (सूरेवाला), मानक टिब्बी (खाराखेडा), 6 जीजीआर (टिब्बी) में भवन नहीं हैं। यहां भवन बनाने के लिये आप बजट दें, ताकि वहां पर लोग इलाज करा सकें। अभी ये प्राइवेट लोगों के घर में चल रहे हैं। पिछले साल आपने उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन दिये थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये जो भवन देते हो, उसके साथ चारदीवारी जरूर दिया करो। चारदीवारी आप देते नहीं तो वहां उसमें कुत्ते वगैरह आकर काफी नुकसान करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां चारदीवारी भी साथ में दें।

(श्री गुरदीप सिंह)

मैं कुछ मेरे उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये मांग करना चाहूंगा। पी एच सी, सुरेवाला को सी एच सी किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपीनी को पी एच सी किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीरकामडिया को पी एच सी किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र, खाराखेडा को भी पी एच सी किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र, सालीवाला को भी पी एच सी किया जाये। एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 केएसडी ग्राम पंचायत मालारामपुरा में भी मंजूर किया जाये। हमारी सी एच सी, संगरिया को भी अपग्रेड किया जाये। मेरी 26 पंचायतें और नगरपालिका हैं, मैं मांग करूंगा कि वहां इसको अपग्रेड किया जाये।

मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा-पंजाब से लगता हुआ है और वहां मेडिकल नशा और चिट्टा का नशा बहुत ज्यादा है। आपने बजट में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिये घोषणा भी की है। मेरे संगरिया से पंजाब-हरियाणा की बोर्डर लगती है, संगरिया में आप एक नशा मुक्ति केन्द्र खोलें, ताकि जो नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं, उनको नशे से बचाया जा सके और उनका इलाज करके उनको घर लौटाया जाये, ताकि उनके मां-बाप अच्छी जिंदगी जी सकें। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है और किस प्रकार आमजन को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिये निरंतर काम कर रही है। गत दो वर्षों में प्रदेश ने वैश्विक महामारी कोरोना का सामना किया, परंतु अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में कोरोना से बचाव का शानदार प्रबंधन माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा आमजन हेतु आयुष चिकित्सा पद्धतियां, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद को उपयोग में लेने की अपील की गई है। इन चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास को लेकर सजग है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने बजट में सभी चिकित्सालयों में पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

(श्रीमती मीना कंवर)

श्रीगंगानगर में आयुष चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है। सभी ब्लाक मुख्यालयों में होम्योपैथी चिकित्सा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। बालोतरा में होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गयी है। जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने की ऐतिहासिक घोषणा बजट में की गयी है। यूनानी महाविद्यालय जोधपुर में खुलने से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा सुविधा एक ही परिसर में आमजन को उपलब्ध हो पायेगी। राज्य सरकार ने 100 ब्लाकों में यूनानी चिकित्सा उपलब्ध कराने की घोषणा इस बजट में की है, जो कि सराहनीय है, परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस तरह आयुर्वेद चिकित्सा सभी ब्लाक में उपलब्ध है, होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा भी सभी ब्लाक स्तर पर उपलब्ध करवाने की घोषणा सरकार के द्वारा इस बजट में की जाये। उसी तरह यूनानी चिकित्सा सुविधा भी समस्त ब्लाक स्तर पर उपलब्ध करवायी जाये, ताकि समस्त आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ आमजन को ब्लाक स्तर पर उपलब्ध हो सके।

राज्य सरकार यूनानी, होम्योपैथी को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की घोषणा करे, ताकि आमजन को इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिल सके। इससे राज्य सरकार का निरोगी राजस्थान का सपना साकार होने में मदद मिले।

माननीय सभापति महोदय, जे के लोन अस्पताल राजस्थान ही नहीं, अपितु देश का बहुत बड़ा बच्चों का अस्पताल है। वहां सालाना शिशु औसत ओ पी डी 2022 में 3 लाख 5 हजार 42, लगभग 970 प्रतिदिन रही है। आई पी डी 47 हजार 868, लगभग 130 प्रतिदिन रही है। यह पेशेंट लोड एक यूनिट के द्वारा प्रतिदिन संभालना असंभव प्रतीत होता है। मरीजों के हित में मेरा अनुरोध है कि जे के लोन अस्पताल में शिशु विभाग में कार्यरत मेडिकल इकाइयों की संख्या तुरन्त प्रभाव से बढ़ाकर 10 मेडिकल इकाइयां की जायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जोधपुर में एमडीएम हास्पिटल में यू टी बी में जो डाक्टर लगे हुए हैं उन्हें परमानेंट करने की मेरी मांग है, यह आप अवश्य करें। आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री अविनाश)

चिकित्सा की मांग संख्या 27 और चिकित्सा शिक्षा की मांग संख्या 28 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे द्वारा लगाये गये कट-मोशन पर अपनी बात रखूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जैतारण मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय की स्वीकृति करायें। सी एच सी, जैतारण में ट्रोमा सेंटर बनायें, डायलिसिस सुविधा शुरू करवायें और साथ ही रिक्त पड़े महिला चिकित्सक का पद, सोनोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति दिलाने का श्रम करावें। साथ ही, जैतारण विधान सभा क्षेत्र के सभी सी एच सी, पी एच सी, सब-सेन्टर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 24 घन्टे बिजली आपूर्ति करने, सभी में पेयजल की व्यवस्था करने एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी सी एच सी, पी एच सी और सब-सेन्टर में रिक्त पदों को भरने, जर्जर हो गये भवनों की मरम्मत कराने, नवीन पी एच सी और सब-सेंटर स्वीकृत कराने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, अभी हाल ही में विधान सभा क्षेत्र जैतारण के नवीन स्वीकृत सी एच सी, बर और आनन्दपुर कालू की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर उनके नवीन भवन बनाने, उनमें चिकित्सक लगाने एवं चिकित्सा सुविधा शुरू करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार के अन्दर विधान सभा क्षेत्र जैतारण की आदर्श सी एच सी, जैतारण को 50 से 100 बेड में क्रमोन्नत करने की बजट घोषणा की थी। उसकी वित्तीय स्वीकृति देने, रिक्त पदों को भरने और पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण कराये जाने की आपसे मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नर्सिंग कालेज की स्वीकृति के लिए मांग करता हूं। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में फार्मेसी शिक्षा, लैब टेक्निशियन कोर्स एवं अन्य पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स की शिक्षा हेतु सरकारी संस्थान खोले जाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर चिकित्सा मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वह इसलिए कि मैंने जब-जब आपसे चिकित्सकों की मांग की, आपने मेरे वहां पर चिकित्सक लगाये। मैं इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि कल ही आपने मेरे जैतारण ब्लाक के अन्दर 18 चिकित्सक

(श्री अविनाश)

लगाये और रायपुर ब्लाक के अन्दर 5 चिकित्सक लगाये। मेरा निवेदन बस यह रहेगा कि चिकित्सक लगाने के बाद उनमें से अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जोइन नहीं करते हैं। ऐसा दिशा-निर्देश उन चिकित्सकों को जारी करें, ताकि वे पी एच सी और सी एच सी में जोइन कर लें, जिससे गांव की आबादी के लोगों को परेशानी नहीं हो।

अभी सफिया जी बात कर रही थीं कि बाहर की मेडिकल की शाप पर इतनी भीड़ होती है। मैंने सदन में पहले भी कहा था, ये सारी व्यवस्थाएं, हम लोग जितनी भी अच्छी पालिसी बनायेंगे, सबसे बड़ा कारण है इस प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या, जब तक जनसंख्या नियन्त्रण की पालिसी लागू नहीं होगी, न हास्पिटल में भीड़ कम होगी, न बसों में भीड़ कम होगी, न रेल में कम होगी, न हवाई जहाज में कम होगी, न मेले में कम होगी, न स्कूलों में कम होगी, न कालेज में कम होगी। इसलिए यह प्रदेश अगर जनसंख्या नियन्त्रण की पालिसी बनाकर पूरे भारत में एक नजीर पेश करे तो इससे बड़ा सौभाग्य इस सरकार का नहीं होगा। मैं इन डाक्टर्स के लिए जो कि दिन-रात मेहनत करते हैं, उनके लिए दो लाइनें कहूंगा।

"दिवाली की रोशनी, होली के रंग न होते,
जीवन के ये रंग-रंगीले उत्सव अंबर थम जाते,
मौत घरों में मातम करती,
यदि भगवान रूपी डाक्टर नहीं होते।"

इसलिए मैं डाक्टर्स का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय परोपकार के काम में मानव जीवन की सेवा में लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने कुल मिलाकर मेरे वहां पर 23 डाक्टर लगा दिये हैं। संभवत: मेरे जैतारण ब्लाक में जो पी एच सी हैं, 14 पी एच सी में शायद ही कोई ऐसी पी एच सी है, जिसमें चिकित्सक नहीं है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैतारण ब्लाक के अन्दर टोटल 38 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें 2 सी एच सी, एक नवीन सी एच सी आनन्दपुर कालू में खुल गयी है। एक जैतारण मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र में और उसके बाद पी एच सी एवं 21 सब-सेन्टर हैं। रायपुर ब्लाक के अन्दर सब-सेन्टर और पी एच सी में जो-जो खाली पद हैं, उनको भराने की कृपा करें।

(श्री अविनाश)

माननीय मंत्री महोदय, जैतारण की जो सी एच सी की बिल्डिंग है, वह बहुत कंजेस्टेड इलाके में है। वहां माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा 50 से 100 बेड की स्वीकृति की घोषणा की जा चुकी है। और तो और मुख्य मंत्री जी ने यहां 50 से 100 बेड की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक भी वहां पर स्टाफ थोड़ा-सा कम लगा हुआ है। उसकी बिल्डिंग को, या तो जो बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर बना दें या कहीं और शिफ्ट करके नया भवन बना दें, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। कहीं कोई हादसा न हो जाये, इसलिए मैं आपसे इसके नये सेंटर की मांग करता हूं। ट्रोमा सेंटर की मांग करता हूं क्योंकि दो-दो नेशनल हाईवे के बीच में ये सी एच सी स्थित है।

माननीय सभापति महोदय, जैतारण सी एच सी की ओ पी डी कम से कम 800 से 1000 की रहती है। 800 से 1000 की ओ पी डी के बीच में सोनोलाजिस्ट का पद रिक्त है, महिला चिकित्सक का पद रिक्त है, विशेषज्ञ चिकित्सक का पद रिक्त है, एनेस्थैटिक चिकित्सक का पद रिक्त है। आपने पिछले बजट में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने का एलान किया था। अभी तक जैतारण में शुरू नहीं हुई है। मैं आपके सहयोग से 01 अप्रैल से इस डायलिसिस मशीन को जैतारण में शुरू करने वाला हूं।

माननीय सभापति महोदय, सी एच सी निमाज, जहां भामाशाहों के द्वारा सी सी यू वार्ड बना हुआ है और वहां पर भी बहुत सारे पद खाली हैं। महिला चिकित्सक का खाली है, सर्जन का खाली है, विशेषज्ञ का खाली है। मैं मांग करूंगा कि निमाज सी एच सी में 30 बेड की क्षमता बढ़ाकर 50 बेड किया जाये। सी एच सी, रास के अन्दर विशेषज्ञ सर्जन, महिला चिकित्सक के पदों को स्वीकृत किया जाये। निमाज के अन्दर 8 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, उनमें छह कार्यरत हैं, दो के पद रिक्त हैं। नर्सिंग स्टाफ के छह पद स्वीकृत हैं, उनमें से तीन कार्यरत हैं और तीन रिक्त हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि एक डाक्टर के लिए कम से कम तीन नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जहां आठ पद स्वीकृत हैं, वहां पर कम से कम 25 का नर्सिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन निमाज सी एच सी में मात्र 6 नर्सिंग स्टाफ है, बाकी सारे के सारे रिक्त हैं। ये पोस्टें स्वीकृत कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। निमाज सी एच सी में जिस प्रकार की हालत है, माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग स्टाफ और हास्पिटल वालों ने जितनी मुझे जानकारी दी, 41 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 23 कार्यरत हैं और 19 पद रिक्त हैं। इनको भरने की

(श्री अविनाश)

कृपा करावें। लगातार अखबारों के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका में 'चिकित्साकर्मियों का टोटा, कैसे मिटे मरीजों का दर्द' यह खबर छपी है। दैनिक भास्कर में 'निमाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 41 पद स्वीकृत, 19 खाली' उनको भी मैं भरने का निवेदन करता हूं।

(समय: 17.59 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अभी इसी बजट वर्ष में आनन्दपुर कालू के अन्दर नयी सी एच सी की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी है। जहां पी एच सी का भवन पहले बना हुआ है, उसके बिलकुल पड़ोस में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन बना हुआ है। उस विद्यालय में अगर सी एच सी का भवन स्वीकृत कर दिया जायेगा तो इसमें बहुत बड़ी मेहरबानी हो जायेगी।

(समय: 18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक चिकित्सा अधिकारी की प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 209 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 133 कार्यरत हैं और 76 रिक्त हैं। इनको भरने के लिए आपसे निवेदन है। मैंने आपको बताया जैतारण पी एच सी, सी एच सी के अंदर जो आपने डाक्टर लगाए, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, एक और मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जैसा बजट के पैरा 49 से लेकर 60 तक आपने नवीन पी एच सी, सी एच सी, सब-सेंटर की घोषणा की थी कि हम खोलेंगे, इसी क्रम में सेंधड़ा, सुमेल, रेलड़ा, कानूजा, लाबड़ियावास, टूकड़ा, गरनिया, देवरिया भगतपुरा, ये सब-सेंटर हैं, इनको पी एच सी में क्रमोन्नत करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

साथ ही, पी एच सी, गिरी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। इलेक्ट्रोपेथी बोर्ड का गठन पूर्ववर्ती सरकार में 2018 में इसी विधान सभा के सदन से पारित हुआ। 5 अक्टूबर, 2018 को मुख्य मंत्री कार्यालय से राजस्थान इलेक्ट्रोपेथी सिस्टम आफ मेडिसन बोर्ड का गठन कर उसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों को नामित कर दिया गया, लेकिन पिछले चार साल से इसी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रोपेथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन को लटका कर रखा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसमें भी आप सहयोग करें।

श्री सभापति: श्री रफीक खां।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, सी एच सी स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में आपसे निवेदन है कि आप उसमें सहयोग करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया।

श्री अविनाश (जैतारण): साहब, आधे मिनट में। मात्र साढ़े तीन परसेंट के करीब ही होम्योपैथी चिकित्सा स्टाफ है। इसलिए उनको स्वीकृत करावें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में कोरोना काल के अंदर जितने भी लोग मर गये, जो मृतक हैं, उनको किसी भी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। उन्हें चिह्नित करके आप एक सूची बनाएं और अधिकारियों को निर्देश देकर उनको आर्थिक सहायता देने का काम कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन मांगों पर सकारात्मक रूप से माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दोनों पक्षों में बहुत सारी चर्चा हुई बहुत सारे विचार-विमर्श हुए। सबने अपने सजेशन और अपनी बातें रखीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में और खाली हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप नजीर देंगे तो राजस्थान से बढ़िया हेल्थ सेक्टर में किसी जगह काम नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूरे ब्रह्मांड में।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ब्रह्मांड की नौबत आवगी, जब ब्रह्मांड री भी बताऊंगा। एक बात और बता देऊं थानै, आप बार-बार फर्स्ट टाइमर कह कर संबोधित करते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। फर्स्ट टाइमर होने से कोई राइट नहीं बदल जाते हैं कि आपको चार वोट का राइट हो गया और मेरे को एक वोट का राइट हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कीजिए। आपसी वार्ता नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक शेर और बता देता हूं आपको इसी पर। 84 विधायक हैं फर्स्ट टाइमर। गालिब का शेर है।

(श्री रफीक खान)

"मेरे बारे में कोई राय मत बनाना,

मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी बदलेगी।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान, हिन्दुस्तान के अंदर वह स्टेट बना, जिसने नये आयाम सैट किये। जब 2019 में सरकार बनी तो निरोगी राजस्थान की कल्पना को लेकर मुख्य मंत्री आए, तब कोई कोविड नहीं था। तब किसी महामारी का अंदेशा नहीं था, लेकिन मुख्य मंत्री ने सपना देखा कि मेरे राजस्थान का हर आदमी निरोगी होना चाहिए। निरोगी राजस्थान की कल्पना की और उसके एक साल बाद में आप लोग ट्रम्प की चम्पी में मस्त थे उस वक्त और कोविड आ रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी महामारी आने वाली है कि लोग मरेंगे सुनामी की तरह। आप लोगों ने नहीं सुनी। राजस्थान वह पहला माडल स्टेट बना जिसने लॉकडाउन किया और राजस्थान के लॉकडाउन को देखकर आपने सबक लिया। बाकी नजीर दुनिया ने देखी है। आपके जयपुर वाले विधायक गायब हो जाते हैं। सांगानेर वाले सुबह बहुत भड़क रहे थे। एक-एक बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा मंत्री महोदय का रंग फीका पड़ रहा है। एक का गोरा हो रहा है। आपको बता देना चाहता हूं कि आप चिकित्सा मंत्री थे, जयपुर के डाक्टर्स को नहीं हिला पाए। एक सेंटर के ऊपर 60-60, 70-70 डाक्टर हाजिरी करके जाते थे एक सी एम एच ओ आफिस में। प्राइवेट जगह काम करते थे। यही वे मंत्री महोदय हैं, जिन्होंने स्ट्रांग डिसीजन लिया। पिछले चार मंत्रियों का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, कोई नहीं हिला पाया और ये हिला पाए। इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूं।

"दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं,

शायद जो वक्त-बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं,

मेरी गली से गुजरते हैं छिपाकर खंजर,

रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं।"

सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, जब कोविड आया हिन्दुस्तान के अंदर तो पूरे हिन्दुस्तान में किसी स्टेट ने अगर बेस्ट मैनेजमेंट किया तो वह राजस्थान है। भीलवाड़ा माडल प्रस्तुत किया, रामगंज माडल प्रस्तुत किया और एक नया एग्जाम्पल सैट किया। चाहे वह रेमडेसिविर अवेलेबल कराने का मसला हो, चाहे टेस्टिंग कराने का मसला हो, चाहे ब्लाक लेवल पर कोविड

(श्री रफीक खान)

मैनेजमेंट करने का मसला हो, चाहे इंजेक्शन रेमडेसिविर का मसला हो, चाहे इम्पोटेरेजिन का मसला हो, चाहे टोसेलिज्म का मसला हो। किसी भी दवाई के लिए आदमी को पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। हर आदमी को फ्री इलाज मिला। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि दूसरी स्टेट से लोग आए मेरे पास फोन आते थे, गुजरात के एम एल ए फोन करते कि एक टोसेलिज्म दिला दो, हमारे आदमी को रेमडेसिविर दिला दो, यहां तो ब्लैक में बिक रही है। यूपी में ब्लैक में बिक रही थी, गुजरात में ब्लेक में बिक रही थी और हरियाणा में ब्लैक में बिक रही थी और राजस्थान ऐसी स्टेट थी, जहां हम नि:शुल्क प्रोवाइड करवा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा मंत्री और मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को कि ऐसी नजीर सैट की। 2 लाख से ज्यादा मरीज एस एम एस के अंदर, अकेले एस एम एस के अंदर, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आकर राजस्थान के अंदर आकर इलाज करवा कर गये।

मैं कुछ कम्पेरिजन देना चाहता हूं कि कितने सब्सेंटर्स, हास्पिटल्स कितने दूसरी स्टेट्स में हैं और कितने राजस्थान में हैं। बहुत सारी क्रिटिसिज्म की। चिरंजीवी का क्रिटिसिज्म करोगे तो जनता हिसाब मांगेगी। 30 लाख से ज्यादा लोगों ने चिरंजीवी में फ्री इलाज करवाया है। 30 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन परिवारों के सामने आप जाकर चिरंजीवी का क्रिटिसिज्म करेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। वोट मांगने जनता के बीच जाओगे। एम पीज की तरह मत कर लेना कि चुनकर राजस्थान से जाओ और बात करो दिल्ली की। जब कोविड के समय मदद करने की नौबत आए तो आप पैसा दो प्रधान मंत्री को, मुख्य मंत्री की बात मत कीजिए। चुना राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की खाओगे और दिल्ली की गाओगे तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता के बीच में जाओगे तो जवाब देना पड़ेगा।

सब-सेंटर कितने हैं? राजस्थान के अंदर पर-एक लाख की पापुलेशन में सब-सेंटर 18, टाप पर है। पूरे हिन्दुस्तान में टाप पर है। यूपी में कितने हैं? 8, गुजरात में कितने हैं? 12 और राजस्थान में हैं 18, हिसाब लगाना ये जितने भी सवाल कर रहे थे। उनको बताइए कि राजस्थान वह माडल स्टेट है जो हेल्थ के मामले में हर जगह पहले नंबर पर है। पी एच सी, हर दस लाख आदमी के ऊपर राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 32, उत्तर प्रदेश में है 15, आधे से भी कम है। 40 परसेंट भी नहीं है आबादी के हिसाब से। गुजरात में कितनी है? 25 और राजस्थान में 32 है। आपको यह समझना

(श्री रफीक खान)

पड़ेगा कि पहली उंगली उठाएंगे तो बाकी की चार-पांच उंगलियां आपकी तरफ हो रही हैं। पूरे इंडिया का हिसाब लगाइए और सोचिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अगर हेल्थ के मामले में क्रिटिसाइज करेंगे तो सारी दुनिया को मालूम है कि सबसे ज्यादा काम अगर किसी फील्ड में हुआ और किसी डिपार्टमेंट में हुआ तो वह हेल्थ है राजस्थान के अंदर।

मेडिकल कालेज। अभी प्रीति जी बोल रही थीं, धन्यवाद तो दिया है इन्होंने। सांगानेर वाले विधायक भी बोल रहे थे। एक और बोल रहे थे। वासुदेव जी भी बोल रहे थे। मेडिकल कालेज की आप बात करो, आंकड़ा तो दे दूं थानै, अभी से ही क्यूं तकलीफ हो रही है? मंत्री जी तो शेर बनकर आवगा, छा जावगा थारै ऊपर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आग्रह करूंगा, आप आसन को संबोधित करें। इन्हें इनवाइट मत कीजिए। समय पर अपना काम करें। बहुत से वक्ता बोलने से रह जाएंगे। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेडिकल कालेज, 50 लाख की पापुलेशन पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, शेर बघेरों से तो बचाइए हमें। ये कह रहे हैं शेर आ जाएगा, खा जाएगा, हम तो वैसे ही डरे बैठे हैं। इनको कहिए इंसानों की बात करें। मेडिकल पर बहस हो रही है। ये शेर-बघेरे ला रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 50 लाख की पापुलेशन से ऊपर मेडिकल कालेज गुजरात में 1, राजस्थान में एवरेज 2.5 का और उत्तर प्रदेश की बात करो तो 1 का भी एवरेज नहीं है। एलोपैथिक डाक्टर्स पर-लाख, उत्तर प्रदेश में 5, गुजरात के अंदर, गुजरात का तो नंबर ही नहीं है इसमें। गुजरात में तो 5 से भी नीचे है और राजस्थान के अंदर 18, इससे आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि राजस्थान में कितनी संख्या के ऊपर कितने डाक्टर अवेलेबल हैं। नर्सिंग स्टाफ।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं दो मिनट में मेरी डिमांड रख देता हूं, नहीं तो मेरी डिमांड रह जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान बेस्ट

(श्री रफीक खान)

मैनेजमेंट स्टेट है अगर स्वास्थ्य की बात करो तो। पूरी दुनिया से लोगबाग राजस्थान में इलाज करवाने आते हैं, जयपुर में इलाज करवाने आते हैं।

मैं दो बातें मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लिए कहना चाहता हूं कि मेरे यहां की दो डिस्पेंसरीज, मंत्री महोदय, दूसरी जगह पर चल रही है गोरधनपुरी और वनविहार की, तो मेरी आपसे सदन के माध्यम से यह गुजारिश है कि ये दोनों डिस्पेंसरीज मेरे यहां पर खोली जायें। जिस तरह से आपने आयुर्वेद और दूसरे डाक्टर्स की भर्ती की है तो होम्योपैथिक और यूनानी की भी भर्ती उसी तरीके से की जाये। एट-लीस्ट 350 सीट्स यूनानी में हमें क्रिएट करनी चाहिए जिससे आम आदमी को और जो डाक्टर्स काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितनी भी राजस्थान के अन्दर योजनाएं हैं, 2011 में जब हमारी सरकार थी तो 2011 में हमने फ्री दवाई की स्कीम शुरू की थी और जब 2022 के अन्दर हमारी सरकार दुबारा आयी तो हमने किसी भी दवाई को पेंडिंग नहीं रहने दिया और सभी तरह की दवाई सब आम आदमी के लिए फ्री कर दी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि दस लाख रुपये तक की बीमारी का इलाज पहले फ्री करते थे और जैसे ही यह पिछला बजट मुख्य मंत्री ने दिया तो दस लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपये कर दी। कुछ ऐसी बीमारियां थीं, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो दस लाख से ऊपर की उनको बीमारी के इलाज में जरूरत पड़ती थी तो कुछ डिजीज के अन्दर लोगों के पास में, गरीब आदमी, आम आदमी, मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ कि उसके यहां काम करने वाले एम्प्लाई की जब दस लाख रुपये की यह सीमा खतम हो गयी तो उसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो ऐसे लोगों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने गरीब आदमी की सुनी और उसकी सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपये कर दी।

मैं एक और कम्पेरिजन यहां पर देना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य अधिकतम औषधि और सर्जिकल ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बस, एक मिनट में कन्क्लूड करता हूं। 1553 दवाओं की संख्या जो राजस्थान सरकार प्रोवाइड करवा रही है, दूसरे राज्यों में इसकी संख्या 650 से भी कम है।

(श्री रफीक खान)

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 एवं 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्षों के बजट में निरोगी राजस्थान की बात कही है। भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया। नाम बदलकर अब राजस्थान माडल स्टेट होने का प्रचार किया जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मेरा यह निवेदन है कि प्रदेश की सरकार आत्म प्रशंसा से बाहर आकर चिकित्सा के क्षेत्र में आम अवाम को आ रही परेशानियों को समझकर चिकित्सा विभाग का स्वास्थ्य पहले ठीक करे।

मैं कुछ उदाहरणों का उल्लेख करूंगा इस मामले कि गत दिनों सिरोही के जिला अस्पताल में एक मां के पास सोए हुए नवजात शिशु को कुत्ता उठाकर ले गया और नोच कर मार डाला। इस घटना को देखकर भी सरकार की संवेदना जगी या नहीं जगी, यह आप बतायें। अभी हमारे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे तो वे सरकार की बहुत बड़ाई कर रहे थे तो आप यह बतायें कि एक कुत्ता बच्चे को उठाकर ले जाता है और हास्पिटल वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में 35 दिनों में 107 बच्चों की मौत हो गयी तो क्या यह सरकार संवेदनशील है? क्या यह अव्यवस्था की पराकाष्ठा नहीं है? जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि बच्चों की मौत ठंड से हुई है। वहां के हीटर व वार्मर खराब थे।

प्रदेश के अस्पतालों में एक्सपायरी दवाइयों के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में कचरे व राख के ढेर के बीच एक्सपायरी दवाइयां पड़ी हुई मिलती हैं। उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में पचास लाख रुपये की मेमोग्राफी मशीन जो स्तन कैंसर के काम आती है, वह खराब पड़ी है पर वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हर चीज की बड़ाई करते हैं पर यह नहीं सोचते हैं कि राजस्थान में यह क्या हो रहा है।

अभी राजस्थान की सरकारी दवाई से कोई आदमी, गांव का कोई आदमी भी इलाज करवाना नहीं चाहता है। वह टैबलेट नहीं लेना चाहता है।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

उसको राजस्थान की सरकार की दवाइयों पर विश्वास नहीं है क्योंकि वह दवाई इलाज नहीं करती है। मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलायें कि ये जो सरकारी दवाइयां जो आपने मुफ्त दी हैं, ये पूरा इलाज करेंगी, उससे आम गरीब आदमी, जनता का इलाज होगा तब ही जाकर यह अच्छा होगा।

कई बार निजी लैब में रोगी भेजने के लिए भी मशीन में खराबी बता दी जाती है तो इस विषय में मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। प्रदेश में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित एम्बुलेंस के लिए कोई नियम एवं किराया दर भी तय नहीं है। रोगियों के परिजन इनकी मोनोपॉली से परेशान हैं और वे मजबूरीवश अधिक किराये का भुगतान करते हैं।

मैंने अभी हमारे बिजौलिया चिकित्सालय में एम्बुलेंस दी थी परंतु वह छह महीने खड़ी रही। वहां के डाक्टर उसके ड्राइवर की व्यवस्था नहीं कर पाये और डीजल की व्यवस्था भी नहीं कर पाये तो अब उसको 108 में देनी पड़ी है। यह इसलिए अपनी राज्य सरकार की व्यवस्था है।

दौसा जिले से चिकित्सा मंत्रीजी सहित तीन-तीन मंत्री आते हैं। वहां का नमूना बताता हूं कि दौसा जिला अस्पताल का ड्राइवर शाहिद खान एम्बुलेंस में जूते-चप्पल के बोरे ले जा रहा था। उसका वीडियो वायरल हुआ और अखबारों में छपा है। यह आपकी राजस्थान सरकार की व्यवस्था है जो आपके सामने पूरे राजस्थान के अखबारों में छपा है।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गये हैं। नाम तो बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन नाम से हेल्थ की वेलनेस नहीं होगी। कर्मचारी, दवाइयां एवं जांच की पूरी व्यवस्था होगी तब ही हेल्थ की वेलनेस होगी, तब ही जाकर अच्छा होगा।

मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिंदु संख्या 12 में है कि प्रदेश स्तर पर, सभी 7 सम्भागीय स्तर पर इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ कालेज खोले जाने की घोषणा की गयी है। क्रियान्विति स्वरूप प्रथम चरण में इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ, जयपुर खोला गया है जिसकी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि उस हेल्थ सेंटर में गत चार माह से कक्षाएं नहीं लग रही हैं और पच्चीस सीटों के विरुद्ध में केवल पन्द्रह छात्रों का ही प्रवेश होना, यह दुर्दशा है। एम.पी.एच. पाठ्यक्रम

(श्री गोपाल लाल शर्मा)
की स्कीम में एग्जामिनेशन करने के लिए गठित बोर्ड में किसी भी सदस्य का एम.पी.एच. योग्यताधारी नहीं होना। द्वितीय सेमेस्टर की एक भी कक्षा नहीं लगना, यह मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा का काम है जो आपके सामने है।

मैं मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की मांग करता हूं कि मेरा भीलवाड़ा जिला अस्पताल जो कि मेडिकल कालेज भी है, हमारे वसुन्धराजी की सरकार में मेडिकल कालेज खोला गया, परंतु वहां पर एक कार्डियक केयर यूनिट नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहुत से आदमियों के हार्ट अटैक होता है और वे मर जाते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो मिनट, साहब। मेरा माण्डलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, पूर्व में मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर साहब ने रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया था परंतु वापस माण्डलगढ़ सामुदायिक अस्पताल कर दिया गया है जो वहां की जनता के साथ अन्याय है। मैं यह मांग करता हूं कि माण्डलगढ़ अस्पताल को उप जिला अस्पताल घोषित करें।

माण्डलगढ़ में एक्स-रे मशीन खराब है, सोनोग्राफी मशीन खराब है तथा डाक्टर्स और कम्पाउंडर्स के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। माण्डलगढ़ शहर बहुत बड़ा कस्बा है और वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। सिजेरियन आपरेशन तक की भी व्यवस्था नहीं है और वहां पर 50 किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा ले जाना पड़ता है। इसी तरह से मेरा बडलियास कस्बा, जो कि 1971 में पी.एच.सी. हास्पिटल खुला था, वहां 53 वर्ष के बाद भी उस पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। वहां का भवन इतना पुराना जर्जर हो गया है कि बारिश के दिनों में वहां पर डाक्टर्स के बैठने की जगह भी नहीं है और एक भी डाक्टर वहां पर नहीं है। वहां पर डिलीवरी तो होती है, परंतु सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। मेरे उस बडलियास के पास ही यह आमा कस्बा है, वहां पर महीने में सौ से ज्यादा डिलीवरी होती है, परंतु वहां पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं यह मांग करता हूं कि आमा और बडलियास में दोनों सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था भी आप करायें।

बडलियास में एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है, क्योंकि भीलवाड़ा तीस किलोमीटर दूर है और इसका कोटड़ी मुख्यालय, उप खण्ड कार्यालय 25

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

किलोमीटर दूर है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे बिजौलिया कस्बे में जो भीलवाड़ा शहर से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने बजट में ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी, परंतु अब तक वह ट्रोमा सेंटर नहीं खुला है और वहां पर कोई भी सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर डाक्टर है, परंतु वहां पर यह निश्चेतना करने वाला डाक्टर नहीं है, तो इससे अन्य डाक्टर्स भी काम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): बिजौलिया में 100 बेड का चिकित्सालय खोलने की मांग करता हूं। मेरे काछोला कस्बे में चार डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं पर वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): मैं मेरे क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्रीमती रमीला खड़िया। आप विराजिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): 000

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 एवं 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरा छोटा में 30 बेड का अस्पताल था, उसको बढ़ाकर 50 बेड का कर दिया, हमारे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 100 बेड थे, उसको 100 बेड से 150 बेड किये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसारवाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया। उप स्वास्थ्य केन्द्र, जीवाखुटां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरा छोटा; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवा; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उकाला; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन में बेड बढ़ाये व भवन के लिए पैसे दिये। वह काम आज की तारीख में प्रगति पर है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा पर है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब और मंत्री महोदय को बहुत

(श्रीमती रमीला खड़िया)

बहुत धन्यवाद देती हूं कि मेरे विधान सभा के भीलकुआं में ट्रोमा सेन्टर खोलने की घोषणा की। मैं दोनों हाथ जोड़ कर मेरी जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र मुझे दिये। बावड़ीपाडा, कुण्डा, मछारासाथ, गोंडा, नयागांव पालीछोटी, महुडी मस्का वाली, देवदासाथ, बिलीपाडा भीमपुरा, वरसाला, मुदडी, गोपालपुरा, सरोना, बावडिनिनामा, आमलीपाडा, खजुरा, भवरदा, कुल 15 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में डाक्टर्स नहीं हैं। वहां सी एच सी में टोटल 46 पद हैं, उनमें से 17 पद भरे हुए हैं और 25 पद खाली पड़े हुए हैं। छोटी सरवा में टोटल 5 पद हैं, उनमें से एक पद भरा हुआ है और चार पद खाली पड़े हुए हैं। सज्जनगढ़ में 5 पद हैं, उनमें से दो पद भरे हुए हैं और तीन पद रिक्त पड़े हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रिक्त पदों को मंत्री महोदय भरवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की योजनाओं के तहत आयुर्वेद का कैम्प लगाया गया था, उस कैम्प में करीब 1,072 रोगियों को ठीक किया गया है। बहुत अच्छा कैम्प था। रिटायर्ड डाक्टर्स भी उस कैम्प में आये और सभी तरह की बीमारियों का इलाज उन्होंने किया। अच्छे से इलाज हुआ। टोटल 4,742 रोगियों को उन्होंने ठीक किया है। हमारे यहां आयुर्वेद का भवन नहीं है तो मैं मांग करती हूं कि मेरे यहां आयुर्वेदिक भवन के लिए बजट दें जिससे वहां अच्छा भवन बने और अच्छी तरह से डाक्टर काम करें।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के कसारवाड़ी में सी एच सी क्रमोन्नत हो गयी है। उसके लिए मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब और मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 एवं 28, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली इस मायने में हूं कि मैं जिस जिले और जिस शहर से चुन कर आता हूं वहां ई एस आई सी का मेडिकल कालेज संचालित है और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अलवर शहर में कालेज का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। मैं भाग्यशाली इस मायने में हूं कि हमें सौगात में दो-दो मेडिकल कालेज मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेडिकल कालेज अलवर शहर में निर्माणाधीन है, आने वाले समय में बहुत जल्द ही उसमें सत्र भी शुरू हो जायेगा और हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। शहर की जनता को अच्छा इलाज मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर का जो सामान्य चिकित्सालय है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, उस सामान्य चिकित्सालय में अलवर शहर सहित अलवर जिले के, साथ ही साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मरीज भी इलाज करवाने आते हैं और वहां पर हमारे पास जो स्वीकृत बेड है, सामान्य चिकित्सालय में 332 बेड स्वीकृत हैं और वहां आज की तारीख में 437 बेड लगे हुए हैं, यानी कि 105 बेड अतिरिक्त लगे हुए हैं। यदि मैं महिला चिकित्सालय की बात करूं तो 255 बेड स्वीकृत हैं, 301 बेड लगे हुए हैं। 46 अतिरिक्त लगे हुए हैं। कुल मिला कर स्वीकृत बेड 587 हैं और लगे हुए 738 हैं, यानी कि 153 बेड अतिरिक्त लगे हुए हैं और लगभग पूरे साल हमारी यही स्थिति रहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो हमारी महती आवश्यकता है, वहां की बैड्स की संख्या में वृद्धि की जाये। सामान्य चिकित्सालय में ओ पी डी लगभग 2,500 से अधिक होती है। कल की मैं बात करूं, दो तारीख को ओ पी डी की संख्या सामान्य चिकित्सालय में 2215, जनाना अस्पताल में 310 और शिशु वार्ड में 662 थी। अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में महती आवश्यकता है इसलिए वहां बेड की संख्या बढ़ायी जाये। साथ ही वार्ड बनाने के लिए भी बजट का अतिरिक्त आबंटन किया जायेगा तो निश्चित रूप से अलवर शहर सहित अलवर जिले के आमजन को और आस-पास के क्षेत्र के मरीजों को भी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधायक की अनुशंषा पर माडल सी एच सी का चयन करने का अधिकार दिया था और उसके निमित्त मैंने राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य

(श्री संजय शर्मा)

केन्द्र मूंगस्का, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह बताते हुए कि मेरे शहर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। जो 6 सिटी डिस्पेंसरीज हैं, वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। मैंने लिख कर भी यही दिया था और वह स्वीकृत भी हो गयी। मॉडल सी एच सी के रूप में हमसे लगभग सवा करोड रुपये विधायक निधि से मांगे गये थे, लेकिन एक साल बाद आपके विभाग द्वारा उस आदेश को निरस्त करते हुए यह कहा गया कि चूंकि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसलिए हम इसको बनाने में सक्षम नहीं हैं। आप किसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख कर दें तो हम उसको क्रमोन्नत कर देंगे मॉडल सी एच सी में।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नम्बर 1, जगन्नाथजी की डिस्पेंसरी, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नम्बर 2, एन ई बी, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नम्बर 4, शिवाजी पार्क, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़गंज, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूंगस्का; राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अखैपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि आप क्रमोन्नत करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में रहने वाली जनता को भी लाभ मिलेगा और जो मांग विभाग ने मुझसे की है, तो इनमें से ही किसी एक को माडल सी एच सी के रूप में मैं अलवर शहर की जनता को सौगात के रूप में आपके माध्यम से दे सकूंगा। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सामान्य चिकित्सालय, अलवर में हमारे स्पेशलिटी चिकित्सकों की बहुत भारी मात्रा में कमी है। चाहे वह कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरो फिजिशियन हो, न्यूरो सर्जन हो, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हो, इन चिकित्सकों की महती आवश्यकता है। यदि आप इन चिकित्सकों की वहां पर नियुक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर शहर सहित पूरे जिले की जनता को लाभ मिलेगा। चिकित्सकों के कुल 71 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 65 भरे हुए हैं और 7 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के 6 पद रिक्त हैं, उप नियंत्रक का एक पद रिक्त है, मेडिकल आफिसर के 5 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ व कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों के विरुद्ध मेडिकल आफिसर लगाये हुए हैं तो जनरल मेडिसन चिकित्सक का पद शल्य रोग या नाक, कान, गला रोग या दंत चिकित्सकों के माध्यम से भरे हुए हैं। रेडियोलॉजिस्ट के दो पद,

(श्री संजय शर्मा)

एक पद पर किसी और को लगा रखा है, एक पद रिक्त है। सामान्य चिकित्सालय, जनाना चिकित्सालय में डिप्लोमाधारी चिकित्सकों से सोनोग्राफी करवाकर काम चलाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो हमारे यहां रिक्त पद हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरकर अलवर शहर सहित अलवर जिले की जनता को राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा और मांग भी करूंगा कि अलवर शहर में जो जनाना अस्पताल है, उसके लगता हुआ शिशु वार्ड है। उसके बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है गीतानंद शिशु चिकित्सालय और उस शिशु वार्ड में वर्तमान में 12 चिकित्सक कार्यरत हैं। 79 बेड्स स्वीकृत हैं, जिनमें 42 जनरल हैं, 20 FBNC, 10 MTC, 7 ETET इमरजेंसी और 24 NICU निर्माणरत हैं। लगातार बहुत लम्बे समय से हमारे वहां के चिकित्साधिकारी हमारे CMHO साहब और अलवर शहर की जनता की भी महती मांग है, क्योंकि यहां काम चिकित्सालय जैसा हो रहा है। तमाम वे सुविधाएं हैं। इसी के साथ मदर मिल्क बैंक भी संचालित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह है कि आप इस शिशु वार्ड को चिकित्सालय का दर्जा दे दें तो हमें और सुविधाएं मिल जायेंगी। बच्चों का इलाज और आसानी से हो जायेगा और जयपुर का भी भार कम हो जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी घोषणा में निश्चित रूप से हमें यह सौगात देकर लाभान्वित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं नर्सिंगकर्मियों की बात करूं तो नर्सिंग व अन्य कर्मियों के कुल 336 पद स्वीकृत हुए हैं जिनमें 302 भरे हुए हैं और 34 पद रिक्त हैं। नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम का एक पद व द्वितीय के दोनों पद रिक्त हैं। नर्स ग्रेड-द्वितीय के 7 पद रिक्त हैं। नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य व उप प्राचार्य के दोनों पद रिक्त हैं। नर्सिंग ट्यूटर का एक पद रिक्त हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन के 5 पद रिक्त हैं। लैब टेक्नीशियन के 2 पद रिक्त हैं, लैब असिस्टेंट के 5 पद रिक्त हैं, एक्स-रे विभाग में रेडियोग्राफर अधीक्षक का एक पद रिक्त है, सहायक रेडियोग्राफर के 6 पद रिक्त हैं और LHV व MCW का एक-एक पद रिक्त है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 23.1.2023 को चिकित्सा विभाग के आदेश के अनुसार जो राजमेस का आदेश है, उसमें अलवर में 164

(श्री संजय शर्मा)

पद खतम कर दिये गये। मेरा यह मानना है, क्योंकि मेडिकल कालेज 400 बेड का स्वीकृत हुआ है और हमारे पास 587 बेड तो अभी अस्पताल में लगे हुए हैं तो हमारी मांग उन बेड को और बढ़ाने की है। संभवतया हमारे अधिकारियों ने 400 बेड के अनुसार जानकारी करते हुए इन पदों में कटौती कर दी। इसमें मेल नर्सिंग ग्रेड-प्रथम 47, असिस्टेंट रेडियोग्राफर एक्स-रे तक्नीशियन 06, MTW इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 01, ड्राइवर 01, ECG टेक्नीशियन 01, फार्मासिस्ट 17, जूनियर अकाउंटेंट 01, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट 02, आफिस असिस्टेंट 02, MTW क्लास फोर्थ 81, इस तरह 164 पद खतम किये हैं माननीय मंत्री महोदय। मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पद बढ़ायें, लेकिन इन पदों को किसी भी हालत में खतम नहीं होने दें, क्योंकि हमको अलवर शहर में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, उसके लिये इन पदों के साथ-साथ अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने जनता क्लिनिक की बात कही थी। स्कीम नंबर दो में हमारे पास एक पुराने चिकित्सालय विभाग का स्थान है, यदि उसके अंदर जनता क्लिनिक खोलेंगे तो उस शहर की जनता को भी लाभ होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मनोज कुमार।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। अभी माननीय विधायकों ने बहुत सारी होम्योपैथी के बारे में बात रखी हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री मनोज कुमार।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। समय पर मांग पूरी करनी है। बहुत सारे माननीय सदस्य हैं। प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। विराजिये अब आप। मैं सभी माननीय वक्ताओं से आग्रह करूंगा, जब मैं कहूं तो आप आवश्यक रूप से विराजने की चेष्टा करें, क्योंकि समय सीमित है और वक्ता बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। यह समय जो मैं निर्धारित कर रहा हूं डिप्टी चीफ व्हिप साहब ने और इधर के सचेतक जी ने दिया है, मैंने मेरी तरफ से कोई समय निर्धारित नहीं किया है। आपकी पार्टी ने समय दिया है और पार्टी का समय बताऊं तो आप आवश्यक रूप से विराजें। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार बजट दिया है। राजस्थान के विकास को, राजस्थान को कैसे आगे ले जायें, इसको ध्यान में रखकर बजट दिया है। मूलभूत सुविधा-रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ चिकित्सा और शिक्षा पर आज के समय में बहुत ध्यान दिया है और इसको छुआ है। चिकित्सा की बात करें तो जो कोरोना काल आया, उसमें उन्होंने देखा कि कैसे चिकित्सा सुविधा की कमी होती है और क्या दिक्कत आती है तो उसको देखते हुए इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर बहुत सुधारने का काम किया है। विशेष तौर से जो इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर है, पहला तो ढांचा सुधारने का काम किया है और दूसरा जो CHC, PHC और सब-सेंटर पहली बार इतने चार साल के कार्यकाल में बढ़ाने का काम किया है और इसके साथ ही क्रमोन्नत भी किये हैं, चाहे उप-जिला चिकित्सालय हों, चिकित्सालय हों, ताकि हर दूरस्थ व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही दूसरा काम भर्ती का किया। उससे पहले उन्होंने संविदा पर लगाकर तुरंत इस काम को शुरू किया, क्योंकि खाली पद रहेंगे तो उनको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। पैरेलल एक भर्ती चालू की और आज स्थिति यह है कि लगभग सारे पद चाहे डाक्टर के हों, ANM के हों, भरे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही नये ब्लाक स्तर पर कार्यालय ब्लाक CMHO खोले गये हैं। पिछली बार जितनी भी पंचायत समितियां थीं, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर उन्होंने ब्लाक CMHO कार्यालय खोला। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि यह शायद उनके ध्यान में नहीं आया कि नई पंचायत समिति मुख्यालय पर ब्लाक CMHO कार्यालय खुल गये, परंतु कुछ पुराने और बड़े तहसील मुख्यालय या उप खण्ड मुख्यालय और जो बीच में पंचायत समितियां बनी थीं, वे रह गयीं। वे बड़े क्षेत्र हैं, वे रह गये। ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन उनको भी ब्लाक CMHO कार्यालय से खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा बीदासर जो उप खण्ड मुख्यालय है, क्योंकि वह पहले पंचायत समिति बन चुकी थी, इसलिए वहां अभी तक भी ब्लाक CMHO का कार्यालय नहीं खोला है। वहां भी एक ब्लाक CMHO कार्यालय खोला जाये।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। समय कम है। सुजानगढ़ शहर में जो सरकारी अस्पताल है, उसको 100 बेड से 150 बेड किया। उसके बाद जगह कम पड़ने पर उसके जो अतिरिक्त बेड थे, एक पुराना जनाना अस्पताल वहां चला करता था, उसको पूर्व सरकार के समय बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी और जनाना अस्पताल को मूल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अब वापस उस जनाना अस्पताल में बेड लगा दिये गये और उसको चालू कर दिया गया है। यहां से दुबारा डायरेक्टर आफिस से आदेश निकल जाये तो जो पद हैं, जो उस समय मर्ज कर दिये थे, वे वापस डी-मर्ज कर दिये जायें और जो मूल पद हैं, वे वापस उसी जनाना अस्पताल में, MCH विंग बनी हुई है, जिसको चालू कर दिया गया है, वहां चले जायें। डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ का कैडर अलग हो जाये और उसकी व्यवस्था अलग बन जाये, उसके लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग उठायी थी कि सुजानगढ़ का अस्पताल भीड़ भरे मार्केट के बीच में है। वहां जगह कम है, उसको कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया जाये, उसके लिये जमीन भी अब चिह्नित कर ली गयी है। करीब 57 बीघा जमीन विभाग के नाम सुपुर्द कर दी गयी है और उसके लिये MOU भी साइन होने जा रहा है। करीब 150 करोड़ रुपये भामाशाह लगाने जा रहे हैं। अब उसके जल्दी ही आदेश निकालकर इसको शुरू कर दिया जाये। उसका 300 बेड के हिसाब से 150 करोड़ रुपये का MOU करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी यह काम पूरा कर दिया जाये, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पर यह मैटर है। यह जनाना अस्पताल उधर शिफ्ट हो जायेगा तो जो जगह निकलेगी, वहां जो आई सी यू 2021-22 के बजट में स्वीकृत हो गया था, उसके आधे उपकरण भी आये हुए पड़े हैं, सिर्फ उसको चालू करना है। अब अगर वहां वह पूरी तरह से शिफ्ट हो जायेगा तो वह जो जगह निकलेगी वहां आई सी यू भी शुरू हो जायेगा और उसका सामान भी हो जायेगा। आप उसका आदेश भी जल्दी ही करा दें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में पी एच सी, सी एच सी बहुत बड़ी संख्या में खोले हैं। मैं शहर के लिये एक अरबन पी एच सी की मांग करूंगा क्योंकि जो जमीन है वह चिह्नित कर दी गयी है। चिकित्सा विभाग के नाम ट्रांसफर भी कर दी गयी है। कोर्ट के पीछे वह जमीन स्थित है। वहां घनी

(श्री मनोज कुमार)

आबादी है। अल्पसंख्यक बहुल वह इलाका है। अगर वहां अरबन पी एच सी खुल जायेगी तो सर्दी, जुकाम, बुखार के जो मरीज हैं, उनको मुख्य अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। वहां की भीड़ से बचकर वहीं उनका छोटा-मोटा इलाज हो जाये। अगर वह अरबन पी एच सी चालू हो जाती है तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा और अस्पताल का भी लोड कम हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बीदासर की सी एच सी में 30 से बढ़ाकर के 50 बेड किये गये थे, लेकिन उसके बाद वहां जो पद विशेषज्ञ डाक्टर्स के बढ़ने चाहिए थे, वे अभी तक बढ़ नहीं पाये हैं। बाकी सब जगह बढ़ गये पर किसी कारण से वे रह गये। वे जो बेड बढ़ने के बाद में 50 बेड के हिसाब से जितने पद होने चाहिए, वह बढ़ा दिये जायें। 50 हजार की आबादी का बीदासर कस्बा है, उप खण्ड मुख्यालय है, उससे कस्बे और आसपास के लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया और चिकित्सा क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, मंत्री जी खुद लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें हम देखें तो इस बजट में और आगे ले जाते हुए दवा फ्री कर रखी है। ई डब्ल्यू एस के लिये भी चिरंजीवी योजना के माध्यम से इलाज फ्री कर दिया। जांच का दायरा बढ़ाकर सी एच सी स्तर पर ले गये, जहां कि 56 जाचें उन्होंने और जोड़ी हैं।

हर जिले में मेडिकल कालेज खोल दिये गये हैं। बड़ी संख्या में सी एच सी और पी एच सी खोली गयी हैं। उनके भवनों के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो निर्माण कार्य हैं वह एन आर एच एम के माध्यम से हो रहे हैं। एन आर एच एम की जो काम करने की स्पीड है, वह बहुत स्लो है। उनके जो ठेकेदार हैं, कांट्रेक्टर हैं, वे भी काम करने में स्लो हैं। बहुत कम कांट्रेक्टर हैं। दूसरी जो मानिटरिंग है इंजीनियर्स की, ज्यादातर वे रिटायर्ड अफसर हैं। इसमें थोड़ा सा सिस्टम करके जो बड़े काम हैं, अगर पी डब्ल्यू डी के अटैच कर दिये जायें तो अच्छा रहेगा। पी डब्ल्यू डी कंस्ट्रक्शन के कामों में ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। इससे क्या है कि जो बड़े काम हैं वे समय पर हो जायेंगे। आज से 3-3 साल पहले जो काम शुरू हुए थे, वह आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम करें कि एन आर एच एम के साथ पी डब्ल्यू डी भी इसमें आये।

(श्री मनोज कुमार)

सभापति महोदय, एक मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि 108 एम्बुलेंस, जिसमें किसी पेशेंट को रैफर करके दूसरी जगह भेजा जाता है तो कहते हैं कि उप जिला चिकित्सालय में ले जाओ, उसके बाद जिला चिकित्सालय में ले जाओ। उसके बाद कहेंगे कि संभाग मुख्यालय पर ले जाओ। कई ऐसी गम्भीर बीमारियां होती हैं, तात्कालिक बीमारियों के इलाज की जरूरत होती है, जिनमें तुरंत जयपुर, बीकानेर, हमारे 2 बड़े सेंटर हैं पास में, वहां रैफर करते हैं। डाक्टर लिख देता है।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 36)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च 2023 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने पैंतीसवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 04 मार्च 2023 से सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

शनिवार, दिनांक 04 मार्च 2023 से रविवार, दिनांक 12 मार्च 2023	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 मंगलवार, दिनांक 14 मार्च 2023 बुधवार, दिनांक 15 मार्च 2023 गुरुवार, दिनांक 16 मार्च 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 16 मार्च, 2023 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)	

(श्री महेन्द्र चौधरी)

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 एवं 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 18 मार्च 2023 रविवार, दिनांक 19 मार्च 2023	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023	1- बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023 एवं 2- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अनुदान की मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 27 एवं 28 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 27 एवं 28 के पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा की मांग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, विश्व में चिकित्सा की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनमें सबसे लोकप्रिय पद्धति एलोपैथी है। एलोपैथी अभी विश्व में व्यापक रूप से चल रही है। उसके अलावा आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति और होम्योपैथिक पद्धति है। एलोपैथी पद्धति ऐसी है जो कैमिकल पर आधारित है, जिसमें सारी औषधियों का निर्माण कैमिकल के आधार पर होता है, लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, वह ऐसी पद्धति है जिसके न तो कोई साइड़ इफेक्ट है और न ही औषधियों को लेने से कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। उससे मानव जीवन लगातार सुधरता है। यह हमारी और विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिसको आज हमारी दादी और नानी भी जानती है, जिनको घरेलू नुस्खे कहते हैं, उन सब आयुर्वेदिक नुस्खों के आधार पर बहुत बड़ा हमारा चिकित्सा का आधार बना हुआ है।

एलोपैथी में जिस प्रकार से कैमिकल का उपयोग किया जाता है, जिस तरह से खेतों में उर्वरक और पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ जाता है। बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वे आज मानव जीवन और हमारी भूमि का जो स्वास्थ्य है, उन दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। धीरे-धीरे पूरा विश्व जैविक कृषि की ओर आ रहा है। उसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाला समय आयुर्वेद का समय है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आने वाले समय में विश्व में सबसे लोकप्रिय पद्धति अगर कोई होगी तो वह आयुर्वेद होगी। आज जिस तरह से जैविक कृषि को पूरे विश्व में प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा दिया जायेगा। आज जो हमारी यह भारतीय पद्धति है, इसके लिये अगर हम अपना बजट ज्यादा से ज्यादा एलोकेट करेंगे और इस पर ध्यान दिया जायेगा तो विश्व में आने वाले समय में चिकित्सा जगत में हमारा स्थान सबसे प्रमुख देशों में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलवर से पधारे माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी थी माडल सी एच सी की, मेरे भीलवाड़ा शहर जो एक अरबन एरिया है, पूरा विधान सभा क्षेत्र अरबन एरिया है, मेरा एक उप नगर है पुर, उस उप नगर पुर में 50 हजार की आबादी निवास करती है और भीलवाड़ा से उसकी दूरी 15 किलोमीटर है। आज 50 हजार की आबादी के लिए 40 साल पहले पी एच सी बनी हुई थी, उस पी एच सी को माडल सी एच सी बनाने के लिए आपके सरकार का प्रस्ताव था, उसके अनुसार लिखवाकर भिजवाया था। हर बार वो मना करके आ जाता है कि अरबन एरिया में पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता। यह हर शहर की समस्या है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कानून में भी कोई बदलाव कर सकें तो करें, लेकिन हर विधान सभा क्षेत्र में जो आपने मॉडल सी एच सी की घोषणा की है तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी उप नगर पुर को मॉडल सी एच सी के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। इसी पुर के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज से तीन साल पहले एक करोड़ की घोषणा वहां पुर में जाकर स्वयं ने की थी कि इस पी एच सी में हम भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये लगाएंगे। आज तीन साल बीतने के बाद भी एक पैसा वहां नहीं लगा है। न यू आई टी ने लगाया है, न किसी और ने। मुख्य मंत्री की घोषणा का अगर यह हश्र होगा तो निश्चित रूप से सरकार पर प्रश्न चिह्न खड़ा होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि पुर को माडल सी एच सी के रूप में क्रमोन्नत किया जाए और मुख्य मंत्री ने एक करोड़ रुपये की घोषणा की थी, वो उस भवन में लगाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उन व्यक्तियों के लिए आपने 50 हजार रुपये प्रत्येक के लिए घोषणा की थी। आज मेरे भीलवाड़ा शहर में सैकड़ों ऐसी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हुई, उनका पैसा आज भी बकाया चल रहा है। कृपा करके सी एम एच ओ और कलेक्टर को आप पाबंद करें कि जो पैसा बकाया है, जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई है, उनका पैसा आप तत्काल रिलीज करके उनको राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भीलवाड़ा शहर में एक मेडिसिटी की घोषणा हुई थी। उस मेडिसिटी में यू आई टी ने पूरा प्लान बनाया था और

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सरकार की घोषणाओं की जो लिस्ट बनी है उसमें भीलवाड़ा शहर में सरकार की उपलब्धियों में उस मेडिसिटी को दर्शाया गया है। उस मेडिसिटी का आज तक अता-पता नहीं है जबकि सरकार ने अपनी उपलब्धियों में यह दर्शा दिया कि भीलवाड़ा में मेडिसिटी बन चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस मेडिसिटी को तत्काल कार्यरूप दिया जाए जिससे भीलवाड़ा शहर में जो तेजी से चिकित्सा व्यवस्था विकसित हो रही है प्राइवेट क्षेत्र में, तो वो मेडिसिटी बन जाए तो उससे हमारे शहर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपसे प्रार्थना है कि हमारे जिला अस्पताल पर बहुत लोड है, फर्श पर पेशेंट पड़े रहते हैं, कई बार फर्श पर उनको भर्ती करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि वहां पर शहर में जो सात-आठ जो भी पी एच सी हैं, उनमें डी एम एफ टी के माध्यम से अगर एक-एक वार्ड बन जाता है तो उस वार्ड में छोटी-मोटी बीमारियों के पेशेंट वहीं रुक जाएंगे, उनको वहां भर्ती कर लिया जाएगा, जिससे जिला अस्पताल पर लोड कम होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपका आभार।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने राज्य का पांचवां बजट पेश किया और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने कोरोना के काल से लेकर आज तक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में भी और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय और वर्तमान के बजट में ट्रोमा सेंटर, सी एच सी, सब-सेंटर और बेड बढ़ाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है और बहुत बड़ा स्टेट है। पिछली सरकार के समय में इस स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से अनदेखी की गई, उसी का नतीजा है कि हम इस क्षेत्र में पिछड़ गए। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसने पी पी पी माडल पर हमारी सी एच सीज को प्राइवेट हास्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया। यह पहला अवसर था जब कोई सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह

(श्री आलोक बेनीवाल)

सी एच सीज को प्राइवेट हास्पिटल्स से जोड़कर पी पी पी माडल पर दे दिया। हमारी राज्य सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य हरदम ऊपर रही है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता में उस सरकार ने काम किया होगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने भी इस चीज को समझा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन हमारे विधान सभा क्षेत्र और इस स्टेट में किया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बे समय से स्वास्थ्य विषय पर विचार-विमर्श चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कार्यकालों में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दी, 10 लाख रुपये उसमें बीमा राशि रखी, इस बजट में उसको 25 लाख रुपये किया। जो एक्सीडेंटल बीमा था उसको बढ़ाकर 10 लाख किया और 25 लाख रुपये की चिरंजीवी योजना से आम आदमी को लाभ मिल रहा है। यह इतनी बड़ी योजना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे सी एम एच ओ का शाहपुरा ब्लाक है, इसमें लगभग 10 हजार 427 लोगों ने इसका लाभ लिया। कोई छोटी फिगर नहीं है ये। उस गरीब आदमी की सोचिए जो अपना इलाज कराने जाता था तो उसको सोचना पड़ता था कि मैं यह इलाज कहां से कराऊंगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये दोनों योजनाएं जो लागू की हैं वो आने वाले समय में भी आम आदमी के लिए जीवनदायिनी के रूप में काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने मेडिकल कालेज भी खोले हैं। पूरे स्टेट में मेडिकल कालेज खोले हैं, जो तीन जिले रह गये थे उनमें भी मेडिकल कालेज स्टेट फंड के एक हजार करोड़ रुपये से खोलने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स की कमी रही है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी रही है पर मैं माननीय मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि इन चार साल के कार्यकाल में पैरा मेडिकल स्टाफ की भी भर्ती हुई, डाक्टर्स की भी भर्ती हुई और अगर ये भर्ती नहीं होती तो निश्चित रूप से सी एच सी, पी एच सी और जो हमारे मेडिकल कालेज हैं, हमारे हास्पिटल्स हैं उनमें डाक्टर्स की कमी और भी ज्यादा होती। इसलिए मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्रीजी को कि 1763 डाक्टर्स की पोस्टिंग कल की तारीख में करके लगभग सभी सी एच सी और खास तौर से मैं

(श्री आलोक बेनीवाल)

बताना चाहूंगा कि पी एच सी राजस्थान में शायद ही कोई बची होगी जिसके अंदर डाक्टर नहीं लगा हो। यह बहुत बड़ा काम सरकार लगातार कर रही है, लेकिन मांग बहुत है पर पूर्ति करने का काम सरकार लगातार कर रही है और नौकरी पर लगाने का काम भी लगातार चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं जिससे हमारे यहां जो कमी-बेशी है उसकी पूर्ति हो सके। यह कमी-बेशी क्यों हो रही है, ये आंकड़े आपने सबने सुन लिए होंगे। काम क्यों नहीं हुआ, यह आप सबने देख लिया है। पिछली सरकार यदि यह काम करती तो आज यह स्थिति इस स्टेट की नहीं बनती।

(समय: 19.00 बजे)

कोरोना काल में क्या स्थिति हमने झेली, ऑक्सीजन की कमी, हास्पिटल्स में व्यवस्थाओं की कमी, ये सारी चीजें हमारी नजर में रही हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसे सोचते हुए ही सी एच सी पर आक्सीजन प्लांट की स्थापना की। मेरे यहां दो सी एच सीज हैं, दोनों पर आक्सीजन प्लांट आज बनकर तैयार हो गये हैं, चालू हैं।

मैं अपने इलाके की बात करूंगा। मेरे यहां दो सी एच सीज खुली थीं, धौली और धानोता के अन्दर। जो ए एन एम की पोस्ट थी, उसकी अभी तक मैपिंग नहीं की गयी है। मैं उसकी मैपिंग की मांग करता हूं। मेरे उपजिला चिकित्सालय में भी फार्मासिस्ट, ई सी जी टैक्निशियन, एलएचवी की पोस्ट का भी मैपिंग का काम जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे इन पोस्टों पर काम करने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये पोस्टें अभी तक मेरे यहां पर लैप्स दिखायी जा रही हैं। इनकी मैपिंग पूरी नहीं हुई है, उस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। वहां जो स्टाफ लगना चाहता है या लगा हुआ है, उसे परमानेंट रूप से तनख्वाह मिलने में भी तकलीफ आ रही है।

साथ ही, मेरे यहां मनोहरपुर में 75 बेड का हास्पिटल बनाया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार। उसमें भी जो पोस्टें आनी थीं, वे भी अभी नहीं आयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अन्दर भी जो आपके विभाग की प्रक्रिया है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें और पोस्टें भेजने का काम करें। मेरे यहां एक खेजरोली पंचायत है, जिसकी जनसंख्या

(श्री आलोक बेनीवाल)

लगभग 50 से 51 हजार है। बहुत बड़ी पंचायत है। उसके आसपास पांच-छह पंचायतें और लगती हैं। अभी वहां सी एच सी संचालित है।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं मांग करूंगा कि 30 बेड की वह जो सी एच सी है, उसे 50 बेड की करें, ताकि आस-पास की जनता को और भी लाभ मिल सके। साथ ही, मेरे यहां जो निवाणा पंचायत है, वह पी एच सी है।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): उसे अगर आप सी एच सी कर देंगे तो उसके आस-पास में जो 7-8 पंचायतें हैं, वहां के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मेरे यहां पिछले कार्यकाल में पी एच सी नहीं खुली है, उसकी सूची मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 27 और मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: कहां चले गये थे आप?

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, कल की जो डाक्टर्स की लिस्ट आयी है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंटाली, बदनौर, गुलाबपुरा, आसीन्द, सब जगह आपने डाक्टर्स दिये, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ जगहें खाली हैं। मेरा निवेदन है, आप बहुत संवेदनशील मंत्री हैं, भले आदमी हैं, मेरा निवेदन है आपसे, जो खाली जगह हैं, उन्हें आप भरें। आपकी कृपा होगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, कोविड सहायकों की पीड़ा को भी आपको समझना पड़ेगा। जो 27 हजार कोविड सहायक राजस्थान में घर पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उस समय सरकार और राजस्थान प्रदेश की जनता का सहयोग किया, जिस समय हम सब लोग अपने-अपने घरों में छिपे हुए थे और सोये हुए थे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कोविड सहायकों के लिए भी आप कोई एजेंडा बनाकर उनकी सुनवाई करें।

आपने जनता क्लिनिक वाली बात की। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी जनता क्लिनिक अब तक चालू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, आप उस पर भी थोड़ा

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

गौर करें। चिरंजीवी योजना में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख से 25 लाख रुपये किये हैं। मैंने बजट में भी मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त किया था और आज भी कर रहा हूं। विधान सभा के इस पवित्र सदन में जो ये घोषणाएं की गयी हैं, यदि आचार संहिता से पहले ये सारी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी तो आपका भी भला होगा और राजस्थान की जनता का भी भला होगा। मेरा यह निवेदन आपसे रहेगा।

चिरंजीवी योजना में थोड़े सुधार की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। चिरंजीवी में विशेष तौर से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वे जब शहरों के प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हास्पिटल वालों का जो व्यवहार होता है, वास्तव में वह बहुत खराब व्यवहार होता है। उनके साथ धक्का-मुक्की तक हो जाती है और उनसे पैसा लूटा जाता है। यह स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंत्री महोदय, थोड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है। मेरा यह निवेदन रहेगा आपसे।

आज पूरे दिन सदन में चिकित्सा पर चर्चा हुई। एक भी माननीय सदस्य ने सिलिकोसिस की बात नहीं की। मेरा विशेष तौर पर निवेदन रहेगा, सिलिकोसिस पर कोई भी सरकार रही हो, सबने गम्भीरता से काम किया है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बदनौर एरिया है, वह पूरा मगरा एरिया है। वहां सिलिकोसिस के पेशेंट ज्यादा हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, आप एक ऐसा एजेंडा बनाएं जिसमें कम से कम 15 दिन में एक सिलिकोसिस का कैम्प लगे। इससे सिलिकोसिस के पेशेंट्स को थोड़ा आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। मेरे यहां बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं सिलिकोसिस के। 15 दिन में एक कैम्प उप-खण्ड क्षेत्र में लग जाये, जहां ज्यादा पेशेंट्स हैं। इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी अति कृपा होगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज का जो मिलावट का दौर है, हर दुकान में हर जगह मिलावटखोरी होती है और मिलावटखोर, चारों तरफ आप सुनते भी हैं और अखबारों में भी आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आता है, घी पकड़ा जाता है, दूध पकड़ा जाता है, मावा पकड़ा जाता है। फूड इंस्पेक्टर की कमी है मेरे यहां। आप फूड इंस्पेक्टर लगा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा, उनकी भी मॉनिटरिंग जरूरी है।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मेरे यहां तीन सी एच सीज हैं- आसीन्द, हुरड़ा, बदनौर। अस्पतालों में जो सफाई का ठेका होता है, आदरणीय मंत्री महोदय, जो पूंजीपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वे साफ-सफाई का ठेका ले लेते हैं। उसमें काम वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। आधे से कम पैसे में वे लोग काम करते हैं। लगभग 60-70 प्रतिशत पैसा ठेकेदार घर बैठे-बैठे खा जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि एक एजेंडा बनाएं। कानून बनाना पड़े तो वह भी बनाएं। हास्पिटल्स में साफ-सफाई का ठेका कम से कम वाल्मीकि समाज को ही मिले, क्योंकि जब सरकार पैसा खर्च कर रही है तो वह पैसा सौ प्रतिशत वाल्मीकि समाज को ही मिलना चाहिए, क्योंकि काम वे ही लोग करते हैं वहां। यह मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से।

आसीन्द सी एच सी मेरे आसीन्द शहर के बीच में है। चारों तरफ संकरी रोड्स हैं। शहर की आबादी बहुत बड़ी है। एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी कोई भी पेशेंट को लेकर आती है तो उन गलियों में मेडिकल की, किराने की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, रास्ता नहीं है आने-जाने के लिए। तीन रास्ते हैं, तीनों ही संकरे हैं। बहुत बार जाम लगता है वहां। इससे पेशेंट को लाने में वहां आधा घण्टा पूरा हो जाता है। मेरा निवेदन है, आसीन्द शहर में पंचायत समिति की एक जमीन है, जो हाईवे रोड पर है। आप चाहेंगे तो एक प्रस्ताव मैं नगरपालिका से बनवाकर दे दूंगा। आसीन्द सी एच सी को आप शहर से बाहर ले आएंगे और इसके लिए कुछ फंड की भी व्यवस्था कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। वहां जो शहर के बीचों-बीच सी एच सी है, हमें वहां बहुत ज्यादा परेशानी आती है। आसीन्द सी एच सी को, मेरी यह मांग रहेगी, जो 75 बेड की सी एच सी है, आदर्श सी एच सी है, उसे आप 100 बेड की करें। आप थोड़ा इस पर गौर करें, क्योंकि आसीन्द शहर के पास में भीलवाड़ा 60 किलोमीटर पड़ता है और ब्यावर भी 60 किलोमीटर पड़ता है। बीच में आस-पास में सौ-सवा सौ किलोमीटर के एरिया में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। आसीन्द सी एच सी को आप सौ बेड की करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी।

मेरा एक विशेष निवेदन और रहेगा। आसीन्द सी एच सी को आप उप-जिला अस्पताल घोषित कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। मेरा हाथ जोड़कर व्यक्तिगत निवेदन है। आदरणीय सभापति महोदय, ट्रोमा सेंटर की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। मेरे आसीन्द में जगह नहीं है। आप एक

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

आदेश निकालें। आदेश निकालकर नगरपालिका के नाम से ट्रोमा सेंटर के लिए जगह वहां मिल जाये, क्योंकि मेरे वहां दो हाईवे रोड्स हैं। एक एनएच 148, एक एनएच 158, वहां ट्रोमा सेंटर की अति आवश्यकता है। आप इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे तो ठीक रहेगा।

एक मेरे वहां मालासेरी देवनारायण भगवान का मन्दिर है। मालासेरी देवनारायण भगवान की जन्मस्थली है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सवाई भोज, मालासेरी और बंक्यारानी माताजी, तीनों ही जगह लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। मेरा व्यक्तिगत निवेदन रहेगा, मालासेरी जो एक पंचायत हैडक्वार्टर है, एक बहुत बड़ा प्राचीन मन्दिर है, जहां अभी 28 फरवरी को आदरणीय प्रधान मंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ है। वहां आप एक पी एच सी की घोषणा कर देंगे इसी सत्र में, तो आपकी अति कृपा होगी।

मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया था, मेरी मांग भी है, कंवलियावास, ब्राह्मणों की सरेरी, कंवलियावास, गुलाबपुरा से भीलवाड़ा के बीच में एक 60 किलोमीटर का गैप है। उसके बीच में कंवलियावास गांव है। उस 60 किलोमीटर के एरिया में एक भी पी एच सी नहीं है। आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, कंवलियावास और ब्राह्मणों की सरेरी को आप सी एच सी में घोषित करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि दोनों हाईवे पर हैं। कंवलियावास तो सिक्स लेन पर है। वहां आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। भीलवाड़ा वहां से बहुत दूर पड़ता है। कंवलियावास और ब्राह्मणों की सरेरी, ये दोनों सी एच सी आप मुझे दे देंगे तो आपकी अतिकृपा होगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने पिछले दिनों भी यहां मांग की थी कि बरसनी एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जिसमें 8 हजार वोट हैं और उसके 21 मजरे-ढाणियां लगते हैं तथा 15-20 किलोमीटर के एरिया में वहां पर कोई भी पी एच सी नहीं है। आसीन्द शहर से भी वह गांव 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरा निवेदन रहेगा कि बरसनी और भादसी, भादसी अरावली की पहाड़ी पर बसी हुई ग्राम पंचायत है और वहां 40 गांव हैं तथा वहां दो पंचायतें हैं रतनपुरा और भादसी, दोनों में नीचे से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं और 40 गांव वहां बसे हुए हैं तो भादसी में भी एक पी एच सी की आवश्यकता है। बरसनी, भादसी और कटार, तीनों ही जगह आप मुझे पी एच सी दे देंगे तो आपकी अतिकृपा होगी, क्योंकि इन तीनों ही जगह अति

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

आवश्यकता है। जहां जरूरत होगी मैं वहीं पर मांगूंगा माननीय मंत्री महोदय। आपलियास और मरेवड़ा, ये दोनों ही गांव बोर्डर पर हैं। आपलियास शाहपुरा के बोर्डर पर है और मरेवड़ा मांडल के बोर्डर पर करेड़ा के पास में है जहां पर चिकित्सा की सुविधा नहीं है, इसलिए दोनों जगह आप सब-सेंटर की इसी सत्र में घोषणा कर देंगे तो आपकी अतिकृपा होगी।

आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप बहुत संवेदनशील हैं, आप जनता के दु:ख-दर्द को भी समझते हैं, मैं आपसे दो-तीन बार मिला भी हूं और आपसे मैंने जो भी मांगा वह आपने दिया है। यह तो चिकित्सा की है इसलिए आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम एक एजेंडा तो ऐसा कामन हो जिस पर सब माननीय सदस्य मांगते हैं, उनकी मांग पूरी की जाये।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। विराजिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): चिकित्सा तो सबके लिए है और राजस्थान प्रदेश की जनता आपके भरोसे ही है। आप मेरी मांग को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मांग करना चाहूंगा कि ए एन एम 2013 की भर्ती को पूरा करो। वे लड़कियां ओवरएज हो रही हैं और बार-बार मांग करती हैं। सी एच ओ की भर्ती भी नये सिरे से की जाए, ताकि वे नौजवान जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, जनता का साथ दिया था उनका समाधान हो। सभापति महोदय, होम्योपैथिक डाक्टर्स की भर्ती को भी पूरा किया जाये। अभी सिर्फ 350 की संख्या में वे लगे हुए हैं।

मैं सबसे जो बात करना चाहता हूं, वह यह है कि आपने हमारे यहां सी एच सी दी, पी एच सी दी, उनके काम भी शुरू हुए लेकिन काम इतनी सुस्त गति से हो रहे हैं कि अचम्भा हो रहा है कि ऐसे भी काम होते हैं क्या। पी डब्ल्यू डी ने पिछले साल जो काम शुरू किये, वे इस बार पूरे कर दिये और लोकार्पण चल रहा है। मेरे रामगढ़ सी एच सी में, मुंसरी पी एच सी में, उप

(श्री बलवान पूनियां)

स्वास्थ्य केन्द्र, मोज्याणा में दो-दो, तीन-तीन महीने से ठेकेदार गायब हैं। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि एन आर एच एम के सिस्टम को थोड़ा टाइट किया जाए और मंत्री महोदय इसको देखें, क्योंकि हमने पहले भी इस मामले को उठाया है और इनके काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। पिछली बार शेरपुरा पी एच सी बनी हुई थी, तीन साल पहले 2018 के बजट में दी हुई थी वह अब लटक गयी। गेऊ पी एच सी के अन्दर दीवारों के बीच में तरेड़ आ गयी और उसके बाद दीपलाना में आज से 7-8 साल पहले बनी हुई पी एच सी नीचे लटक रही है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि काम बढ़िया हो।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि हेल्थ बिल पर आज चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ बिल में जिस तरीके से तैयारी शुरू की गयी और विधान सभा शुरू हुई तब इस हेल्थ बिल की चर्चा हुई तथा प्रवर समिति की बैठकें भी हुईं। मैं समझता हूं कि सरकार बहुत मजबूती के साथ इस बिल को लागू करे। मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना के साथ, निरोगी राजस्थान की बात करते-करते हमें यह तय करना है कि लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ले ही ले और किसी भी तरीके के दबाव में सरकार नहीं आये तथा हेल्थ बिल को जल्दी से जल्दी लाकर इस सदन में पारित करवाये, क्योंकि यह लास्ट बड़ा सदन है और अगर इसमें बात रह गयी तो फिर रह जायेगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सदन में मांग उठी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के दायरे में मुख्य रूप से आज हार्ट अटैक से और कैंसर से जो लोग मर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं तो नेसेसरी रूप से मनुष्य की जांच हो जिससे जिम्मेदार आदमी घर से हाथ में से नहीं निकले। सभापति महोदय, 15 साल से लेकर 25-25, 30-30 साल के नौजवान हाथ में से जा रहे हैं। हमारे इलाके में तो कैंसर का इतना बड़ा दबदबा हो गया कि हर गांव में 5-5, 7-7 पेशेंट हैं। मेरा हाथ जोड़कर मुख्य मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे भादरा-नोहर के क्षेत्र में कैंसर का रिसर्च सेंटर बनवायें। चाहे हमारी जगह छोटी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कैंसर है कि हर गांव में पसरा हुआ है। हमारे यहां पंजाब, हरियाणा से जो पानी आता है, पता नहीं उस पानी का असर है या हवाओं का असर है कि एक-एक गांव में दस-दस, बीस-बीस कैंसर के पेशेंट हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कैंसर पर रिसर्च सेंटर हमारे इलाके में खुले।

हम बात करना चाहेंगे चिकित्सा शिक्षा की। आपने डाक्टर लगा दिया,

(श्री बलवान पूनियां)

डाक्टर लग गया और डाक्टर का पी जी एडमिशन हो गया तो वह डाक्टर उच्च शिक्षा अध्ययन करने चला गया। उसका नाम वहां मेरी कांस्टीट्यूएंसी की पी एच सी, सी एच सी में बोल रहा है। एक साल के बाद जब वह आयेगा तब तक वह पद खाली रहेगा। वहां गायनी का पद खाली, एम डी फिजिशियन खाली है। जहां उसका एडमिशन हो जाए तो उसका पद वहीं बोलना चाहिए और वहां पर दूसरे डाक्टर को लगाने का यह संशोधन मंत्री महोदय, करना चाहिए, ताकि जनता को हम सहूलियत दे पायें।

'शुद्ध के लिए युद्ध' की बात चल रही है। सभापति महोदय, आज खाने और पीने में जितनी मिलावट है, उसका कोई स्तर नहीं बचा है। इतनी भयंकर मिलावट है कि हम जयपुर में शाम को जो दूध पीते हैं उसमें डर लगता है कि पता नहीं दूध के अन्दर क्या है। सभापति महोदय, जिस तरीके से दूध में और खाने के सामान में मिलावट है यह हम सबके जीवन के लिए खतरा है, आम जनता के जीवन के लिए खतरा है इसलिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को आप तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

सभापति महोदय, हम मांग करते हैं आशा सहयोगिनी, उन बहनों का मानदेय सरकार बढ़ाये। हम चाहते हैं कि डिलीवरी हास्पिटल में हो और सरकारी हास्पिटल में हो और डिलीवरी के समय यह धमकी नहीं मिले जच्चा को कि आपका तो सिर्फ एक इलाज बचा है और आपरेशन से डिलीवरी होगी। 80-90 परसेंट नोर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, जबकि आज आंकड़े ये हैं कि 80-90 परसेंट डिलीवरी आपरेशन से हो रही हैं। सभापति महोदय, मैं डाक्टर लाइन का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन हम महसूस करते हैं। अगर प्राकृतिक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से दूसरी बीमारियों का महिलाओं के लिए न्योता आ रहा है इसलिए सरकार इस बात पर गम्भीरता से काम करे।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारे भादरा शहर में आयुर्वेदिक हास्पिटल है उसको क्रमोन्नत किया जाए और भादरा में नर्सिंग कालेज खोला जाए। वहां पर पी एच सी, अजीतपुरा को सी एच सी में क्रमोन्नत किया जाए।

एक मैं विधान सभा के सारे कर्मचारियों की एक मांग है वह रखना चाहूंगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की राजस्थान विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना, धावास, अजमेर रोड, जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाये। यह ज्ञापन विधान सभा के कर्मचारी साथियों ने मुझे दिया था।

(श्री बलवान पूनियां)

इन सब बातों को रखते हुए मैं आपके बीच यह बात कहना चाहता हूं कि उत्तम स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो दायरा मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है उसके लिए मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे भादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उन्होंने उप जिला अस्पताल बनाया, इस बात के लिए भी धन्यवाद।

मंत्री महोदय, बस एक बात चाहते हैं कि जिस तरीके से साथी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, हर योजना में कमियां हैं, हर योजना में लेकुने हैं लेकिन अपने को इसको और बेहतर तरीके से ठीक करने की जरूरत है। जो निराशा की बात इधर के साथी कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और कोरोना के उन बुरे दिनों को याद करना चाहूंगा कि राजस्थान के माननीय 200 सदस्यों ने और राजस्थान के सरकारी मुलाजिमों ने, सारे के सारे सिस्टम ने जनता की जान को बचाने का काम किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हिन्दुस्तान के हर कोने में राजस्थान के बैठे हुए लोगों के सम्पर्क में थे, लेकिन जिस तेजी के साथ राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के डाक्टर्स ने आपस में एक-दूसरे को बचाने का काम किया, यह बहुत अच्छा उदाहरण था और इस उदाहरण को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छा किया है उस अच्छे के लिए हमें वाहवाही करनी चाहिए न कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। जो साथी अभी भी यह कह रहे हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बाद भी यह कह रहे हैं कि आज कुछ भी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ है आशा की किरण है, इसको मजबूती के साथ हर आदमी का स्वास्थ्य उत्तम हो यह सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 27, 28 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रयासों को नया आयाम देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जो पूर्व में 10 लाख रुपये तक प्रत्येक परिवार के उपचार के लिए राशि थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी का चिकित्सा क्षेत्र में एक सराहनीय कदम है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश के लोग

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

लाभान्वित होंगे। इसी योजना के अन्तर्गत जो दुर्घटना बीमा योजना पूर्व में 5 लाख रुपये था उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

माननीय सभापति जी, सम्पूर्ण प्रदेश के चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पूर्व में 30 जिलों में मेडिकल कालेज खोले गये थे परन्तु प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमन्द में मेडिकल कालेज नहीं थे। उक्त शेष बचे तीनों जिलों के मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी केन्द्र की भाजपा शासित सरकार ने इस पर कोई रूचि नहीं दिखायी और उसे स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गयी, परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि इसी बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के आमजन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के खर्चे पर तीनों जिलों में मेडिकल कालेज खोले हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है।

मैं पिछला याद दिलाना चाहूंगा कोरोना के समय का, जिस समय पूरे प्रदेश, देश, संसार में जिस तरह से कोरोना की बीमारी भयानक रूप से फैल रही थी, उस समय भीलवाड़ा में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और भीलवाड़ा, जो माडल था, वह किसी से छिपा नहीं है। उस समय का प्रबन्धन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस तरह से वहां कोरोना की रोकथाम करने के लिए जो माडल तैयार तैयार किया, जिसकी स्वयं हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी तारीफ की, उसके लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वह एक ऐसा समय था, हम सब लोगों ने, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी न किसी ने किसी न किसी को खोया था। उसके लिए भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एकदम कंट्रोल हुआ और आज हम सब लोग अच्छे वातावरण में स्वस्थ हैं।

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी बजट सत्र 2023-24 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला उप अस्पताल में 14 अस्पतालों को क्रमोन्नत किया। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

नवीन सेटेलाइट चिकित्सालय दो खोले गये, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24 क्रमोन्नत किये गये, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 14 खोले गये, उसके लिए भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 32 क्रमोन्नत किये गये और उप-स्वास्थ्य केन्द्र 50 और एक ब्लड बैंक की घोषणा की गई। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का।

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने बजट के रिप्लाई से पहले, जब 10 तारीख को बजट था, प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रयासों को नये आयाम देते हुए, मुख्य मंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में, जिस तरह मैंने अभी बताया और उसके साथ-साथ बजट का जो रिप्लाई था, उस रिप्लाई में भी 200 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की।

मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश में 23 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी इसी बजट के रिप्लाई में खोले गये और साथ-साथ 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की भी घोषणा की है। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी उप-जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। साथ ही, भरतपुर मेडिकल कालेज में भी क्रिटिकल केयर यूनिट खोले जाने की पिछले दिनों घोषणा की गई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

इसी बजट सत्र 2023-24 में, मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत बरगा के गांव चन्दनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर मैं माननीय मंत्री जी का माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

साथ ही, अभी हाल ही में कल रात को, जो डाक्टरों की सूची आई है और जो नवीन पदस्थापित हुए हैं, उनमें से एक चिकित्सक मेरी सी एच सी,

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

खानवा को, पी एच सी पेरसर को एक चिकित्सक, पी एच सी लखनपुर को एक चिकित्सक और पी एच सी न्यौठा को एक चिकित्सक दिया गया है। ये कुछ दिनों से रिक्त चल रहे थे। उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

साथ ही, माननीय सभापति जी, यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की कुछ मांगें हैं, जो अति आवश्यक हैं। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील नदबई व उच्चैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप-खण्ड अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाये, क्योंकि बहुत पुरानी तहसील है और लम्बे समय से मांग चली आ रही है।

इसी तरह से, मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में नेशनल हाईवे से सटे ग्राम पंचायत पैरसर में नवीन ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने की भी मैं मांग करता हूं। साथ ही विधान सभा क्षेत्र नदबई है, उसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो मेरे स्वयं का गांव है, पुश्तैनी गांव है, बारहमाफी, उच्चैन पंचायत समिति के अन्तर्गत आता है, उतलछेड़ा, नदबई पंचायत समिति के अन्तर्गत आता है, अगापुर उच्चैन पंचायत समिति के अन्तर्गत आता है, रोणीजा नदबई के अन्तर्गत अता है, तेरूलूदा, उच्चैन के अन्तर्गत आता है व बछाम्दी नदबई के अन्तर्गत आती है। वहां पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पी एच सी खोले जाने की मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुर व कल्याणपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं। इसके साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र नदबई में तहसील मुख्यालय नदबई में नवीन नर्सिंग कालेज की स्थापना की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र नदबई में रिक्त पड़े चिकित्सकों के अन्य जो पद हैं, उनको भरने की भी मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा आज दिनांक को मेरे विधान सभा क्षेत्र को, जो अभी मैंने कहा, चार चिकित्सक दिये हैं, मैं उनका पुन: एक बार और धन्यवाद करता हूं।

साथ ही, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि जब-जब चिकित्सा के क्षेत्र में मैं मेरी विधान सभा नदबई के अन्तर्गत किसी भी समस्या के लिए माननीय मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

हमेशा मेरे विधान सभा क्षेत्र का ध्यान रखा और हमेशा जो-जो मेरी मांगें थीं, उनको पूरा करने का मंत्री जी ने प्रयास किया। मैं आज सदन में माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सीधे-सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मंत्री महोदय सामने विराजमान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र में पूरे विधान सभा क्षेत्र में जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको आप भरने की कृपा करें। ट्राइबल एरिया है और गुजरात से लगता हुआ एरिया है, सबको गुजरात जाना पड़ता है, इसलिए, आप उन रिक्त पदों को भरने की मेहरबानी करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर और आबू रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से लम्बा और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। वहां रेलवे स्टेशन, ब्रह्माकुमारी संस्था और नगरपालिका क्षेत्र है और जिला अस्पताल खोलने के सारे मापदण्ड पूर्ण हो रहे हैं। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि उसको यदि जिला अस्पताल किया जाए तो पूरे क्षेत्र को वहां सीधे-सीधे फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है के अन्दर 8 में से मात्र 3 पद भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं और उपखण्ड स्तर का केन्द्र है तो उनको भी भरने की कृपा करें।

रेवदर के अन्दर शिशु रोग, सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं, उनको भी भरने की आवश्यकता है। अनादरा और आबू रोड के शहरी चिकित्सालय में महिला रोग विशेषज्ञ के पद को प्राथमिकता देंगे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि रेवदर उप खण्ड स्तर का है। वहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। सिरोही 52 किलोमीटर और आबू रोड 35 किलोमीटर पड़ता है। वहां पर ट्रोमा सेन्टर और ब्लड बैंक नहीं है, तो इनको भी आप खोलें, ताकि उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिले।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि अनादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किये एक साल हो गया है। उसके अन्दर 22 पोस्टें हैं और 22 में से सिर्फ और सिर्फ 6 पद भरे हुए हैं। वहां पर डाक्टर नहीं हैं और कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं। उनको भी भरा जाये, क्योंकि आपने पिछले साल प्राथमिक केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया है, लेकिन आज न तो वहां बिल्डिंग बनी है और वहां डाक्टर, स्टाफ एक भी नहीं लगा उसके क्रमोन्नत होने के उपरान्त, तो इनको भी लगाने की आवश्यकता है।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र दत्ताणी, नागाणी और रायपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। मण्डार, दात्रायी, आदिवासी बहुल और सन्नार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। रेवदर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र के सेबराखेड़ा, गौरेली, छालोतरा पालड़ी खेड़ा, राजगढ़ बिलड़ा खेड़ा, करेली, रानाड़ी और पंचायत समिति आबूरोड के गांधी नगर व धामसरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र है, वह ट्राइबल क्षेत्र है, बहुत लम्बा क्षेत्रफल है। यदि आप सुविधा देंगे तो क्षेत्र की जनता को, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सबको अपनी-अपनी चिन्ता रहती है, उस क्षेत्र की जनता को भी चिन्ता रहती है, उसको आप संज्ञान में लें।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र, मूंगथला वर्तमान में स्कूल के कमरे में संचालित है। वहां पर जमीन भी अलॉट नहीं है तो वहां पर जमीन और भवन की आप व्यवस्था करवायें, ताकि क्षेत्र की जनता को फायदा मिले। रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जांच के सम्बन्ध में, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चल रही है, उसमें वहां पर कुल मिलाकर सामान की व्यवस्था नहीं है तो मंत्री महोदय वहां पर चूंकि उप खण्ड स्तर का है, लेकिन वहां यह व्यवस्था नहीं है तो इसको करवाने की आवश्यकता है। रेवदर और आबू रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिसर के अन्दर ही डॉक्टर्स की रहने की व्यवस्था हो जाये तो उससे वहां पर लोगों को फायदा मिलेगा और रात को पेशेंट जब आते हैं तो उनको इधर-उधर जाना नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समस्त राजकीय चिकित्सालयों के अन्दर दवाइयां समय पर नहीं मिलती हैं और लोगों

(श्री जगसी राम)

को प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर जाना पड़ता है तो इस पर भी आप व्यवस्था करें। अभी आप जवाब देंगे तब बतायेंगे कि हमने सारी व्यवस्था की हुई है, सब तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि उस समय नहीं मिलती है तो उसमें मॉनिटरिंग भी करें और सारी जो सरकार की ओर से दवाइयां हैं वे उपलब्ध करायी जायें।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि रेवदर उप खण्ड पर नर्सिंग कालेज की आवश्यकता है। यदि नर्सिंग कालेज उप खण्ड स्तर पर खोला जाये तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सार्थक चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के साढ़े चार करोड़ मतदाता आठ करोड़ की आबादी हम दो सौ विधायकों को चुन करके भेजती है और चुन कर इसलिये भेजती है कि हम उनके चिकित्सा की, शिक्षा की और सभी प्रकार के विकास की चिन्ता करें, लेकिन जिस तरह से सदन में बैठकों की संख्या कम होती जा रही है यह चिन्ता का विषय है। चिन्ता का विषय, सभापति महोदय, इसलिये है जब सदन में चर्चा होती है और चर्चा में माननीय विधायक चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भी सार्थक चर्चा करता है और सार्थक विचार रखता है उस पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन का राजस्थान की आठ करोड़ की जनता की नजर में अगर महत्व घट जायेगा तो हमारे यहां आने का कोई महत्व नहीं रह जायेगा। इसलिये सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो विनम्र आग्रह करूंगा कि कोई भी चाहे नया हो, चाहे चार बार का हो, चाहे पांच बार का विधायक हो, उसकी बात पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत है और पक्ष और विपक्ष मिल करके अगर इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं तो जिस तरह से कोरोना काल में पक्ष और विपक्ष ने मिल कर के हमारे राजस्थान का नाम विश्व स्तर के पटल पर ले जाकर रख दिया, उसका श्रेय मैं मुख्य मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय और तमाम

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

हमारे विधायकों को और जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने मानव की जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रयास किये, वे बेहतर प्रयास रहे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इससे मुझे पीड़ा भी है कि एक विषय को, जब वो ही टेबलेट जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो फायदा करती है और कांग्रेस का शासन होता है तो फायदा नहीं करती है। टेबलेट वो ही है, माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि पक्ष में आदमी अलग बात बोलता है उसी टेबलेट के लिए और विपक्ष में जाकर उसी बात को नकार देता है। मैं समझता हूं कि जनता के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें पक्ष और विपक्ष की बात छोड़ करके राजस्थान की जनता के चिकित्सा और स्वास्थ्य की चिन्ता करने की आवश्यकता है।

सम्माननीय मंत्री महोदय मेरे जिले से आते हैं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से चिकित्सा विभाग की कमान सम्भाल रखी है वह तारीफे काबिल है। आपने 1,700 डॉक्टर्स को एक साथ भर्ती करके राजस्थान की पी एच सी, सी एच सी और जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल में जिस तरह से पोस्टिंग की है इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। जहां बहुत सारी पी एच सी खाली पड़ी हुई थीं, आदमी सोचता था घोषणा हो गयी है, लेकिन डाक्टर कब लगेगा इस बात की चिन्ता के लिए और इस बात की व्यवस्था के लिए माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय परसादी लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

राजस्थान एक पहला राज्य है जिसने नि:शुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर की चिन्ता की और उसको उपलब्ध कराने के लिए बात कही है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सपना है, संकल्प है कि निरोगी राजस्थान किस तरह से बने। माननीय सभापति महोदय, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है कि जब आदमी बीमार होता है तो रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानने से मना कर देता है कि पैसे मांगने आ जायेगा। आज सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की कि एक सिर्फ जनाधार कार्ड, एक चिरंजीवी योजना का कार्ड लेकर के वह अस्पताल चला जाता है और उसका फ्री इलाज होता है। यह हमारे पूरे राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें खास तौर से चिरंजीवी योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सवर्णों के लिए जो ई डब्ल्यू एस है, उस श्रेणी के लिए भी नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन की जो बात कही है, यह भी एक बहुत बड़ा उपकार राजस्थान की जनता पर किया है। मैं कहना चाहता हूं छोटी-छोटी जांचें हैं, लेकिन जांचों में जब 5-7 सौ रुपये लगते हैं तो उस गरीब को पीड़ा पहुंचती है। कई बार तो यह देखा है कि सोनोग्राफी के कारण महिला अस्पताल में आती है और सात सौ रुपये उसकी जेब में नहीं होते हैं। बच्चा पेट में होता है, सोनोग्राफी नहीं कराने के कारण बच्चे की कई बार मृत्यु हो जाती है, उसकी मां को भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है और उस परिवार को पीड़ा झेलनी पड़ती है। आज राजस्थान सरकार ने मिल कर के 56 प्रकार की जांचें ब्लाक स्तर पर करने की बात कही है, मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, नशे की ओर हमारा युवा भटक रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कुछ जिलों में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की है। माननीय परसादी लाल मीणा जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे दौसा जिले में भी अगर आपकी मेहरबानी हो जायेगी और नशा मुक्ति केन्द्र खुल जाता है तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने सारे विधायक और सारे हमारे अधिकारियों ने मिल करके एक युद्ध स्तर पर आम जन की मदद करने के लिए चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे दवाइयों की सप्लाई हो, चाहे खाने की सप्लाई हो, हर वर्ग ने इसमें सहयोग किया है। खास तौर से धरती के भगवान डॉक्टर्स, ए एन एम, हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी यानी टीम स्वास्थ्य विभाग ने बहुत शानदार और जानदार काम किया। भीलवाड़ा माडल का हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने भी, माननीय मुख्य मंत्री जी की जो एक माडल था, उसकी प्रशंसा की। हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जिस प्रदेश के माडल की देश का प्रधान मंत्री अगर प्रशंसा करता है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): तो मैं समझता हूं कि यह बहुत सौभाग्य की बात है। अब सी एच ए पर भी हमें विचार करना चाहिये, उन्होंने भी कोविड में हमारी बड़ी मदद की।

मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में आपने जिला अस्पताल खोला इसके

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

लिए धन्यवाद। मेरे गांव में आपने सी एच सी खोली, बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में आपने सी एच सी खोली, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने खानपुर और अलीपुर में सब सेन्टर खोल दिये हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सांथा और पावटा जो पी एच सी है उसमें सी एच सी खोलने की कृपा करेंगे। हिंगोटा और गहनोली में आपने पी एच सी खोल करके दी है। पीपलखेड़ा, समलेटी, सालिमपुर थाना बरीतकी, ऊकरूंद, बेरखेड़ा, टीकरीकलांनोद, बनावण, धौलखेड़ा सहित सभी उप केन्द्रों पर भवन के लिए आपने पैसे दिये, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़िया, डिगारिया भीम, रामगढ़, खानपुर और अलीपुर में भवन जर्जर अवस्था में हैं तो वहां भी आप राशि देने की कृपा करेंगे। खौंचपुरी, सालिमपुर, ऊकरूंद, धौलखेड़ा, पाखर एवं नाहेड़ा, बालाहेड़ा में पी एच सी खोलने की मांग करता हूं। साथ ही, मण्डावर बड़ा कस्बा है जहां रेलवे स्टेशन है, उप खण्ड कार्यालय है, वहां के अस्पताल में आप उप जिला अस्पताल खोलने की घोषणा करेंगे। साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में और चिकित्सा मंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान बढ़ रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

विकास एक निरन्तर प्रयास है। यह एक ऐसा प्रयास है जो अनवरत जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। मैं सदन के साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि महवा का जो उप जिला अस्पताल है जिसको अभी जिला अस्पताल किया है, वहां हर दिन एक अलग रंग की बेडशीट बिछाते हैं वह बेडशीट बिछाने से हर मरीज को यह पता लग जाता है कि किस दिन कौन से रंग की बेडशीट बिछती है, वह एक तारीफ है। मैं समझता हूं कि पूरा प्रदेश इस पर अनुसरण करने का काम करेगा।

हमारे छोटे से अस्पताल में हर्निया जैसी बीमारियों का, छोटे-छोटे आपरेशंस का महवा ब्लाक पर हमारे डाक्टर्स काम कर रहे हैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): एक मिनट सर, लास्ट। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि सी एच सी स्तर पर भी होम्योपैथी का अस्पताल होना चाहिये और मैं ये ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा प्रयास है जो सभी सरकारें करती हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

'आंसू न होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत न होतीं।
अगर मिल जाता एक ही बजट में सब कुछ तो अगले बजट का इंतजार न होता।'

जय हिन्द। जय सर्व समाज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 - चिकित्सा और 28 - चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इस बजट की टैगलाइन है 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी लगातार इस ओर प्रयासरत हैं कि यह टैगलाइन मूर्त रूप से आत्मसात हो रही है। हर बजट में उत्तरोत्तर हो रहा है। कोरोना काल एक ऐसा वक्त आया था जिसके बाद सबसे बड़ा काम चिकित्सा विभाग का था और बखूबी चिकित्सा विभाग ने इसको किया और अभी लगातार इसको करते जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं कि आम लोग अपनी बीमारी का इलाज किस तरह करा सकें। किस तरह से सारी चिंताएं छोड़ कर अपने परिजनों का, अपना, अपने बच्चों का इलाज करा सकें, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी जनता की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने 1,763 डाक्टर्स की भर्ती करके राजस्थान की जनता को एक नया तोहफा दिया है। डाक्टर्स की बहुत बड़ी कमी चल रही थी। एक ऐसे समय में डाक्टर्स को लगाना निश्चित रूप से एक बड़ा काम था और डाक्टर्स भी वह जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और उनका प्रोबेशन काल है, उस प्रोबेशन काल में डाक्टर्स लगाकर उन अस्पतालों को आपने बहुत बड़ी राहत प्रदान की है, वहां की जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है, इसके लिये मैं आपका मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। 11 डाक्टर्स आज मुझे मिले हैं, इसके लिये दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वहां बहुत बड़ी कमी थी। मैंने तीन दिन पहले माननीय मंत्री महोदय के नजदीक जाकर निवेदन भी किया था और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि दो-तीन दिन में डाक्टर्स लग जायेंगे। आज आपने वह करके दिखाया। आपका बहुत-बहुत साधुवाद।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना पर आज हर कोई बोला है। इस पर जितनी बार बोला जाये, उतना ही कम है। यह एक

(श्री सुरेश टाक)

माडल है, यह एक इतिहास बना है कि इस तरह से 10 लाख, 25 लाख रुपये का इलाज फ्री होना, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये मिलना, यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से अपना परिवार मानते हुए राजस्थान के लोगों को यह सौगात दी है, इसको राजस्थान कभी भी नहीं भूल पायेगा। एक कठिन समय के बाद राजस्थान की सरकार ने जनता के साथ खड़ी होकर जो रोल निभाया है, वह वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है।

इसी के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी 54 जांचें चालू करके आपने एक नया नवाचार किया। उस गरीब जनता को भी आपने सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि आप गांवों में उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर, सी एच सी पर जाकर अपनी जांचें फ्री करा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सेक्टर में किया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके इस कार्यकाल में निश्चित रूप से नवाचार हुए हैं। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ऐसे डाक्टर्स को आपने अलग-अलग किया है जो बहुत सालों से जमे हुए थे। बड़ी हिम्मत का काम था और आपने यह करके दिखाया है, इसके लिये भी आपका बहुत-बहुत साधुवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 15 स्थानों पर 20 करोड़ रुपये की लागत से नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की है। जो हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, उसको नशे से रोकने के लिये जो काम किया है, यह भी एक बड़ा काम है। बच्चों में नशाखोरी की आदत से उनमें धीरे-धीरे अपराध की प्रवृति बढ़ रही है, यह एक बड़ा काम होगा। राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कालेज खोलना। इसी के साथ-साथ आपने जो नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नये सब-सेंटर के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसके लिये भी मैं धन्यवाद दूंगा।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि 2021-22 में आपकी और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से मेरा यज्ञनारायण चिकित्सालय जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुआ था, लेकिन किसी कारणवश शायद उसको अभी तक जिला अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिली हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बजट की घोषणा में किशनगढ़ के यज्ञनारायण चिकित्सालय को प्राथमिकता पर लें। वहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, 5 लाख लोगों की

(श्री सुरेश टाक)

आबादी है, 3 लाख वोटर हैं। वहां पर बाहरी लोगों का भी आना जाना है। अजमेर सेंटर के बाद सबसे ज्यादा ओ पी डी मेरे किशनगढ़ की है। जिला अस्पताल तो माननीय मुख्य मंत्री जी और आपने कर दिया, पर उसकी सुविधाएं बढ़ाएं, स्टाफ बढ़ाएं, वहां पर एक्सपर्ट डाक्टर लगाएं और सीटी स्कैन मशीन और एम आर आई की मशीन विशेष तौर से किशनगढ़ को उपलब्ध कराएं, जिससे वहां के मरीजों को पूरी तरह से इलाज मिल सके।

एक निवेदन मेरा और है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 60 वार्ड, 41 ग्राम पंचायतें, 210 गांव हैं। वहां एक मात्र अस्पताल यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय है और वहां पर प्रतिदिन गर्भवती महिलाएं प्रसव हेतु आती हैं, जिनकी प्रतिवर्ष की संख्या लगभग 7,000 है। साथ ही इस चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 700 नवजात शिशु एसएनसीयू एवं शिशु वार्ड में प्रतिवर्ष लगभग 3,000 शिशु उपचार हेतु भर्ती होते हैं, परंतु चिकित्सालय में गायनिक विभाग, लेबर रूम, जे एस वाई वार्ड, शिशु वार्ड तथा एसएनसीयू वार्ड अलग-अलग जगह संचालित है, जिससे गर्भवती महिलाओं को, प्रसूताओं को, नवजात शिशुओं को और चिकित्सा अधिकारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): यह बजट 15वीं विधान सभा का आखिरी बजट है, चिकित्सा पर आखिरी चर्चा हो रही है, इसके बाद इस 15वीं विधान सभा की चर्चा नहीं हो पायेगी। आज मैं आपसे यह आग्रह करूंगा और विशेष तौर से मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक जन की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे वहां पर एम सी एच विंग की घोषणा की जाये, ताकि वहां पर हमारे बच्चों को, प्रसूताओं को, चिकित्सकों को असुविधा नहीं हो। किशनगढ़ यह मांग भी करता है और डिजर्व भी करता है, बहुत बड़ा इलाका है।

इसी के साथ आज आपने मेरे यहां 11 डाक्टर्स लगाये हैं, लेकिन यज्ञनारायण चिकित्सालय में अभी भी दो चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। एक वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग का पद रिक्त है, एक नर्सिंग अधीक्षक का पद, तीन नर्स ग्रेड प्रथम के पद और 22 नर्स ग्रेड द्वितीय के पद रिक्त हैं। कृपया इन पर भी ध्यान करके जितनी मेहरबानी आपने अभी रखी है, उतनी ही रखें, ताकि वहां की चिकित्सा सुविधा को बेहतर कर सकें।

(श्री सुरेश टाक)

ब्लाक अरांई के अधीनस्थ विभिन्न पी एच सी एवं सी एच सी में सभी संवर्गों में चाहे नर्स प्रथम हो, चाहे नर्स द्वितीय हो, ए एन एम हो, एल टी हो, लैब असिस्टेंट हो, सीआरए हो, फार्मासिस्ट हो, करीबन 100 पद रिक्त हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी यह लगे तो किशनगढ़ अरांई को प्राथमिकता दें।

किशनगढ़ ब्लाक के शहरी क्षेत्र में मेरी शहरी पी एच सी में बजरंग कॉलोनी व चैनपुरिया में एन एच एम के अंतर्गत 1-1 चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है, उसको भी भरवाया जाये।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): किशनगढ़ ब्लाक के अन्य अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों पर सभी संवर्ग, जिनमें नर्सिंग आफिसर, ए एन एम के 73 पद रिक्त हैं। कृपया इन बातों पर ध्यान दें और मेरे पदों को भरवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सी एच सी अरांई का चिकित्सालय भवन पूरी तरह जर्जर है, जिसको पी डब्ल्यू डी ने भी कंडम कर दिया है। मैंने पहले भी आग्रह किया था और अभी फिर आग्रह कर रहा हूं, अस्पताल में कोई बड़ी केजुअल्टी नहीं हो, वह बिल्डिंग कभी भी नीचे आ सकती है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि अगर मेरे जैसा लंबा व्यक्ति उस सी एच सी में जाता है तो छत टच करती है। अभी जो 150 करोड़ का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने आबंटित किया है, कृपया इसमें अरांई सी एच सी को प्राथमिकता देकर वहां पर एक नये भवन की आप घोषणा करवा दें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरी ज्यादा डिमांड नहीं है, मैं दो उप स्वास्थ्य केन्द्र आपसे मांग रहा हूं जो अतिआवश्यक है, डबरेला और बांदरसिंदरी। बांदरसिंदरी एन एच 8 पर है और वहां हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर है, बिरला स्कूल है, बच्चे रोज आते हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। वहां पर उनको फर्स्ट-एड मिल जाये, इसलिए जरूरी है कि बांदरसिंदरी में एक पी एच सी और डबरेला में एक पी एच सी हो जाये, ताकि मेरे लोगों को वहां पर प्राथमिक इलाज मिल जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): डबरेला, बांदरसिंदरी, टिकावडा, छोटालाम्बा, बरना, आकोडिया, भोगादीत, झाड़ोल, निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद, सिलोरा, कटसूरा को भी आप प्राथमिकता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रखें। धौलपुरिया-अराई, भोजियावास-किशनगढ़, कल्याणीपुरा-अराई, डांग-अराई, नयागांव-किशनगढ़, गुजरवाड़ा-अराई, टोंकड़ा-किशनगढ़ और गेहलपुर सिरोंज गांवों में मैं नवीन उप केन्द्रों के लिये आपसे आग्रह करूंगा। उम्मीद करूंगा कि ढसूक में जो आपने अभी नई पी एच सी दी है, उसके भवन निर्माण के लिये स्वीकृति प्रदान करेंगे। एक खंडाच के लिये मैंने आपसे आग्रह कर दिया था। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, नव क्रमोन्नत पी एच सी, खंडाच के भवन निर्माण व भूमि देने के लिये भामाशाह आर के फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अशोक पाटनी जी द्वारा सहमति दे दी गई है। वह पत्र भी मैंने आपको दे दिया है। अत: पी एच सी, खंडाच का नामकरण अतिशीघ्र श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी पी एच सी किये जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि आर के फाउंडेशन द्वारा वहां पर भवन निर्माण करवाकर लोगों को राहत दी जा सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह आप सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की बात कह दीजिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सभापति महोदय। मंत्री महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी कार्य प्रणाली और आपने चिकित्सा व्यवस्था में जो सुधार किया, उसके लिये आपको सैल्यूट है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे गांव में 70 बेड का सी एच सी दिया है और उसके भवन का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। आपने मुझे पांच पी एच सी दिये हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पांचों में से चार का तो कार्य प्रारम्भ हो चुका है और एक में आप स्वयं वहां पधारे थे।

मंत्री महोदय, एक पी एच सी है, उसके लिए निवेदन करूंगा कि आऊवा गांव में 1970 के दशक में पी एच सी बनी थी पर वह सब-सेन्टर जितना छोटा भवन है। मैं चाहूंगा कि आप नया भवन इस बजट में स्वीकृत करायें। मैंने पहले भी आपसे मांग कर रखी है। मारवाड़ जंक्शन जो कि तहसील मुख्यालय है, एस डी एम हैडक्वार्टर है और रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि

(श्री खुशवीरसिंह)

वहां सी एच सी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े गांव किवाड़ा और कटालिया हैं। वहां की जनसंख्या को देखते हुए और आसपास के क्षेत्र को देखते हुए पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने की मांग कर रहा हूं। साथ ही, मैं नये पी एच सी के लिए मांडा, सुराढ़, धूंधला, बोरीमादा, सोमेसर की भी मांग करता हूं।

मंत्री महोदय, सबसे महत्वपूर्ण देवली पाबूजी है। वह अपने आप में ही एक पहचान रखती है। वह उस महापुरुष की जन्मभूमि है शहीद मेजर दलपत सिंह की, जिन्होंने हाइफा में प्रथम विश्व युद्ध के अन्दर ऐसा अनूठा काम किया। मैं स्वयं 1996 में जब प्रधान था और हमारे मुख्य मंत्री महोदय शेखावत साहब ने मुझे वहां पर भेजा था, तब मैं हाइफा जाकर देखकर आया। उस वक्त वहां की पाठ्य पुस्तकों में मेजर दलपत सिंह जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। यहां तो हम अनभिज्ञ हैं, हमको कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसे महापुरुष जिनकी जन्म स्थली मेरे विधान सभा क्षेत्र में है तो मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि दलपत सिंह, जैसे तीन मूर्ति जो कि दिल्ली में है, उसमें से एक प्रतीकात्मक मूर्ति मेजर दलपत सिंह की है। मैं चाहूंगा कि एक पी एच सी आप देवली पाबूजी में उनके नाम से स्वीकृत करें। उन शहीदों को याद करने के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मंत्री महोदय, इसके साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर अगर उनके नाम से पैनोरमा कर दिया जाये तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई सौगात नहीं होगी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि देवली पाबूजी में शहीद मेजर दलपत सिंह जी का पैनोरमा भी वहां बनाया जाए। मंत्री महोदय, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इसमें सिफारिश करेंगे।

साथ में, जो भामाशाह लोग हैं, मंत्री महोदय, आप स्वयं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पधारे थे और एक पी एच सी का शिलान्यास जाणूदा गांव में किया था। जाणूदा गांव के एक बहुत बड़े भामाशाह हैं मूलचन्द मुकेश नहार जी, जिन्होंने एक करोड़ रुपये का काम मातृ शिशु कल्याण भवन का, अपन गये थे तब वहां पर वह कार्य चल रहा था। वे प्रतिवर्ष लाखों रुपये चिकित्सा उपकरण की सुविधा के लिए रोटरी क्लब में, बेंगलूर में रहते हैं और बेंगलूर में भी देते हैं। करोड़ों रुपये का चन्दा वे प्रतिवर्ष देते हैं, हमारे मुकेश मूलचन्द जी नहार, जाणूदा वाले। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को प्रदेश

(श्री खुशवीरसिंह)

स्तर पर सम्मानित करें, ताकि उनका हौसला अफ़ज़ाई हो और भामाशाह कदम बढ़ाकर आगे आयें।

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। प्रत्येक सी एच सी पर, अभी होम्योपैथी डाक्टर्स बाहर बैठे थे और वे मिल गये। जिस बीमारी से मैं लड़ रहा हूं, उसके लिए मेरा होम्योपैथी का इलाज चल रहा है और मुझे कुछ राहत महसूस हुई है। उनकी एक मांग है कि सी एच सी पर उनका एक पद सृजित कर दिया जाये। यह भी एक स्थायी कारगर और ठोस चिकित्सा पद्धति है। मैं चाहूंगा कि आप उनका भी सी एच सी पर एक पद नियुक्त कर दें। मैंने एक सब-सेन्टर की सूची आपको दी है। आपने मेरे कई सब-सेन्टर का किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, अत्यन्त हर्ष का अवसर है कि नि:शुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को लगभग 3 हजार 700 करोड़ से जो नि:शुल्क सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वह एक सराहनीय कदम है। इसी तरीके से चिरंजीवी में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं।

जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, मैं सदन में आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे यहां पिछले वर्ष सेटेलाइट हास्पिटल की घोषणा हुई थी। उसकी जमीन का आबंटन हो चुका है, उसका टेण्डर हो चुका है, उसका अवार्ड हो चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि सक्षम स्तर पर बात कर उसका शिलान्यास जल्दी से जल्दी कराया जाये। इसी तरीके से मेरे यहां पर जिस तरीके से पिछले बजट में रामगंज जच्चा खाना को आपने आरजी तौर पर सेटेलाइट हास्पिटल चलाने के लिए परमिशन दी, उसमें सेटेलाइट से पहले जो ओ पी डी थी, वह तकरीबन डेढ़ सौ से दो सौ थी, लेकिन चूंकि आपने बहुत मन से मदद कर पिछले वर्ष डाक्टर्स लगाये, 13

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

डाक्टरों की नियुक्ति हुई और आज उस हास्पिटल की ओ पी डी साढ़े सात सौ से साढ़े आठ सौ प्रतिदिन हो गयी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। मैं अपनी डिमांड में आपसे यही कहना चाहता हूं कि वार्ड 73, जो कि हमारा पुराना हैरिटेज का वार्ड है, उसके अन्दर एक सिटी डिस्पेंसरी के नाम से सैंक्शन है, लेकिन वह कागजों में कहीं और चल रही है। मैंने नगर निगम से बात कर एक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जो भवन है, उसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जगह है, चाहे सरकार उसमें पैसा न दे, मैं विधायक कोटे से अपना पैसा देकर उस बिल्डिंग का भवन बनाने के लिए आपको सहमति देता हूं, लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी मेरे क्षेत्र में शुरू करवाया जाये।

इसी क्रम में जयपुर शहर में एन यू एच एम के लगभग 25 स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें चिकित्सक हैं, परन्तु समस्त केन्द्रों पर जी एन एम, ए एन एम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, लैब असिस्टेंट आदि सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। मेरा आपसे आग्रह है कि सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आप जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करायें। इसी तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस तरीके से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो रामगंज जच्चाखाना है, उसका जो पुराना भाग है, उसका मैंने भी निवेदन किया था, उसमें पांच करोड़ रुपये के एक नये भवन की जो स्वीकृति दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद।

कोरोना के समय राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण, आक्सीजन प्रबन्धन इत्यादि के पश्चात् पोस्ट कोविड काम्प्लीकेशंस पर ध्यान रखते हुए आर यू एच एस के अधीन centre for covid rehabilitation का काम किया। आप लोग जानते हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत गम्भीर कोविड की स्थिति थी। वहां एक मोती कटला डिस्पेंसरी के नाम एक पुराना भवन है। उसके अन्दर हम एक नयी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिसके अन्दर मैंने विधायक कोटे से 2 करोड़ 91 लाख रुपये की एक स्वीकृति दी है। उसका टेण्डर जारी होना है, लेकिन मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वहां पर, जिस तरीके से यहां पर मदर एंड केयर हास्पिटल, जो सेन्टर चालू होता है, उसके साथ में ही मोती कटला में रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए एक छोटा सेन्टर खोला जाये। चूंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर आर यू एच एस में यह फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं, बजट में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन मेरा आग्रह

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

है कि एक छोटा रेस्पिरेटरी डिजीज सेन्टर इस इलाके में बना दिया जाए। चूंकि वहां पर लोग गम्भीर कोरोना के दौर से गुजर चुके हैं तो वहां इसकी सख्त आवश्यकता है। बहुत कुछ ज्यद्दा कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना-सा कहूंगा कि जो लोग आज हमारी सरकार की बातें करते हैं और जिन लोगों को यह पता नहीं है कि 2019 से पहले राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं कहां थीं और आज कहां हैं, जो लोग आज इसकी बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद में जहां हमारी पी एच सी में इजाफा हुआ है वह 19 परसेंट हुआ है। हमारे यहां 2019 से पहले 1,890 पी एच सी थी, आज 2,265 हैं। इसी तरह सी एच सी हमारे यहां पहले 554 थीं, अब 760 हैं। सारे सेक्टर्स में चाहे सब-सेंटर हो, ट्रोमा सेंटर हो, सब जगह हमारे मुख्य मंत्री जी ने इतना इजाफा किया कि आज राजस्थान माडल पूरे हिन्दुस्तान में फेमस है।

(समय: 20.00 बजे)

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हम चिरंजीवी में जो स्टेंट्स लगा रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेंट हास्पिटल चिरंजीवी योजना में लगा रहे हैं, वे न तो अमरीकन स्टैण्डर्ड पर हैं, न यूरोपियन स्टैण्डर्ड पर हैं, वह हमारे यहां के स्टैण्डर्ड पर हैं। इससे मरीजों को अचानक से तकलीफ होती है और उसका पता भी नहीं चलता। मेरा आपसे आग्रह है, तमाम अधिकारीगण बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): इस पर एक बार पुन: विचार करके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फायदा हो, इसके लिए विचार करें।

अंत में, जिस तरह से कल ही 1,765 मेडिकल आफिसर्स की सरकार ने नियुक्ति की है, उसके लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, सरकार के मंत्री और तमाम लोगों को बधाई। राजस्थान में एक इतिहास हम रचने जा रहे हैं मेडिकल सेक्टर में। आने वाला समय राजस्थान के लिए मेडिकल सेक्टर का बहुत उज्ज्वल है। दुनिया आज राजस्थान के मेडिकल सेक्टर को देखती है। पूरे हिन्दुस्तान के राज्य ये देखते हैं कि मेडिकल में ऐसा क्या हुआ? अभी जिस तरीके से हमारे यहां अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में कांग्रेस के पूरे हिन्दुस्तान के लोग आए और उन्होंने देखा कि राजस्थान में किस तरीके से मेडिकल सेक्टर पर हमारे मुख्य मंत्री जी और सरकार के लोग काम कर रहे हैं,

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

हर व्यक्ति ने उसकी सराहना की। हम कई जगह विपक्ष में हैं, लेकिन यहां से जो लोग गए, वे हमारे अधिवेशन से प्रेरणा लेकर गए, जो हमारा एक सेंटर वहां बना था, उसकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे थे। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो आज मेडिकल सेक्टर में हमने नये आयाम स्थापित किए हैं, उसके लिए मुख्य मंत्री जी, तमाम मंत्री और साथियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद है, उसके मुस्तहिक हैं। बहुत-बहुत मुबारक। जय हिन्द। जय कांग्रेस।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, अच्छी स्कीम हो तो तारीफ करने में भी परेशानी नहीं होती। मांग संख्या 27 व 28 बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। 2019-20 में 11,661 और 2023-24 के बी ई में 18,038, यात्रा कितनी-सी है? जहां 5.46 परसेंट बजट का कुल व्यय का प्रतिशत था, वह घटकर 4.61 प्रतिशत हो गया। यह तो सारा सिस्टम इन्वाल्व है। अभी बात हो रही थी सिर्फ एलोपैथी की। एलोपैथी में 2019-20 में कुल व्यय का प्रतिशत 2.17 था, आज हो गया 2.27, इतना ही बढ़ा है। बीच में 2.62 भी हुआ है, 2.35 भी हुआ है। यह बजट घटता जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं इतनी आप कर लेंगे? घोषणा तो आप कर देंगे, लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरेगा, ऐसा संशय सभी को है। इस राशि में अन्य चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भी शामिल हैं।

अब एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन कर दिया। एक्ट बन गया और आर्डर पास हो गये। एक्ट बनाना है और बोर्ड गठन करना है, लेकिन ये नहीं कर रहे। इस तरह से निर्णय नहीं होते। नई-नई पैथीज आयी हैं। एक और लेटेस्ट आयी है, मेरे ख्याल से दस साल पुरानी है। यू एस में एक्सपेरीमेंट्स हुए हैं। आप जिस डाक्टर को कहेंगे, उसको खुद को ट्राई करवा देना। मैंने देखा है अस्थमा, जिसको सांस नहीं आ रहा था, सिर्फ तलवे पर एक बार ऐसे तेल लगाया और सूंघा है, उस आधार पर अगर वह एक हफ्ते थैरेपी ले लेता है, खुद को ही करनी है, कोई डाक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। You have to be open. आप काफी ओपन हैं लेकिन एक रिपोर्ट है - 'Impact of India's Population Growth on Economic Development' उसमें पापुलेशन ग्रोथ में Malthus and Ricardo, उसने भी लिखा है एन्वायर्नमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और इस पर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जितना भी हम खर्च करेंगे, अगर समाज कल्याण और परिवार कल्याण के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये सारा का सारा जितनी तारीफ़ें आप कर रहे हैं, पांच साल बाद, दस साल बाद ये ग्रोथ तो होगा 78 करोड़ बच्चे पापुलेशन में इन्क्रीज करते हैं हम हर वर्ष, you have to meet the system. उस इंस्टीट्यूशन को आपको डवलप करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, पूंजीगत व्यय में केन्द्रीय निधि कितनी है? सरकार ने केन्द्र सरकार को कोसा तो खूब है लेकिन जहां पर 2022-23 के बजट एस्टीमेट में 52 परसेंट के करीब था, 3,138 करोड़ के कुल व्यय में 1,496 करोड़ केन्द्र का। 2022-23 में ये ही है करीब 50 परसेंट और 2023-24 में 51 परसेंट केन्द्रीय निधि है। इतना केन्द्र दे रही है उसके बाद में कम से कम थोड़ी तो शाबासी दी होती कि केन्द्र सरकार ने अच्छा किया है। Vaccination-medical & health is a state subject...

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): स्टेट सब्जेक्ट में आप किसी पर थोप नहीं सकते। फिर भी दो बार, जितने वैक्सीनेशन हैं, फ्री लगा है। हमारे सदन के नेता ने तो ग्लोबल टेंडर खोलकर भी डिमांड करके कोशिश की है, लेकिन पार नहीं पड़ी और वहां से मुफ्त में हुआ है तो कम से कम एप्रिशिएट तो करना चाहिए। कोरोना अपने आप नहीं चला गया है। वैक्सीनेशन का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अभी हमारे रतनगढ़ से आने वाले साथी विधायक ने जब बात बताई रेमडेसिविर और स्टेरॉयड्स, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट हैं। 100 प्रतिशत इन्हीं की है। कहीं कोई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रूव्ड नहीं है। दिए जा रहे हैं। एक प्रिन्टेड सिस्टम बन गया। कोरोना तो मेरे को भी हुआ था लेकिन मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक ली हैं, माइल्ड एंटीबायोटिक और 14 दिन आइसोलेशन रखा। अपने आप ठीक हो गया। अब D-dimer बढ़ेगा, लास्ट में आएंगे। बुखार होगा तब भी दिखाएंगे नहीं तो फिर परेशानी होनी ही है।

चिरंजीवी योजना की खूब तारीफ हुई। अच्छी योजना है लेकिन मंत्री महोदय, इम्प्लीमेंटेशन डिजास्टर्स में आ गया, दोबारा कहता हूं डिजास्टर्स है। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होता है? आप जाकर देखिए तो सही प्राइवेट हास्पिटल्स में, जहां उसको टर्न डाउन कर दिया जाता है। उसको भेज देते हैं वापस कि आपका ये पिक नहीं कर रही है। 12 बजे बाद में अगर कोई जाता है, चाहे

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अच्छे स्टैण्डर्ड वाले में, मैं हास्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेट हास्पिटल में अगर 12 बजे बाद जाता है तो अगले दिन आइए। अब जिसको तकलीफ अभी है, अगर एंजाइना का पेन है और उसको मायोकार्डियल इन्फार्कशन नहीं हो जाए, अगर वह समझता है तो वह कहेगा, भइया, जो इंवेस्टिगेशन करना है वह तो शुरू कर ले। स्टेंट की पोजिशन क्या है? आपके परचेज करने वाले कौनसे स्पेशलिस्ट हैं? वह सब्जिक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट हो, उसकी टीम हो और वह बताए, वह चीज खरीदे तब तो सही है। आपका अपना खुद का, अभी नहीं तो दो-तीन साल बाद में केटेरेक्ट का आपरेशन कराना पड़ेगा। ये एज के हिसाब से आती है। केटेरेक्ट का आपरेशन कराएंगे तो स्टेंडर्डाइज है कि ये ही इम्प्लांट हम तो लगाते हैं, दूसरा आपको लगाना है, उससे बैटर है तो आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा। आज विधायकों के, अगर किसी के आवश्यकता है तो वह तो केस करके भी ले लेगा कि हम तो एक्ट से गाइडेड हैं। अल्टरनेटिव्स तो आपको रखने चाहिए। अगर यह रास्ता बंद है तो यहां से एग्जिट होगा।

पेंशनर्स, पेंशनर सिर्फ 60 साल का ही नहीं है। 90 साल से ऊपर की एज का भी है। बहुत-सी बार दवाइयां नहीं मिलती हैं और वे चले जाते हैं। यह किसने शुरू किया था? बांसवाड़ा और चित्तौड़ को लेकर जेनेरिक मेडिसन को सस्ती करने का क्रम, जब मैं चिकित्सा मंत्री था, हम लोगों ने मिलकर शुरू किया है। तब का आप ले लें, सेट्राजिन 27 रुपये 40 पैसे की आती थी, हमने 1 रुपये 05 पैसे में कापरेटिव के माध्यम से देना शुरू किया था, लेकिन हमने राइडर रखा था। 150 करोड़ से कम के टर्न ओवर की कोई कम्पनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आज 5 करोड़ वाले भी कर रहे हैं। पहले जैसे सीरप कढ़ाइयों में बनता था, वैसा ही सीरप आएगा, उसी क्वालिटी की ड्रग्स आएगी। Massive purchasing जो भी परचेज कर रहे हो लॉट के हिसाब से इन्वेस्टिगेट कीजिए, पक्का कीजिए, लेकिन आप कौनसे लॉ में पनिश कर दोगे? पनिशमेंट करने का आपके पास एनेब्लिंग क्लाज तो ही नहीं। चाहे फूड अल्टरेशन में हो, चाहे ड्रग अल्टरेशन में हो। Government has no power. एनेब्लिंग क्लाज नहीं है। बनाइये लॉ, कहां दिक्कत है? लॉ बनाएंगे, तभी जाकर रूकेगी। यू एस में अगर कोई दवाई में मिलावट करता है, कैपिटल पनिशमेंट, 15-15 जिन्होंने मारा, अभी बच्चों के स्कूलों में जहां फायरिंग हो रही है, उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, फांसी नहीं है परन्तु जिसने दवाई में मिलावट की है, वह

(श्री नरपत सिंह राजवी)

समाज के साथ खिलवाड़ है, उसको आज भी वहां फांसी की सज़ा जारी है। बनाइये न लॉ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला कानून हम यह बनाएंगे। आपके तो बस में नहीं है।

चिरंजीवी योजना अच्छी है, लेकिन इसका आई पी डी बेस है। यह प्लेन है, यह इंश्योरेंस नहीं है। बजट में कहीं इंश्योरेंस की प्रीमियम रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। अगर प्लेन है, तो स्टेट की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, यह आगे चलने वाली भी नहीं है। 2008 के अंत तक, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था। भामाशाह योजना का तो उसको एक नाम दिया है। उस कार्ड के साथ बी पी एल के लाभ और मेडिकल का भी क्योंकि यहां तो ऐसे-ऐसे कलाकार भी हैं, कि हाथ फ्रैक्चर हो रहा है जोगेश्वर जी का और मेरा कार्ड लेकर इलाज करवा कर आ जाएंगे। उस चीज को रोका है। उस चीज को रोकना था तो इस तरह से बायोमेट्रिक्स पर कार्ड बेस था। मेरे ख्याल से अप्रैल की बात है, राजीव महर्षि हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे, कि साहब यह भी, इसमें बेनिफिशियरी को और जोड़ते हैं और वह समय लग गया, वरना यह योजना तब भी चालू हो रही थी लेकिन इम्प्लीमेंटशन में जहां-जहां सुधार करना है, हम कोई आपको या सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटशन में आपको लूपहोल्स को प्लग करना पड़ेगा।

एग्जाम्पल देता हूं। आज जयपुर की कोई भी यूनिट अगर एस्टेब्लिश करेगा, चाहे फोर्टिस हो, ईएचसीसी हो, प्राइवेट संतोकबा दुर्लभी, तो यह बड़ी है। जयपुर के पास है। जयपुर के हार्ट पर है। यहां पर जमीन लैंड कॉस्ट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। छोटे डिस्ट्रिक्ट में, करौली या धौलपुर में ऐसा नहीं होगा, छोटी यूनिट है, उसका इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है तो ए, बी, सी, डी ग्रेडिंग करके, उस हिसाब से करते।

आर्थोपेडिक, किसी के एक्सीडेंट हुआ है, आर्थोपेडिक की अगर उसके पास फैसेलिटी नहीं है, इमरजेंसी के नाम पर वह पेशेंट को भर्ती कर लेगा, फिर कहेगा यहां पर अपलोड नहीं हो रहा, आपको दूसरी जगह जाना है। झक मारकर, वह वहां पैसा देकर आएगा और दुबारा दूसरी जगह से इलाज लेगा। आपको थोड़ा सा इसमें, what is the emergency? राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मेरे छोटे भाई हैं। इनके अगर पेट में दर्द हो तो हमारे लिए तो वही इमरजेंसी है लेकिन जो एक्सीडेंट इमरजेंसी है, जिसके पांव में फ्रैक्चर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हो गया, बड़े अस्पताल में पूछते हैं कि कहां से टूटा है। अब पेशेंट को पता है क्या कि घुटना टूटा है या एंकल टूटा है? उसको इन्क्लूड करना है तो वही entertain कर सकेगा, जिसके पास आर्थोपेडिक सर्जन है और वहां पर उसका इलाज हो सकता है। कई स्कीम पता है क्या? आधे माननीय सदस्यों को तो यह ही पता नहीं है, that it is not an insurance. It is a plan. यह एक्सपेंडिचर through the government and private players को भी जाएगा, जो इलाज कर रही है।

आप राइट-टू-हेल्थ बिल ला रहे हैं। बहुत अच्छा बिल है। इमरजेंसी का कौन डिफाइन कर रहा है? इसके बारे में सोचो तो सही। इमरजेंसी डब्ल्यू एच ओ है या नहीं है? आपको तो राजस्थान के अन्दर ही करनी पड़ेगी। यहां इमरजेंसी किसकी? अभी तक आपकी डेफिनेशन है, 'notwithstanding anything contained in any other act' यह-यह इमरजेंसी होगी, वह ही माना जाएगा, डब्ल्यू एच ओ नहीं माना जाएगा।

प्रक्रिया, अगर 12 बजे से पहले पहुंचेंगे तो अपलोड का प्रयास करेंगे। सॉफ्टवेयर को थोड़ा और डवलप करवा लीजिए। अपलोड किया, किस टाइम में अटेम्प्ट किया, ताकि वह अपलोड नहीं हुआ है, तब भी उसका इलाज चालू हो जाए। आपका सर्वर डाउन होता है। अब रजिस्ट्री कराने वाला तो जिसका होगा, लेकिन यहां जिसके इमरजेंसी है, जिसका हार्ट अटैक आने की स्थिति में है, जिसके हार्मोनल चेंजेज हुए हैं, निश्चित तौर पर आएगा। जिसके ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, अपलोड नहीं हुआ। You cannot let the patient die लेकिन प्राइवेट हास्पिटल वाले बिना अपलोड के हाथ ही नहीं लगाएंगे। इसको थोड़ा चेक कीजिए।

जिनको कंसेशनल जमीन दी है, वहां सरकार को अधिकार है। वह जाकर चेक कर सकते हैं। एक सिर्फ फोर्टिस पर विथड्रा किया था कि वहां 30 परसेंट का बेरियर नहीं है। बाकी सब में, सबको आप चेक कर सकते है। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो गरीब को लाभ होगा। गरीब को लाभ देने के लिए ही हम यहां बैठे है, और काहे के लिए बैठे हैं? but you have to do something. स्टडी करो। जिला स्तर, सम्भाग स्तर, बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में कोस्ट का आपने अन्तर नहीं रखा। ए, बी, सी, डी कैटेगराइजेशन करें। ऐसे भी केसेज यहां आए हुए हैं, जहां पर आपरेशन किसी और किसी का किया है, कार्ड उसका यूज किया है, बाद में आडिट में पकड में आ गया। इसकी रनिंग आडिट भी होनी चाहिए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इतने एमएलएज बैठे हैं। हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटी दी है, इस विधान सभा में पारित एक्ट ने दी है, किसी प्लेन ने नहीं दी है। आज अगर कैटरेक्ट का आपरेशन मैं कराने जाऊंगा, वही लगाना है जो चिरंजीवी योजना आर जी एच एस में शामिल है, वरना 32 हजार रुपये दीजिए, जैसा लेंस चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। यही एंजियोग्राफी का है। पैकेजेज को स्टडी करके, एस एम एस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जमीन भी फ्री है, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ रहा है। यहां का टैक्सपेयर, बाहर से आ रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं। टैक्स तारीफ के लिए दे रहे हैं क्या? यहां के टैक्सपेयर पर हरियाणा का, पंजाब का, गुजरात हो या मध्यप्रदेश हो, वहां के लोग, यहां पर आकर कर रहे हैं। आप उसको लिंक अप कीजिए न रेजिडेंस के साथ। यहां का मूल निवासी है, तब फ्री है, हरेक के लिए नहीं है।

जो पेंशनर्स हैं, चाहे वह क्लास फोर्थ एम्प्लोयी हो, चाहे क्लास वन हो, अगर 70-80 साल का हो गया है, तो उसको अल्टरनेटिव कुछ न कुछ तो रास्ता मिले, ताकि वह तुरंत दवाई ले ले। अभी अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। मैंने भी कई मेडिसिन परचेज की है। यहां पर बिल बनने की प्रक्रिया नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर से बात करें और एक कमेटी बनायें रिड्रेसल की, एक 181 या 13 जो भी नम्बर आपने रखे हैं कॉल सेंटर के, वहां से एक का भी इलाज नहीं हुआ है, एक का भी निस्तारण नहीं हुआ है।

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सम्भागीय स्तर पर एक बार कम्प्लेंट करने की अथॉरिटी बने और अपीलेट अथोरिटी भी बने जो सरकार के हाथ में हो ताकि कम से कम इन प्राइवेटाइजेशन जितना हुआ है, इन्होंने बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है। मेडिकल टूरिज्म भी राजस्थान में डवलप हो जायेगा, लेकिन जो बेसिक है हमारे गरीब की सुरक्षा करना, गरीब को इलाज पहुंचाना, वह तो करना आवश्यक है।

जनता क्लिनिक, यह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन 2022 में शुरू किया और इसमें 47 जनता क्लिनिक के अरबन हेल्थ वेलफेयर सेंटर (यू.एच.डब्ल्यू.सी.) के तहत आपको यह राशि अलाट हुई है। एट प्रजेंट 25 जनता क्लिनिक वर्क कर रही है राजस्थान में और यह और खोलो न, ट्राई करें। हमारे को बतायें जहां पर प्रोब्लम है, हम कोशिश करते हैं और आपको दिलवाते हैं फंड्स, लेकिन एक सुधार आपको करना पड़ेगा कि जो भी सी.एच.सीज., पी.एच.सीज. डिविजनल हैडक्वार्टर पर या जयपुर में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अलाट हो रही हैं उसको जमीन लेने में ही इतना टाइम लग जाता है। मेरे यहां पर एक सेटेलाइट हास्पिटल सेंक्शन हुआ है, साढ़े सात करोड़ रुपये डिपार्टमेंट के पास हैं। पंचायत समिति से मिले हुए उस जमीन को, निर्णय हुए मेरे ख्याल से चार साल हो गये। दूसरी जगह पंचायत समिति को अलाट भी हो गयी पर पजेशन नहीं दे रहे हैं, तो पजेशन दिलवाने के लिए कोशिश कर लो आप भी। इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां पर डवलप होगा और गरीब आशीष देगा वरना करेंगे, काकाजी उद्घाटन करेंगे और फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, 2022-23 इसमें 7.48 करोड़ रोगियों का इलाज हुआ है। मुफ्त दवाइयां दी हैं 854.40 करोड़ रुपये की। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके डाक्यूमेंट्स ही बोल रहे हैं, बजट बोल रहा है। यानी प्रति व्यक्ति ऐसे रोगी को 115 रुपये की दवाई आप लोगों ने दी है। मई, 2001 से लागू हुई कैशलेस आई.पी.डी. ट्रीटमेंट फैसेलिटी एट इम्पैनल्ड हास्टिपल्स, इम्पैनल्ड हैं 899 और सरकारी है 834, इस स्कीम में पांच दिन पहले का और 15 दिन पोस्ट हास्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर इन्क्लूड किया है। इसको और विस्तार से प्रचारित भी करो, सबको यह बताओ कि यह योजना क्या है, ताकि इसमें कोई छोटे-मोटे डिफरेंसेज हों, कमियां हों तो वह दूर करवायी जा सकें।

बाकी तो पोल खुली ही है। सिरोही अस्पताल के बारे में एक माननीय सदस्य ने बताया था कि एक शिशु को कुत्ते द्वारा उठाकर ले जाकर मार दिया गया। यह ऐसी चीजें होना कितना शर्मनाक लगती है? जोधपुर जिले में गर्भवती महिला को प्रसव अस्पताल के बाहर करवाना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, देश की ज्वलंत समस्या का कह दिया। मेडिकल कालेज आपने काफी किये हैं, अब सिर्फ तीन जिले बाकी रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसमें 60 परसेंट व्यय तो केन्द्र दे रहा है और आप पीठ खुद की थपथपा रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, यह कुछ सुधार करने के लिए मैंने बताया, आप इनकी सुधार की कोशिश करें। कैटेगराइजेशन ए, बी, सी, डी का करके एरिया अलग-अलग जहां पर है, दूरस्थ स्थान है, चिकित्सक वहां पर बैठा है, कठिनाई का सामना कर रहा है तो ऐसे कुछ कैटेगराइजेशन करके इसको इंश्योरेंस फार्म में अगर आप देंगे तो बिना चाहे ही इंश्योरेंस कम्पनी के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एम्प्लोयी और उनका वर्कर उस चीज को सूंघता फिरेगा, पर इसमें सरकारी कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी गरीब को चिकित्सालय पहुंचने के बाद वापस टर्न-डाउन नहीं करें, ऐसी व्यवस्था आप करें। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं) एवं श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़) द्वारा मांग संख्या 27 व 28 पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज 49 माननीय सदस्यों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की चर्चा में भाग लिया। मैं सब माननीय सदस्यों का तहेदिल से अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुमूल्य सुझाव दिये, कमियां बताईं और निश्चित रूप से आपके सुझाव और जो कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करने के पूरे प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह सही बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल में 02 अक्टूबर, 2011 को नि:शुल्क दवा योजना शुरू की थी तब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था कि यह पैसा कहां से लाएंगे, इतनी दवाइयां कैसे सप्लाई होंगी।

माननीय सभापति महोदय, हम सब ज्यादातर लोग गांवों से आते हैं। जब गांव का गरीब व्यक्ति या आम आदमी बीमार कोई होता है और वह जब डाक्टर के पास जाता है तो वह पर्ची लिखता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। कभी गम्भीर बीमारी होती है, तो हमको तो पूरा मालूम है कि किस तरह की कठिनाइयां लोगों के सामने आती थीं। जेवर बेचना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी और कोई भी बेटा अपने मां-बाप का इलाज करवाने के लिए सब कुछ करता था। मुख्य मंत्रीजी ने जब पहली बार इस योजना को शुरू किया, 2013 के बाद सरकार बदल गयी और यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। जब दुबारा 2018 में सरकार बनी और जब कोविड यहां पर आया तो निश्चित रूप से लोगों को यह आभास हुआ कि कोविड में कितना महंगा इलाज, कैसा इलाज, कोई पता ही नहीं कि क्या दवाई होगी, क्या इलाज होगा, कैसे इलाज होगा, फर्स्ट वेव और सैकण्ड वेव में जो हालात हमारे देश के बने, वे हालात बहुत ही चिंताजनक थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस समय कितनी

(श्री परसादी लाल)

वी.सी. की? खुद भी कोविड से ग्रस्त हो गये थे। दो बार हुए फिर भी उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी और यह कह दिया कि मेरे को इस सरकार का चाहे पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े पर लोगों की जान मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लोगों की जान बचनी चाहिए, एक भी आदमी दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और आप देख लीजिए कि उसके बाद जितनी भी महंगी दवाइयां आईं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या दूसरा इंजेक्शन हो, दवाइयां हों, व्यवस्था हो, कितना बेहतर प्रबंधन कोविड का किया।

माननीय सभापति महोदय, उसकी मैं ही तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश के प्रधान मंत्रीजी ने भी तारीफ की है। हम यह भी कहते हैं कि इस कोविड की लड़ाई में भारत सरकार ने भी हमारा सहयोग दिया, बराबर जो भी मांगा, पर जितना प्रबंधन राजस्थान का भीलवाड़ा माडल का हुआ, भीलवाड़ा माडल निश्चित रूप से पूरे देश में चर्चित रहा और भीलवाड़ा माडल के बाद रामगंज माडल हुआ, उसकी सब जगह पर चर्चा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह पहला रिकार्ड होगा कि उन्होंने 22 घंटे तक लगातार वी.सी. करके सब माननीय सदस्यों से, सब माननीय सांसदों से, पूर्व मुख्य मंत्रीजी से, नेता, प्रतिपक्ष से कंटीन्यू 22 घंटे का रिकार्ड है, उन्होंने उस महामारी से लड़ने के लिए सबसे अपनी-अपनी राय मांगी, सबसे सहयोग मांगा और मुझे यह खुशी है कि पूरा सदन एक था, पूरे प्रदेश के लोग एक थे कि इस कोविड की बीमारी से कैसे लोगों को छुटकारा मिले।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, दूसरी दवाइयां भी हैं, वह सारी फ्री दीं। जब दवाइयां नहीं मिलीं तो स्पेशल प्लेन भी भेजकर उन्होंने बाम्बे और अहमदाबाद से इंजेक्शन मंगवाये और लोगों की जान बचाई। 40 हजार वाला इंजेक्शन हो या चाहे 20 हजार वाला हो या कितनी भी दवाइयां हों, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता पर लोगों की जान बचाने का काम किया और उन्होंने यह कह दिया कि मैं एक भी मेरे आदमी को मरने नहीं दूंगा और न ही भूखा सोने दूंगा। इसमें एन.जी.ओ. ने और हमारी दूसरी संस्थाओं ने भी पूरे प्रदेश का अच्छा सहयोग किया।

जब वैक्सीनेशन की बात आयी तो प्रधान मंत्रीजी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा सबसे पहले, प्रधान मंत्रीजी, वैक्सीनेशन आप फ्री लगवाइये। जब वहां से फ्री का सिग्नल नहीं आया तो मुख्य मंत्रीजी ने फैसला

(श्री परसादी लाल)

किया कि हम राज्य के बजट से लगायेंगे। आपको भी पता है कार्यकारी नेता महोदय, प्रतिपक्ष, कि सौ करोड़ रुपये राज्य सरकार ने एजेंसी को दिये। फिर बाद में प्रधान मंत्रीजी के ऊपर सारे देश का दबाव पड़ा तो वैक्सीनेशन फ्री किया। हमारा संकल्प था हमको चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़ता। भारत सरकार ने केवल हमारे लिए फ्री नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए किया। अच्छा किया, उनको धन्यवाद भी हमको देना चाहिए। इसमें हमारी कोई कंजूसी नहीं है। 200 करोड़ लोगों को दो-दो डोज लगायी। यह बहुत बड़ी चुनौती थी। हम सबने मिलकर किया। अगर मिल कर नहीं करते तो मुख्य मंत्रीजी सबसे बात क्यों करते? कई बार मीटिंग बुलाई। नेता प्रतिपक्ष को, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी से भी, आपसे, सबसे कि इस महामारी से हमको किस प्रकार से छुटकारा मिले। बहुत बड़ी चुनौती थी। आज उस चुनौती से अनाथ हुए बच्चे जिनके मां-बाप दोनों चले गये, उनको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस साल बुलाया। उनको 25 हजार रुपये पर बच्चे के हिसाब से तब तक सरकार देती रहेगी जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते। 18 साल का होने के बाद भी उनको 5 लाख रुपये और दिये जाएंगे, जिससे अपना कारोबार करें, जो भी करें। उसके बाद भी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ऐसे बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने का भी फैसला सरकार ने किया। इतना बड़ा काम किया। हम कब कहते हैं कि प्रधान मंत्रीजी ने सहयोग नहीं दिया? सब कामों में भारत सरकार देती ही है। चाहे मेडिकल कालेज हों, चाहे दूसरी चीजें हों, क्योंकि वह जी एस टी, टैक्स तो हमसे लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज की स्कीम इनके समय की नहीं थी, यू पी ए गवर्नमेंट के समय की थी। उस समय राजस्थान में माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय गुलाम नबी आजाद साहब ने कालेज दी थी। इसी पैटर्न पर दी थी 60:40 पर। कोई नयी बात नहीं है जिसको आप बार-बार गिनाओ। मेडिकल कालेज देने के काम को उन्होंने पांच साल तक बन्द कर दिया सरकार बदलने के बाद। फिर वापस शुरू किया। शुरू किया तो हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं। मेडिकल कालेज खोलने के लिए उस समय 3 जिलों को छोड़ कर हमने सभी जिलों में 16 मेडिकल कालेज का उनका आफर स्वीकार किया। देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कालेज किसी सरकार ने प्रस्ताव समय पर दिया वहां पर तो

(श्री परसादी लाल)

वह राजस्थान सरकार थी। आज हमारे जिले में मेडिकल कालेज खुलने से कितना बड़ा काम हुआ है? हमारे यहां डाक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं, तो हमारे सभी जिलों में मेडिकल कालेज 2024-25 तक चालू हो जायेंगे। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में हमारे तीन जिलों में मेडिकल कालेज के लिए वहां के सांसद महोदय ने भी कई बार कोशिश की, जालौर, सिरोही और राजसमन्द के लिए की। राजसमन्द में प्राइवेट मेडिकल कालेज था इसलिए वहां नहीं हुआ। कितना बड़ा एक हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा है और कह दिया कि हर जिले में मेडिकल कालेज होगा चाहे राजनीति कोई भी हो। मेडिकल कालेज खुलने से हमारी एम बी बी एस की सीटें चार गुना बढ़ गयीं, हमारी पी जी की सीटें बढ़ गयीं, हमारी दूसरी सीटें बढ़ गयीं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं सिरोही गया था। वहां के मेडिकल कालेज में भी गया था। 100 बच्चों का वहां पर एडमिशन हुआ है। पहला बैच है। हमने पूछा कि आप कहां-कहां के रहने वाले हो? उन्होंने कहा कि सब राजस्थान के हैं। अगर ये मेडिकल कालेज नहीं खुलते तो या तो चेन्नई जाते, बैंगलोर जाते, बाहर जाते। कितनी खुशी की बात है कि हमारे स्थानीय बच्चे राजस्थान में ही रहकर एम बी बी एस की पढ़ाई कर रहे हैं। हम कब कहते हैं, यह स्कीम पहले की थी? बार-बार उसको गिनाना नहीं। चाहे स्कीम आपके समय की हो, हमारे समय की हो। भारत सरकार के सहयोग के बिना कोई स्कीम नहीं चलती।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमने नर्सिंग कालेज खोले। उसमें तो भारत सरकार का पैसा नहीं, आपने तीन नर्सिंग कालेज खोले थे। हमने 25 का काम शुरू कर दिया। सारे नर्सिंग कालेज हम इसी सत्र से शुरू कर देंगे। एक भी नर्सिंग कालेज ऐसा नहीं होगा जिसको हम शुरू नहीं कर पायेंगे। सारे कर देंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। यह तो हम हमारे ही बजट से कर रहे हैं। तीन मेडिकल कालेज हमारे बजट से कर रहे हैं। यह संकल्प जब लिया कि हर जिले में मेडिकल कालेज होगा, हर जिले में नर्सिंग कालेज होगा। इतना बड़ा काम सरकार कर रही है, उसका थोड़ा बहुत धन्यवाद तो सबको करना चाहिए इसलिए निश्चित रूप से जो भी काम हुए आज मेडिकल कालेज की बात है, दूसरी बात है, निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया मेडिकल में, वह सराहनीय है।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, क्या कोई सोचता था कि मेरा इलाज फ्री हो जायेगा, मेरी जांच फ्री हो जायेगी? प्राइवेट हास्पिटल्स भी हैं, सरकारी भी हैं। कितना बड़ा काम हुआ है? किसी आदमी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी नरपत सिंहजी ने कुछ शंका व्यक्त की। मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट भाषण में कहा था कि जो बीमार हो गया और उसका कार्ड नहीं है तो कलेक्टर उसका कार्ड भी बनवायेगा और उसका इलाज भी करवायेगा। कलेक्टर्स ने इलाज भी करवाया है और कार्ड भी बनवाये हैं। ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं आयी कि मेरा इलाज नहीं हुआ। चाहे वह प्राइवेट में गया, चाहे वह सरकारी में गया। पूरा हमारे पास सिस्टम है। वह प्राइवेट में इलाज करेगा और कौनसे पैकेज का कर रहा है, वह सिस्टम हमारे पास डायरेक्ट है। उसका इलाज हुआ या नहीं हुआ, सारा सिस्टम बना रखा है। ऐसे ही हमने इस योजना को लागू कर दिया हो। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना में जो शंका व्यक्त की, वह सही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दवाइयां कितनी ही महंगी क्यों नहीं हों। कैंसर का इलाज काफी महंगा है। 5 लाख रुपये था, उसको 10 लाख रुपये किया। बड़ी बीमारी में 5 लाख, 10 लाख से कवर नहीं हो रहा था, उसको बढ़ा कर मुख्य मंत्रीजी ने 25 लाख किया। हमको आलोचना क्यों करनी चाहिए। 25 लाख का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट है, माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा जिले का प्रभारी मंत्री हूं, मैं वहां गया। हमारे सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट एक नरेगा के मजदूर का हुआ था। जिसके पास दो पैसे नहीं, कोटा जाने के पैसे नहीं बूंदी से, उसको ब्लाक सी एम एच ओ वहां ले गया। पूरा परिवार वहां था। एक पैसा खर्च नहीं हुआ और वह कह रहे थे अशोक गहलोत का भला हो कि हमारे बच्चे का जीवन बच गया। मैं खुद मिला हूं उससे जाकर। पहला आपरेशन किडनी का। यह कितना बड़ा काम है? कोई सोच सकता है कि किड़नी ट्रांसप्लांट करवा ले, लीवर का इलाज करा ले, हार्ट का इलाज करा ले, कैंसर का इलाज करा ले। आज आदमी सोच सकता है। यह अशोक गहलोत की देन है, इसको सबको मानना चाहिए।

आप कह रहे हैं कि भारत सरकार का पैसा है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों के 2,200 करोड़ से, सरकारी खजाने से करवा रहे हैं। माननीय राजवी साहब, आपकी भारत सरकार का 280 करोड़ का सहयोग है सिर्फ। इतना बड़ा काम सरकार कर रही है। किसके लिए कर रही है? आप और हम सब गरीबों के लिए। आम आदमी के लिए ही तो पैरवी करने आये हैं यहां। वही लोग तो

(श्री परसादी लाल)

हमको यहां भेजते हैं। उनका इलाज कैसे हो, उनका जीवन कैसे बचे, उनके बच्चों का इलाज कैसे हो, इसीलिए तो हम यहां आये हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लोग भी आते है, दूसरे जिलों के लोग भी आते हैं। कोटा भी जाते हैं। वहां तीन -चार आपरेशन हो गये। आम आदमी सोच सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेगा? यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए सरकार ने जो काम किया, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी की जो योजनाएं हैं, वैसी पूरे देश में नहीं है। राजस्थान पूरे देश में माडल स्टेट है। यह हमको मानना चाहिए। आप और हम सब पहले राजस्थानी हैं इसलिए राजस्थानियों को गर्व होना चाहिए। पैसा भी हम दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? पूरे प्रदेश के 90 परसेंट परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके हैं। माननीय राठौड़ साहब, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मेडिकल एण्ड हेल्थ में खर्च कर रहा है तो वह राजस्थान है। 7 परसेंट बजट हम खर्च कर रहे हैं। कहीं भी नहीं है पूरे देश में। कोई स्टेट नहीं कर रहा है। आप और हम सब मिल कर, चाहे आप विपक्ष में हैं और हम इधर हैं, पर उद्देश्य हम सब का एक है कि लोगों का इलाज कैसे हो, जीवन कैसे बचे, लोगों की सहायता कैसे करें। इसीलिए ही तो हम सब यहां आ रहे हैं, इसलिए ही तो जनता हमको चुन कर भेजती है।

जो भी कोई कमी-खामी है, आपने सुझाव दिये, निश्चित रूप से हम उसको दूर करेंगे। पैकेज में कोई कमी है, प्राइवेट हास्पिटल वालों की कभी-कभी शिकायत आयी है, उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है। उनको सस्पैण्ड किया है हमने। उनको उस पैकेज से बाहर निकाल दिया। कई हास्पिटल्स को सस्पैण्ड किया है। क्यों नहीं करेंगे? आपका सुझाव सही है। जिनको हमने फ्री में लैण्ड दी है, वह इलाज नहीं कर रहे हैं। उनकी हम जांच करवा रहे हैं कि वह इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वह पैकेज पर इलाज कर रहे हैं? आपका सुझाव सही है, इसको मानने में हमको कोई एतराज नहीं है, सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, जो भी हमने काम किये, चिंरजीवी योजना है, दूसरी है, हमने प्रदेश में काफी काम किये, मुख्य मंत्रीजी ने इतने काम किये। आप भी सरकार में पांच साल रहे हैं, आपने सब-सेंटर कितने खोले पांच साल में? आपने 7 खोले हैं, आपने पांच साल में सिर्फ 7 खोले हैं। हमने सब-सेंटर खोले हैं 1002, और 50 की अभी और घोषणा कर दी। हो सकता है हमारे जादूगर मुख्य मंत्री और बढ़ा दें, 50 से भी ज्यादा। हम कहीं कंजूसी नहीं कर रहे हैं। लोगों को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में सुविधा दे रहे हैं।

(श्री परसादी लाल)

राठौड़ साहब, आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है, जहां हमने सब-सेंटर सैंक्शन नहीं किये हों। सब जगह किये हैं हमने, बिना भेदभाव के किये हैं। बिना कोई राजनीति के सैंक्शन किये हैं। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को किया है। अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में हो, कोई ग्राम पंचायत सब-सेंटर से वंचित रह गयी हो तो आप सूचना दे दो, वहां भी खोल देंगे। यह मुख्य मंत्रीजी का आदेश है। पहले हर ग्राम पंचायत कवर हो, जो पंचायत रह गयी, हमने कोशिश की है सभी की सूचियां मंगाने की, क्योंकि हमने कोशिश की है। इसके साथ ही इनकी बिल्डिंग भी मंजूर कर दी जो ये 1002 सब सेंटर खोले हैं। इनकी बिल्डिंग के पैसे की भी मंजूरी कर दी। जमीन हो जायेगी उस दिन पैसा भी दे देंगे और इनका हमने स्टाफ भी मंजूर कर दिया, उसकी भी सैंक्शन कर दी। जो काम करेंगे, जिसको करना है, वह पूरा करना है। 1002 सब-सेंटर और आपके समय सिर्फ 7 सब-सेंटर और फिर भी आप कहते हैं हम आ जायेंगे। आप कैसे आ जाओगे? काम तो करो। आते हो तो काम किया करो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम आयेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आ जाना। पर आते हो तो काम किया करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उप स्वास्थ्य केन्द्र का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनके समय में पांच साल में केवल 38 सब-सेंटर्स को इन्होंने PHC बनाया। पांच साल में सिर्फ 38 को बनाया और हमने 365 तो बना दिये और 233 और घोषित कर दी। अब कहां मुकाबला है? राठौड़ साहब तो बहुत प्रभावी मिनिस्टर रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे ज्यादा हेल्थ मिनिस्टर का दायित्व संभाला तो राठौड़ साहब ने संभाला है, ये ज्यादा समझते हैं। हमने इतनी PHC खोली, क्यों खोली? इसलिये कि सब

(श्री परसादी लाल)

जगह दवाइयां मिले, सब जगह उनकी जांच हो, सब जगह सिस्टम सुधरे, इसलिये ही तो हमने CHC, PHC खोली हैं। आपने CHC कितनी खोली पांच साल में? मात्र 45 और हमने 2023 तक 211 CHC खोल दीं। इसके साथ ही 88 CHC और खोलने जा रहे हैं। हो सकता है मुख्य मंत्रीजी एप्रोप्रियेशन बिल पर और बढ़ा दें। माननीय सभापति महोदय, हम जब तक पूरे ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, हमारा ग्रामीण ढांचा मजबूत होगा और गांवों में दवाइयां पहुंचेंगी, वहां स्टाफ रहेगा तो निश्चित रूप से लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आपने उप जिला चिकित्सालय पांच साल में एक भी नहीं खोला। हमने 41 तो खोल दिये और 19 इस साल खोल रहे हैं। आपने जिला अस्पताल एक भी नहीं खोला था। हमने 21 खोल दिये और इस साल 5 और खोल रहे हैं। आपका और हमारा काम करने में कहां मुकाबला है? जनता जो चाहे करे, हम काम की बात कर रहे हैं। हमने लोगों के लिये क्या किया और आपने क्या किया, इसका तो जनता फैसला करती है कि हमने कितना किया और आपने पांच साल में कितना किया। मैं तो आपको यह बता रहा हूं जो काम किया है। हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है। तभी तो इतनी बड़ी स्कीम फ्री, दवाइयां फ्री, जांच फ्री सब हो गया और वहां हास्पिटल ही नहीं है, वहां संसाधन ही नहीं है तो कौन करेगा? हमने बाड़मेर में सबसे ज्यादा सब-सेंटर खोले हैं। एक भी पंचायत वहां ऐसी नहीं है, जहां पर सब-सेंटर नहीं हो। हमने सब जगह खोल दिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को फिर कह रहा हूं कोई ग्राम पंचायत मुख्यालय शेष रह गया हो, चाहे किसी का भी हो, वह हमको सूचना दे दें, हम वहां पर तुरंत खोल देंगे। उसकी बिल्डिंग का पैसा भी हम दे देंगे। किसी के भी रह गया हो, हम तो आपको मौका दे रहे हैं। सबको दे रहे हैं। मैं तो सभी से अपील कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पांच साल में एक सैटेलाइट अस्पताल खोला और हमने 8 सैटेलाइट अस्पताल खोल दिये। हमने सतीश पूनियां जी के कहने से भी खोल दिया। हमारे मुख्य मंत्री इतने उदारवादी हैं कि सतीश पूनियां जी ने चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी से ही खोल दिया। शय्याओं की वृद्धि में, आपने पांच साल में 875 बेड्स बढ़ाये थे और हमने 6,705 बेड

(श्री परसादी लाल)

बढ़ाये हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की जनता के लिये जो स्कीम शुरू की, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही हो, जब हमारे पास सिस्टम नहीं होगा तो कैसे होगा? हर आदमी शहर में नहीं आ सकता है। अगर गांव में हर पंचायत पर हमारा सब-सेंटर होगा और सब-सेंटर पर हमारी 50 दवाइयां रहेंगी, 10 तरह की जांच होगी तो छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज वहीं सब-सेंटर पर हो जायेगा। इसलिये जो भी हमने यह ढांचा बनाया है वह निश्चित रूप से मेडिकल कालेज हो, नर्सिंग कालेज हो, कितना अच्छा काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग, मेडिकल कालेज सीकर, चूरू, झुंझुनूं के कैसे आ गये? वहां के लोग एडवांस हैं। सबसे ज्यादा 80 प्रतिशत नर्सिंगकर्मी हमारे वहां के मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उनके-हमारे पहले से ही प्रेम है दोनों में। न वह कभी बुरा मानते, न मैं उनकी बात का कभी बुरा मानता हूं। जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं और इसमें अभी आपने देखा होगा, मैंने कहा था मैं मंत्री रहूं या न रहूं पर डेपुटेशन नहीं करूंगा, नहीं किया। सरप्लस नहीं रहने दूंगा, नहीं किया। अभी 1,763 डाक्टरों की पोस्टिंग की है उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। राजस्थान में 800 PHC ऐसी थीं जहां एक भी डाक्टर नहीं था। हमने सबसे पहले 800 PHC को भरा। हमने जहां CHC पर डाक्टर नहीं थे, वहां पर लगाये। दो-तीन CHC हमारी छूट गयी। वहां पर कुछ लोग APO हो गये पर हम वहां पर भी लगा देंगे। जब डाक्टर नहीं होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा तो हम कैसे वहां पर दवाइयों का वितरण कर लोगों की मदद करेंगे? इसलिए हमने जो ढांचा बनाया है, कोई कांस्टीट्यूएंसी के भी डाक्टर सलेक्ट हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, पर एक की भी सिफारिश नहीं की। मैंने कहा कि आपका जो राज पोर्टल एप है, उससे काउंसलिंग करके लगाओ सबको। मैंने एक भी डाक्टर की सिफारिश नहीं की। मैंने हेल्थ मिनिस्टर होते हुए किसी की सिफारिश नहीं की। काउंसलिंग से सबको लगाया। जहां पर एक भी डाक्टर नहीं था, वहां पर पहले लगे। 800 PHC ऐसी थीं जहां पर एक भी डाक्टर नहीं था। हमारे सब डाक्टर जायेंगे और दो साल पहले किसी का भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। जिसको नौकरी करना होगा, वह जायेगा, नहीं तो हम दूसरा बैच और तैयार कर रहे हैं।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सभापति महोदय, आज कई चीजें हैं। ये दुर्घटनाएं होती हैं, सिरोही की घटना है, जोधपुर की घटना है, कई जगह घटनाएं हुईं। पहले जोधपुर में हुआ। इनको रोकने के लिये भी हम प्रभावी कदम उठायेंगे। यह घटना हुई है, यह हम सबके लिये बहुत चिन्ताजनक है। सिरोही की घटना हो, चाहे जोधपुर की हो, हम पाबंद कर रहे हैं CMHO और ब्लाक CMHO को, अगर रात के 12.00 बजे भी मरीज आयेगा तो उसको वहां पर डाक्टर मिलेगा। अगर डाक्टर नहीं मिलेगा तो ब्लाक CMHO को रवाना कर देंगे, CMHO को रवाना कर देंगे। इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, पांच-छह डॉक्टर हैं, इन डॉक्टरों को सरकार तनख्वाह देती है, हाउस रेंट देती है तो फिर वहां पर क्यों नहीं रहते? हम हैडक्वार्टर पर पाबंद करेंगे। हम 01 अप्रैल के बाद पाबंद कर देंगे CHC, PHC पर रात को 12.00 बजे भी कोई पेशेंट जायेगा और अगर डाक्टर नहीं मिला तो CMHO और ब्लाक CMHO की छुट्टी होगी। किसी की शिकायत आने पर हो जायेगी। या तो अपना रवैया ठीक कर लें और डाक्टर वहां पर रहें, डाक्टर वहां पर काम करें। यह बहुत बड़ा काम है। माननीय सदस्यों की ये शिकायतें सही हैं। मैं भी सदस्य था तब इस तरह की शिकायतें थीं। डाक्टर्स का डेपुटेशन था, उस कचरे को हमने साफ किया। लोग हाई कोर्ट भी गये। सिंगल बेंच में वे जीत गये तो हम डी.बी. में जोधपुर गये। डी.बी. जोधपुर ने कहा कि सरकार का फैसला सही है। सरप्लस और डेपुटेशन निरस्त किया। हाई कोर्ट ने जनता के हित में ही कहा, इसलिये उसके बाद कोई हाई कोर्ट नहीं गया।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि बहुत सारे डाक्टर्स पी.जी. करने चले जाते हैं, उनको रोक नहीं सकते। मैं यही कहूंगा अभी किसी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि वहां पर पोस्ट वैकेंट बोलती है, अब पोस्ट वैकेंट नहीं बोलेगी, उनका अलग से बना दिया। वहां तुरंत दूसरे डाक्टर लगा रहे हैं। पी.जी. जाने वालों की जगह दूसरे डाक्टर लगा देते हैं। उन पी.जी. वालों का वेतन एक पूल बना रखा है, माननीय सभापति महोदय, वहां से देते हैं हम। माननीय सभापति महोदय, ऐसी जो बातें आयीं, ऐसी जो शिकायतें आयीं, उनका हम निराकरण करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके जो सुझाव आयें, जिस तरह की कोविड की बात हुई, और भी कई तरह की दूसरी बातें हुईं।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान के लोगों के लिये वरदान है। कितना बड़ा, अब कह रहे हैं 25 लाख क्यों कर दिये, कैसे लाभ मिलेगा? प्रीमियम हम दे रहे हैं। सरकार के खजाने से प्रीमियम दे रहे हैं। अगर किसी को 10 लाख का, 20 लाख का होगा तो क्या वह बार-बार घूमेगा? एक साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि जिसका खर्चा हो, 25 लाख तक का सबका बीमा करेंगे। बीमा का 10 लाख तक का देंगे, बाकी पैसा सरकार अपने खजाने से देगी। अब खर्च हो या न हो, जरूरी नहीं है कि सबका ही खर्च हो। जरूरी है कि सारा ही हो, पर हम प्रीमियम सबका करायेंगे। इसलिए जो भी योजनाएं हैं, कोविड में, माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा काम किया और प्रधान मंत्रीजी ने तारीफ की।

दूसरी जो चीजें हैं। मैंने आपको कहा जो बालक अनाथ हो गये, उनका मुख्य मंत्री ने कितना सम्मान किया? उनको मुख्य मंत्री निवास पर बुलाया, मुख्य मंत्री ने उनके साथ भोजन किया। सारी कैबिनेट ने भोजन किया। उनको यह आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार आपके साथ है। मां-बाप नहीं हैं तो राजस्थान सरकार आपकी हर समय मदद करेगी। इतना बड़ा पैकेज देश में किसी मुख्य मंत्री ने नहीं दिया। 2,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये वे 18 साल के हो जायेंगे, तब मिलेंगे। जो जिस काबिल होगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। यह देश में कहीं नहीं है। यह राजस्थान सरकार का फैसला है, माननीय मुख्य मंत्री जी का फैसला है। उन बच्चों को संबल देने के लिये, उनका नया जीवन शुरू करने के लिये। यह कितना बड़ा फैसला है?

कोविड में सबने मिलकर काम किया, मैं कब कहता हूं कि नहीं किया? भारत सरकार ने भी सहयोग दिया, हमने भी काम किया, आप सबने भी सहयोग दिया। यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, 1 अप्रैल, 2021 से अब तक 3,566 करोड़ रुपये की राशि व्यय करके 34 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों का चिरंजीवी योजना में इलाज हुआ है। जितने भी लोग आते हैं, उन सबकी फ्री जांच की जाती है। चाहे कैंसर की जांच महंगी है, बच्चों की कोई एक जांच 40 हजार की है, उसको भी हम फ्री करा रहे हैं। कैंसर की जांच को फ्री करा रहे हैं। कैंसर का एक इंजेक्शन डेढ़ लाख का था। वह भी फ्री करा रहे हैं।

(श्री परसादी लाल)

हमने किसी तरह की शिकायत, अगर दवाइयां नहीं हैं तो मुख्य मंत्री महोदय ने सारे मेडिकल कालेज को, डी एच को, एस डी एच को, सी एच सी को, पी एच सी को, सबको एडवांस पैसा दे दिया। यह नहीं कहें कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं, यह नहीं कहें कि जांच अंदर से नहीं हो रही तो बाहर से कराओ। 15 लाख दिये, सब दिये, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दिया। जब खर्च हो जाये तो वापस ले लो सरकार से। ऐसी कहीं व्यवस्था है किसी सरकार में? किसी प्रदेश में हो तो बता दें।

सभापति महोदय, कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है, किसी जांच को बाहर कराने की आवश्यकता नहीं है। हम तो यह भी कहते हैं कि दवाइयां नहीं हैं, जन औषधि केन्द्र हैं, उनसे भी खरीद की अनुमति दे रखी है। जन औषधि केन्द्रों के लिए भी कह दिया कि वहां से दवाइयां खरीदकर दो। यह बहुत बड़ा जो काम हुआ। बहुत बड़ेबड़े काम, इसमें कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका भी इलाज फ्री है। आपको शंका नहीं करनी चाहिए कि इलाज फ्री नहीं होगा। सारा इलाज फ्री है। उसका पैसा 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा होगा, 25 लाख तक का जो दिया है, वह मुख्य मंत्री जी ने सोच-समझकर दिया है।

सभापति महोदय, किसी की बीमारी में 25 लाख भी लगे, उसका बाहर भी इलाज कराना पड़े, अब तो यह भी सुविधा दे दी कि अगर राजस्थान में नहीं है, बाम्बे इलाज कराना पड़े, दिल्ली कराना पड़े, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुमति दे दी है। इतना बड़ा काम किया है। इलाज कहीं हो देश में पर प्रदेश के लोगों की जान बचनी चाहिए। इसलिए इतने बड़े काम की हम सबको तारीफ करनी चाहिए। अगर इसमें कोई कमियां हैं, आप सब बतायेंगे तो हम उसको दूर करेंगे।

सभापति महोदय, 'शुद्ध के लिये युद्ध' की बात आयी। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कितना जुर्माना हुआ, क्या सज़ाएं दीं? सब सजाएं हैं। आपको पता है कि इसमें मिलावट के खिलाफ सूचना देने वाले को भी 51 हजार रुपये दे रहे हैं। 51 हजार रुपये दिये हैं। कितने लोगों को हमने दे दिये, हमने कितने लोगों को सज़ा करा दी, बताऊं आपको पूरा? 2018 से पहले 6-7 हजार से ज्यादा नमूने नहीं लिये जाते थे, हमने 14 हजार नमूने लिये। उसमें से 3,770 नमूने अनसेफ पाये गये। इस अवधि में 3,800 प्रकरणों के चालान संबंधित न्यायालय में दिये गये। संबंधित न्यायालयों द्वारा

(श्री परसादी लाल)

2,165 प्रकरणों में निर्णय कर 8,47,91,600 रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया। इसलिए आपको बुलाया था। बोलकर चले जाते हैं, कभी सुनते नहीं हैं।

सभापति महोदय, हमारे पहले कोविड की जांच का सिस्टम ही नहीं था, सब जांच पुणे या दिल्ली भेजते थे। 10 दिन में आती थी। हमने पूरी लैबोरेट्री लगा दी। जीनोम की भी लगा दी हमने। फूड सेफ्टी की पूरे देश में 53 हैं, हमारे यहां 11 लैब कार्यरत हैं और 7 लैब अभी प्रक्रियाधीन हैं। हम ऐसा सिस्टम और कर रहे हैं, पूरे जिलों में हम करने जा रहे हैं कि मोबाइल लैब होगी, वहीं सैंपल लिया, हाथों-हाथ जांच और वहीं हाथों-हाथ निर्णय। हम 25 जिलों में नहीं, सारे जिलों में इन गाड़ियों की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

हम चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध चीजें मिलेंगी, शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध तेल मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध आटा मिलेगा, सब चीजें शुद्ध मिले। आज दूध में मिलावट है, सब चीजों में मिलावट है। इसके बाद निश्चित रूप से लोगों को जो सजाएं हुई हैं, लोगों पर जिस तरह का जुर्माना लगा है, उसके बाद 'शुद्ध का युद्ध' अभियान मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया, वह हमेशा है। हम इसको और मजबूत कर रहे हैं।

हम फूड सेफ्टी आफिसर भर्ती कर रहे हैं। दूसरी उनकी ट्रेनिंग भी करा दी। भारत सरकार हमको पूरा सहयोग दे रही है। सारी लैब्स लगाने का पैसा वह दे रही है। हमको क्या काम है? हमको काम करने की जरूरत है। इनके समय में एक भी नहीं लगी। भारत सरकार ने जो कंडीशन डाली, हम उन सबको मानते हैं। हमको क्या दिक्कत है? उनकी शर्तें हैं वह पूरे देश में हैं।

यहां पर मान लो जांच में अनसेफ हो गया तो उसको रेफरल लैब में जाने की छूट है। राजस्थान को तीन जगह हैं, मैसूर, बाम्बे और पुणे, वहां जांच करा लाओ। अगर कोई अनसेफ हो गया और किसी को एतराज है तो वहां जाकर जांच करा लाये। हम कहां कहते हैं? भारत सरकार का जो नोर्म्स हैं, राज्य सरकार ने उनको शत-प्रतिशत अपनाया है। हम चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध चीजें मिलें, शुद्ध खानपान हो। यह बीमारियां भी कम होंगी।

सभापति महोदय, एम्बुलेंस भी हमने खूब लगायीं। एम्बुलेंस खूब हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने जो एम्बुलेंस विधायक कोटे से दीं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। हमने 108 को ही उन्हें देने का फैसला कर दिया। 1

(श्री परसादी लाल)

अप्रैल से कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं रहेगी। हम सारी एम्बुलेंसों के लिए माननीय विधायकों के आभारी हैं कि एम्बुलेंस दी। निश्चित रूप से उन एम्बुलेंसों को भी हम चलायेंगे।

सभापति महोदय, हमने काफी भर्तियां की हैं। पिछले 4 वर्षों में 29,538 कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है, जिसमें 4,898 मेडिकल आफिसर भी हमारे हैं। हमने प्रमोशन भी किये हैं। जब जगह खाली हुई, आप देखिये कि जगह खाली होने के 15 दिन बाद हमको फाइनेंस ने अनुमति दे दी कि आप 600 डाक्टर्स और भर्ती कर लो। इसलिए हम 1,765 डाक्टर्स भर्ती कर पाये। फाइनेंस व मुख्य मंत्री जी का कहीं कोई मना नहीं है।

सभापति महोदय, जिस तरह की व्यवस्था है उसमें नई भर्तियों में भी ए एन एम, जी एन एम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, सब भर्ती कर रहे हैं। अब 2013 का नर्सिंग का मामला उठा रहे हैं। 2013 की तो बहुत पुरानी बात हो गयी। उसके बाद तो आपने भर्ती कर ली। आपके समय में कटौती हुई। उसके बाद तो कम से कम 20 हजार नर्सिंग कर्मी यहां भर्ती कर चुके। जो इस तरह के लोग लगे हुए हैं, जिनको 7-8 साल हो गये, उनको हम परमानेंट के लिए फिर मौका दे रहे हैं। उनको हमने कह दिया, भर्ती नर्सिंग की करा रहे हैं, 20 हजार की भर्ती करा रहे हैं। जिन माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि हमारे नर्सिगकर्मी नहीं हैं, यह नहीं हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2 महीने के अंदर कोई नर्सिंगकर्मी की पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगी।

अभी हमने जब डेपुटेशन खतम किया तो 3 हजार नर्सिंग कर्मी सरप्लस मिले। सरप्लस, एक-एक जगह 2-2, 3-3 मिले। सबको हमने जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सभी जगह भेजा। झालावाड़ में 100 थे, जोधपुर भेज दिया। हमने 5 जिलों से एक भी ट्रांसफर नहीं किया। 5 जिले जहां हमारी कम सर्विस थी, हमने कह दिया कि एक भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि इन्होंने मेरी सब शर्तों को माना है। किसी ने ट्रांसफर के लिए नहीं कहा कि वहां से एक ट्रांसफर कर दो। आज डेपुटेशन के लिये कोई माननीय सदस्य, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मेरे को आकर नहीं कहा कि मेरा डेपुटेशन कर दो। हमारे एक-दो सी एम एच ओ ने गलती की डेपुटेशन करने की, हमने उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया। और भी कोई करेगा सी एम एच ओ या ब्लाक सी एम एच ओ तो उनको हम तुरंत सस्पैंड कर देंगे।

(श्री परसादी लाल)

जब हमारा इतना बड़ा ढांचा है। नर्सिंग कर्मी सब सेंटर पर होगा। हमने जो हेल्थ वेल्थ सेंटर भारत सरकार ने बनाये हैं, वहां 6 हजार पोस्टिंग कर दिये हैं। अब हर सब सेंटर पर एक सी एच ओ रहेगा, एक ए एन एम रहेगी। पहले एक ही कर्मी रहता था अब दो रहेंगे तो निश्चित रूप से रोज जायेंगे। गांव में दवाइयां मिलेंगी। अब यह जो सब सेंटर्स की हैं, इनकी जल्दी ही भर्ती करके इनको भी लगा देंगे। नयी भर्तियां जो भी करेंगे, वह बहुत जल्दी ही करेंगे।

(समय: 21.00 बजे)

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि हमारी जो एन एच एम में भर्तियां हुई हैं इनमें भी 4 साल में 10 हजार भर्तियां की हैं। हम तो यह कहते हैं कि हमारे सी एम एच ओ वगैरह काम नहीं करते हैं। हम इसको सेन्ट्रलाइज करेंगे। हमको जहां भी लगेगा कि डाक्टर की पोस्ट वैकेंट है, कहां है, कहीं नहीं है, जैसे हमारे मेडिकल कालेजों में, राजमेस में, सेंटर्स में सी एम एच ओ भर्ती नहीं कर पाते, पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं। यू टी बी में लगाने में क्या दिक्कत है? हमारे मेडिकल कालेज, हमारे राजमेस में यू टी बी में लगाते हैं। कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती। कभी शिकायत ही नहीं आती। हमने इन सबको भी परमिशन दे रखी है। चाहे ए एन एम की पोस्ट हो, चाहे जी एन एम की हो, चाहे लैब टेक्निशियन की हो, जो भी हो, आप यू टी बी पर भर्ती कर लें। इसमें कहां दिक्कत है? इसलिए जो भी हम कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, भवन निर्माण के लिए भी भारत सरकार ने हमको पी आई पी में खूब पैसा दिया है। हमको सी एच सी का, पी एच सी का 2,500 करोड़ रुपये उन्होंने दिया, हमने बिना कोई भेदभाव के डी एच की, पी एच सी की बिल्डिंग बनाने का, सबकी बिल्डिंग बनाने का जब भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को, मान लो, उसमें नहीं हो तो जब भी निवेदन करते हैं, फाइनेंस को फाइल भेजते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि कभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी विधायक की कोई फाइल नहीं रोकी। सारी वित्तीय स्वीकृति वहां से आ जाती है। यह बड़ी खुशकिस्मती है, मेडिकल और हेल्थ के नाम से ही स्वीकृति आ जाती है। एक भी सी एच सी, पी एच सी, जिनकी जमीन हो गई हो, जिनकी फाइनल हो गई हो, डी एच का हो, एस डी एच का हो, जमीन का होते ही हम प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेज देंगे, इससे निश्चित रूप से हमारे सी एच सी, पी एच सी की बिल्डिंग बनेगी।

(श्री परसादी लाल)

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि वहां पर सी वी सी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है। माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मैं भी विधायक हूं, सी वी सी मशीन पी एच सी खुलती है नई, मैं 8 लाख रुपये विधायक कोटे से उसके लिए देता हूं। वहां पर सी वी सी मशीन वगैरह लगाने का जो भी खर्च है 8 लाख फिक्स है, सी वी सी मशीन के लिए। बिल्डिंग बन जाती है तो वहां पर एक्सरे मशीन लगवा देता हूं एम एल ए कोटे से। अगर वो सी एच सी है तो वहां पर सोनोग्राफी और देता हूं। सब जगह है, ऐसी कोई पी एच सी, सी एच सी नहीं है जहां पर जांच नहीं हो। माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके इलाके में जो भी सी एच सी या पी एच सी है, आप विधायक कोटे से दे दें। जनता की सेवा के लिए हम आये हैं, इस कोटे का क्या करेंगे हम? सवा दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये कर दिया। सबसे हमारा अनुरोध है कि ये जो जांच की मशीनें हैं, सी एच सी और पी एच सी लेवल पर आवश्यकता के अनुसार लगाएं।

माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर्स की जिस तरह की व्यवस्था है, हमने खूब काम इस मेडिकल में किये हैं, मैं तो यह कहूंगा कि आपके जमीन का फाइनल हो गया हो, चाहे सी एच सी का हो, पी एच सी का हो, एस डी एच का हो, डी एच का हो, हम सबके लिए बिना कोई राजनीतिक भेदभाव किए आपके बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। राज पोर्टल जो हमने एप बनाया है, माननीय सभापति महोदय, हमें आगे राज पोर्टल हमारा बता देगा कि कौन कर्मी कहां काम कर रहा है। राज पोर्टल तैयार किया है हमारे विभाग ने और उसमें एक-एक कर्मी का डेटा रहेगा, कोई भी देख सकता है कि यह आदमी यहां काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी पोस्टिंग यहां है। पहले पोस्टिंग कहां होती थी और काम कहां करता था।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर सी एम एच ओ-फर्स्ट के पांच साल से 75 डाक्टर लगे हुए थे। माननीय सदस्य विराटनगर से आने वाले मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मालूम किया तो 75 डाक्टर पांच साल से वहां क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं, हमने सबको वापस भेज दिया, उसी रात को भेजा कि सुबह जाकर जोइन करो तो ऐसी व्यवस्थाओं को हमने किया है। माननीय राठौड़ साहब ने सलाह दी थी कि हम यह काम कर नहीं सके, माननीय कटारिया साहब को हम याद करते हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था, अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र

(श्री परसादी लाल)

होंगे, अब वे महामहिम बनकर चले गए। हमने वही काम किया, हमने हमारे माननीय सदस्यों को कह दिया कि हम यह काम नहीं करेंगे, चाहे मंत्री रखो या नहीं रखो। हमने राजस्थान की जनता की सेवा के लिए यह तय किया है कि जहां उसकी ड्यूटी है, वहां पर नौकरी करे। अगर वहां नहीं करेगा तो कौन वहां पर दवाई देगा, कौन किस तरह की व्यवस्था करेगा? राज पोर्टल पर आप देख सकते हैं, कहां हमारी पोस्ट वैकेंट है और कौन आदमी कहां काम कर रहा है। सब पूरा उस पर आप डेटा इस तरह का देख सकते हैं। हमने इस तरह का डेटा उस पर विकसित किया है।

माननीय सभापति महोदय, जनता क्लिनिक की बात आती है, जनता क्लिनिक भी हमने खोले, इसमें कुछ दिक्कतें भी आई हैं। हमने उसको देखा भी है और मैं कह सकता हूं कि 75 हमने शुरू कर दिए हैं। 75 जनता क्लिनिक राजस्थान में चालू कर दिये हैं। हम बहुत जल्दी ही जितनी सैंक्शन हैं, आपका सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग आपको देनी पड़ेगी, जहां भी बिल्डिंग हो जाएगी, जहां भी व्यवस्था हो जाएगी। हमने 01 अप्रैल तक सारे राजस्थान में जनता क्लिनिक को शुरू करने की योजना बना ली है। हम चाहे कैसे भी करें, लेकिन सबको शुरू करेंगे। यह कहने का मौका नहीं मिले कि जनता क्लिनिक हमने शुरू नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, हैल्थ वैल्थ सेंटर जो बनाये हैं वहां पर भी हमने दवाइयां जिस तरह की हैं, आपको कल ही बता दिया। मातृ-शिशु संस्थाएं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कहा कि बच्चों की मौत हो रही है, पहले से बैटर स्थिति है। पूरे देश में जो ग्राफ है, उसमें राजस्थान हमारा बैटर स्थिति में है। अभी ये आंकड़े हैं, आप कहें तो बता दूं, बैटर है, बच्चों की मौत में भी कमी आई है। नेशनल आपके एवरेज है उससे राजस्थान बैटर है। महिलाओं की प्रसूति में भी राजस्थान बैटर है, इसलिए हम कहीं कम नहीं है। ठीक है, पहले कोटा में कोई घटनाएं हुई, हमने सब चीजों को करके वहां पर बहुत पैसा दिया है। जितना चाहिए उतना बच्चों के लिए दिया है।

आप देखिये आर यू एच एस में, माननीय सभापति महोदय, मैं गया था, मैं तो राठौड़ साहब को भी कहूंगा कि आप देखकर आएं। इतना बड़ा ढांचा हमारा बना हुआ है और वह काम नहीं आ रहा है। 300 आई सी यू के बेड हैं, वे वहां कोई काम नहीं आ रहे हैं। केवल वो कोविड के समय जरूर काम आए होंगे। मैंने देखा कि इतना बड़ा, बहुत सारी चीजें वहां शिफ्ट कर

(श्री परसादी लाल)

रहे हैं। हम कैंसर का वहां पर शिफ्ट कर देंगे, महिलाओं का कर देंगे, बच्चों का कर देंगे। एस एम एस हमारा बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका हो गया है, बहुत भीड़भाड़ है। आप सही कह रहे हैं, कभी-कभी तो बेड नहीं मिलता, राठौड़ साहब तो मंत्री रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा काम किया है, आई पी डी टावर, वह बनने के बाद देश में हमारा पहला आई पी डी टावर होगा, देश में कह रहा हूं मैं, जहां पर हेलिकाप्टर भी इमरजेंसी में छत पर आ सकता है। यह एक बड़ा काम है आई पी डी टावर का, तो राजस्थान में हमें गर्व है कि इतना बड़ा आई पी डी टावर हमारा दो साल में तैयार हो जाएगा। उसके बाद एस एम एस हास्पिटल का भार स्वत: ही कम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आर यू एच एस में कुछ यूनिट्स शिफ्ट कर देंगे, एस एम एस का भार स्वत: ही कम हो जाएगा। सारे बेड खाली पड़े हैं, आई सी यू बेड है, वेंटिलेटर है, क्या नहीं है वहां पर? सारा कोई काम ही नहीं आ रहा। उसको करने में कहां दिक्कत आ रही है? उसको करेंगे। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके चारों दिशाओं में बन रहे हैं। जमीन आइडेंटिफाई हो गई है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, लाहोटी साहब, वो काम होकर रहेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो निश्चित रूप से बनाएंगे हम चारों दिशाओं में चार। आर यू एच एस को भी हम बहुत गतिशील बना रहे हैं। कितना पैसा दिया, आपने बजट देखा है आर यू एच एस के लिए? जितना चाहिए, सौ करोड़ लो, दो सौ करोड़ लो, कोई बजट की कमी नहीं है, मेडिकल और हेल्थ के लिए। कभी हमको तो कहा ही नहीं, मेरे जैसे आदमी को हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद, हम तो जो फाइल भेजते हैं, चाहे बजट हो या नहीं हो, सी एच सी, पी एच सी खोल रहे हो तो खोल देते हैं, कभी ना नहीं कहते, कभी फाइल रिटर्न नहीं होती हमारी। कोई माननीय सदस्य भेजेंगे, कोई तीन पी एच सी, कोई चार पी एच सी, भेज दो, सब करते हैं वो, किसी एक भी माननीय सदस्य की फाइल लौटाई हो तो बता दें मुझे। आप भी देंगे कोई तो निश्चित रूप से उसका भी करेंगे। राजस्थान के हित में, आपका और हमारा, सबका काम है जनता की सेवा करना, आप सब और हम लोग पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिशुओं के लिए भी कितने अच्छे वार्ड बने हैं। आप देखकर आओ जेके लोन अस्पताल में कि क्या कायाकल्प हुआ है।

(श्री परसादी लाल)

क्या कायाकल्प हो गया आपके एस एम एस का, क्रिटिकल वार्ड जो बने हैं उनका तो निश्चित रूप से।

माननीय सभापति महोदय, जो काम किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए जो काम किया है, पहले 2015-16 में, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 41.3 थी, जो राष्ट्रीय औसत 40 से अधिक थी पर अब 2019-20 में राज्य की शिशु मृत्यु दर 30.3, राष्ट्रीय औसत दर 35.2, उसको ठीक नहीं किया हमने? ग्राफ को कितना नीचे लाए हैं हम। आप जो छोड़कर गए, उसको ठीक नहीं किया? इसी तरह से प्रसूति में महिलाओं की मृत्यु का देखें, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान में मेडिकल में जैसा काम हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। आप निष्पक्ष होकर उस पर मंथन करो, हम सबको करना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए वह बताओ माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जब एप्रोप्रिएशन बिल हो तो और बताएं उनको आप सारे सुझाव मानेंगे आपके, निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान स्टेट माडल बना है, यह ऐसे ही नहीं बन गया है।

माननीय सभापति महोदय, एस एम एस में कौनसे आपरेशन नहीं हुए? पूरे आपरेशन की लिस्ट है हमारे पास, आप चाहेंगे तो आपको दे देंगे हम। इतना बड़ा काम हुआ है। निश्चित रूप से सब जगह हमने काम किया है, बड़ी मशीनें भी लगाई हैं। अभी एस एम एस में हार्ट की कितनी अच्छी मशीन लगाई है, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं उसका उद्घाटन करके आये हैं। एस एम एस वाले जो मांगते हैं वो देते हैं। मेडिकल कालेज देखो, कितने खोल दिए? आपका मारवाड़ मेडिकल कालेज हो गया जोधपुर में। कहां कमी है? यूनिवर्सिटी हो गई। निश्चित रूप से आज जो काम कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित होगा। आप और हम आलोचना करें, पर आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि हमारे पूर्वज, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के लिए अच्छा काम करके गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मामले माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। हमारे मेडिकल में हमने डाक्टरों की पोस्टिंग की, वो सब जिलों में की है। एक भी जिला ऐसा नहीं है और हम तो यह कहते हैं कि आज एक भी पी एच सी ऐसी नहीं है जहां पर डाक्टर नहीं मिलेगा, हण्ड्रेड परसेंट मिलेगा। आठ सौ पी एच सी खाली थीं, सब जगह लगाए हैं। सी एच सी में लगाये हैं। डी एच में जिन्होंने एसआरशिप कर रखी थी, पी जी के जो छात्र थे, उनको हमने एस डी

(श्री परसादी लाल)

एच में लगाया है। जो एम ओ थे, उन्हें हमने पी एच सी में लगाया है, हमने उनका भी मान रखा है। जो ज्यादा योग्य हैं, उन्हें सी एच सी, एस डी एच में। हमारे डी एच में भी लगाये हैं नौ डाक्टर्स। एस डी एच में 39 लगाये हैं, सी एच सी में 772 लगाये हैं, पी एच सी में 943 लगाये हैं तो हमने बिना किसी राजनीतिक भेद-भाव के काम किया है। मुझे पता था, कल डाक्टरों की मांग उठेगी हाउस में। मैंने हमारे शासन सचिव को कहा, एनी हाउ, आज रात में ही लिस्ट जारी करें, जिससे लोगों को यह लगे कि हमारे इलाके में डाक्टर लग गये। जोइन करेंगे, स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी, दवाइयों की कोई कमी नहीं रहेगी। हम चाहते हैं, पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना है, वह माहौल हमेशा कायम रहे।

आर जी एच एस योजना की भी बात यहां उठायी गयी थी। मैं कहना चाहूंगा कि ये फाइनेंस वाले देखते हैं। हमारे मेडिकल के पास यह काम नहीं है। निश्चित रूप से जनता क्लिनिक की जो हमने कही, वह है ही। निश्चित रूप से हमारे राजसमन्द, प्रतापगढ़, जालौर, कोई सोचता था मेडिकल कालेज हो जाएंगे? यहां तो 7 परसेंट दे दें, आप कह देंगे, इसलिए आप कर रहे हैं। वहां कौन दे रहा है? पूरा स्टेट देगा एक हजार करोड़, जो भी होगा। सभापति महोदय, शुरू-शुरू में परेशानी आ सकती है, डाक्टर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी आ सकती है, इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। शुरू-शुरू में आयेगी, पर जब हमारे मेडिकल कालेज शुरू हो जाएंगे तो हम सब डाक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छा वेतन देंगे। हम वादा करते हैं, 2024-25 में एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा, जहां पर मेडिकल कालेज नहीं होगा।

इसी साल हम सारे के सारे तीस जिलों में नर्सिंग कालेज की भर्तियां शुरू करा देंगे। अभी काउंसलिंग हो रही है। इससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गयी है, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। अभी अजमेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे उदयपुर हो, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आवश्यकता के अनुसार सब जगह मेडिकल कालेज, सुपर स्पेशलिटी, सब जगह पैसा दिया है। आपने बजट देखा होगा। निश्चित रूप से, राजस्थान में मेडिकल में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है।

(श्री परसादी लाल)

आर यू एच एस के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। आर यू एच एस में इतना बड़ा हमारा सिस्टम बना हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वह काम नहीं आ रही है। भर्तियां वे खुद कर लेंगे। डाक्टर्स, नर्सिंगकर्मी, वे खुद लगा लेंगे। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी की एक-एक यूनिट की स्थापना की जायेगी आर यू एच एस में। स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, जनरल सर्जरी, मेडिसिन की तीन-तीन यूनिट्स, ई एन टी की दो यूनिट्स आर यू एच एस में बहुत जल्दी ट्रांसफर करके शुरू कर देंगे। इससे हमारे एस एम एस का भार कम होगा।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, गत वर्ष भी उन्होंने अपनी पीड़ा बतायी थी। इस बार भी उन्होंने कहा कि माडल सी एच सी किसे बनाएं, जब वहां सी एच सी ही नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो पुर है, भीलवाड़ा शहर में जो पी एच सी है, उसे सी एच सी बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे। आपकी रिकमडेशन भेज देंगे। बहुत जल्दी आपकी सी एच सी बने। आपने गत वर्ष भी बड़े दर्द से यह बात कही थी। मुझे याद है कि आपने यहां आकर भी कहा था, 01 अप्रैल से पहले हम इसे सी एच सी बना देंगे।

हमारे पड़ोस में ही बैठते हैं माननीय मंत्री जी। उनके यहां भी दो सी एच सी हैं- पायला कलां, आडिल, फागलिया हमारे चौहटन की, माननीय मुख्य मंत्री जी को इन्हें भी सी एच सी बनाने का निवेदन कर देंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो सिस्टम बना है हेल्थ का, नीरोगी राजस्थान का, जिस तरह का हमने किया है, मेडिसंस फ्री, जांच फ्री, माननीय सदस्य के कोई ध्यान में आये कि यहां पर कोई डाक्टर लापरवाही कर रहा है, यहां पर यह काम नहीं हो रहा तो हमें बताएं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं यह कहूंगा कि जो हमारा राइटटू-हेल्थ बिल है, उसमें भी माननीय नेता प्रतिपक्ष, कार्यकारी समझ लें, नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं तो आप ही हैं, हमने उसमें भी कहा, सब चीजें इनकी स्वीकार कर लेंगे। हम डाक्टरों के अलावा किसी को नहीं रखेंगे। जो सुझाव देंगे, उन सबको मानेंगे। इमरजेंसी का पैसा सरकार देगी। अगर चिरंजीवी में नहीं होगा तो सरकार पे करेगी। सभापति महोदय, यह बिल राजस्थान की जनता के हित

(श्री परसादी लाल)

में है। आज बड़े हास्पिटल गरीबों का इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी राजवी साहब सही कह रहे थे, निश्चित रूप से उन लोगों को, 12 बजे के बाद आना, अब आना, तब आना, इमरजेंसी अभी है तो अभी इलाज हो। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। राइट-टू-हेल्थ बिल आ जायेगा तो जनता को अधिकार मिल जायेगा कि इलाज करें मेरा। उसे रोकें मत। सर्वसम्मति से, जब कटारिया जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि आप इसे एक बार सलेक्ट कमेटी में दे दें। उनके कहने से दिया, काफी विचार भी हो गया। आपकी सब बातें हमने उसमें मानी हैं कि हम प्रधान, एम एल ए, सरपंच कोई नहीं रखेंगे, सारे डाक्टर्स रखेंगे। पूरा इमरजेंसी का खर्चा देंगे। फिर क्या दिक्कत है? प्राइवेट हास्पिटल्स को क्या परेशानी है? हमें तो एक होना चाहिए कम से कम। सलेक्ट कमेटी में प्राइवेट वालों को भी सुना है हमने, सरकारी को भी सुना है। जब प्राइवेट हास्पिटल हमारे चिरंजीवी में जुड़ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं जुड़ेंगे? 900 हास्पिटल हैं हमारे प्राइवेट। वे कैसे काम कर रहे हैं? किसी इक्के-दुक्के की शिकायत आये, वह बात अलग है। उन्हें क्या एतराज है?

सभापति महोदय, आज मैंने माननीय सदस्यों से कहा, मुख्य मंत्री जी, आप सब राज़ी हों, हम तो कहते हैं, डी जे को बना दें न उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का, हमें कहां एतराज है? लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को इलाज मिलना चाहिए। हम कहते हैं, प्रधान, सरपंच, प्रमुख को बनाएं। आप चाहे जिन डाक्टर्स को रख दें, प्राइवेट को रख दें, सरकारी को रख दें, हम तो खुले दिमाग के आदमी हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को हम सारे सदस्य और आप सबको मिलकर कहें, चाहे डी जे को बना दें आप, कलेक्टर को चाहे मत बनाएं, पर यह राइट-टू-हेल्थ बिल पास होना चाहिए। राजस्थान की जनता के हित में है यह।

माननीय राठौड़ साहब, अगर यह पास नहीं होगा तो इसका दोषारोपण आपके ऊपर आयेगा। आप काफी लम्बे समय तक हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आप सब चीजों को समझते हैं। हमसे ज्यादा समझते हैं आप कि जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। राइट-टू-हेल्थ बिल में अगर उसे राइट मिल जायेगा तो निश्चित रूप से कोई डाक्टर मना नहीं करेगा। इमरजेंसी क्या है? मान लें इमरजेंसी में वह हास्पिटल गया और उसकी मौत हो गयी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, गया न उसका जीवन। अगर वह

(श्री परसादी लाल)

हास्पिटल इलाज कर देता तो उसका क्या बिगड़ जाता? उसका पेमेंट सरकार देगी, आपको हम कह चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। कटारिया जी को कर चुके, सब मैम्बर्स को कर चुके।

सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा, सारे लोग मिलें, हाउस में चर्चा हो जाये, हम खुले दिमाग से चर्चा करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कह दिया, राइट-टू-हेल्थ बिल जनता के हित में है, यह आना चाहिए। आप जो कहें, वह शर्त मानने के लिए तैयार हैं। यह बिल आयेगा तो राजस्थान की जनता का भला होगा, इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है। राठौड़ साहब, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बार-बार मेरा नाम लेकर इंगित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं, सलेक्ट कमेटी में बिल आयेगा, निश्चित तौर पर यदि बिल सही होगा तो हम मदद करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, पर आप बिल के अन्दर डेफिनेशन ही डिफाइन करके न लाएं, इमरजेंसी इलाज क्या है, उसे भी डिफाइन न करें और इस तरह की बात करके...। आज खुद का हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी आपको, कि आपने अब तक जितनी बातें कहीं, यथार्थ के साथ कहीं। आपने उन गलतियों पर भी बात की, उन बातों पर पीड़ा भी व्यक्त की, चाहे जोधपुर में ब्लड बैंक की हो, चाहे बच्चे की हो, पर अगर हम उन सब स्टेकहोल्डर्स को भी साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा।

आज आप राइट-टू-हेल्थ दे रहे हैं, कल राइट-टू-फूड की बात भी आयेगी। राइट-टू-हेल्थ दें तो कम से कम इन्फ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का बनना चाहिए और जिस प्रकार स्टेकहोल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहिए, उसे आप लेकर बात करें। हम कब आपका विरोध कर रहे हैं? आएं, सब मिलकर बात करेंगे, परन्तु आज आप एक ऐसा बिल लेकर आ जाएं, मैं सदन में कहना चाहता हूं, अब तक आपने जो ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया, उस पर तो हमें एतराज है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, उसमें स्टेकहोल्डर्स को आपने कान्फिडेंस में नहीं लिया। उन्हें लेंगे तो हम भी आपका साथ देंगे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहूंगा, हमने उस कमेटी में खुले दिमाग से आपकी सब बातें मानीं। आप और जो भी कहेंगे, सब मानेंगे। अब तो आप

(श्री परसादी लाल)

ही कर्ता-धर्ता हैं इस पूरे दल के। अब तो आपके पास चाबी है। जनता के हित में आप जो सुझाव देंगे, हम उन्हें मानेंगे। हम अध्यक्ष महोदय से कह देते हैं सलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए। आप जब कहेंगे, हम तैयार हैं। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के लिए मुख्य मंत्री जी का विजन है, लोगों को इतनी सुविधाएं हम दे रहे हैं, अगर उसे अधिकार नहीं मिला, यह मुख्य मंत्री जी का सपना है, निश्चित रूप से जनता यह कहेगी, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अधिकार मिलने के बाद लोग पूछने लग जाएंगे। उसका इलाज करना ही करना पड़ेगा। इमरजेंसी का पैसा हम देने की बात कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है किसी को? आपने कहा, प्रधान, प्रमुख नहीं रहेंगे, हमने मान लिया। इमरजेंसी के लिए डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन का हमने मान लिया। कौन-सी चीज हमने आपकी नहीं मानी? सारी बातें मानेंगे। आप स्पीकर महोदय से कहें, वे सलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाएं। हम नहीं कहते, किसी जिला प्रमुख, प्रधान को, पोलिटिकल लोगों को रखेंगे, एम एल ए को भी मत रखें। जैसा ट्रांसपेरेंसी हो और जैसा प्रदेश के हित में हो, वैसा यह कानून बनना चाहिए। मुख्य मंत्री जी का विजन है, वह देश, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं और हम सबको उनको सहयोग देना चाहिए। कमियां होंगी तो निश्चित रूप से आप सारे मैम्बर्स के सामने आना तो चाहिए। अब कब मना करते हैं? आप हमसे सीनियर हो, आप हमसे लम्बे समय तक हेल्थ मिनिस्टर रहे हो और जो जनता के हित में हो वह आप कह दो, हम मानने को तैयार हैं। कहां मना कर रहे हैं?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अब तो सभी चीज क्लियर कर दी।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह परम्परा नहीं रही है। अपने सलेक्ट कमेटी की बातों को यहां हम सदन में जब तक रिपोर्ट नहीं आये, तब तक बात करने की परम्परा नहीं है। मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम राइट-टू-हेल्थ के विरोध में नहीं हैं पर राइट-टू-हेल्थ बिल का अधिकार आप दे रहे हो, वह सही परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। जनता को अधिकार देकर हम ऐसा झुनझुना नहीं पकड़ा दें कि जो प्राइवेट स्टेकहोल्डर हैं, जो हास्पिटल आ रहे हैं, यहां पर मेडिकल टूरिस्ट का हब बन रहा है तो कल को आपके यहां से लोग भाग नहीं जाएं। आज सुपर स्पेशियलिटी के लोग जयपुर में आकर इन्वेस्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करके अपने हास्पिटल कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में प्राइवेट हास्पिटल हमारे चिकित्सालयों का भार बांट रहे हैं, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। सहयोगी करके एक साथ चलाएंगे तो सब चलेंगे, पर आप लादो इसको, इस बात तक ही विरोध है। बाकी राइट-टू-हेल्थ के मैं और मेरा दल कोई विरोध में नहीं है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय कटारिया जी के सुझाव पर सलेक्ट कमेटी बनी है और अब उनका काम आप देख रहे हैं। आप स्पीकर महोदय को कहें, सलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए उनको निवेदन करें, हम तैयार हैं। हमें कहां दिक्कत है? अभी बहुत टाइम है। आप जब कहो तब मीटिंग कर लेंगे, सारी बातें मान लेंगे। कहां दिक्कत है हमको? प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है और आप और हम सब जनता के लिए आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सदन की जरूरत नहीं है, इसी हाउस में हो जाएगा। सलेक्ट कमेटी की मीटिंग के लिए आप कहोगे तब अध्यक्ष महोदय बुला लेंगे, जब भी कहोगे तब। इसलिए यह बिल यदि पास नहीं हुआ तो आपको और हमको जनता माफ नहीं करेगी। होना चाहिए, जनता के मन में है कि हमको अधिकार मिल रहा है उसमें कैसे रुक गये आप? लोग कहते हैं कि बहुत प्रचार प्रसार हो गया, डाक्टरों के कहने से कैसे बिल को रोक दिया? लोग हमको कोसते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी तो यही विनती है, सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष से।

जो भी आपके सुझाव आये। लाहोटी साहब ने एस एम एस की मशीन की एक-दो बात उठायी थी। वह आपकी बात कुछ हद तक सही है, मैं उसकी जांच कराऊंगा। निश्चित रूप से उसमें जहां गड़बड़ी है, वारंटी एक साल की नहीं, एक साल लगने में लग जाते हैं। हम उसको सही करेंगे और मशीन लगेगी, वारंटी रहनी चाहिए। यह पी पी पी मोड पर क्यों दिया, कैसे दिया, उसकी भी जांच करायेंगे। आपका अच्छा सुझाव था और मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। उसको हम दिखवायेंगे तथा जनता के हित में जो भी होगा, वह हम करेंगे। अच्छे सुझाव मानने के लिए हम कोई वह नहीं हैं। आप अच्छे सुझाव दें, हमारे कई लोग बड़े ज्ञानी हैं, उनके सुझाव को सरकार मानेगी और आप सबने जो सुझाव दिये हैं, सभापति महोदय, उन सबका मैं स्वागत करता

(श्री परसादी लाल)

हूं। जो भी हमारी, गर्ग साहब का काम था, वह भी हम कर देंगे। निश्चित रूप से कर देंगे, आपको कह तो दिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि डिमांड 27 और 28 को पारित किया जाए।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो भीलवाड़ा विधायक जी ने बात बतायी, मंत्री जी, सी एच सी की आज ही घोषणा कर दो।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये तो सही। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप विराजिये।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घोषणा कर दी है, वह आपकी सी एच सी बन जायेगी।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये आप। मंत्री महोदय, आपने भी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लेकर काफी आग्रह किया। यह जो राइट-टू-हेल्थ बिल है, यह पूरे प्रदेश के हित की बात है। मैं जहां तक समझता हूं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई भी आदमी, इस प्रदेश की जो जनता है, उसके अहित की ही बात नहीं सोचेगा। इससे पहले कि सलेक्ट कमेटी हो, मेरी अपनी ओपिनियन है, इससे पहले कि आप सलेक्ट कमेटी इनवाइट करें, व्यक्तिगत रूप से आप और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और इनके साथ जो भी सहयोगी जुड़ना चाहें, आप एक बार कंसेंसस बनायें। जब तक आपसी सहमति नहीं होगी, तब तक सलेक्ट कमेटी में भी इस तरह के मतभेद उभरेंगे। इससे पहले कि सलेक्ट कमेटी हो, आप व्यक्तिगत रूप से एक बार बैठकर इसमें चर्चा करें कि जो भी प्राइवेट हास्पिटल्स हैं, उनकी अपनी क्या प्रोब्लम्स हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। यह तो है नहीं कि आप नहीं समझ रहे, ये समझ रहे हैं। समाधान आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। सलेक्ट कमेटी से पहले आप अपनी कंसेंसस बनायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, कंसेंसस बनना चाहिए। राइट-टू-हेल्थ आये, इस पर किसी को एतराज नहीं, पर सही परिप्रेक्ष्य में हो। हम एक ऐसे सेक्शन को, जो आज सरकारी हास्पिटलों का भार बांट रहा है, उनको विरोध में लाकर ऐसा काम नहीं करें। हम उनकी भी सुनें। आप लाओ न। मैं खुद कहूंगा कि सलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलायें। मैं खुद कहूंगा। हम विरोध में नहीं हैं। आप यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वातावरण नहीं बनायें कि हम विरोध में हैं, पर आज स्टेकहोल्डर को आप अनोय करके और उनको बिना सुने इस प्रकार का कानून बनाओ तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी भावनाओं का आदर किया और स्टेकहोल्डर को तंग करने की कोई बात नहीं लिखी। सलेक्ट कमेटी में बिल को भेजने का उद्देश्य यही था कि स्टेकहोल्डर इस बात को महसूस नहीं करें कि उन पर कानून थोप रहे हैं। आपकी भी भावना यही थी, लेकिन सलेक्ट कमेटी इन्वाइट हो, उससे पहले एक बार कंसेंसस तो बने, आपसी सहमति तो बने।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने वाकई राइट-टू-हेल्थ के खिलाफ माहौल बनाया है। यह गलत कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम इसके पक्ष में हैं। आप आज सदन में दिखावे के लिए कह रहे हैं। आपने हमेशा इसका विरोध किया है। आपके दल ने हमेशा विरोध किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, शायद आप मेरा स्वभाव नहीं जानते। मैं उन बुजदिलों में नहीं हूं। इस वक्त जो राइट-टू-हेल्थ बिल आया है, उसके मैं विरोध में हूं। जब तक आप उसकी कमियां दूर नहीं करोगे, मैं विरोध में रहूंगा। आप किसको डरा रहे हो?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपका स्वभाव मेरे से बेहतर कौन जानता है?

श्री सभापति: मैं आप दोनों के स्वभाव से परिचित हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराजिये आप। मैं आप दोनों के स्वभाव से परिचित हूं। आप कुछ कहना चाहते थे? फरमायें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे भीलवाड़ा के विधायक जी ने जो पिछली बार भी कहा और मैंने भी निवेदन किया था, मुख्य मंत्री जी को भी कहा, उसकी घोषणा कर ही दो। बहुत ज्यादा जिनाइन है। उसकी बिल्डिंग हम डी एम एफ टी या सी एस आर में बनवा देंगे, गवर्नमेंट का एक पैसा ही नहीं लगने देंगे, सी एस आर में बनवा देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है? प्लीज, शांति रखें। माननीय सदस्य, ऐसा तो कभी नहीं देखा।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,74,40,00,000/- (एक सौ एक अरब चौहत्तर करोड़ चालीस लाख) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 28 चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,07,40,89,000/- (उनचास अरब सात करोड़ चालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.27 बजे सोमवार, 13 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर शहर को विमान सेवा से जोड़ने की कार्ययोजना

281. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नागौर शहर को विमान सेवा से जोड़ने हेतु माह नवम्बर, 2016 में कोई योजना बनाकर विमान कंपनियों द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अन्तर्गत आवेदन मांगे गये थे, यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु 90.36 बीघा जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिह्नित कर 361.44 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार हवाई पट्टी का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नागौर शहर को विमान सेवा से जोड़ने हेतु नवम्बर, 2016 में कोई योजना नहीं बनाई गयी थी

विधान सभा क्षेत्र नागौर हेतु विमान कम्पनियों से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अन्तर्गत कोई आवेदन नहीं मांगे गये हैं।

(2) नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु राशि 361.44 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.08.2017 एवं 04.10.2017 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी प्रति संलग्न है। विस्तार की कार्यवाही, भूमि अधिग्रहण के उपरान्त ही की जा सकेगी। कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, नागौर से प्राप्त सूचना संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हरसानी (बाड़मेर) में उप तहसील खोलने की योजना

226. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सीमावर्ती जिला बाड़मेर की तहसील शिव में भीयाड व गडरारोड तहसील में हरसानी को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बजट सत्र 2023-24 के दौरान प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण के बिन्दु संख्या 148 (V) द्वारा हरसानी (बाड़मेर) में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। उक्त की अनुपालना में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बालाहेडी (महवा) में उप तहसील खोलने की योजना

227. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत बालाहेडी में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट सत्र 2023-24 के दौरान प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सामान्य वाद-विवाद पर की गयी घोषणाओं के बिन्दु संख्या 68 (V) द्वारा बालाहेड़ी (दौसा) में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। उक्त की अनुपालना में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

डग में पटवारियों के रिक्त पद

228. श्री कालूराम (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कितने पटवार हल्के हैं तथा उक्त में पटवारी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूराम)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवार मण्डल के भवन बने हुए हैं व कितनों के भवन नहीं हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में 89 पटवार हल्के हैं तथा पटवारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
पटवारी	100	27

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में 36 पटवार मण्डल में भवन बने हुए हैं तथा 53 पटवार मण्डल में भवन नही हैं।

डूंगरपुर में नवीन राजस्व गांव

229. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला डूंगरपुर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक कितने नवीन राजस्व गांवों का सृजन किया गया तथा कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला डूंगरपुर में नवीन राजस्व ग्रामों की वर्षवार सूची निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	अधिसूचना दिनांक	कुल नवीन ग्रामों की संख्या
1	2018	04.01.2018	04
2		21.03.2018	01
3		12.09.2018	05
4	2019	14.08.2019	01
5	2020	-	00
6	2021	-	00
7	2022	05.12.2022	09
8		30.12.2022	02
योग			**22**

(राजस्व मंत्री)

उक्त तालिकानुसार अधिसूचनाओं की छायाप्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। वर्तमान में जिला डूंगरपुर के कोई भी नवीन राजस्व ग्राम सृजन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

प्रतिहारियों को देय वेतन

230. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कार्यरत पटवारियों के साथ कार्य करने वाले प्रतिहारियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को लगाने की व्यवस्था कब से की गई है? उक्त को कितना वेतन दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त को संविदा सेवा नियम, 2022 में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त का वेतन अंतिम बार कब बढ़ाया गया? क्या सरकार प्रतिहारियों को वेतन प्रतिमाह देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 10,909 अंशकालिक सहायक (ग्राम प्रतिहारी) पटवारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-41 में village servant की नियुक्ति तथा धारा-261 की उप धारा 2(8) में village servant से संबंधित सेवा नियम के प्रावधान थे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संशोधन संख्या 34, दिनांक 03.12.1992 से उक्त प्रावधानों एवं नियमों को विलोपित कर दिया गया है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा village servant की व्यवस्था में से ग्राम प्रतिहारी का पद अंशकालिक सहायक के रूप में राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.7(47)राज/ग्रुप-2/88, दिनांक 12.10.1988 जारी की गई।

एक वर्ष में चार माह की अधिकतम अवधि के लिए पटवार हल्कों में प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ की गिरदावरी व राजस्व वसूली के लिए अंशकालिक

(राजस्व मंत्री)

सहायक (ग्राम प्रतिहारी) का पारिश्रमिक रुपये 2000/- प्रतिमाह की दर से चार माह के लिए 8000/- रुपये समेकित दर से स्वीकृति प्रदान की गई है।

अंशकालिक सहायक (ग्राम प्रतिहारी) को संविदा सेवा नियम, 2022 में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव वतर्मान में राज्य सरकार के Active consideration में नहीं है।

(3) ग्राम प्रतिहारियों का वेतन अंतिम बार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प.11(2)राज-1/2012, दिनांक 27.06.2017 से बढाया गया है।

जी नहीं। अंशकालिक सहायकों (ग्राम प्रतिहारी) को प्रतिमाह वेतन देने संबंधी प्रस्ताव वतर्मान में राज्य सरकार के Active consideration में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

टी एस पी क्षेत्र में मार्बल खनन पट्टे

231. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्ष में जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों को कितने खनन पट्टे जारी किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में कितने मार्बल खनन पट्टे जारी किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में निजी खातेदार को स्वयं की भूमि पर मकान निर्माण हेतु पत्थरों की खनन के कितने पट्टे जारी किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों को विभिन्न खनिजों के 9 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में खनिज मार्बल के 4 खनन पट्टे जारी किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में खातेदारी भूमि में निजी खातेदारों को मकान निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज चेजा पत्थर का कोई भी खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

करौली में नन्दीशाला की स्थापना

232. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला करौली में किस-किस पंचायत समिति पर कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत से नन्दीशाला का निर्माण कर प्रारम्भ कर दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नन्दीशालाओं में कितने-कितने नन्दी हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के माडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

जिला गोपालन समिति, करौली द्वारा जिले की आठ पंचायत समितियों पर पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खोलने हेतु दिनांक 16.03.2022 को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिनमें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। जिले की आठ पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला स्थापित करने हेतु पुन: निविदा दिनांक 13.01.2023 को जारी की गई थी जिसमें पंचायत समिति, हिण्डौन सिटी में नंदीशाला खोलने हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त पंचायत समिति में श्री गोपाल गौशाला समिति, हिण्डौन सिटी में नंदीशाला की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) पंचायत समिति, हिण्डौन सिटी में श्री गोपाल गौशाला समिति हिण्डौन सिटी में नंदीशाला की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण नंदियों की संख्या शून्य है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई।

सागवाड़ा में पर्यटन विस्तार के कार्य

233. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामप्रसाद)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नीलकंठ महादेव में पर्यटन विस्तार हेतु बग़ीचे, घाट निर्माण, विश्रांति गृह, हाई मास्ट लाइट आदि के कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु विगत तीन वर्षों में कितना बजट आबंटित किया गया व आबंटित बजट से क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत बजट में गलियाकोट टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु क्या-क्या कार्य किया गया व कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आकलन कर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(2) वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 106 के अन्तर्गत डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वागड़ टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पर्यटन विकास कोष से गलियाकोट स्थित मेहरनाथ मंदिर के विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 270.00 लाख के तथा शीतला माता मंदिर के विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 299.00 लाख के विकास कार्य स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

गढ़ी में मनरेगा में कराये गये कार्य

234. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत सुजाजी का गढा, उम्बाडा, सागवाडियां, वजवना एवं मौयावासा में विगत चार वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की मनरेगा योजना में कितने कार्य स्वीकृत किये गये व कितनी राशि व्यय हुई एवं कितने कार्य हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुजाजी का गढा में खेल मैदान एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरोडिया पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति अरथुना के नवाघरा में विगत चार वर्षों में मनरेगा योजना में कितने कार्य हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत सुजाजी का गढा, उम्बाडा, सागवाडियां, वजवना एवं मौयावासा में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत चार वर्षों में स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं पूर्ण कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की ग्राम पंचायत सुजाजी का गढा के ग्राम सुजाजी का गढा में खेल मैदान व विकास कार्य स्वीकृत नहीं है। ग्राम पंचायत सुजाजी का गढा के ग्राम बरोडिया में खेल मैदान विकास कार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होकर प्रगतिरत है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की पंचायत समिति अरथुना के ग्राम पंचायत नवाघरा में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत चार वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

जोधपुर में कब्रिस्तान व श्मशान हेतु स्वीकृत राशि

235. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जन सहभागिता योजना के तहत कब्रिस्तान, श्मशान हेतु कोई कार्ययोजना संचालित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विगत तीन वर्ष में जिला जोधपुर में कब्रिस्तान, श्मशान हेतु कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जन सहभागिता के तहत कब्रिस्तान, श्मशान के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान में महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत जिला जोधपुर में कब्रिस्तान, श्मशान हेतु 243 कार्यो हेतु राशि रुपये 2413.92 लाख स्वीकृत की गई है। कार्यो का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

लाडनूं में शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि

236. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बी पी एल परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है?

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में विगत चार वर्षो में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में, कितनी-कितनी राशि का, किस-किसको कब-कब भुगतान किया गया तथा कितने परिवार वंचित रहे? उक्त को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा बी पी एल परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(2) विगत चार वर्षो में विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत किये गये भुगतानों की ग्राम पंचायतवार, लाभार्थीवार राशि सहित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भुगतान से वंचित 36 परिवारों का भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी।)

बस्सी के श्मशानों में सामुदायिक सेवाएं

237. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कौन-कौनसे गांवों में श्मशान

(श्री लक्ष्मण मीणा)

बने हुए हैं? उक्त में से कितने श्मशानों पर चारदीवारी, टीनशेड व अन्य सामुदायिक सेवाएं, पानी एवं बैठने का स्थान आदि उपलब्ध नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत भूडला के ग्राम रजवास में नदी के किनारे सिवाय चक भूमि श्मशान हेतु आबंटित करने तथा ग्राम रोजवाड़ी एवं रामसर के श्मशानों में पेयजल व टीनशेड लगवाने एवं उक्त सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के ग्रामों में श्मशान स्थलों पर निर्मित चारदीवारी, टीनशैड, पानी, बैठने का स्थान एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं (स्नानागार) आदि का ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार/पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत भूडला के ग्राम रजवास में खसरा नं. 178 में से 0.125 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आबंटित हो चुकी है। ग्राम रोजवाडी एवं रामसर के श्मशानों में पेयजल एवं टीनशेड लगवाने के लिए ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शामिल कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सिरोही में जिला परिषद् मद से स्वीकृत कार्य

238. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही की जिला परिषद् मद से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये तथा इनका कार्यादेश कब जारी किया गया व इनकी वर्तमान प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किस-किस संस्था व फर्म को किस नियम एवं किस दर के तहत प्रदान किये गये? प्रत्येक कार्य का संवेदक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) उक्त कार्यों का किस-किस अधिकारी ने निरीक्षण किया व उसमें क्या-क्या कमियां पाई गईं तथा कमियों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले की जिला परिषद् मद से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत कार्य, कार्यादेश तथा वर्तमान प्रगति से संबंधित सूचना प्रपत्र-1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त कार्य से संबंधित संस्था/फर्म, दर व मय ठेकेदार का विवरण प्रपत्र-2 पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त कार्यों के निरीक्षण अधिकारी व उक्त कार्यों में पाई गई कमियों व उन कमियों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र-3 पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

शाहपुरा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

239. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व सहायिकाओं के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां व उक्त में कितने-कितने पद प्रस्तावित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में बाल विकास परियोजना, शाहपुरा एवं बाल विकास परियोजना, बनेड़ा में क्रमश: 217 एवं 138, कुल 355 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बाल विकास परियोजना, शाहपुरा एवं बाल विकास परियोजना, बनेड़ा में स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनियों के पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	परियोजना	आं.बा. कार्यकर्ता	सहायिका	आशा सहयोगिनी	कुल स्वीकृत पद
1	शाहपुरा	217	187	187	591
2	बनेड़ा	138	124	124	386
योग		**355**	**311**	**311**	**977**

विभागीय पत्रांक 46029 दिनांक 23.03.2022 द्वारा आशा सहयोगिनी का पद चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग में केन्द्रांश के कारण नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.07.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि आई सी डी एस सेवा विस्तार हेतु अभी नवीन केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

इसके उपरान्त भी स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

जालौर में सड़कों का डामरीकरण

240. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम चोंचवा फांटा से फाफरिया नगर (नव सृजित राजस्व गांव) एवं चोंचवा फांटा से खेड़ा तथा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सिराणा गांव से रंगाला की सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जालौर का ग्राम फाफरिया नगर वर्ष 2011 की जनगणना के बाद घोषित राजस्व गांव है जिसकी आबादी 1,012 है। चोंचवा फांटा से फाफरिया नगर सड़क की लम्बाई 5.50 किमी है। यह गांव बजट घोषणा संख्या 95(II) वर्ष 2023-24 में वर्ष 2011 की जनगणना के बाद 500 से अधिक आबादी के घोषित नये राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोडा जाना में सम्मिलित है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

चोंचवा फांटा से खेड़ा तक कुल लम्बाई 10.00 किमी है। चोंचवा फांटा जालौर जिले में तथा जूनामीठा खेड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है। विधान सभा क्षेत्र जालौर में चोंचवा फांटा से जिला सीमा बाड़मेर तक कुल लम्बाई 5.00 किमी ग्रेवल सड़क तथा शेष 5.00 किमी कच्चा रास्ता बाड़मेर जिले में स्थित है। उक्त सड़क मिसिंग लिंक श्रेणी की है, जिसका निर्माण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सिराणा गांव से रंगाला तक कुल लम्बाई 6.75 किमी. है, जिसमें 5.25 किमी. लम्बाई ग्रेवल सड़क विधान सभा क्षेत्र जालौर में तथा शेष 1.50 किमी. लम्बाई की डामर सड़क विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में स्थित है। उक्त सड़क मिसिंग लिंक श्रेणी की है, जिसका निर्माण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

फुलेरा की सड़कों का डामरीकरण

241. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कितने किलोमीटर की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण हेतु कौन-कौनसे प्रस्ताव कब से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की 69.69 किमी लम्बाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के वर्तमान में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बीकानेर (पूर्व) की क्षतिग्रस्त सड़कें

242. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कितने-कितने किलोमीटर की? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में किन-किन सड़कों की मरम्मत, पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में 14.44 किमी. लम्बाई की 15 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें से 9 सड़कें 9.083 किमी. लम्बाई की स्वीकृत की जाकर कार्य प्रगतिरत है। शेष 6 सड़कें लम्बाई 5.357 किमी. की मरम्मत/ पुनर्निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) म्यूजियम सर्किल से बीछवाल वाया दीनदयाल उपाध्याय सर्किल-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उरमूल सर्किल (ओल्ड एनएच-15) के किमी 0/0 से 11/0 के 4 लेन से 6 लेन के चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण 11 किमी. लम्बाई की सड़क राशि रु. 33.00 करोड़ बजट घोषणा 2023-24 में शामिल की गई है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट घोषणा के अन्तर्गत ही प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रु. 10.00 करोड़ से मिसिंग लिंक/नोन पेचेबल सड़कें जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत् किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थी

243. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई है तथा इसके लिए क्या-क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में उक्त योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा कितने शेष रहे? क्या सरकार शेष रहे छात्रों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजानाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में वितरित छात्रवृत्ति राशि एवं नामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, डां. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवेदन, लाभान्वित एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

विभाग द्वारा संचालित उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

नागौर में छात्रवृत्ति का भुगतान

244. श्री रूपा राम (मकराना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र-छात्राओं को किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में माह जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु चयन कर कितनी राशि एवं अन्य प्रकार की सहायता स्वीकृत की गई? उक्त छात्रवृत्ति से वंचित रहे छात्र-छात्राओं को भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से जिला नागौर में उक्त अवधि में कई छात्र-छात्राओं को भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजानाओं के अन्तर्गत देय राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 (24 फरवरी, 2023) तक स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या एवं भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों में से छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) नागौर जिले में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से दिसम्बर 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। कतिपय विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां, समय पर वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं करना, शिक्षण संस्थाओं के मान्यता/ सम्बद्धता नही होना, बैंक खाते का त्रूटिपूर्ण विवरण होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2022-23 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 28.02.2023 निर्धारित है जिसके कारण वर्ष 2022-23 में प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की मांग के अनुरूप बजट प्राप्त नहीं होकर नोशनल एलोकेशन के आधार पर बजट प्राप्त होने के कारण उक्त योजनान्तर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

किशनगढ़ में कन्यादान योजना के आवेदन

245. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत दो वर्षो में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कई आवेदन प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों अनुसार कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया एवं कितनों को किया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत 02 वर्षों में 49 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राप्त आवेदनों में से 39 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 9 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं, सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है और 01 आवेदन पत्र आक्षेपित होने के कारण प्रार्थी के स्तर पर लम्बित है, सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कोई पात्र आवेदन लम्बित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

बड़ी सादड़ी में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

246. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2019 से 2022 तक श्रमिक कार्ड द्वारा कितने पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रमिक कार्ड के तहत श्रमिक कल्याण योजनाओं के कितने प्रकरण लम्बित हैं? क्या सरकार लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादडी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में किये लाभान्वितों का ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादडी में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में जिला कलेक्टरों द्वारा गठित दलो द्वारा पात्र श्रमिकों का सत्यापन कराया गया है। मण्डल में उपलब्ध कोष की स्थिति को देखते हुए प्रथम चरण में मण्डल की शुभशक्ति, सुलभ्य आवास एवं सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु सहायता की योजनाओं को छोडकर शेष 10 योजनाओं के शीघ्र निस्तारण पात्रतानुसार एवं वरीयतानुसार किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

यूनानी चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन

247. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए यूनानी चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यूनानी चिकिता पद्धति में प्रचलित हिजामा (कपिंग) थैरेपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई विशेष कार्ययोजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निरोगी राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में 58 तथा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 19 ब्लाक मुख्यालयों पर पर एक-एक पद यूनानी चिकित्साधिकारी, कुल 77 पद स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में 100 आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई है।

(2) जी हां। यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रचलित हिजामा (कपिंग) थैरेपी के द्वारा विभागीय चिकित्सालयों**,** औषधालयों में आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। समय-समय पर राज्य/संभाग स्तरीय आरोग्य मेलों तथा SCSP/TASP योजनान्तर्गत कैम्प आयोजित कर जनमानस को हिजामा (कपिंग) थैरेपी से विभिन्न रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) निरोगी राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए आयुष विभागान्तर्गत निम्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं:-

1. राज्य में आयुष चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा में प्रगति लाने हेतु नवीन आयुष महाविद्यालय, चिकित्सालय तथा औषधालय चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।
2. आयुर्वेद विभाग की 3,982, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग की 335 एवं यूनानी चिकित्सा विभाग की 359 चिकित्सा इकाइयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आयुष की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

3. उक्त चिकित्सालयों औषधालयों में 45 आंचल प्रसूता केन्द्रों पर महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् पथ्य औषध वितरण तथा परामर्श किशोरी बालिकाओं को रक्ताल्पता निवारण औषधि तथा बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मे वृद्धि हेतु स्वर्णप्राशन दवा पिलायी जाती है। इसके अतिरिक्त 46 पंचकर्म केन्द्र, 45 जरावस्था जन्य व्याधि निवारण केन्द्र एवं 10 क्षारसूत्र केन्द्र भी विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

4. 1,000 आयुष औषधालयों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित कर आमजन को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही नियमित योगाभ्यास कराया जाता है।

5. जन-सामान्य में स्वास्थ्यप्रद आदतों का अभ्यास बढ़ाने, घरेलू उपचार को प्रोत्साहित करने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने हेतु राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाता है।

6. प्रतिवर्ष समस्त जिलों में दस दिवसीय क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किये जाते है जहां अर्श, भगन्दर एवं फिशर इत्यादि रोगों का क्षारसूत्र के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। साथ ही पथ्य, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार-विहार आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सोजत में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत जिला पाली में दो बांध हैं- दीपावास बांध तथा गजनाई बांध। वर्षा ऋतु में दोनों बाँध खाली पड़े हैं। इन बांधों से 35 से अधिक पंचायत क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होती है।

दीपावास बांध का फिल्टर प्लांट कपूरडी है और गजनाई बांध का फिल्टर प्लांट चण्डावल नगर है। इन दोनों को जवाई फिल्टर प्लांट से जोड़ दिया जाए तो जनता को काफी राहत मिलेगी। कंटिंजेंसी प्लान में ओपन वेल करवाया जाए और जो गांव इनसे नहीं जुड़े हैं, वहां टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाए। जो हैण्डपम्प नाकारा पडे हैं उनकी मरम्मत की जाए जिससे स्थानीय निवासियों को पानी की उपलब्धता हो सके।

सोजत शहर में 10 से 12 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति मुश्किल से हो पाती है। पश्चिमी बैल्ट में खारे पानी की वजह से मवेशी भी मुंह नहीं डालते हैं।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

बीकानेर में अवैध खनन की रोकथाम

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर)

महोदय, बीकानेर जिले में खनन माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि जिस खेत में अन्तरराष्ट्रीय तारबंदी है उसी जगह खनन हो रहा है। अन्तरराष्ट्रीय सीमा के आधा से एक किलोमीटर तक एरिया बज्जू से, दंतौर से, बल्लर से, खाजूवाला में तो हर दूसरे-तीसरे खेत में अवैध खनन हो रहा है। 10 किमी. क्षेत्र में खनन के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन उक्त क्षेत्र में धड़ल्ले से सैकड़ों मशीनें चल रही हैं।

अवैध खनन से प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो कि वर्तमान सरकार में 8 से 10 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान राजस्थान को हुआ है।

यह अवैध खनन माफिया इतना मजबूत है कि राजनेताओं के नाम पर 25 से 100 रुपये प्रति टन नकद वसूली कर रहे हैं।

खुली धांधली चल रही है, सरकारी जमीन खोद रहे हैं, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व माइनिंग के सभी अधिकारी लगे हुए हैं लूट में, क्योंकि वर्तमान सरकार जो दुबारा न आएगी।

'मिली है खुली छूट'

'लूट सके तो लूट'।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

खींवसर में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)

महोदय, अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं। विशेषकर ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए बीमार होने पर इलाज के लिए शहर तक आना मुश्किल होता है। जनसंख्या बढ़ने से जिस प्रकार ग्राम पंचायतों का विस्तार करके नयी ग्राम पंचायतों का निर्माण किया है, इसके साथ ही क्षेत्र मे राजमार्गों की सख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी के अनुरूप चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार कर ग्राम स्तर पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर, अधिक आबादी वाले गांवों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के साथ-साथ पूर्व में क्रमोन्नत किये चिकित्सा केन्द्रों हेतु मापदण्डानुसार भवन निर्माण करने एवं उनमें संसाधनों का विकास करने की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी एच सी, पांचला सिद्धा व पी एच सी, पाचोडी को 2013 में सी एच सी में क्रमोन्नत करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आज 10 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उनमें न तो पूरे पद भरे हैं और न ही मापदण्डानुसार भवन निर्माण करवाया है तो कैसे राइट-टू-हेल्थ का सपना साकार होगा? इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। पिछले साल बजट घोषणा में घोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनाना, शीलगांव व करनू का भी अभी तक नया भवन नहीं बना है। इनका अतिशीघ्र निर्माण करने का कार्य करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

मेरे विधान समा क्षेत्र के राजस्व गांव सुखोलाव, धवा, बैरावास, बीन्ठवाल, बासनी खलील, लूणावास, गोल्यासनी मे नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। बैराथल कला, पालड़ी जोधा, भोमासर, ग्वालू के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की सख्त आवश्यकता है। खजवाना, बिरलोका के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है।

आज अनेकों उप स्वास्थ्य केन्द्र जो भवन रहित हैं, उनमें भवन भी बनावें तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहा अतिशीघ्र भू-आबंटन कराने का श्रम करावें।

अतः महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उक्तानुसार चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु नये चिकित्सा केन्द्र खोलने, मौजूदा चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने, क्रमोन्नत किये चिकित्सा केन्द्रों के लिये मापदण्डानुसार भवनों का निर्माण किया जाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। सधन्यवाद।

मवड़ी ग्राम (सिवाना) में हुई संदिग्ध मौतों की जांच

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में मवड़ी गांव के खेतों में ढाणियां बनाकर निवास करने वाले जगदेवसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह व माता रूप कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह, जब अपने घर से 3-4 दिन, दिनांक 04.02.2023 तक बाहर नहीं आये तो गांव वालों ने उनके मकान में जाकर देखा कि कहीं बाहर तो नहीं गये हुए हैं, परन्तु गांव वाले घर में घुसे तो वे अपने ही घर में अपने बिस्तर पर मृत मिले।

दिनांक 08.02.2023 को पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर देखा कि दोनों अपने बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे, परन्तु आज दिनांक तक जांच में पता ही नहीं चला कि दोनों की मृत्यु कैसे हुई।

इस सारी परिस्थिति में स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसके लिए मैं सरकार से चाहूंगा कि जो भी एजेन्सी से या सी बी आई से जांच करावें क्योंकि ग्रामजनों में तथा पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। एक साथ दो-दो हत्याएं हो जाती हैं और अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, न कोई नामजद अपराधी को पकड़ा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शीघ्र ही इस प्रकरण पर कार्यवाही की जाए।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

डग में अघोषित बिजली कटौती

श्री कालूराम (डग)

महोदय, पूरे प्रदेश सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में लम्बे समय से बिजली कटौती से निर्दोष किसान एवं आमजन त्रस्त है। विगत कुछ समय से विद्युत निगम बिजली आपूर्ति तथा आर्थिक कुप्रबंधन में अपनी नाकामियों का बोझ क्षेत्र के गरीब किसानों व आमजन पर डाल रहा है। विधान सभा क्षेत्र डग में घरेलू बिजली भी पूरी नहीं मिल रही है। घरेलू बिजली भी 7 से 8 घंटों तक काटी जा रही है। जब किसान व आमजन काम करके घर आता है तो उसे घर पर बिजली नहीं मिलती है। घर में अंधेरे में खाना बनाकर अंधेरे मे खाना खाता है। बिजली कटौती से संबंधित जानकारी के लिये ए ई, जे ईएन को फोन करते हैं तो उनका फोन बंद आता है।

क्षेत्र के किसानों द्वारा माह मार्च से अभी तक डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी गई, परन्तु उनको अभी तक किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरण नहीं दिये गये। विद्युत निगम द्वारा फर्जी वी सी आर भरने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है जिस कारण आये दिन गरीब किसान व आमजन मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त लोड शैडिंग के नाम पर बार-बार अघोषित बिजली कटौती करके भी आमजन को त्रस्त कर रखा है जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि बिजली कटौती पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जा रही फर्जी वी सी आर पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो पाया तो निश्चित ही आमजन व गरीब किसान आंदोलन करने को विवश हो जायेगा और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होने की स्थिति हो सकती है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में बिजली कटौती पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जा रही फर्जी वी सी आर पर अंकुश लगाकर गरीब किसानों एवं आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

धौलपुर में परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर)

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में परिवहन विभाग के चंबल-सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर परिवहन निरीक्षकों के द्वारा अपने रिश्तेदार और प्राइवेट लड़के लगाकर ट्रक वालों से अवैध वसूली की जा रही हैं।

श्रीमानजी, कुछ माह पहले परिवहन विभाग की अवैध वसूली की प्रदेश भर से शिकायत आ रही थी तो राज्य सरकार ने अच्छा फैसला लेते हुए सभी चेक पोस्टों को बंद कर दिया था, लेकिन धौलपुर मात्र एक ऐसा जिला है जहां जिला परिवहन अधिकारी की हठधर्मिता के कारण अवैध वसूली जोरों पर है। कुछ इंस्पेक्टर धौलपुर से जाना ही नहीं चाहते। लंबे समय से यहीं पर नौकरी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में रिकार्ड बना रहे हैं, जिस कारण राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्री विजय कुमार मीणा जी लंबे समय तक यहां इस्पेक्टर लगे थे और अब जिला परिवहन अधिकारी की कुर्सी संभाल कर बैठे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, जिससे जनता में अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद।

प्रदेश में स्थायी टैक्सी स्टैण्ड हेतु आबंटन

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)

महोदय, प्रदेश में टैक्सी ड्राइवरों ने कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में निःस्वार्थ भाव से कार्य किया और लोगों को चिकित्सालय तक भर्ती करवाया। प्रदेश के सभी जिलों में टैक्सी ड्राइवर जहां अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उन्हीं स्थानों को चिह्नित कर निःशुल्क अलाट किया जाये। टैक्सी ड्राइवर बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। जब ड्राइविंग करते हैं और उनके गाड़ी के आगे यदि साइकिल वाला आ जाता है तो उसको भी बचाने का प्रयास करते हैं।

मेरे क्षेत्र में नगरपालिका, अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैण्ड के पास, नई मण्डी घड़साना में भारतमाला रोड पुलिया के पास और रावला कस्बे में बाजार में व रामसिंहपुर में कुपली चौराहे के पास काफी वर्षों से इन्हीं स्थानों पर गाड़ियां खडी करने का स्थान निश्चित है और स्थान प्रशासन के भी ध्यान में है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और जन-प्रतिनिधियों द्वारा भी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को भी टैक्सी स्टैण्ड बनाने के लिए पत्राचार किये हैं। प्रदेश में

टैक्सी ड्राइवर है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा भी आये दिन टैक्सी ड्राइवरों की गाड़ियों के चालान/जुर्माना काटे जाते हैं तो इसमें भी राहत देवें। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश के सभी जिलों में टैक्सी स्टैण्ड के लिए यथावत स्थान ओर शेष रहे स्थानों को चिन्हित कर राज्य सरकार संबंधित विभागों को आदेशित कर सभी जिलों में टैक्सी स्टैण्ड के लिए निःशुल्क जमीन आबंटन करने की ओर विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

मण्डावर पंचायत समिति की बजट घोषणा का क्रियान्वयन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा)

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा के अन्दर बजट वर्ष 2022-23 में मण्डावर को पंचायत समिति बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं की गई है। उक्त सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बजट वर्ष 2022-23 में मण्डावर को पंचायत समिति बनाने की बजट घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति करते हुए पंचायत समिति मण्डावर बनाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत बालाहेड़ी, टुडियाना एवं गगवाना पंचायत समिति महवा से सटी हुई हैं तथा महवा से इनकी दूरी 05 से 10 किलोमीटर ही है। तीनों ग्राम पंचायतों का उप खण्ड मुख्यालय भी महवा है। उक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों की मांग है इन ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महवा में शामिल किया जाए।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं पंचायती राज मंत्री जी से मांग करता हूं कि बजट वर्ष 2022-23 में मण्डावर को पंचायत समिति बनाने की बजट घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति करते हुए पंचायत समिति मण्डावर बनाने के आदेश जारी किये जाएं तथा गगवाना, बालाहेड़ी एवं टुडियाना ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महवा में शामिल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में जनगणना वर्ष 2011 के अनुरूप बढ़ोतरी

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी)

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं

जनजाति के सामाजिक, राजनीतिक, कर्मचारी एवं अन्य संगठनों द्वारा राजस्थान में राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं में राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत 16% एवं 12% से बढ़ाकर 17.8% एवं 13.5% करने की मांग विभिन्न माध्यमों से की जाती रही है।

झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं अन्य कई राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप बढ़ाया जा चुका है, परंतु बड़े खेद का विषय है कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत अभी तक भी राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुरूप नहीं बढ़ाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय अध्यादेश द्वारा राजस्थान में राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य विभिन्न राजकीय योजनाओं में राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण वर्तमान प्रतिशत 16% एवं 12% (जो कि वर्ष 1961 की जनगणना पर आधारित है) से राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुरूप बढ़ाकर 17.8% एवं 13.5% करने के राजस्थान सरकार से आदेश जारी करवाकर अनुगृहीत करें।

स्टेट हाईवे 20-बी का सुदृढ़ीकरण

श्री बिहारीलाल (नोखा)

महोदय, राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में बीकानेर-नापासर-जसरासर स्टेट हाईवे-20 बी के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाने की घोषणा की गई थी, लेकिन दो साल बाद भी बजट घोषणा कागजों में अटकी पड़ी है और अभी तक धरातल पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह स्टेट हाईवे पांच विधान सभा क्षेत्र नोखा, बीकानेर पूर्व, श्रीकोलायत, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ में से होकर गुजरता है जिसकी दूरी 65 किमी है। इस सड़क की हालत बहुत खराब है और आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि बीकानेर-नापासर-जसरासर स्टेट हाईवे 20-बी का तत्काल कार्य शुरू करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

इसके अलावा नोखा विधान सभा क्षेत्र स्थित स्टेर्ट हाइवे 87बी जांगलू से भामटसर तक है, जो अभी सिंगल लेन में है। हमारी मांग है कि उसे दो लेन में किया जाये और स्टेट हाईवे 87बी को भामटसर से आगे विस्तार करते हुए सलूण्डिया, घट्ट, अणखीसर होते हुए मुकाम स्टेट हाईवे 20 से जोड़ा जाये या उसे कोई नया नंबर दिया जाये।

अभी स्टेट हाईवे 87 ए का चौड़ाईकरण-नवीनीकरण चल रहा है, परंतु उसमें रोड़ा से कक्कू तक 18 किमी. (173/0-190/0) व साधूणा से सारूण्डा 9 किमी. (205/0-214/0) की स्वीकृति सी आर आई एफ में भिजवाई हुई है उसे जल्द स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारम्भ करवाया जाए। पांचू पंचायत समिति मुख्यालय से संगाल धोरा की 10 किमी डब्ल्यू बी एम सड़क बन रही है, उसमें भी डामरीकरण का पैसा जारी किया जाए।

जोधपुर के डा. एस.एन. मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर)

मान्यवर जी, निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी के विगत कार्यकाल वर्ष 2012 की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में सूचना सहायक के 59 पदों का सृजन कर कार्मिकों का पदस्थापन किया गया। सूचना सहायकों द्वारा कम्प्यूटर एवं नवीन तकनीक के माध्यम से निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का लाभ मरीजों तक पहुंचाया गया। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के पदों में आनुपातिक वृद्धि की गयी है, परन्तु कम्प्यूटर संवर्ग के पदों में वृद्धि करने के स्थान पर कैडर पुनरीक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर द्वारा सूचना सहायक के पदों में कटौती कर 59 से 29 पद कर दिये गये।

अतः डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में नवीन चिकित्सालयों, विभागों एवं मेडिकल यूनिट के विस्तार एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन करते हुए सूचना सहायक के 61 पदों को स्वीकृत किया जावे।

रेडियोग्राफर संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि लम्बे समय से सोसायटी आफ राजस्थान रेडियोग्राफर्स एण्ड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, राजस्थान, जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से सम्बध रखता है, के संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में मांग की जा रही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान अति गम्भीर विकिरण क्षेत्र में मरीजों के एक्स-रे एवं सीटी स्कैन का कार्य जान जोखिम में डाल कर प्रदेश के रेडियोग्राफर्स द्वारा जनसेवा का कार्य किया गया है और समय-समय पर प्राकृतिक आपदा एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी एवं भागीदारी निभाते हैं। संगठन की मांग है कि सामाजिक सम्मान एवं अन्य वर्ग में पूर्व में किये गये नाम परिवर्तन करने की समकक्षता की स्थिति में रेडियोग्राफर संवर्ग का पदनाम परिवर्तित कर रेडियोलॉजी आफिसर किया जावे। इस प्रकार के आदेश हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सितम्बर, 2022 में जारी किये हैं।

प्रदेश में उक्त समकक्ष प्रकरणों में लिपिकीय वर्ग, ग्रामसेवक आदि अन्य वर्ग में भी इस प्रकार से सम्मानजनक पदनाम परिवर्तन किये गये हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सोसायटी आफ राजस्थान रेडियोग्राफर्स एण्ड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, राजस्थान की मांग के अनुसार रेडियोग्राफर संवर्ग का पदनाम परिवर्तित कर रेडियोलॉजी आफिसर करावें। यह गैर वित्तीय पदनाम होगा एवं सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा।

फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की सर्विस लेन एवं ओवरब्रिज निर्माण कार्य में विलम्ब

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

महोदयजी, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में NH52 मेरे गांव में से होकर गुजरता है। लगभग एक साल छह माह पूर्व हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसका कार्य आदिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरे द्वारा बार-बार अधिकारियों को दूरभाष पर अवगत करवाया गया। मेरे गांव रोलसाहबसर में सर्विस लेन के

साथ जो रास्ते निकलते हैं उनको ठीक किया जावे और मेरे घर के सामने जो कार्य बाकी है उसको पूर्ण किया जावे। साथ ही फतेहपुर शहर में ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है वह भी काफी लम्बे समय से बन्द पड़ा है। उससे हाईवे पर आवागमन में आये दिन ट्रैफिक जाम रहता है। अतः इसको भी जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जावे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त सर्विस लेन एवं ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण करवाकर जनता को सुविधा दी जावे और मेरी मांग है कि उक्त दोनों कार्यों में विलम्ब होने के कारणों की जांच करवाई जावे।

बयाना में बदहाल सिंचाई व्यवस्था

श्री अमर सिंह (बयाना)

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना की बदहाल सिंचाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता है। पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई तो दूर, गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या बहुत रहती है।

भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बंध-बारेठा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के इसी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। बंध-बारेठा से निकलने वाली नहरों से क्षेत्र की हजारों बीघा बंजर जमीन पर सिंचाई होती थी, किन्तु समय के साथ-साथ बंध-बारेठा में पानी कम होने से इसका पानी पेयजल के लिए रिजर्व कर दिया गया, जिससे हजारों बीघा जमीन बंजर रह जाती है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा धौलपुर जिले से लगती है। सरकार मन बनाकर धौलपुर से निकलने वाली चम्बल नदी से लिफ्ट परियोजना द्वारा पानी बंध-बारेठा में लाया जा सकता है, जिससे कि क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है।

इस लिफ्ट परियोजना से पानी अगर बंध-बारेठा में आता है तो भविष्य में मेरा विधान सभा क्षेत्र बयाना ही नहीं अपितु सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र नदबई एवं वैर के काश्तकारों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पिण्डवाड़ा नगरपालिका स्थित सामुदायिक भवनों का रखरखाव

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू)

महोदय, निवेदन है कि पिंडवाड़ा नगरपालिका में वर्ष 2011-12 में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 5 सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया था। इन भवनों की अब हालत पूरी तरह से खस्ताहाल है। ये भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। ऐसे में इन भवनों में जो खिड़की दरवाजे लगे हुए थे, वे भी पूरी तरह से टूट-फूट गये हैं। मेरी सरकार से मांग है कि पिंडवाड़ा में जिस तरह को-आपरेटिव बैंक व सहकारी बैंक का किराये के भवनों में संचालन हो रहा है तो इन सामुदायिक भवनों को रिपेयरिंग करवाकर सामुदायिक भवनों का रखरखाव करने के लिए किसी सहकारी बैंक या अन्य किसी निजी संस्थाओं को सौंपा जाए और किराया भी वसूल किया जाए, जिससे सरकार को भी आय के रूप में राजस्व भी प्राप्त होगा। पूर्व में मेरे व महिला समूहों द्वारा कई बार इन सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखकर मांग की गई थी कि इन सामुदायिक भवनों का उपयोग किया जाए जिससे इन भवनों का उचित ढंग से रखरखाव किया जा सके और इन भवनों से आय के रूप में राजस्व प्राप्त हो, लेकिन जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने पर आज इन भवनों की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ये एक खण्डहर के रूप में मौजूद हैं। सरकार का करोड़ों रुपये का खर्च आज किसी काम नहीं आ रहा है।

मेरी सरकार से यही मांग है कि इन भवनों की मरम्मत करवाकर जो पिंडवाड़ा में सहकारी बैंक किराये के भवनों में संचालित हो रही हैं उन्हें इन सामुदायिक भवनों को सौंपकर भवनों का किराया वसूल किया जाए, जिससे इन सामुदायिक भवनों का रखरखाव भी हो सकेगा और सरकार को आय के रूप में राजस्व भी प्राप्त होगा।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. सादुलशहर में नर्सिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

2. विधान सभा क्षेत्र नदबई में तहसील मुख्यालय नदबई में नवीन नर्सिंग कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

3. बांसवाड़ा जिला हैडक्वार्टर पर नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने व प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय देने के साथ ही इनकी सुरक्षा व समुचित प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

4. सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा बाहरी एवं राज्य के प्रशिक्षणार्थियों का रजिस्ट्रीकरण समय पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. राजकीय मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राजमेस के अधीन मेडिकल कालेजों में एक समान फीस निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

9. झालावाड़ व कोटा मेडिकल कालेजों में नये विषय संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

10. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के जनजाति क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आवास की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के TSP क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा हेतु अतिरिक्त सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. TSP क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये चिकित्सा शिक्षा हेतु विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

13. चितौड़गढ़ मेडिकल कालेज को शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

15. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतेहनगर में नर्सिंग कालेज स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. बेदला (उदयपुर) में नर्सिंग कालेज स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

17. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण (कोटा) के न्यू मेडिकल कालेज में पैरा मेडिकल कोर्स प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण (कोटा) के न्यू मेडिकल कालेज में सोलर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

19. चिकित्सा महाविद्यालय, बाड़मेर में स्वीकृत सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

20. रामगढ़ (अलवर) में स्वीकृत राजकीय नर्सिंग कालेज को संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

22. विधान सभा क्षेत्र नोखा में डी.एम.एल.टी. ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र नोखा में बी.एससी. नर्सिंग कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र नोखा में सेमी मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र नोखा में जी.एन.एम ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

26. डूंगरपुर जिले में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

27. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा (कोटा) को राजकीय मेडिकल कालेज कोटा से सम्बद्ध कर नियमित विशेषज्ञ सेवाएं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय कोटा में इमरजेंसी एवं ब्लड बैंक भवन के सामने वर्तमान में बन्द द्वार को खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. न्यू मेडिकल कालेज भवन कोटा में द्वितीय तल पर वार्ड चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. न्यू मेडिकल कालेज कोटा में कॉटेज वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने से हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

31. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक कदम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

33. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मेडिकल छात्रों को अलवर मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

36. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में नवीन राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

37. विधान सभा क्षेत्र चूरू में गत 4 वर्षों में मेडिकल कालेज हेतु आबंटित बजट की राशि खर्च नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र चूरू के मेडिकल कालेज में प्रोफेसरों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र चूरू के नर्सिंग कालेजों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. चूरू मेडिकल कालेज हेतु आबंटित उपकरणों को इंस्टाल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. चूरू मेडिकल कालेज में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संविदा समान कार्य संवेदक द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

42. भीलवाड़ा मेडिकल कालेज में बाहर से आने वाले मेडिकल छात्र-छात्राओं के लिये पर्याप्त मात्रा में समुचित आधुनिक छात्रावासों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. मेडिकल कालेज भीलवाड़ा में SC, ST, OBC, MBC और विभिन्न आरक्षित श्रेणी के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति वितरण करने पर चर्चा के लिये।

44. मेडिकल कालेज भीलवाड़ा में अपने स्तर पर की जा रही विभिन्न भर्तियों में आरक्षण आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. मेडिकल कालेज भीलवाड़ा में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा व्यवस्था हेतु उपकरणों की उपलब्धता पर चर्चा के लिये।

46. नव स्थापित मेडिकल कालेज भीलवाड़ा में मरीजों को स्वच्छ पर्यावरणीय वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

47. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में रिक्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राजकीय जयपुरिया हास्पिटल जयपुर में शिशु रोग विभाग में 60 बेड का शिशु वार्ड, 18 बेड का आई.सी.यू. वार्ड एवं 8 बेड का पी.आई.सी.यू. वार्ड संचालित होने से शिशु रोग चिकित्सकों की आवश्यकता के अनुरूप शिशु रोग चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. राजकीय जयपुरिया हास्पिटल जयपुर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 100 बेड का वार्ड संचालित होने से स्त्री रोग चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर शहर के सवाई मानसिंह हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज के मध्य अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. जयपुर शहर के सवाई मानसिंह हास्पिटल पर बढ़ रहे मरीजों के दबाव को कम करने के लिए शहर के RUHS हास्पिटल, कांवटिया, जयपुरिया एवं गणगौरी हास्पिटल में सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

52. अजमेर, जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में न्यूनतम एक-एक प्रोस्थेटिस्ट व आर्थोटिस्ट के पद सृजित कर उस पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. आर.यू.एच.एस. विश्वविद्यालय जयपुर के साथ-साथ प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में रिक्त पड़े शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश के निजी नर्सिंग कालेजों में फीस के नाम पर विद्यार्थियों से हो रही वसूली के खेल पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल शिक्षा की सीटें और बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में नये सिरे से मेडिकल शिक्षा नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

57. जालौर जिले के मेडिकल कालेज को आहोर-जालौर के मुख्य मार्ग पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. आहोर के सियाणा में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

59. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ मुख्यालय में नवीन नर्सिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में बीमारियों के अनुसंधान को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कालेजवार, पाठयक्रमवार सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में कालेजवार, पाठयक्रमवार, प्रवेश क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. गंगानगर जिले में स्थित डा. S.S. टांटिया मेडिकल कालेज में PG के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

64. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के सम्बन्ध में बजट घोषणा 2021-22 के तहत पब्लिक हेल्थ कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. प्रदेश के चिकित्सालयों में खराब उपकरणों की मरम्मत/नये उपकरण उपलब्ध करवाने व अन्य सुविधाओं में वृद्धि करवाने हेतु चर्चा के लिये।

66. चूरू मेडिकल कालेज में शिक्षकों व पैरा मेडिकल के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नर्सिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

68. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में हो रही प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में हो रही प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. राजस्थान के सम्भागीय मुख्यालयों पर लोक स्वास्थ्य महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. अनुदानित दरों पर भूमि लेने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धन वर्ग के रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. राजसमन्द एवं राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर दन्त रोग चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

73. यूक्रेन में शिक्षारत भारतीय छात्रों को विदेश की मेडिकल कालेजों के समकक्ष कक्षा में प्रवेश दिलाने की आवश्यकता, सरकारी मेडिकल कालेजों में फीस वृद्धि को कम करने की आवश्यकता तथा डूंगरगढ़ (बीकानेर) में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

74. प्रदेश के एस.एम.एस. अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का अलग से विभाग खोलने, श्वांस रोग संस्थान (S.M.S. HOSPITAL-CHEST AND TB) का अलग से टावर बनाने तथा एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई

में अलग से पूर्व की तरह S.M.S. HOSPITAL के वार्ड्स में CLINICAL-EXPERIENCE हेतु क्लासेज लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

75. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर में नर्सिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

76. प्रदेश में CHO परीक्षा के पेपर लीक के बाद भी परीक्षा निरस्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश में वर्ष 2010 स्टाफ नर्स परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में नियुक्ति प्राप्त स्टाफ नर्स को अयोग्य होने पर भी रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय में नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

78. खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज शुरू करवाने, नागौर जिले में जिला मुख्यालय पर बन रहे मेडिकल कालेज भवन निर्माण गुणवत्ता जांच कमेटी में जन-प्रतिनिधियों को शामिल करने, नागौर जिले में संचालित निजी नर्सिंग कालेजों में अध्यापन करवा रहे शिक्षकों का मापदण्डों के अनुसार भौतिक सत्यापन कर जांच करवाने तथा नागौर जिले में आबादी व जन घनत्व के अनुसार सुपर स्पेशियलिस्ट चिकित्सकों के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

79. विधान सभा क्षेत्र जालौर के उप खण्ड मुख्यालय सायला में नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जालौर जिला मुख्यालय के पास लेटन गांव में निर्मित नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज भवन का पूर्व निर्धारित उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. जालौर में फार्मेसी शिक्षा, लेब टेक्निशियन कोर्स एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्स की शिक्षा हेतु सरकारी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. बजट भाषण में हुई घोषणा के अनुसार जालौर में मेडिकल कालेज खोलने एवं कालेज का निर्माण शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानीय प्रतिभावान विद्यार्थियों को आसानी से प्रवेश मिले, इस हेतु जालौर में कोचिंग सेंटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

84. सवाई मानसिंह अस्पताल/मेडिकल कालेज में जरूरतमंद रोगियों/गम्भीर रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर ICU उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज में लगाये गये आक्सीजन प्लांट्स के बन्द होने एवं घोषित किये गये प्लांट्स की स्थापना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग कालेजों द्वारा प्रवेश लेने वाले/अध्ययनरत छात्रों से मनमानी/अधिक शुल्क वसूलने पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में मधुमेह रोगियों हेतु पृथक से विंग स्थापित करने एवं समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों द्वारा सरकारी योजनाओं के अनुसार चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

89. किशनगढ़ (अजमेर) में नया राजकीय मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

90. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

91. जिला अजमेर के राजकीय मेडिकल कालेज के नेफ्रोलोजी विभाग में नेफ्रोलोजिस्ट शिक्षक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. राजकीय मेडिकल कालेजों में डाक्टर एवं पैरामेडिकल के विभिन्न स्टाफ की अत्यधिक कमी होने के कारण कालेजों की मान्यता पर संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. अजमेर सम्भाग के सबसे बड़े JLN चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. जिला अजमेर के राजकीय मेडिकल कालेज के यूरोलॉजी विभाग में एम.सी.एच. कोर्स संचालन में आ रही बाधा के कारण दो और संकाय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में मेडिकल, कैंसर विज्ञान और सर्जिकल कैंसर विभाग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

96. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय मेड़ता व रियां बड़ी में नर्सिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर):

97. प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यकतानुसार नये पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

98. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नर्सिंग कालेज की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में फार्मेसी शिक्षा, लैब टेक्निशियन कोर्स एवं अन्य पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्स की शिक्षा हेतु सरकारी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद):

100. प्रदेश में नर्स श्रेणी प्रथम की वरिष्ठता सूची 2018-19 के अनुसार पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

101. प्रदेश में रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती करने एवं सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. प्रदेश के नर्सिंग कालेजों में GNM/ANM की सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

103. विधान सभा क्षेत्र डग की भवानी मण्डी में नर्सिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. भीलवाड़ा के मेडिकल कालेज में न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी के डाक्टरों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

105. कोटा के नवीन मेडिकल कालेज में कैंसर चिकित्सालय खोलने तथा पेप मशीन लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. कोटा के नवीन मेडिकल कालेज चिकित्सालय में द्वितीय तल के संचालन हेतु चिकित्साकर्मी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

2. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सादुलशहर में X-Ray मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

2. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सुविधाओं को और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

3. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में चिकित्सा अधिकारियों एवं ANM के रिक्त पदों को भरने तथा मेडिकल कालेज बाड़मेर में MRI मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. मेडिकल कालेज एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, बाड़मेर के सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

5. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

6. विधान सभा क्षेत्र दूदू की (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चोरू, सेवा, मरवा को (CHC) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. विधान सभा क्षेत्र दूदू के दूदू एवं फागी के उप जिला अस्पताल हेतु भवन निर्माण का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने के साथ ही PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) से CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) नव

क्रमोन्नत किये गये बोराज, मौजमाबाद एवं साखून हेतु अविलम्ब भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. विधान सभा क्षेत्र दूदू के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप जिला अस्पताल में रिक्त पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

9. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय की स्वीकृति देने तथा जैतारण (CHC) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रोमा सेन्टर बनाने, डायलिसिस सुविधा शुरू करने के साथ ही सोनोलोजिस्ट की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी CHC, PHC, SC में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति करने, पेयजल की व्यवस्था व आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी CHC, PHC, SC में रिक्त पदों को भरने, जर्जर भवन की मरम्मत कराने व नवीन PHC व SC स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के नवीन स्वीकृत CHC बर व आ. कालू की वित्तीय स्वीकृति जारी कर नवीन भवन बनाने, चिकित्सक लगाने व अन्य चिकित्सीय सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की जैतारण CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) को 50 बेड से 100 बेड में क्रमोन्नत करने की बजट घोषणा की वित्तीय स्वीकृति देने, रिक्त पदों को भरने व पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

14. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील नदबई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप खण्ड जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र नदबई में नेशनल हाईवे से सटे ग्राम पंचायत पहरसर में नवीन ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम पंचायत मुख्यालय झारकाई (उच्चैन), तलछेरा (नदबई), अघापुर (उच्चैन), रोजीजा (नदबई) व बछामदी (नदबई) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम पंचायत धरिधा के गांव चन्दनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत धरिधा के मुख्यालय पर नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के उप जिला चिकित्सालय, बाड़ी को 200 शय्या से 300 शय्या में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी करने तथा कृषि उपज मण्डी बाड़ी में नवीन चिकित्सालय भवन निर्माण किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के उप जिला चिकित्सालय, बाड़ी में ट्रोमा सेन्टर खुलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम डांग बसई में नवीन पी.एच.सी. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम सिगोरई में नवीन पी.एच.सी. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोलने हेतु स्वीकृति जारी करने की आवश्कयता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम परोआ (सेपऊ) में नवीन पी.एच.सी. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

24. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने तथा एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जनसंख्या के अनुपात में धनवा, जेठन्तरी एवं चाडो की ढाणी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सी.एच.सी. (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) सिवाना को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधा दिये जाने की घोषणा के अनुरूप राजस्व गांवों में भी सब-सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

30. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (C.H.C.) रामगढ़ (सीकर) को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने एवं फतेहपुर में ट्रोमा सेन्टर में नियमानुसार चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

31. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की सी.एच.सी. (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) छबड़ा को उप जिला अस्पताल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

34. प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

35. प्रदेश के मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली नशीली दवाइयों पर रोक लगाने हेतु ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की आदिवासी बहुल बस्तियों में कुपोषण से ग्रसित बालक-बालिकाओं का सर्वे करवाकर उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित 108 व 104 एम्बुलेन्सों के स्थान पर नवीन एम्बुलेन्स लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सकों एवं कार्मिकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के भवन रहित (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कठार में भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

40. प्रदेश के चिकित्सा विभाग के सभी भवनों का निर्माण (P.W.D.) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जक्शन में भवन रहित सब-सेन्टर हेतु भवन निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

42. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल एवं कोटड़ा में सेटेलाइट हास्पिटल खोलने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

43. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के उप स्वाथ्स्य केन्द्र मंढा, पालड़ी व बड़ोदिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तालुका बास व अमरपुरा में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साईवाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

47. विधान सभा क्षेत्र कपासन की सभी चिकित्सा इकाइयों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम रूद, भीमगढ़, मुंगाना, सुरपुर, कंथारिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र कपासन की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपालसागर, आकोला एवं कपासन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमाना एवं जाश्मा में नवीन 108 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज से पूर्व जांचों के नाम पर निजी चिकित्सालयों द्वारा वसूली जा रही राशि के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित CHC, PHC तथा सब-सेन्टर पर चिकित्सकों एवं सभी श्रेणी के कार्मिकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

52. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में लाम्बागोठड़ा (LAMBA GOTHARA),

इूलानिया, बेरी तथा बनगोठड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

53. अलवर शहर में शिशु चिकित्सालय, जनता क्लिनिक एवं माडल CHC खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

54. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जगह की कमी को देखते हुए नवीन भवन के लिए जमीन आबंटन हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के सलावद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर में ट्रोमा सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

58. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ी सादड़ी को 100 बैडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगला को 75 बैडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्सी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलवाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

63. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्रों पर सोनोग्राफी, एक्सरे, सी.बी.सी. मशीनों सहित सभी जांच उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक सहित सभी स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित सभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विधायक कोष से उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंसों के सफल संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के सभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों के भवन निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

68. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में रोगी के साथ आने वाले व्यक्तियों के ठहरने हेतु चिकित्सालय में स्थित जीर्ण-शीर्ण हो चुकी सीताराम धर्मशाला का नव निर्माण कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के उप नगर पुर में चिकित्सा व्यवस्था सुचारु करने हेतु 40 वर्ष पुराने (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को (CHC) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में स्थित सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में वार्ड निर्माण हेतु D.M.F.T. फंड से राशि जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. भीलवाड़ा शहर के उप नगर पुर की PHC में मुख्य मंत्री द्वारा 3 वर्ष पहले 01 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य की घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

72. विधान सभा क्षेत्र मावली के घासा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र मावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मावली को उप जिला अस्पताल या सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में ट्रोमा सेन्टर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र मावली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मावली के भवन एवं शौचालय की मरम्मत एवं पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

76. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं किवरली एवं मोरस में (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

77. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के शेष रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

78. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सुहागपुरा, चुपना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के पानमोडी, मोखमपुरा, खेरोट, लुहारिया, बोरी A, पण्डावा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियमित करने, ANM, TC प्रतापगढ़ में लम्बे समय से पद सृजित नहीं होने से प्रशिक्षणार्थियों के अध्यापन में हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

81. जोधपुर में स्थित रेजिडेन्सी हास्पिटल में पड़े खाली पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

82. पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) के भवन निर्माण एवं अन्य आवश्यक सामग्री/उपकरण हेतु बजट आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. रावतसर, पीलीबंगा एवं डबली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के जाखड़ावाली, पीलीबंगा व गन्धेली, रावतसर PHC को CHC में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पीलीबंगा, गोलूवाला, डबली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में बेड बढ़ाने एवं रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

87. विधान सभा क्षेत्र नोहर के उप स्वास्थ्य केन्द्र मालासर मोटेर, दलपतपुरा, जबरासर, थालड़का को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. नोहर में उप जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र नोहर के विभिन्न गांवों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र नोहर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों का

पुनर्निर्माण तथा भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन व चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुईया, धानसिया, टोपरिया, मन्दरपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (अलवर शहर):

92. कोटा में श्रीनाथपुरम या आर. के. पुरम में जनता क्लिनिक खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

93. विधान सभा क्षेत्र लोहावट (जोधपुर) में नवस्वीकृत PHC, CHC व ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण कार्य के टेण्डर होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

94. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवडी, बलाउजाटी, सिणली जागीर, चान्देसरा, दुदवा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपदरा में मानदण्डानुसार भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हेतु वांछित राजस्व ग्राम मुख्यालयों पर नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुडी, सराणा, गोल-भीमरलाई एवं ढाणी सांखला में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में जिला अस्पताल बालोतरा के नवीन भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा):

99. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में चिकित्सकों की कमी व चिकित्सालय के भवनों की जर्जर अवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

100. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में गोविन्दगढ़ के ग्राम मालपुर में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

101. प्रदेश के बाजारों में बिकने वाली नकली एवं अमानक दवाइयों, नकली वैक्सीन आदि की नियमित जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार सोनोग्राफी, एन्जियोग्राफी, सी.टी. स्कैन, एम.आर. आई. आदि जांच की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी राजस्व गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के बडावली, बरोड़ा सराड़ी, करावली, पलोदड़ा, बडगांव, सगतड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों, मेल नर्सों के उपयोगार्थ क्वार्टर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ईडाणा, खरखा, गामडापाल, गुडेल, खैराड, डाल, टोडा पीलादर केवड़ा, नठारा, बलुआ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चावण्ड, ईंटाली, खेड़ा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखण्ड का खेडा में भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

106. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डार व सिरोड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा उप केन्द्र

मूंगथला, मावल, जाम्बुड़ी व नीचलागढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र रेवदर उप खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर में शिशु रोग विशेषज्ञ एवं महिला रोग विशेषज्ञ व शेष रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबूरोड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला स्तर के राजकीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार बांट, दांतराई, सनवाडा निम्बज, चनार, भट्टाणा आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं क्षेत्र के अन्य उप केन्द्रों में चिकित्सकों व मेडिकल, पैरामेडिकल, तकनीकी स्टाफ के रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के दूर-दराज में सरकारी नि:शुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से वंचित क्षेत्रों में नवीन स्वास्थ्य सब-सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्ड़लगढ़):

111. प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

112. विधान सभा क्षेत्र आहोर में शंखवाली एवं ऊण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा भाद्राजून, बागरा, चादराई, गुडाबालोतान भवरानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र आहोर के अनुसूचित जनजाति बहुल गांव सुमेरगढ़ खेडा, रसियावास खुर्द में निर्मित नवीन भवन में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

115. विधान सभा क्षेत्र नोखा के सभी निजी चिकित्सालयों को चिरंजीवी योजना से जोड़ने हेतु चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र नोखा के सुथारों की ढाणी सारूण्डा, लिखालों की ढाणी बंधड़ा, प्रहलादपुरा, भौम बगसेउ, सिंवरों की ढाणी स्वरूपसर, रासीसर पुरोहितान, बाढ़ काकड़ा, बुदरों की ढाणी, गोविन्दनगर, रामनगर, किशनासर दक्षिण, शरह तेलिया, शरह माणकसर मे नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. नोखा तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुकाम, जांगलू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. नोखा तहसील के सब-सेन्टर भामटसर, जांगलू, जैसलसर, जयसिंहदेसर मगरा, किसनासर, बिलनियासर व सूरपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. नोखा तहसील में पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर एक अतिरिक्त ब्लाक सी एम एच ओ कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

120. विधान सभा क्षेत्र मकराना में बजट घोषणा अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) पर डायलिसिस सुविधा शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मकराना के सभी C.H.C., P.H.C., S.C. व उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों, A.N.M., G.N.M. सहित अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

122. विधान सभा क्षेत्र ओसियां (जोधपुर) में मदर व चाइल्ड अस्पताल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र ओसियां (जोधपुर) में तिंवरी हटुण्डी PHC से CHC में क्रमोन्नत केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक बजट आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

124. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में चांसदा पी.एच.सी. को

सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं इनमें रिक्त पदों को भरने के साथ ही नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

126. विधान सभा क्षेत्र लूणी की PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) एवं CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर खाली पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

127. बाड़मेर जिले के शिव में चिकित्सकों व ए.एन.एम. के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

128. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम कुराड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दीगोद एवं कुन्दनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही मेडिकल कालेज, कोटा की व्यवस्था को सशक्त करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

130. सांगोद के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात्रि में चिकित्सा विभाग के चिकित्सक व स्टाफ के नहीं रहने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

131. विधान सभा क्षेत्र बस्सी-जयपुर में राजकीय अस्पतालों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तूंगा को उप जिला अस्पताल एवं सांभरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के साथ ही भटेरी, बूड़थल, रूपाहेडीकला के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

132. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के रानीपुरा एवं भोजपुर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के ल्हास, चन्दीपुर, कोल्दूखेड़ी उप

स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के (P.H.C.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावर, गेहुखेड़ी, चुरेलिया, भालता एवं सरड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (C.H.C.) में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (C.H.C.) मनोहर थाना को 30 बेड से 50 बेड करने एवं उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

136. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के PHC, CHC पर रात्रि को चिकित्सक नहीं मिलने एवं चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण इनके लिए निर्मित आवासों के खण्डहर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. डूंगरपुर सामान्य चिकित्सालय में हो रही अनियमितता, चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं दिलाने एवं चिकित्सकीय उपकरणों के बार-बार खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

138. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के उप स्वास्थ्य केन्द्र भन्दर, भाटुन्द, बोया बारवा व भीटवाड़ा में मेल नर्स प्रथम के पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र बाली के उप जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादड़ी में ब्लड बैंक की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

141. बाली के उप जिला अस्पताल के लिए जमीन आबंटन के उपरान्त भी भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र बाली में चिमनपुरा, भारला, गोरधनपुरा, अणेवा, फतापुरा, सादरला टीपरी, इन्द्रा कालोनी, रडावा (बाली) मीणों की ढाणी (सादड़ी) वीरमपुरा रेबारियान आदि में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

143. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के मरेवड़ा, आपलियास, भोजरास में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में भादसी, बरसनी, कटार के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के कंवलियास तथा ब्राह्मणों की सरेरी में PHC को CHC में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

146. राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल, अलवर शहर में रोगियों की संख्या के अनुसार बेड की संख्या में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. अलवर शहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गंज, जगन्नाथ जी मंदिर, अखैपुरा, N.E.B. मूंगस्का शिवाजी पार्क को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल अलवर शहर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

149. विधान सभा क्षेत्र शिव (बाड़मेर) के हरसानी व खलीफेकी बावड़ी PHC को CHC में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

150. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में PHC कोचरी, डूंगर, करावाड़ा, गधवा, सरथूना के भवन नहीं बनने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

151. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के चिकित्सा संस्थानों में स्थानान्तरित होकर आये कार्मिकों को वेतन नहीं मिलने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

152. राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थगन प्राप्त कर पिछले 1-2 वर्षों से जबरन लगे हुए कार्मिकों के मामलों में प्रभावी पैरवी/कार्यवाही नहीं करके उनसे आदेशित स्थान पर कार्य लेने में विभागीय विफलता पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में अनेक चिकित्सा केन्द्रों के भूमि एवं भवन विहीन होने पर भी उनके लिए भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण करवाने में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. इटावा (कोटा) में उप जिला स्तरीय चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकता हेतु न्यूनतम बजट का आबंटन भी नहीं करवाने में विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

155. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

158. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर, नीमराणा व शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. समस्त कोविड सहायकों व चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा P.H.C. (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

163. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र धानोल, भाटीप, राजपुरा, गजीपुरा एवं पावली को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा में शय्याओं की संख्या बढ़ाकर 50 बेड चिकित्सालय किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. रानीवाड़ा में नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय सरनाऊ पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडगांव, मालवाड़ा, सांकड, सरनाऊ एवं राजीकावास को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

167. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मोबाइल यूनिट एम्बुलेसों द्वारा इलाज के नाम पर फर्जी भुगतान उठाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोरोना काल में विधायक मद से दी गई राशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोविड महामारी के बचाव हेतु विधायक मद से स्वीकृत राशि से दवाइयों तथा उपकरणों की खरीद में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

170. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में एन.यू.आर.एच.एम. के तहत निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रवरदायी एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नाका मदार में चिकित्सकों के लिए संविदा व्यवस्था समाप्त कर नियमित चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रवरदायी एवं सेटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर हेतु नवीन महिला चिकित्सकों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. अजमेर शहर के सेटेलाइट हास्पिटल आदर्श नगर को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भू-भाग पर चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के स्टाफ क्वार्टर्स बनाये जाने एवं धोलाभाटा स्थित राजकीय नगर स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु डीएमएफटी फण्ड से बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

172. अजमेर के सेटेलाइट चिकित्सालय में प्रतिदिन 1500 की OPD को ध्यान रखते हुए अतिरिक्त दवा काउन्टर व पर्ची काउन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. अजमेर सेटेलाइट चिकित्सालय में पी पी पी मोड पर संचालित डायलिसिस सेवा की निविदा फर्म को सरकार द्वारा पूर्व के बकाया का भुगतान नहीं किये जाने तथा बन्द कर दिये जाने के कारण स्थानीय रोगियों को आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

174. सरकार द्वारा सदन में लाये गये स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के कारण निजी अस्पतालों के संचालकों, डाक्टरों द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आर.जी.एच.एस. योजना में रोगियों का उपचार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

175. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित चिकित्सालयों में बेड बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित माडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरजगढ़ को मापदंड के आधार पर उपकरण, कार्मिक एवं संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित सूरजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित सभी राजकीय चिकित्सा इकाइयों पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित चिकित्सा इकाइयों पर मूलभूत उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

180. श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ में एम.आर.आई. मशीन उपलब्ध कराकर मरीजों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में संचालित विभिन्न राजकीय चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा के नवीन वाहन उपलब्ध कराने एवं वाहनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

183. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

185. विधान सभा क्षेत्र NHM के तहत ग्राम पंचायत फूटोलाव तहसील-आंधी (जयपुर) के नये उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले ठेकेदार तथा ANM के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

186. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में NH-148 पर स्थित रायसर के पास ट्रोमा अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

188. विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत गहनौली तथा उकरूंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र महवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावर में बेडों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 तक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

190. उप जिला अस्पताल, महवा को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

191. चूरू के सिरसला में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. चूरू के लालासर सहनाली खीवासागढ़ तथा चूरू शहर में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र चूरू के उपकेन्द्र के नवीन भवनों में चिकित्सा व्यवस्था संचालित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. चूरू जिला चिकित्सालय में विधायक विकास कोष से स्वीकृत राशि का उपयोग लम्बा समय गुजर जाने के बाद भी नहीं होने से उत्पन्त स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. जिला चिकित्सालय चूरू के ट्रोमा वार्ड में पूरा स्टाफ नहीं होने व सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

196. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा (भीलवाड़ा) में पर्याप्त एम्बुलेंसों की सुचारु व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा (भीलवाड़ा) में स्वास्थ्य व चिकित्सा हेतु भवनों की कमी को देखते हुए नये भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. जिला अस्पताल शाहपुरा (भीलवाड़ा) के सेटेलाइट हास्पिटल में स्वीकृत पदों पर चिकित्साकर्मियों यथा डाक्टर, नर्स व अन्य तकनीकी व सहायककर्मियों की रिक्तियों पर पदस्थापन की चर्चा के संबंध में।

199. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा (भीलवाड़ा) में स्थापित दवाइयों की दुकानों पर उचित मूल्य पर प्रमाणित दवाइयों की उपलब्धता के पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा (भीलवाड़ा) में चिकित्सा व स्वास्थ्य हेतु स्थापित इकाइयों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

201. प्रदेश में 2013 में नि:शुल्क जांच योजना में ई.सी.जी. जांच को शामिल किये जाने के कारण ई.सी.जी. टेक्नीशियन के पद रिक्त होने तथा जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

202. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन):

204. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में चिकित्सा के क्षेत्र में भामाशाहों द्वारा सहयोग किये जाने पर उनको राज्य स्तर पर सम्मानित करने हेतु विभागीय पहल तथा ग्राम अऊवा में नवीन भवन की स्वीकृति पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

205. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण (कोटा) के मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विंग में नई कैथ लैब लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कैंसर चिकित्सालय खोलने व पेप मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. कोटा दक्षिण के न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे आयुर्वेद व होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

208. रामगंज मण्डी में 70 बेडेड हॉस्पिटल व ट्रोमा अस्पताल की सुविधा प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

209. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम नेलिया, बिकनवास, वाडा भवजी, उचमत, धनपुरा एवं चेकला में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

210. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में बजट में घोषित जनता क्लिनिक को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. अजमेर स्थित जेएलएन मेडिकल कालेज में 2015 में स्थापित सीटीवीएस में हार्ट बाइपास सर्जरी की सुविधा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. जेएलएन हास्पिटल अजमेर सहित प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में न्यूनतम 01 योग विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कैंसर रोग संबंधी महंगे इंजेक्शन शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

215. विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) ऊण एवं उम्मेदपुर में बिल्डिंग (भवन निर्माण) के लिए बजट घोषणानुसार बजट आबंटित कराने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

216. पंडित भंवरलाल शर्मा उप जिला चिकित्सालय, सरदारशहर के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम जैतासर, खेजड़ा, मालसर व भादासर दिखनादा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम गोलसर व भानीपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न ग्राम आसासर, मांगासर, कुसुमदेसर, राजासर चोर्डिया, पातलीसर पुरोहितान, पनपालिया, उदासर चारणान, खुण्डिया, बणियासर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

220. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में सफाईकर्मियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

222. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के मास्टर खींवराज कच्छवाहा राजकीय चिकित्सालय को सेटेलाइट स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता की चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के एड पोस्ट कालीबेरी और एड पोस्ट मसुरिया को पी.एच.सी. स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के जिला अस्पताल प्रताप नगर और सेटेलाइट अस्पताल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में उनके स्तर के अनुरूप समस्त संसाधन उपल्ब्ध कराने की आवश्यकता की चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सेठ सूरजमल राजकीय चिकित्सालय, राजबाग, सूरसागर को सी.एच.सी. (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता की चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

226. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ग्राम गढ़बसई, अंगारी तथा द्वारापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

227. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उप जिला हास्पिटल में पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध कराने, सालवा कलला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा बुडकिया,

साथीन सब-सेन्टर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

228. विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्वीकृत (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊण एवं उम्मेदपुर में भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

229. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा की (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाणा (ब्लाक- गोविन्दगढ़) (जयपुर) को (CHC) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

230. विधान सभा क्षेत्र डग के उप स्वास्थ्य केन्द्र उमरिया, इरनावदा, पिपलिया खुर्द, देवगड़ तथा सिलेगड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र डग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बेड मय स्टाफ घोषित करने, आवर, उन्हेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने, डग में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र डग में चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने तथा नई एंबुलेंस उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

233. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और Sub-centre में पैरामीटर्स के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ की जर्जर बिल्डिंग के स्थान पर नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 365 RD (2KLD) को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. श्रीगंगानगर जिले में गर्भवती महिलाओं, शिशुओं एवं बच्चों के लिए

प्रेगनेन्सी, चाइल्ड ट्रेकिंग एवं हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम (PCTS) का सुचारु क्रियान्वयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्रामीण दूरस्थ एवं दूरगामी क्षेत्रों में प्रसूताओं के सुरक्षित प्रसव हेतु जननी एक्सप्रेस योजना से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

238. उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर शहर से बाहर नया भवन बनाकर शिफ्ट करने तथा मलसीसर, लाढ़ेसर, चरला सहित सभी पंचायत मुख्यालय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

239. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता क्लिनिक खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव प्रेमनगर व ढाकावाली में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

242. राजकीय जिला अस्पताल रतनगढ़ में सी.टी. स्कैन व सी.आर.एम. मशीन उपलब्ध करवाने एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव गोरीसर, परसनेऊ, जेगनिया बिदावतान स्थित राजकीय उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाछड़सर को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

244. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की सभी ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

245. प्रदेश की 4000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिए।

246. आर.के. जिला चिकित्सालय, राजसमंद में सघन चिकित्सा इकाई की शय्याओं में वृद्धि करने पर चर्चा के लिए।

247. आर.के. जिला चिकित्सालय राजसमंद में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं बड़ी संख्या में चिकित्सकों एवं सहचिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने हेतु चर्चा के लिए।

248. प्रदेश के स्थायी अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों एवं खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

249. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव रेवाड़ा, केऊ नई, मेहरामसर, गजपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रात्रि में रुकने एवं समय पर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की दुलचासर पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने, चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांव सोनियासर मीठियां, बापेऊ, बरजांगसर व बाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

252. जयपुर के विधान सभा नगर आवासीय कालोनी धावास, अजमेर रोड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

253. खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में पंचायत नालपुर तथा माधोगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, ग्राम पंचायत शिमला तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, अजीत अस्पताल खेतड़ी में 100 बेड की सुविधा शीघ्र शुरू करने तथा बडाऊ (CHC) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 बेड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

254. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के बोरखेड़ा क्षेत्र में जिला अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जगन्नाथपुरा में UPHC को PHC में, ग्राम कोलाना के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम किशनपुरा तकिया के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के आरामपुरा पंचायत में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के रायपुरा क्षेत्र में डिस्पेंसरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

259. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत मुख्यालय 16पी.एस. उप स्वास्थ्य केन्द्र को PHC में क्रमोन्नत करने, रायसिंहनगर CHC में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने, CHC रायसिंहनगर, श्रीबिजयनगर, समेजा में रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों को भरने तथा श्रीबिजयनगर CHC को बाजार से बाहर अन्यत्र आर.सी.पी. कालोनी पंचायत समिति भवन के पास स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

260. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्राम भट्टपुरा में PHC खोलने, PHC खोह को क्रमोन्नत करने तथा नगर के उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

261. विधान सभा क्षेत्र करौली की PHC में चिकित्सक व रेडियोलॉजिस्ट के पदस्थापन तथा PHC कोटरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

262. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के चिकित्सालयों में चिकित्सक के रिक्त पदों

को शीघ्र भरने, अस्पतालों के भवनों की मरम्मत कराने तथा नये क्वार्टर बनाने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र शाहपीनी, सालीवाला, पीर का मडिया, खाराखेड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिब्बी के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करने तथा CHC टिब्बी में एम्बुलेंस की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

264. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बजटीय घोषणा के बावजूद वार्ड 65 से 103 में जनता क्लिनिक नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बजटीय घोषणा के बावजूद सेटेलाइट हास्पिटल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में PHC/CHC पर विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बनने वाले सेटेलाइट हास्पिटल को खुली जेल की खाली भूमि या खादी बोर्ड के पास खाली पड़ी सरकारी भूमि पर निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

268. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर बीसीएमओ कार्यालय खोलने, नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित जेएलएन राजकीय चिकित्सालय में एमसीएच विंग के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने, नागौर जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में बायो वेस्ट एवं मेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने, खींवसर विधान सभा क्षेत्र के पालड़ी जोधा, ग्वालू, भोमासर, कांटिया, बैराथल कलां, रियां श्यामदास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं खजवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने तथा बासनी खलील, गोल्यासनी, कालियास, खुड़खुड़ा कलां, गुलासर, लुणावास, रावों की ढाणी, बेनीवालों की ढाणी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

269. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की CHC को सेटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किशनमानपुरा PHC के भवन निर्माण हेतु दानदाता द्वारा भूमिदान करने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

271. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का पट्टा जारी होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की PHC हस्तेड़ा व PHC चीथवाड़ी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के उप केन्द्र अनन्तपुरा-जैतपुरा, भूतेड़ा, उदयपुरिया को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

274. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के विस्तार को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (PMO) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के पदों को उप निदेशक स्तर का बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

275. प्रदेश में नई लागू RGHS योजना की प्रक्रिया एवं नियम जटिल होने के कारण सरकारी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनेक प्रकार की बाधाएं एवं कठिनाइयों का सामना करने के कारण, प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने अथवा पुरानी RPSF योजना को पुन: लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

276. जालौर जिले में दुर्घटना एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त नागरिकों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाये जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

277. विधान सभा क्षेत्र जालौर के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, टेक्नीशियनों एवं अन्य कार्मिकों के समस्त रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

278. जालौर में संचालित मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र में अत्याधुनिक शल्य क्रिया सम्पन्न किये जाने हेतु "लेप्रोस्कोपी एवं हिस्टेरोस्कोपी" मशीन तुरन्त उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

279. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में छात्रगंज/बादीपुरा में PHC खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के केलवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

282. जयपुर जिले में अजमेर रोड स्थित विधान सभा नगर 'धावास' में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

283. नव क्रमोन्नत सेटेलाइट हास्पिटल आमेर (जयपुर) के लिए भूमि आबंटन सेटेलाइट हॉस्पिटल के अनुरूप चिकित्सा स्टाफ एवं आवश्यक संसाधन अविलम्ब उपलब्ध करवाये जाने व वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र आमेर की CHC जालसू एवं CHC आमेर (नव क्रमोन्नत सेटेलाइट हॉस्पिटल) में विधायक कोष से उपलब्ध करवायी गयी एम्बुलेंसो पर स्थायी वाहन चालक नियुक्त किये जाने एवं CHC जालसू में सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट की स्थायी नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय चिकित्सा केन्द्रों पर विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू मुख्यालय पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. प्रदेश में RGHS स्कीम में OPD इंजेक्शनों की ब्रिकी पर रोक लगाये जाने के कारण सरकारी कर्मियों/पेंशनर्स को डे-केयर/अस्पताल में भर्ती होकर इंजेक्शन लगवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

288. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की ग्राम पंचायत कावतरा में PHC खोलने,

CHC-भीनमाल को 100 बेड तक बढ़वाने तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी):

289. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगांव (केकड़ी) में ANM, DCC Helper एवं LHV के पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में भवन रहित चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के चिकित्सा केन्द्रों के अन्तर्गत रिक्त चिकित्सकों एवं अन्य पदों पर कार्मिकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के नाई खेड़ा, काबरिया, गोवर्धनपुरा, बावड़ी, प्रतापपुरा, पीपरोली धाकड़ों की, काली तलाई का खेड़ा, अरनिया, अजगरी तथा इन्द्रपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

293. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरांई के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने तथा नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में जिला स्तरीय चिकित्सालय की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नव क्रमोन्नत/नव सृजित उपकेन्द्रों/ PHC/CHC के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

298. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर तथा किशनगढ़-रेनवाल स्थित

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

299. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मण्डा-भीमसिंह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डीप-फ्रीजर युक्त नई मोर्चरी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नई 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नये स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

303. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालय में स्तरीय सुविधाएं तथा स्टाफ के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने तथा उनके भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

306. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

307. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन हेतु बजट राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

308. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेडली में उप जिला अस्पताल शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम टिटपुरी, सौंख, गास में नई PHC खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

310. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

311. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नव सृजित ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक चिकित्साकर्मी पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

312. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या के अनुपात में स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

314. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में नर्स श्रेणी प्रथम की वरीयता सूची 2018 के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के नर्स श्रेणी प्रथम की पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

315. डूंगरपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों को आवश्यक उपचार एवं नि:शुल्क जांचों की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

316. डूंगरपुर जिले के PHC सूराता में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

317. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रियां बड़ी में चिकित्सक, सहायक स्टाफ व चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

318. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़तासिटी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

319. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसनगर, पादूकलां व रेण को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र लम्बा जाटान, लिलियां, जारोड़ा कला, लाडवा व रोहिसा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

320. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़तासिटी में स्वीकृत ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर):

321. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय नवलगढ़ में बेड संख्या 250 किये जाने तथा एमसीएच विंग, ब्लड बैंक एवं ट्रोमा सेंटर स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
322. राज्य के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के नये पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
323. राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक का नया पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
324. राज्य में एमबीबीएस डिग्रीधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हुए भी उन्हें राजकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नगराज (धरियावद):

325. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की चिकित्सा इकाइयों में डाक्टरों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

326. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
327. नसीराबाद उप जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
328. नसीराबाद चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
329. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन में डिजिटल एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
330. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के सभी PHC पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

331. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में C.H.C. के नये भवन का निर्माण करवाने व सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मांग संख्या 28-चिकित्सा शिक्षा पर रखे गये माननीय सदस्यों के लिखित वक्तव्य

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं)

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार तथा विधान सभा की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रिप्लाई बजट 2023-24 में निम्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कराने की उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करायें:-

क्र.सं.	पी.एच.सी. केन्द्र का नाम	प्रस्तावित सी.एच.सी.	पंचायत
1	मण्डेसरा	मण्डेसरा	मण्डेसरा
2	चेची	चेची	चेची
3	लाडपुरा	लाडपुरा	जालखेड़ा
4	नन्दवई	नन्दवई	नन्दवई

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार तथा विधान सभा की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रिप्लाई बजट 2023-24 में निम्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराने की उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करायें:-

क्र.सं.	उप.स्वा. केन्द्र	प्रस्तावित पी.एच.सी.	ग्राम पंचायत
1	दूधीतलाई	दूधीतलाई	राजपुरा
2	सिंगोला	सिंगोला	कांटी
3	खारखन्दा	खारखन्दा	खारखन्दा
4	सामरिया खुर्द	सामरिया खुर्द	सामरिया कला
5	गोपालपुरा	गोपालपुरा	गोपालपुरा
6	रेनखेड़ा	रेनखेड़ा	रेनखेड़ा
7	मालखेड़ा	मालखेड़ा	बलकुन्डी कलां

मेरा विधान सभा क्षेत्र बेगूं क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा 240 कि.मी. लम्बा है। ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है। आप द्वारा पिछले बजट में 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र PHC की घोषणा की थी। मेरे विधान सभा

क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत मांग है। मुझे एक भी PHC पिछले विगत वर्षों से नहीं मिली है। इसलिए आप मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 6 PHC स्वीकृत करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	उप.स्व.केन्द्र का नाम	प्रस्तावित पी.एच.सी.	ग्राम पंचायत	वि.वि
1	दूधीतलाई	दूधीतलाई	राजपुरा	ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है व मुख्यालय से 85 कि.मी. की दूरी पड़ती है और आस पास की 8 ग्राम पंचायतों में कोई भी PHC नहीं है।
2	रेनखेड़ा	रेनखेड़ा	रेनखेड़ा	रेनखेड़ा कुण्डाल क्षेत्र में पड़ता है व कुण्डाल क्षेत्र में 7 ग्राम पचायतें लगती हैं। ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है व मुख्यालय से 65 कि.मी. की दूरी पड़ती है और आस पास की 7 ग्राम पंचायतों में कोई भी PHC नहीं है।
3	खारखन्दा	खारखन्दा	खारखन्दा	ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है व मुख्यालय से 45 कि.मी. की दूरी पड़ती है और आस पास की 8 ग्राम पंचायतों में कोई भी PHC नहीं है।
4	सारण	सारण	लालास	ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है व मुख्यालय से 55 कि.मी. की दूरी पड़ती है और आस पास की 9 ग्राम पंचायतों में कोई भी PHC नहीं है।
5	नन्दवई	नन्दवई	नन्दवई	ST/SC बहुल एवं पिछड़ा हुआ इलाका है और आस पास की 7 ग्राम पंचायतों में कोई भी PHC नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार तथा विधान सभा की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रिप्लाई बजट 2023-24 में निम्न स्थानों पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराने की उचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करायें:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित पी.एच.सी.	ग्राम पंचायत
1	दूधीतलाई	दूधीतलाई	राजपुरा
2	सारण	सारण	लालास
3	गोरला	गोरला	सामरिया कलां

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ब्लाक बेगूं, गंगरार, भैसरोड़गढ़ के लगभग समस्त चिकित्सा विभाग में पिछले 5 वर्षों से पद रिक्त चल रहे हैं जिससे आम जनता को चिकित्सा सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। गम्भीर बीमारियां होने पर उनको बाहर जाना पड़ता है जिससे बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है कि पेपर को तुरन्त प्रभाव से टेबल कर चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का कष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र - बेगूं

स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2	0	2
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ	34	5	29
3	चिकित्सा अधिकारी	70	38	32
4	कनिष्ठ लिपिक	9	6	3
5	वरिष्ठ लिपिक	3	0	3
6	मेल नर्स प्रथम	37	19	18
7	मेल नर्स द्वितीय	162	132	30
8	सीनियर लैब टैक्निशियन	9	2	7
9	लैब टैक्निशियन	28	12	16
10	लैब सहायक (एलए)	25	4	21
11	फार्मासिस्ट	24	5	19
12	सीनियर रेडियोग्राफर	5	0	5
13	रेडियोग्राफर	4	1	3
14	सहायक रेडियोग्राफर	12	0	12
15	ईसीजी टैक्निशियन	3	0	3
16	एलएचवी	21	11	10

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
17	एएनएम	157	105	52
18	वाहन चालक	2	0	2
19	च. श्रेणी कर्मचारी	74	15	59
20	स्वीपर	24	2	22
21	अन्य	50	09	41
	कुल योग	**755**	**366**	**389**

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश और दुनिया में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति सामने आई थी। एक लहर आयी, फिर दूसरी आई जिसमें कई अपनों को खोया है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री को जिनके सार्थक प्रयासों से इन परिस्थितियों में भी अपनी डगर नहीं छोड़ी, अपितु और भी मजबूत होकर ऐसी भयावह त्रासदी का सामना करते हुए कोरोना महामारी के विरुद्ध अपने प्रबंधन द्वारा सम्पूर्ण देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में भीलवाड़ा व रामगंज माडल ने एक मिसाल कायम की है।

ऐसी महामारी के बावजूद पिछले 4 बजट व इस बजट में आमजन के लिए कल्याणकारी बजट पेश कर फिर से सम्पूर्ण देश के लिए एक रोल मॉडल का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त हों, इस संकल्प के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को और विराट रूप देते हुए इलाज के लिए होने वाली खर्चे की राशि की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 25 लाख रुपये किया है व राज्य से बाहर के अस्पतालों में भी इस योजना से इलाज का प्रावधान किया है जिसमें गम्भीर बीमारियां भी शामिल हैं जो पूरे देश में एक मिसाल है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले बजटों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उप जिला अस्पताल, ट्रोमा सेंटर, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिए, इसके लिए मै

माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मेरे एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हर आमजन के लिए आवश्यक है, इसलिए मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं जिनको स्वीकृत करने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ से गुजर रहे एन.एच. 148 ए दौसा से मनोहरपुर जो कि 2 लेन हाईवे है, जिस पर डिवाइडर नहीं होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वर्तमान में इस हाईवे पर कोई भी सी एच सी, ट्रोमा सेन्टर नही है। दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों के त्वरित इलाज हेतु हाईवे पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसर को सी एच सी मय ट्रोमा सेंटर में कमोन्नत किया जाता है तो निश्चित रूप से होने वाले हादसों में घायलों की जान बच सकेगी। साथ ही केन्द्र सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि एनएच 148 ए को फोरलेन मय डिवाइडर में तब्दील करे, ताकि हादसों में कमी आ सके।

- पीएचसी, रायसर; चावण्डिया व टोडा मीना को सी एच सी में क्रमोन्नत।

उप जिला अस्पताल, जमवारामगढ़ को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत।

उप जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु कल्याण यूनिट (MCH Wing) खोली जावे।

उप स्वास्थ्य केन्द्र, बुज; डांगरवाडा; नेवर; फुटोलाव; बिलोद, माथासुला, बहलोड, मानोता, धामस्या को पी एच सी में क्रमोन्नत।

मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पी एच सी खुले जिससे योजनाओं का ग्रामीण इलाकों में फायदा मिल सके।

ग्राम खरड, श्रीनगर, भट्ट का बास, छापरवास (बासना), सरजोली, सामोर, बादियावाला, नाभावाला, मीणों का बाढ, हरिकिशनपुरा, रामनगर, टीकमपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावें।